राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 229

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 26 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

शुभकामना संदेश

71वां गणतंत्र दिवस हम सभी देशवासियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग-सचेत कर जन-जन में सद्भाव का संचार करे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको हार्दिक बधाई।

प्रधान संपादक

दैनिक जागरण

उत्सव गणतंत्र का... तंत्र के गण

सराही की हर ओर सराहना

यह प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के छोटे से गांव सराही के लोगों की है, जिन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण-संवर्द्धन को लेकर जो जज्बा दिखाया, उसकी कीर्ति प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची। पेज-15

अरुण जेटली, सुषमा और जॉर्ज को पद्म विभूषण सम्मान

- मेरी कॉम को भी मिला दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान
- पीवी सिंधु, आनंद महिंद्रा और अनिरुद्ध जगन्नाथ पद्म भूषण से सम्मानित

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व केंद्रीय मंत्रियों- अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडीज के साथ-साथ मशहूर ओलंपियन मुक्केबाज मेरी कॉम को 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है।

शनिवार को इन नागरिक सम्मानों की घोषणा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस साल सात प्रमुख हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 शख्सियतों को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित शख्सियतों में जॉर्ज फर्नांडीज (मरणोपरांत), अरुण जेटली (मरणोपरांत), मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, मेरी कॉम, छन्नू लाल मिश्रा, सुषमा स्वराज (मरणोपरांत) और श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी जी श्री पेजावर अधोक्षजा मठ उडुपी (मरणोपरांत) शामिल हैं। जबकि पद्म भूषण से सम्मानित हस्तियों में एम. मुमताज अली, मुअज्जम अली (मरणोपरांत), मुजफ्फर हुसैन बेग, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, बालकृष्ण दोशी, कृष्णअम्मल जगन्नाथ, नगालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एससी जमीर, उत्तराखंड के जाने-माने पर्यावरणविद और समाजसेवी डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, शेरिंग लैंडल, प्रख्यात उद्योगपति आनंद महिंद्रा, नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन (मरणोपरांत), पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रीकर (मरणोपरांत), प्रो. जगदीश सेठ, ओलंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और उद्योगपति वेणु श्रीनिवासन शामिल हैं। जबकि पद्मश्री सम्मान पाने वाली शख्सियतों में अदनान सामी, करण जौहर, कंगना रनौट, एकता कपूर, सुरेश वाडकर, उद्योगपति भरत गोयनका, शूटर जीतू राय और गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह (मरणोपरांत) भी शामिल हैं। मालूम हो कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण भारत रत्न के बाद देश के क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हैं।

अरुण जेटली

सुषमा स्वराज

जॉर्ज फर्नांडीज (सभी फाइल)

पद्मश्री पाने वालों में कई गुमनाम नायक पेज>>5

जम्मू-कश्मीर पुलिस को 108 वीरता पुरस्कार

- गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 409 वीरता पुरस्कारों की घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसियां : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 409 वीरता पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। यह पुरस्कार पाने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर ब्वॉय बुरहान वानी को मार गिराने वाले जांबाज अधिकारी अब्दुल जब्बार भी शामिल हैं। 2008 बैच के आइपीएस अधिकारी अब्दुल जब्बार तब अनंतनाग जिले के एसएसपी थे। मूलरूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले जब्बार ने पुलिस टीम के साथ आठ जुलाई, 2016 को मुठभेड़ में वानी को मार गिराया था। बाद में उन्हें खुफिया ब्यूरो में भेज दिया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 108 वीरता पुरस्कार मिले हैं। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लड़ाई में अदम्य साहस और वीरता दिखाने वाले पुलिस के जवानों को सम्मानित किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस को चार में से तीन राष्ट्रपति पुलिस पदक (पीपीएमजी) भी मिले हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा वीरता पदक पाने वाली पहली पुलिस बल बन गई है। बता दें कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।

सीआरपीएफ को 76 वीरता पदक पेज>>5

रविवार विशेष

हैलो-हाय छोड़िये, जय हिंद बोलिये, अरुणाचल से सीखिये

कोलकाता : पीएम मोदी ने हाल ही में 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश की एक प्रेरक विशेषता का जिक्र किया था। यह जिक्र वह इससे पहले 2015 और फिर 2018 में भी कर चुके थे। पड़ताल के लिए हमने अरुणाचल का रुख किया। मोदी जी ने सच कहा था...। (पेज-5)

न्यूज गैलरी

राज-नीति पृष्ठ 3

नेपाल ने भारत व पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की

काठमांडू : भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए नेपाल ने शनिवार को कश्मीर और सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की है। परमाणु शक्ति संपन्न दोनों पड़ोसियों के बीच मध्यस्थता की पेशकश करने वाला नेपाल पहला दक्षिण एशियाई देश है।

नेशनल न्यूज पृष्ठ 6

कश्मीर में मुठभेड, जैश कमांडर कारी सहित तीन आतंकी ढेर

श्रीनगर : गणतंत्र दिवस पर घाटी में एक बड़े आत्मघाती हमले की साजिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम बना दिया। दक्षिण कश्मीर के त्राल में शनिवार को 11 घंटे तक चली एक भीषण मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मुहम्मद के कुख्यात कमांडर कारी यासिर समेत तीन आतंकियों को ढेर कर दिया।

विश्व कप की तैयारी

दूसरा टी-20	दोपहर 12:20 बजे से
भारत vs न्यूजीलैंड	स्थान : ऑकलैंड
	प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

राष्ट्र के नाम संबोधन ▸ 71वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नसीहत

हिंसा से नहीं मिलता कोई लक्ष्य

कहा, हम लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहें, यही विकास का उत्तम मार्ग

नई दिल्ली, एजेंसियां : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर मचे बवाल के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के लोगों, खासकर युवाओं को नसीहत दी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन में अहिंसा के रास्ते पर चलना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसा से कभी कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता।

हालांकि, शनिवार को शाम 7 बजे राष्ट्रपति कोविंद ने देशवासियों को संबोधित करते हुए सीएए का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करने का सबको हक है। संविधान के मुताबिक चलकर ही सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। किसी भी उद्देश्य के लिए संघर्ष करने वाले लोगों, विशेष रूप से युवाओं को, महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र को सदैव याद रखना चाहिए, जो कि मानवता को उनका अमूल्य उपहार है।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारे संविधान ने हम सब को एक स्वाधीन लोकतंत्र के नागरिक के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। लेकिन संविधान के अंतर्गत ही, हम सब की जिम्मेदारी भी तय है कि हम न्याय, स्वतंत्रता व समानता तथा भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता एवं प्रतिपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति के साथ-साथ, देश के समग्र विकास और सभी देशवासियों के कल्याण के लिए दोनों को मिल-जुलकर आगे बढ़ना चाहिए।

मौजूदा दशक युवाओं का : राष्ट्रपति ने युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि इस शताब्दी में जन्मे युवा, बढ़-चढ़ कर, राष्ट्रीय विचार-प्रवाह में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मुझे, इन युवाओं में, एक उभरते हुए नए भारत की झलक दिखाई देती है। 21वीं सदी का तीसरा दशक युवाओं का होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए, महात्मा गांधी के विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं. सत्य और अहिंसा का उनका संदेश हमारे आज के समय में और भी अधिक आवश्यक हो गया है।

अभियान को लोगों ने जन आंदोलन बनाया : राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि मोदी सरकार ने जनकल्याण के लिए कई अभियान चलाएं। आम लोगों ने इन अभियानों में भाग लेकर उन्हें जन आंदोलन का रूप दिया है। आम लोगों की भागीदारी के कारण 'स्वच्छ भारत अभियान' को बहुत ही कम समय में प्रभावशाली सफलता मिली है। 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत आठ करोड़ लाभार्थियों तक साफ ईंधन पहुंचा है। इसके तहत इन लाभार्थियों को रसोई गैस दिए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत योजना के जरिए जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। 14 करोड़ से अधिक किसानों को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' का लाभ मिला है। इससे हमारे अन्नदाता प्रति वर्ष छह हजार रुपए की न्यूनतम आय प्राप्त करने के हकदार बने हैं।

जीएसटी की भी सराहना की : मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इससे 'एक देश, एक कर, एक बाजार' की अवधारणा को साकार रूप मिल सका है। इसी के साथ 'ई-नाम' योजना द्वारा भी 'एक राष्ट्र के लिए एक बाजार' बनाने की प्रक्रिया मजबूत बनाई जा रही है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचेगा।

देश के विकास के लिए सतत प्रयासरत : राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश के हर हिस्से के संपूर्ण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। चाहे वह जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हो, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हों या हिंद महासागर में स्थित हमारे द्वीप-समूह हों। देश के विकास के लिए एक सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का होना भी जरूरी है। इसीलिए सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं।

राष्ट्रपति ने शिक्षा पर दिया जोर : राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में हमारी कई उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। हमारा प्रयास है कि देश का कोई भी बच्चा अथवा युवा, शिक्षा की सुविधा से वंचित न रहे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों पर हम सभी देशवासियों को बहुत गर्व है।

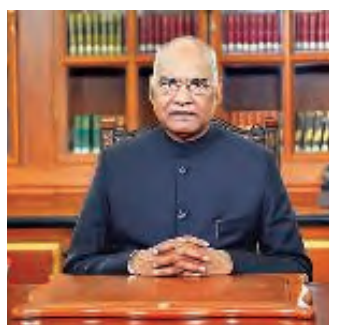

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एएनआइ

खास बातें

- 14 करोड़ लोगों को पीएम किसान निधि का लाभ मिला
- जनकल्याण के लिए देश में कई योजनाएं चलाई गईं
- उज्ज्वला योजना के तहत जरूरतमंद लोगों तक साफ ईंधन पहुंचा
- स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र पर ध्यान दिया गया
- जीएसटी से एक देश, एक कर, एक बाजार की अवधारणा साकार हुई

भीमा-कोरेगांव मामला एनआइए को सौंपे जाने पर घमासान

- महाराष्ट्र सरकार बोली- फैसला संविधान के खिलाफ, हमारी राय तक नहीं ली गई
- भाजपा ने कहा, भीमा-कोरेगांव मामला पीएम मोदी के खिलाफ साजिश थी

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र के यलगार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले की जांच अचानक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के हाथ में जाने से राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि यह फैसला लेने से पहले राज्य सरकार की राय तक नहीं ली गई। वहीं, भाजपा का कहना है कि यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साजिश थी। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनआइए मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा। साफ है कि कांग्रेस-राकांपा को जांच एनआइए के हाथ में जाना बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। हालांकि शिवसेना का कोई बड़ा नेता अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहा है।

31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवार वाड़ा के बाहर सीपीआइ (एम) के सहयोग से हुए यलगार परिषद के बाद अगले ही दिन पुणे के दूसरे हिस्से में भीमा-कोरेगांव में हिंसा हो गई थी। इसमें एक युवक मारा गया था। पुलिस ने इन दोनों मामलों की अलग-अलग एफआइआर दर्ज की थी। पुणे पुलिस का मानना था कि यलगार परिषद में दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण ही भीमा-कोरेगांव में हिंसा भड़की थी। यलगार परिषद की जांच आगे बढ़ने पर इसके तार नक्सलवादियों से जुड़ते दिखाई दिए और अब तक इस मामले में 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी अब भी नहीं हो सकी है। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद इस मामले की पुनः जांच की मांग उठने लगी तो राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर यलगार परिषद मामले की पुनः जांच के लिए एसआइटी गठित करने की सिफारिश की। अब अचानक एनआइए द्वारा इस मामले की जांच अपने हाथ में ले लेने से कांग्रेस-राकांपा दोनों स्तब्ध हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार उद्धव ने पवार के पत्र पर कोई टिप्पणी नहीं लिखी है। इसके बावजूद उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल, पुणे के पुलिस आयुक्त वेंकटेश्वरम् और इस मामले की जांच करने वाले तत्कालीन संयुक्त पुलिस आयुक्त रवींद्र कदम को मंत्रालय बुलाकर जानकारी ली। बताया जाता है कि इन अफसरों ने दोनों को बताया कि पुणे पुलिस द्वारा की गई जांच बिल्कुल सही थी। सभी आरोपितों के विरुद्ध पक्के सुबूत भी हासिल हुए हैं। ऐसे मौके पर, जबकि आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका हो, यह मामला राज्य की ही किसी दूसरी एजेंसी को सौंपना उचित नहीं होगा।

अफसरों ने मंत्रियों को अदालत के निर्देशों की दी जानकारी पेज>>6

दिल्ली में कोचिंग सेंटर की छत गिरी, चार की मौत

- पहली से बारहवीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था ट्यूशन
- मृतकों में एक शिक्षक भी शामिल, पांच बच्चों का चल रहा इलाज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में भजनपुरा इलाके में एक कोचिंग सेंटर की छत गिरने से अंदर पढ़ाई कर रहे तीन बच्चों और एक शिक्षक की मौत हो गई। इमारत की तीसरी मंजिल निर्माणाधीन थी और लेंटर पड़ा हुआ था। इस दौरान लेंटर भरभराकर ढह गया जिस कारण दूसरी मंजिल की छत भी गिर गई। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सुभाष मोहल्ला के गली नंबर-6 में दो भाई हरिशंकर और उमेश अपने मकान में ही एजुकेशनल प्वाइंट के नाम से कोचिंग सेंटर चला रहे थे। इसमें पहली से बारहवीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता था। इस दो मंजिला मकान के ऊपर तीसरी मंजिल पर कमरा बनाया जा रहा था। दूसरी मंजिल की छत गाटर और पट्टियों पर होने के कारण कमजोर थी। शनिवार अपराह्न करीब चार बजे अचानक निर्माणाधीन कमरा गिर पड़ा। गाटर और पट्टियों पर टिकी छत वजन नहीं संभाल पाई और आ गिरी। दूसरी मंजिल के कमरे में पढ़ाई कर रहे करीब 11 बच्चे और दो शिक्षक इसकी चपेट में आ गए। मलबा गिरने की आवाज हुई तो स्थानीय लोग मदद के लिए भागे। मलबे में दबे बच्चों को निकालने का काम शुरू किया गया। इस दौरान भी ऊपर से ईंटें गिर रही थीं। पुलिस के साथ दमकल विभाग, जिला आपदा प्रबंधन और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं। एंबुलेंस से सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन बच्चों और एक शिक्षक को मृत घोषित कर दिया गया। शिक्षक की पहचान उमेश उर्फ बल्ली (30) और बच्चों की पहचान दिशु (14), कृष्णा (12) और फुरकान (6) के रूप में हुई है। पांच बच्चों का इलाज चल रहा है।

40 साल पुराना है मकान

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मकान करीब 40 पुराना है। पहले एक मंजिला था। बाद में इस पर दूसरी मंजिल तैयार की गई। इसकी छत गाटर और पट्टियों से बनी थी, जो मजबूत नहीं होती है।

जेएनयू के छात्र ने कहा, असम को अलग कर देंगे

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन के दौरान विवादित बयान देने का जेएनयू नेता छात्र शरजील इमाम का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें शरजील देश को तोड़ने की धमकी देते हुए कह रहा है, 'हमारे पास संगठित लोग हों तो हिंदुस्तान को असम से अलग कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम व हिंदुस्तान अलग हो जाएंगे, तभी ये हमारी बात सुनेंगे।'

पुलिस ने छात्र पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम दिल्ली रवाना हो गई है। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अलीगढ़ में देशद्रोह का पहला केस दर्ज हुआ है। एसएसपी आकाश कुलहरि ने शनिवार को मीडिया को बताया कि दो दिन से सोशल मीडिया पर यह वीडियो ट्रेंड कर रहा है। 1.18 मिनट का यह वीडियो जेएनयू से पीएचडी कर चुके शरजील इमाम का है। पहले वीडियो को शाहीन बाग (दिल्ली) का माना जा रहा था। वीडियो की पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बयान एएमयू में 16 जनवरी को दिया गया था। खुफिया विभाग व एएमयू प्रशासन ने भी शरजील के बयान की पुष्टि की है। शरजील ने ही बयान को वीडियो को फेसबुक पर वायरल किया है। वीडियो में छात्र नेता असम को लेकर विवादित बयान देते नजर आ रहा है। ट्विटर पर भी शेयर किया है। वीडियो में दिए गए बयान को राष्ट्रविरोधी मानते हुए इंस्पेक्टर सिविल लाइन अमित कुमार ने शरजील के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है।

भाजपा बोली, रची जा रही देश बांटने की साजिश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : शरजील इमाम का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि शाहीन बाग में देश को बांटने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया इस वीडियो को शाहीन बाग का बता रहा है, जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसमें एक व्यक्ति मुस्लिमों से असम को देश से अलग करने का आह्वान कर रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर दिए जा रहे धरने में देशविरोधी साजिश रची जा रही है।

बदला रंग

अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर उल्लास का माहौल, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले समारोह में दिखेगी मजबूत लोकतंत्र की धमक

नए जम्मू-कश्मीर में दिखेगा गणतंत्र का दम

रोहित जंडियाल, जम्मू

इस बार जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूरे देश के लिए गणतंत्र दिवस के मायने कुछ खास हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की बेड़ियां हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब पूरे देश में एक निशान-एक संविधान लागू हो चुका है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ केंद्र शासित लद्दाख में भी पहले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर चारों ओर उल्लास का माहौल है। हालांकि प्रशासन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सामान्य होते हालात के बीच लोगों में पूर्ण विश्वास बहाली, आतंक से मुक्ति प्रशासन के एजेंडे में शीर्ष पर हैं।

हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के आउटरीच प्रोग्राम के तहत सात दिन में 36 केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू-कश्मीर में दौरे इसी तरह के कई मोर्चों पर तस्वीर बदलने के उद्देश्य पर आधारित थे। जम्मू-कश्मीर में गणतंत्र दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए प्रशासन व स्थानीय लोगों ने खास तैयारी की है। सरकारी समारोह स्थल जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम और श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम को खास तरह से सजाया गया है। स्थानीय लोग भी हर चौराहे और ऐतिहासिक स्थलों पर तिरंगा फहराने के लिए उत्सुक हैं। कुल मिलाकर 26 जनवरी को पूरे जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए यह गणतंत्र दिवस खास मायने रखता है। पहले भी यहां पर तिरंगा ही फहराया जाता था, लेकिन जम्मू-कश्मीर के अपने संविधान और झंडे की विशेष उपस्थिति रहती थी। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पूरी तरह भारतीय संविधान प्रभावी है। पहली बार जम्मू-कश्मीर में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का नारा बुलंद हुआ है। देश भक्ति की भावना दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में मजबूत हुई है। तिरंगे के रंग में जगमग हो रहे जम्मू-कश्मीर के सभी चौक-चौराहे और ऐतिहासिक स्थल गणतंत्र दिवस का उल्लास के साथ स्वागत कर रहे हैं। सभी सरकारी इमारतें, मुबारक मंडी के साथ कई निजी इमारतें भी रोशनी से नहाई हुई हैं।

गणतंत्र दिवस को लेकर गुरुवार को श्रीनगर में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल की फाइल फोटो। जागरण

इन चुनौतियों से है निपटना

- आतंक का जड़ से खात्मा और भटके युवाओं को मुख्यधारा में लाना -कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी, इंटरनेट सेवा की पूर्ण बहाली
- राजनीतिक गतिविधियों में तेजी, लोगों के बीच भरोसे को और मजबूत करना
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को विकास की कसौटी पर आगे लाना

उपराज्यपाल फहराएंगे तिरंगा पेज>>6
संवैधानिक स्वतंत्रता का मनमाना इस्तेमाल (प्रमुख आलेख) पेज>>8

भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के प्रचार करने पर 48 घंटे तक रोक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को चुनाव से जोड़कर विवादित ट्वीट करने के मामले में मॉडल टाउन विस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ एक दिन पहले चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होने के बाद अब 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है।

चुनाव आयोग के अनुसार, कपिल मिश्रा ने 22 व 23 जनवरी को विवादित बयान दिया, जिसके कारण उनके चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट में शाहीन बाग को मिनी पाक बताते हुए कहा था कि आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान व पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। इस मामले में चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

कपिल मिश्रा। फाइल

हमने देश का विकास किया अब दिल्ली को चमकाएंगे : शाह

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार को भाजपा की ओर से आयोजित 'जीत की गूंज' कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि अब दिल्ली में भी भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। (पेज-2)

593 पुरुष व 79 महिला सहित कुल 672 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। आप, कांग्रेस व भाजपा के अलावा कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 26 जनवरी 2020

परिवार का साथ और मां का प्यार देता है राघव को ऊर्जा

प्रियंका दुबे मेहता, नई दिल्ली

राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राघव चड्ढा की छवि यूथ आइकन के तौर पर भी स्थापित हो गई है। इसका कारण है उनका स्टाइल, उनकी फिटनेस और उनका प्रजेंटेबल एटीट्यूट। चाहें वह ईश्वर के द्वार पर हों या फिर दिल्ली की गलियों में आम आदमी की समस्याएं जानने में व्यस्त हों, हमेशा अपने कपड़ों, रहन-सहन और खानपान का पूरा ध्यान रखते हैं। वैसे तो उनका कहना है कि एक्टिव रहने से व्यक्तित्व में निखार स्वयं आ जाता है, लेकिन समय मिलने पर वह फिटनेस और सुकून पर भी ध्यान देते हैं। वह कहते हैं कि परिवार का साथ और मां का प्यार उन्हें ऊर्जा और उत्साह से भर देता है।

थकान उतार देती है परिवार के साथ चाय की चुस्की : पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव वैसे तो फिटनेस फ्रीक हैं, लेकिन चुनाव के दौरान, साइकिलिंग, वॉक और जिमिंग पूरी तरह बाधित हो जाती है। दिनभर की रैलियां, सभाएं और लोगों से मिलने-जुलने की थकान उतारने के लिए वह आधे घंटे के लिए अपने लिए वक्त निकालते हैं और परिवार के साथ चाय की चुस्कियां लेते हैं। इस दौरान परिवार का उत्साहवर्धन, मां की केयरिंग बातें और अन्य सदस्यों का स्नेह उन्हें ऊर्जा से भर देता है।

संतुलित आहार से रहते हैं फिट : जिम में कार्डियो करते हुए पसीना बहाना, साइकिलिंग का लुत्फ लेना और बुद्धा जयंती पार्क व सिंधी पार्क में वॉक करना, यह सब चुनाव प्रचार के चलते इन दिनों बंद है। मौका मिलने पर शाम को कुछ डंबल्स आदि कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक इसी तरह की दिनचर्या चल रही है। ऐसे में फिटनेस प्रभावित न हो, इसके लिए वह संतुलित और पौष्टिक आहार लेना नहीं भूलते। कहीं भी हों, मां के हाथ का बना खाना, सलाद, फल व दूध नियमित रूप से पीते हैं। राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी रहे राघव मौका मिलने पर इसमें हाथ आजमाने से भी नहीं चूकते।

राजनीति में आराम नहीं : चुनावी भागदौड़ के बाद ब्रेक लेने की प्लानिंग है। इस सवाल पर राघव कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उतरे हैं, उसमें ब्रेक और आराम जैसी कोई चीज नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने पर पता चलता है कि वह खुद भी बीस-बीस घंटे काम करते हैं और सबसे यही उम्मीद करते हैं।

पालतू कुत्ता है स्ट्रेस बस्टर : कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, काम का कितना भी तनाव हो, आधे से पौन घंटा अपने कुत्ते के साथ बिताना उनके रूटीन का हिस्सा है। राघव कहते हैं कि वह उनका इंतजार करता रहता है और जाते ही उनकी गोद में बैठ जाता है। दिनभर का तनाव उतारने के लिए अपने कुत्ते (लासाएप्सो) के साथ खेलते हैं और वही उनका सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है।

कपड़ों की डिजाइनिंग करते हैं मामा : राघव का मानना है कि जरूरी नहीं कि आप राजनीति में आएं तो अपने मूलअंदाज को बदल दें, तभी सफल नेता बन सकते हैं। आम आदमी की तरह ही फैशन और स्टाइल को भी पहले की ही तरह फॉलो करते हैं। हर ब्रांड, हर तरह के डिजाइन को पसंद करते हैं। इस दौरान आरामदायक कपड़ों में कुर्ता पायजामा और ब्लू जींस, ब्लैक टीशर्ट पहनने में सहज महसूस करते हैं। इसके अलावा फैशन डिजाइनर मामा पवन सचदेव उनके लिए फॉर्मलवियर डिजाइन करते हैं, जिसे राघव शौक से पहनते हैं।

लाइफस्टाइल

अपने पालतू कुत्ते के साथ फुरसत के पल बिताते राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी राघव चड्ढा। जागरण

सूफी से लेकर हिपहॉप म्यूजिक तक का कलेक्शन

राघव संगीत प्रेमी भी हैं। उनके म्यूजिक कलेक्शन में गुलाम अली से लेकर अनु मलिक, सूफी से लेकर हिपहॉप और भोजपुरी से लेकर अंग्रेजी गाने तक मिलते हैं। उनका कहना है कि संगीत अपने हर रंग में खूबसूरत और ऊर्जादायक होता है। इसके अलावा किताबों के दो पन्ने भी पलटने का समय निकाल लेते हैं। नेटफ्लिक्स पर थोड़ी देर फिल्में भी देख लेते हैं।

केजरीवाल का शाह को निमंत्रण दिल्ली के किसी भी स्कूल में चलें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विकास कार्यों व दिल्ली के स्कूलों पर उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाह पर हमला बोला है। उन्होंने शाह को निमंत्रण दिया कि वह किसी भी स्कूल में उनके साथ चलकर देख लें, स्कूलों में जो बदलाव आया है, उसे वह दिखा देंगे। मुख्यमंत्री पार्टी मुख्यालय पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि शाह उन्हें या उनकी पार्टी को खूब गाली दें, लेकिन दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाकर 16 लाख छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों का अपमान न करें। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ देश ही नहीं, बल्कि दुनिया मे हो रही है। शिक्षा को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। वोट इस बात पर पड़ने चाहिए कि आप ने स्कूल अच्छे कराए या नहीं कराए, बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शाह ने दिल्ली के स्कूल खराब होने का गलत बयान दिया है। सरकारी स्कूल के बच्चों, अध्यापकों व उनके माता-पिता की मेहनत का ही नतीजा है कि 12वीं में दिल्ली सरकार के स्कूलों का नतीजा 96 फीसद आया। सरकारी स्कूल के 300 से अधिक बच्चों ने जेईई की प्रवेश परीक्षा पास की है। 400 से अधिक बच्चों ने आइआइटी प्रवेश परीक्षा पास की है। हम दिल्ली सरकार के स्कूलों में सुधार कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश व हरियाणा के स्कूलों में सुधार कीजिए, दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों में सुधार कीजिए और फिर हमारी तरह आप भी स्कूलों में आप के नेताओं को बुलाकर दिखाएं।

चुनाव के समय शाह को याद आता कार्यकर्ताओं का घर : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कालकाजी में चुनावी जनसभा में कहा कि दिल्ली का विकास चाहते हैं तो इस बार फिर से आप को वोट भारी वोटों से जिताएं। केजरीवाल ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त कार्यकताओं के घर जाना याद रहता है।

चुनावी हलचल

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में 56 मामले दर्ज

नई दिल्ली : चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 56 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार, अब तक 358 मामले पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 347 मामलों में एफआइआर व 11 मामलों में डीडी एंट्री कर कार्रवाई की जा रही है। ये सभी मामले चुनाव प्रचार के लिए बैनर-पोस्टर लगाकर संपत्तियों को बदरंग करने में दर्ज किए गए हैं। वहीं करीब एक करोड़ की रकम और जब्त की गई है। एक दिन पहले तक पांच करोड़ 64 लाख 67 हजार 920 रुपये की रकम जब्त की गई थी। अब जब्त रकम बढ़कर छह करोड़ 64 हजार 99 हजार 340 रुपये हो गई है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों व शराब जब्त करने की कार्रवाई भी चल रही है। चुनाव प्रचार में मतदाताओं को लालच देने का खेल भी शुरू हो गया है। सीईओ कार्यालय के अनुसार, वाहनों के दुरुपयोग, लाउडस्पीकर से संबंधित नियमों के उल्लंघन, अवैध बैठकों व मतदाताओं को लालच देने के आरोप में 14 मामले दर्ज हुए हैं। (जासं)

दिल्ली कांग्रेस के महासचिव आप में शामिल

नई दिल्ली : दिल्ली कांग्रेस के महासचिव चौधरी रतन सिंह समेत कई नेता शनिवार को आप में शामिल हो गए। राज्यसभा सदस्य व दिल्ली चुनाव प्रभारी संजय सिंह ने सभी नेताओं को टोपी और पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर विधायक हाजी इशराक खान और मनोनीत पार्षद रामराज तिवारी भी मौजूद रहे। संजय सिंह ने कहा कि चौधरी रतन सिंह लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं और कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली है। (जासं)

आप सरकार ने दिल्ली को वर्षों पीछे कर दिया : शाहनवाज

नई दिल्ली : भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश की राजधानी को वर्षों पीछे कर दिया है। दिल्ली के विकास के लिए जो भी वादा किया गया, उसे अधूरा छोड़ दिया गया है। अभी मैंने लक्ष्मीनगर विस क्षेत्र देखा है सब ओर बदहाली है। कहीं विकास का कार्य दिखता ही नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा। अगली सरकार भाजपा की बनने जा रही है जिससे दिल्ली के विकास को पंख लगेंगे। उन्होंने यह बात लक्ष्मीनगर के ललिता पार्क में आयोजित सभा के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने यहां के भाजपा प्रत्याशी अभय वर्मा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। (जासं)

'देश का विकास किया, अब दिल्ली को चमकाएंगे'

सियासी वार ▶ केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राजधानी की जनता का हक मारा

कहा, केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं बनाया, दिल्ली को सिर्फ जहरीली हवा-पानी दिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार को भाजपा की ओर से आयोजित 'जीत की गूंज' कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पार्टी की आइटी व सोशल मीडिया सेल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शाह ने कहा कि जब-जब हमारे साइबर योद्धाओं ने कमान संभाली है, भाजपा और नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। अब दिल्ली में भी भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।

शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जहरीली हवा-पानी के अलावा कुछ नहीं दिया। केजरीवाल ने हमेशा झूठ बोला है। उन्होंने पांच साल में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बदतर हो गया है। ढाई लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। दिल्ली जल बोर्ड को करोड़ों के घाटे में पहुंचा दिया। वहीं, भाजपा ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के 50 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घरों का मालिकाना हक दिलाया है। भाजपा ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तीन तलाक को खत्म किया लेकिन केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते रहे। इसलिए हमने अपने साइबर योद्धाओं को केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश कर उन्हें बेनकाब करने के लिए बुलाया है।

सीएए पर लोगों को भड़का रही आप व कांग्रेस : अमित शाह ने कहा कि मोदी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश में प्रताड़ना के कारण भारत आए लोगों को नागरिकता देने के लिए सीएए लागू किया। अब आप और कांग्रेस इसके बारे में अफवाह फैलाकर हिंसा फैला रही हैं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। वोट बैंक के लालच में आप व कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वे शाहीन बाग के साथ हैं। क्या ये देश व दिल्ली को सुरक्षित रख सकते हैं। देश को सिर्फ भाजपा सुरक्षित रख सकती है।

शाह ने कहा कि केजरीवाल को जिताने के लिए जेएनयू वाले लगे हैं। उन्होंने नई बसें लाने का वादा किया था, लेकिन 1087 बसें कम कर दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया। वहीं, केजरीवाल ने मेट्रो के चौथे चरण को ढाई साल तक लटकाए रखा। कहां गए केजरीवाल के 15 लाख सीसीटीवी कमरे, कहां गई फ्री वाईफाई। दिल्ली सरकार के अस्पतालों का बुरा हाल है। मोदी सरकार पूरे देश में पीएम आयुष्मान भारत योजना लाई, लेकिन, दिल्ली में केजरीवाल ने इसे लागू नहीं होने दिया। उन्हें डर है कि इस योजना से गरीबों को पांच लाख का मुफ्त इलाज मिलने लगेगा तो जनता मोदी के साथ जुड़ जाएगी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा का मुकाबला झूठ की राजनीति करने वाली आप से है। इससे पहले दिल्ली में 15 साल तक जिन्होंने शासन किया, उनके समय में भी झुग्गी में एक नल तक नहीं पहुंचा। केजरीवाल पिछले साढ़े चार साल तक कहते आ रहे थे कि केंद्र व एलजी उन्हें काम नहीं करने दे रहे। लेकिन अब कह रहे हैं अच्छे बीते पांच साल। शाहीन बाग में मोदी व अमित शाह की हत्या की बात कहने वालों का समर्थन करने वालों को जनता आठ फरवरी को जवाब देगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, सांसद रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, विजय गोयल, गौतम गंभीर, प्रवेश वर्मा, हंसराज हंस समेत तमाम नेता मौजूद रहे।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भाजपा की ओर से आयोजित 'जीत की गूंज' कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जागरण

झूठ बोलने की स्पर्धा में अव्वल रहेगी दिल्ली सरकार : शाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी (आप) पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकारों के बीच विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा तो देखी है, लेकिन ऐसी सरकार नहीं देखी जो झूठ बोलने में प्रतिस्पर्धा करे। अगर कहीं झूठ बोलने की प्रतियोगिता होगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार पहले स्थान पर रहेगी। वह शनिवार की शाम बादली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय भगत व बवाना से प्रत्याशी रविंद्र कुमार इंद्रराज के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम सबको पीने का स्वच्छ पानी देंगे, लेकिन पिछले दिनों 21 राज्यों में हुए सर्वे में दिल्ली के पानी की गुणवत्ता सबसे खराब रही। यहां जहर जैसी हवा और प्रदूषित पानी देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। केजरीवाल सरकार ने 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, पांच हजार बसें, पूरी दिल्ली में मुफ्त वाईफाई व जनलोकपाल के वादे पूरे करने के बजाय लोगों को गुमराह करने का काम किया। दिल्ली में शिक्षा का सत्यानाश करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। यही कारण रहा कि न बस्ती और न ही मोहल्ले में नया स्कूल खुला है।

सुभाष चोपड़ा का तंज, अब अमीरों की पार्टी बन गई है आप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि हर देश में और विशेष रूप से भारत में क्रांति और बदलाव के वाहक युवा और छात्र रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद अपनी प्रतिभा, शिक्षा और जोश का उपयोग देश और समाज निर्माण में किया है। उन्होंने शनिवार को कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद जनसभाओं को संबोधित के दौरान ये बातें कहीं।

उन्होंने त्रिनगर, शालीमार बाग और पटेल नगर विधानसभा में चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि योगगुरु रामदेव संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे जेएनयू और जामिया मिल्लिया के छात्रों से आंदोलन बंद करने को कह रहे हैं। अच्छा होता है कि वह छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए सरकार को उनकी मांगें मानने की सलाह देते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बात आम आदमी की करते हैं, लेकिन बढ़ावा खास आदमी को देते हैं। आम कार्यकर्ता की जगह धनकुबेरों को राज्यसभा भेजा। अन्ना आंदोलन के साथियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आप ने सबसे ज्यादा अमीर और करोड़पतियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल गरीब के हित का नारा केवल सत्ता पाने के लिए दे रहे हैं।

चार बार विधायक रहे बल्ली आप में शामिल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को आप ने बड़ा झटका दिया है। चार बार विधायक रहे हरशरण सिंह बल्ली शनिवार को आप में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे।

बल्ली 1993 से 2013 तक हरिनगर से विधायक रहे हैं और भाजपा की मदन लाल खुराना सरकार में मंत्री भी रहे थे। वह दिल्ली सरकार में पहले सिख मंत्री थे। पत्नी सहित आप में शामिल होने के बाद बल्ली ने कहा कि वह प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में सफलता मिले। केजरीवाल सरकार के विकास कार्यों, ईमानदारी और काम के आधार पर वह जनता से वोट मांगने जाएंगे। इस गृह क्षेत्र से पहुंचे कई अन्य लोगों ने भी आप की सदस्यता ग्रहण की है।

बल्ली ने 20 साल की उम्र में चंद्रशेखर और किशोर जी के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। वह राजनीति सिद्धांतों पर आधारित थी। उन्होंने 1977 में उन्हें एमसीडी का पहला चुनाव लड़वाया था। दिल्ली का पहला सिख मंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें मदन लाल खुराना ने दिया। 20 साल तक दिल्ली के विधायक भी रहे।

बल्ली 2013 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और 2013 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था। मगर हार गए थे। चुनाव के बाद फिर से भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा क्यों छोड़ी यह पूछे जाने पर बल्ली ने कोई सीधा कारण नहीं बताया। कहा कि भाजपा से उन्होंने टिकट नहीं मांगी थी और न ही अब चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है। उन्हें भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है। केजरीवाल का काम अच्छा लगा इसलिए आप में शामिल हुए हैं।

आम आदमी पार्टी कार्यालय में पूर्व विधायक हरशरण सिंह बल्ली (बाएं) को पार्टी में शामिल कराते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (बीच में) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (दाएं)। जागरण

आयोग की तैयारी

मॉडल मतदान केंद्र देंगे स्वच्छता का संदेश

निहाल सिंह, नई दिल्ली : मतदान फीसद में बढ़ोतरी के साथ ही मतदाताओं को स्वच्छता का संदेश देने की भी चुनाव आयोग ने तैयारी की है ताकि मजबूत लोकतंत्र के साथ सशक्त भारत की नींव को मजबूत किया जा सके। इसके लिए आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को मॉडल मतदान केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जहां तीन तरह के कूड़ेदान रखकर उनके उपयोग की जानकारी देने के साथ ही सफाई से जुड़े अन्य जरूरी संदेश भी दिए जाएंगे। इन्हें बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सभी मॉडल मतदान केंद्रों को स्वच्छता की थीम को ध्यान में रखकर तैयार करेगा। इन मॉडल मतदान केंद्रों पर स्वच्छता रखने के संदेश भी लगाए जाएंगे। इसमें गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग करने से लेकर पॉलीथिन का उपयोग न करने की भी अपील की जाएगी। साथ ही सब्जी की खरीदारी के लिए थैला ले जाने की अपील भी होगी।

दक्षिणी निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमारे इलाके में 26 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें निगम 967 स्थानों पर 5500 मतदान केंद्र बनाएगा। इनमें से 26 मतदान केंद्र मॉडल मतदान केंद्र के रूप में भी तैयार किए जाएंगे। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इन केंद्रों को विशेष रूप से सजाया जाएगा। साथ ही पानी से लेकर बैठने तक के लिए व्यवस्था होगी। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष इंतजाम मतदान केंद्रों में होंगे।

कर्मचारियों को मिलेगा गर्म पानी

चुनाव ड्यूटी पर एक दिन पहले पहुंचने वाले कर्मचारियों को ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। तकिया से लेकर गर्म कंबल और बेडशीट का भी इंजताम किया जाएगा। खास बात यह होगी की कर्मचारियों के लिए स्नान व पीने के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी। निगम ने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। निगम की कोशिश है कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

नेशनल कैपिटल

सुबोध जायसवाल हो सकते हैं दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के लिए महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आइपीएस सुबोध जायसवाल का नाम सामने आने से अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी (यूटी) कैडर के आइपीएस अधिकारियों में खलबली मच गई है। इसका कारण यह है कि दिल्ली पुलिस के मुखिया पद पर यूटी कैडर के ही वरिष्ठ आइपीएस को नियुक्त किया जाता रहा है। बस 1999 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के अजय राज शर्मा को आयुक्त बनाया था।

मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 8 जनवरी को जारी होने से पहले 4 जनवरी को गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कहा था कि वह या तो महाराष्ट्र कैडर के आइपीएस सुबोध जायसवाल को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त करने अनुमति दें अथवा वर्तमान पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक (1985 बैच) को सेवा विस्तार दें। पत्र में मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आयुक्त के लिए सुबोध जायसवाल का नाम अंतिम निर्णय नहीं है। निर्णय बदला भी जा सकता है। उक्त पत्र का चुनाव आयोग ने अब तक जवाब नहीं दिया है।

15 को होनी थी अमूल्य पटनायक की सेवानिवृत्ति : फिलहाल अमूल्य पटनायक को 45 दिनों का सेवा विस्तार मिलने की काफी संभावना नजर आ रही है। संभव है 28 या 29 जनवरी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाए। पटनायक की सेवानिवृत्ति 15 जनवरी को थी, लेकिन माह के अंतिम दिन सेवानिवृत्त किए जाने के नियम के अनुरूप 31 जनवरी तक उनका कार्यकाल है।

महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आइपीएस हैं जायसवाल, यूटी कैडर में खलबली

28 और 29 को हो सकती है बारिश

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली में शनिवार को मौसम खुशनुमा रहा। दिनभर धूप खिली रही। अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम के साथ 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को सुबह मध्यम कोहरा छा सकता है। कुछ जगहों पर घना कोहरा भी छाने की उम्मीद है। इस दौरान अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन आएगा। उत्तर भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। इसके कारण मौसम में बदलाव आएगा। 28 और 29 जनवरी के दिन हल्की बारिश होने की उम्मीद है।

जमीन से नभ तक कड़े पहरे में दिल्ली

जासं, नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस, पैरा मिलिट्री, एनएसजी, एसपीजी व सेना के अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने कई हफ्ते पहले से सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस व पैरा मिलिट्री की तैनाती कर दी गई है। आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो सकें, इसके लिए अभेद सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। ताकि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। जमीन से आसमान तक सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा रहेगा। शुक्रवार रात दस बजे दिल्ली की सभी सीमाओं पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी एसीपी अनिल मित्तल के मुताबिक सेना व पुलिस ने आधी रात को ही दिल्ली को अपने हवाले ले लिया है।

असंतोष

दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए जुटे हरियाणा भाजपा के नेताओं से ओमप्रकाश धनखड़ ने लिया फीडबैक

नाराज नेता-कार्यकर्ता की नब्ज टटोल रहे दिग्गज

विजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

भाजपा के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं है। हरियाणा भाजपा के 33 दिग्गज नेता इन दिनों दिल्ली विधानसभा की 17 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं। इन नेताओं से शनिवार को हरियाणा भवन में एक बैठक कर पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने फीडबैक लिया।

धनखड़ हरियाणा से आए भाजपा नेताओं के बीच समन्वयक की भूमिका अदा कर रहे हैं। इस बैठक में हरियाणा भाजपा नेताओं ने साफ तौर पर पार्टी संगठन को बता दिया है कि दिल्ली के नाराज नेता और कार्यकर्ताओं को मनाना इतना आसान नहीं है। खासतौर पर दूसरे प्रदेशों से आए संगठन के नेताओं से ये नेता, कार्यकर्ता नहीं मानने वाले हैं। इनके लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा या केंद्रीय स्तर के प्रभावी नेताओं से राजनीतिक आश्वासन दिलवाना जरूरी है। इन नेताओं के अनुसार दिल्ली में रोहिणी विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर अन्य में कहीं पार्षद नाराज हैं तो कहीं मंडलाध्यक्ष और जिला स्तर के पदाधिकारी। एक विधानसभा क्षेत्र में कई पार्षद हैं जो टिकटार्थी थे और टिकट नहीं मिलने के कारण सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं।

बैठकों और रिपोर्ट देने के दौर हों कम : भाजपा नेताओं ने अपने अनुभव के आधार पर संगठन के नेताओं को यह भी सुझाव दिया कि वे दूसरे प्रदेशों से आए नेताओं से केवल वाट्सएप ग्रुप पर ही फीडबैक लें। बैठकों और रिपोर्ट देने के चक्कर में नाराज कार्यकर्ता अथवा मतदाता तक पहुंच पाने में समस्या आ रही है। इसके अलावा रिपोर्टिंग कक्ष सिर्फ एक ही होना चाहिए। शनिवार भी जब धनखड़ हरियाणा भवन में उत्तराखंड के नेता विनय रोहिला के साथ बैठक ले रहे थे तो हरियाणा भाजपा के नेताओं की एक बैठक दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय पर भी चल रही थी। इसमें केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद थे।

पहले खूब बोल रहे थे, अब नाराज नेताओं ने साधी चुप्पी

हरियाणा भाजपा के दिग्गज नेताओं ने पार्टी संगठन को यहां तक बता दिया है कि वे भी अपने क्षेत्र में पार्टी का काम करते हैं। कोई पूर्व मंत्री है, कोई मौजूदा विधायक तो कोई पूर्व विधायक या पार्टी पदाधिकारी। ऐसे में सब जानते हैं कि किस कार्यकर्ता के मन में क्या है। टिकट वितरण के बाद दो दिनों तक जो नाराज कार्यकर्ता खुलकर अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने चुप्पी साध ली है। ये नेता सिर्फ इतना कहते हैं कि वे पार्टी में हैं पार्टी का काम करेंगे। बावजूद इसके ये नाराज नेता चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर अथवा संस्थान में बैठक करते हैं और उसकी जानकारी ही सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। हरियाणा भाजपा के नेता मान रहे हैं कि यह स्थिति काफी खराब है।

10 महिलाओं महिला प्रशासकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और समाज सुधारकों के नाम पर देश के विश्वविद्यालयों में चेयर की स्थापना की जाएगी। इन महिलाओं में हंसा मेहता और देवी अहिल्या बाई होल्कर शामिल हैं।

फिर किराया वृद्धि की भूमिका बना रहा रेलवे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भारत में अब भी पड़ोसी देशों के मुकाबले कम रेल किरायों का हो रहा प्रचार
- रेलवे के आधुनिकीकरण व विस्तार के लिए यात्रियों को और बोझ सहने का तर्क

प्रतीकात्मक।

पहली जनवरी को सभी दर्जों में हल्की किराया बढ़ोतरी के बाद भी रेलवे को चैन नहीं है। यात्री घाटे को पूरा करने के लिए वह अभी किराया बढ़ोतरी के प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके खोजने में जुटा है। इसे वाजिब ठहराने के लिए मंत्रालय की ओर से इन दिनों एक अभियान छेड़ा गया है। जनता को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में रेल किराया अब भी पड़ोसी देशों से काफी कम है। इसलिए थोड़ी और बढ़ोतरी हो जाए तो उसके लिए तैयार रहें। अतिरिक्त बोझ सहे बगैर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रेलवे का आधुनिकीकरण व विस्तार कठिन होगा।

इसके लिए मंत्रालय की ओर से कुछ अधिकारियों से लेख लिखवाए जा रहे हैं और मीडिया को उनकी प्रतियां बांटी जा रही हैं। साथ ही ग्राफिक्स के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की अपेक्षा भारत में रेल किरायों की स्थिति दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है।

ऐसे ही एक ग्राफिक्स में दर्शाया गया है कि बांग्लादेश में उपनगरीय ट्रेनों का किराया प्रति किलोमीटर 33 पैसे, पाकिस्तान में 48 पैसे तथा श्रीलंका में 48.1 पैसे है, वहीं भारत में अब भी लोकल ट्रेनों में लोग मात्र 22.8 पैसे प्रति किलोमीटर के किराये पर सफर कर रहे हैं। इसी प्रकार लंबी दूरी की गैर-वातानुकूलित ट्रेनों का किराया पाकिस्तान में 48 पैसे, श्रीलंका में 67.9 पैसे और बांग्लादेश में 147 पैसे प्रति किलोमीटर है, वहीं भारत में यात्रियों को केवल 39.5 पैसे प्रति किलोमीटर देने पड़ते हैं। इसी प्रकार वातानुकूलित श्रेणियों के किरायों की भी तुलना दिखाई गई है। इसके मुताबिक एसी क्लास के लिए भारत में लोगों को केवल 175 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना पड़ रहा है। जबकि पाकिस्तान के लोग एसी दर्जे के लिए 176.5 पैसे तथा बांग्लादेश के लोग 227 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया चुकाते हैं। कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश की गई है भारत में अभी किराया वृद्धि की काफी संभावना है।

बजट से पहले मंत्रालय की इन गतिविधियों को जानकार एक और किराया बढ़ोतरी की भूमिका के रूप में ले रहे हैं। यह वृद्धि प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में हो सकती है। सबसे ज्यादा संभावना उपनगरीय ट्रेनों का किराया बढ़ाए जाने की बताई जाती है, जिसे पहली जनवरी से लागू बढ़ोतरी में छोड़ दिया गया था। लेकिन, जिस तरह जनता ने उस बढ़ोतरी को आराम से स्वीकार कर लिया और किसी प्रकार के विरोधी स्वर कहीं सुनाई नहीं दिए, उसे देखते हुए अब इस सेगमेंट को भी छेड़ने की गुंजाइश बनाई जा रही है। परंतु चूंकि उपनगरीय किरायों का मुद्दा सामान्य मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों के किरायों की तुलना में काफी संवेदनशील माना जाता है, इसलिए दूसरी संभावना परोक्ष बढ़ोतरी की हो सकती है। इसमें आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट शुल्क में बढ़ोतरी अथवा स्टेशन डेवलपमेंट सरचार्ज के रूप में एक नया शुल्क लगाए जाने की आशंका भी जताई जा रही है।

माना जाता है कि पहली जनवरी की किराया बढ़ोतरी रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में अपने बेकाबू आपरेटिंग रेशियो को 100 फीसद से नीचे लाने के लिए की थी। जबकि, आगे होने वाली बढ़ोतरी से अगले वित्तीय वर्ष के यात्री घाटे को नियंत्रित किया जाएगा।

गृह मंत्री शाह की उपस्थिति में शांति समझौता करेंगे बोडो अलगाववादी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चार अलगाववादी गुटों के प्रतिनिधि और असम के मुख्यमंत्री करेंगे समझौते पर हस्ताक्षर
- एनडीएफबी ने अलग राज्य की मांग छोड़ी, दिए जा सकते हैं अधिक राजनीतिक व आर्थिक अधिकार

अमित शाह। फाइल

दशकों से हिंसा से जूझ रहे असम में स्थायी शांति की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अलग बोडोलैंड की मांग करने वाले नेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के चार गुटों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इन संगठनों के प्रतिनिधि और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार समझौते में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को नहीं माना गया है। लेकिन, बोडो लोगों को कुछ अधिक राजनीतिक अधिकार व आर्थिक पैकेज दिए जा सकते हैं।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि असम में स्थायी शांति के लिए बोडो समस्या के समाधान की कोशिश लंबे समय से जारी थी। इसी सिलसिले में गुरुवार को बोडो अलगाववादी गुटों के 644 कैडरों ने असम के मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया था। इससे 15 दिन पहले म्यांमार में रह रहे एक गुट से जुड़े 50 कैडरों ने भारत आकर हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे इस समस्या के अंतिम समाधान की उम्मीद बढ़ गई थी।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, जिन चार गुटों के साथ सोमवार को समझौता होने वाला है, उनमें रंजन डैमारी, गोविंदा बासुमातरी, धीरेन बारो और बी साओरैगरा के नेतृत्व वाले गुट शामिल हैं। बी आओरैगरा ने 2015 में आइके सोंगबीजीत गुट की कमान संभाली थी।

आरोप है कि सोंगबीजीत ने दिसंबर 2014 में 70 आदिवासियों की हत्या का आदेश दिया था। इसके बाद उसे हटा दिया गया था। समझौते के तहत दो दिन पहले जेल में बंद डैमारी को रिहा किया गया था। ये चारों समझौते पर हस्ताक्षर के लिए दिल्ली आ रहे हैं। वैसे गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि समझौते के कारण असम के राजनीतिक नक्शे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनडीएफबी ने अलग राज्य की मांग छोड़ दी है।

जाहिर है बोडो क्षेत्रीय परिषद को कुछ अधिक राजनीतिक व आर्थिक स्वायतता का प्रावधान किया जा सकता है। असम के भीतर बोडो लोगों को अधिक अधिकार देने पर राज्य के दूसरे नागरिकों के साथ विचार-विमर्श के लिए एक आयोग का गठन भी किया जाएगा।

न्यूज गैलरी

सोशल मीडिया पर छाया देशभक्ति का रंग

नई दिल्ली : देश का 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सोशल मीडिया भी देशभक्ति की भावनाओं से गुलजार है। गणतंत्र दिवस पर की जाने वाली पोस्ट में हिंदी का हिस्सा सर्वाधिक रहा है। पंद्रह भारतीय भाषाओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला शेयरचैट पर गणतंत्र दिवस के मौके पर दो लाख से भी ज्यादा पोस्ट को 15 करोड़ व्यूज मिले हैं। इन्हें 75 हजार से ज्यादा वाट्सएप शेयर प्राप्त हुए हैं। शेयरचैट कम्यूनिकेशन हेड राहुल नाग के मुताबिक, 23 जनवरी से 25 जनवरी को दोपहर साढ़े बारह बजे तक सबसे ज्यादा पोस्ट हिंदी में आई हैं। सभी भाषाओं में डाली गई पोस्ट में हिंदी का हिस्सा 50 फीसद है। (जाब्यू)

एसएसबी में भत्तों और बकाए का भुगतान रुका

नई दिल्ली : देश की सीमा की रक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों और अधिकारियों को बकाया धन और भत्तों का भुगतान जनवरी और फरवरी के लिए रोक दिया गया है। ऐसा धन की कमी के चलते किया गया है। सारी बकाया धनराशि मार्च में दी जाएगी। यह जानकारी संगठन की ओर से दी गई है। पता चला है कि अर्धसैनिक बल के मुख्यालय ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित कर दिया है कि उसके पास जनवरी और फरवरी में सिर्फ वेतन भुगतान के लिए ही धन बचा है। (प्रेट्र)

नेपाल ने भारत-पाक के बीच मध्यस्थता की पेशकश की

प्रस्ताव ▶ कहा, साथ बैठने और विचार साझा करने से चीजें सुलझेंगी

दोनों देशों के बीच सीधा संवाद विकसित करने पर भी दिया बल

काठमांडू, प्रेट्र : भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए नेपाल ने शनिवार को कश्मीर और सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की है। परमाणु शक्ति संपन्न दोनों पड़ोसियों के बीच मध्यस्थता की पेशकश करने वाला नेपाल पहला दक्षिण एशियाई देश है। नेपाल सरकार के एक सूत्र ने कहा कि आपसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत बहुत जरूरी है और इसी से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को भी नया जीवन मिलेगा।

सूत्र ने कहा, 'किसी भी समस्या के समाधान के लिए वार्ता सबसे बेहतर तरीका है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन उन्हें बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। यदि जरूरी हो तो हम मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं।' उसने कहा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका दोनों देशों के बीच बेहतर संवाद कायम करना होगा। सूत्र ने कहा, 'हमारी भूमिका हो सकती है लेकिन (दोनों पक्षों के लिए) सीधा संवाद विकसित करना बेहतर होगा।'

पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। इस निर्णय के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध कम कर दिए थे और भारतीय राजनयिक को वापस भेज दिया था।

सूत्र ने कहा, 'जब हम साथ आएंगे, बैठेंगे और अपने विचार साझा करेंगे तब चीजें सुलझेंगी। हर स्थिति में हमें एक साथ बैठना होगा और समस्या को सुलझाना होगा, अन्यथा चीजें बिगड़ सकती हैं।'

सार्क में जान फूंकने की जरूरत : सार्क शिखर सम्मेलन को लेकर वर्तमान अनिश्चितता की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए सूत्र ने कहा कि सार्क और आतंकवाद के बीच कोई संबध नहीं है। हम किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। दोनों मुद्दों को जोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस संगठन में प्राण फूंकने की जरूरत है और गलतफहमी दूर की जानी चाहिए। सूत्र ने कहा, 'सार्क मृतप्राय नहीं है। यह जिंदा है। बस एक बात है कि हमारी बैठक नहीं हुई है। आशा है कि हम इसे पुनः जीवंत कर सकते हैं।'

2016 से नहीं हुआ सार्क शिखर सम्मेलन : पिछला सार्क सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। 2016 में सार्क की बैठक इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन उड़ी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद भारत ने बैठक में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। बाद में बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान के भी शामिल होने से मना करने पर शिखर सम्मेलन को रद कर दिया गया था। उसके बाद से यह बैठक नहीं हुई है।

ट्रंप भी कर चुके हैं मध्यस्थता की पेशकश

नेपाल से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कई बार पेशकश कर चुके हैं। लेकिन भारत का स्पष्ट कहना है कि कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता उसे स्वीकार नहीं है। यह द्विपक्षीय मसला है। भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार भी है, लेकिन शर्त यह है कि इस्लामाबाद पहले आतंकियों पर लगाम लगाए और क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए।

सोनिया बोलीं, संविधान और उसके मूल्यों पर हो रहा हमला

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को लोगों से अपील की कि वे अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हों। सोनिया ने दावा किया कि संवैधानिक मूल्यों को एक गहरी साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इसकी रक्षा के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, 'यह हर नागरिक का दायित्व है कि वह देश के संविधान की रक्षा करने और देश की एकता को मजबूत करने की दिशा में कार्य करे। लोगों को धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। देश में अशांति, भय और असुरक्षा का एक अभूतपूर्व वातावरण तैयार कर दिया गया है। आम आदमी यह सोचने लगा है कि मौजूदा सरकार के हाथों में संवैधानिक मूल्य अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं।'

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि वर्तमान की केंद्र सरकार अपनी आर्थिक नाकामियों, प्रशासनिक विफलता, आसमान छूती महंगाई, हर तरफ मंदी के माहौल और बढ़ती बेरोजगारी से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए माहौल खराब करने का काम कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि संविधान का हर अक्षर महज छपा हुआ एक शब्द भर नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के लिए जीता-जागता एक दर्शन है। हमें इसकी रक्षा करने के लिए साथ आने की जरूरत है।

राजपथ पर आज दिखेगी सैन्य ताकत व संस्कृति की झलक

- उपग्रह भेदी हथियार 'शक्ति', चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भव्य सैन्य परेड का होंगे हिस्सा

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में रविवार को राजपथ पर भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राजपथ पर आसमान से भी नजर रखी जाएगी। उपग्रह भेदी हथियार 'शक्ति', थलसेना का युद्धक टैंक भीष्म, पैदल सेना के युद्धक वाहन और हाल ही में भारतीय वायु सेना में शामिल किए गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भव्य सैन्य परेड का हिस्सा होंगे।

इसके अलावा के-9 वज्र और धनुष तोपें, चलित उपग्रह टर्मिनल और आकाश मिसाइल प्रणाली मैकेनाइज्ड दस्ते का मुख्य आकर्षण होंगे। राफेल और तेजस युद्धक विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल प्रणाली और अस्त्र मिसाइल के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। डोर्नियर विमान और सी-130 जे सुपर हरक्यूलीज विमान भी दिखाई देंगे। पांच जगुआर विमान और पांच मिग-29 विमान 'एरोहेड' फार्मेशन में वायुसेना के पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। परेड का समापन सुखोई-30 एमकेआई जेट विमानों के हवाई करतब से होगा।

पहले युद्ध स्मारक जाएंगे प्रधानमंत्री : गणतंत्र दिवस परेड समारोह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट के समीप स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति की बजाय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परेड की सलामी लेने से होगी।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियां : राजपथ पर राष्ट्र की बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक प्रगति को दर्शाने वाली 22 झांकियों में से 16 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी और छह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की होंगी। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की छह झांकियों में 'स्टार्ट अप इंडिया' और 'जल जीवन मिशन' जैसी सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

ले.जनरल असित मिस्त्री के हाथों में परेड की कमान : परेड कमांडर दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री के हाथों में परेड की कमान होगी। परेड में पहला दस्ता सेना की 61वीं घुड़सवार टुकड़ी का होगा।

ब्राजील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि

गणतंत्र के मौके पर डेढ़ घंटे के समारोह में ब्राजील के राष्ट्रपति जायेर बोलसोनारो मुख्य अतिथि होंगे। वह दो दिन से भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। लातिन अमेरिकी देश ब्राजील के साथ भारत के मधुर संबंध हैं।

बाल पोर्नोग्राफी तक पहुंच रोकने को एप की जरूरत

- राज्यसभा समिति ने बच्चों का यौन शोषण व सोशल मीडिया पर बाल पोर्नोग्राफी का प्रसारण रोकने के लिए रिपोर्ट सौंपी
- समिति ने 40 सिफारिशें की हैं, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है

नई दिल्ली, प्रेट्र : बच्चों के यौन शोषण को रोकने और सोशल मीडिया पर बाल पोर्नोग्राफी की पहुंच और प्रसारण रोकने के लिए राज्यसभा की एक समिति ने 40 सिफारिशें की हैं। इनमें सभी उपकरणों पर निगरानी एप को अनिवार्य बनाना और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन का सुझाव शामिल है।

इस समिति के प्रमुख और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को रिपोर्ट सौंपी। इसमें बाल पोर्नोग्राफी रोकने के लिए कई और सिफारिशें की गई हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यापक सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर जांच की खातिर समिति गठित करने के लिए नायडू की सराहना की गई है। रिपोर्ट में रमेश ने कहा कि यह एक अच्छा मॉडल है, जिसे समय-समय पर सामाजिक मुद्दों पर विचार करने के लिए किया जा सकता है।

बाल पोर्नोग्राफी की गंभीरता पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने तकनीकी, संस्थागत, सामाजिक और शैक्षणिक उपाय करने की बात भी कही है। सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे और बच्चों और समाज पर इसके प्रभावों के बारे में राज्य-स्तरीय पहल का सुझाव दिया गया है। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाल पोर्नोग्राफी की समस्या पर संज्ञान लेते हुए 'मन की बात' कार्यक्रम में भी इस विषय को शामिल करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

समिति ने अनुरोध किया कि उन्होंने जैसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया है, वैसे ही इस समस्या से निपटने के लिए भी उन्हें 'वैश्विक राजनीतिक गठजोड़' बनाने की पहल करनी चाहिए।

'संस्थाओं के लिए नौकरशाही व राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति अहम'

नई दिल्ली, प्रेट्र : नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक वेंकटरमन रामकृष्णन ने शनिवार को कहा कि अच्छे संस्थानों के संचालन के लिए नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति बेहद अहम है। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट रामकृष्णन अशोक यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोसाइंस के उद्घाटन अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'अशोक यूनिवर्सिटी एक निजी यूनिवर्सिटी है और शुरुआत में मैं निजी यूनिवर्सिटी के विचार के खिलाफ कुछ-कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित था। लेकिन इसके कुछ पहलुओं से मैं प्रभावित था।'

यूनिवर्सिटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह योग्यता से संचालित है और उच्च मानकों को बरकरार रखा है। अशोक यूनिवर्सिटी का लिबरल आर्ट्स पर जोर वास्तव में अच्छा उदाहरण स्थापित कर सकता है। भारत में जन्मे रामकृष्णन को दो और वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से कैमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें यह पुरस्कार राइबोसोम की संरचना और उसके कार्यों पर शोध के लिए मिला था।

'मतदान की अहमियत नहीं समझते हैं कुछ वोटर'

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि कुछ मतदाता मतदान की अहमियत नहीं समझते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि पहले आम चुनाव से लेकर पिछले साल हुए 17वें लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं ने दुनियाभर में भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाई है। वह इसके लिए देश के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं। लेकिन, आज की तारीख में भी कुछ मतदाता अपने मताधिकार की अहमियत नहीं समझते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में आम लोगों को मताधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था और कुर्बानी देनी पड़ी थी।

राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रिटेन जैसे पुराने लोकतंत्र में भी महिलाओं को बीसवीं सदी में मताधिकार मिला। इसके लिए उन्हें तीन दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन, भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी वयस्क भारतीयों को यह महत्वपूर्ण अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया। कोविंद ने याद दिलाया कि आजादी के तत्काल बाद देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। उस समय इसकी बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि कुछ ही विकसित और समृद्ध देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी।

कहा गया था कि सिर्फ 16 फीसद साक्षरता और गरीबी के चलते सभी वयस्कों को मताधिकार की व्यवस्था सफल नहीं होगी। इस निर्णय को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया गया। लेकिन, हमारे मतदाताओं ने इसे विश्व इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा सफल प्रयोग साबित किया। राष्ट्रपति ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 17वें लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना की।

चुनाव प्रक्रिया को जीवंत बनाने के लिए आयोग का आभार : राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शनिवार को लोगों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश चुनावी प्रक्रिया को जीवंत और भागीदारीपूर्ण बनाने के प्रयासों के लिए चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता है। पिछले 10 वर्षों से चुनाव आयोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना रहा है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में पहली बार मतदाता बने युवाओं को मतदाता पहचान पत्र सौंपा। यह दिवस साल 2011 से मनाया जा रहा है। प्रेट्र

कानूनी हथकंडा

सुप्रीम कोर्ट से दया याचिका खारिज होने की न्यायिक समीक्षा का किया अनुरोध, एक फरवरी को सुबह छह बजे होनी है निर्भया के गुनहगारों को फांसी

निर्भया के गुनहगार ने राष्ट्रपति के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्ष 2012 में हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषियों में से एक ने दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शनिवार को याचिका दायर कर उसने दया याचिका खारिज किए जाने की न्यायिक समीक्षा का अनुरोध किया है।

दोषी मुकेश कुमार सिंह (32) की ओर से यह याचिका वकील वृंदा ग्रोवर ने दायर की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी। वृंदा ग्रोवर ने कहा, 'जिस तरह से दया याचिका खारिज की गई है, उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए अर्जी अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।' उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न चौहान प्रकरण में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। इन मानकों में ऐसे कैदी को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अनिवार्यता भी शामिल है। चारों दोषियों को एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी देने के लिए मृत्यु वारंट जारी किया गया है।

अक्षय की क्यूरेटिव याचिका भी हो गई है खारिज: मुकेश ने फांसी की सजा के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मुकेश ने दया याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फांसी की सजा पाए अन्य दोषी अक्षय कुमार की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। दो अन्य दोषियों पवन गुप्ता (25) और विनय कुमार शर्मा ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर नहीं की है।

क्या थी घटना : साल 2012 में 16 और 17 दिसंबर की दरम्यानी रात को 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से छह व्यक्तियों द्वारा चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म एवं बेरहमी से हमला किया गया था और उसे बाद में दक्षिणी दिल्ली में बस से फेंक दिया गया था। उसे सिंगापुर के अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

फांसी को टलवाने का प्रयास नाकाम : निर्भया के गुनहगारों द्वारा फांसी को टलवाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में दोषियों की तरफ से दिल्ली की सत्र अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि जेल के अधिकारी वे दस्तवेज मुहैया नहीं करा रहे हैं जो दया तथा क्यूरेटिव याचिकाएं दायर करने के लिए जरूरी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अर्जी पर आगे किसी दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है। दोषियों के वकील तिहाड़ जेल के अधिकारियों से संबंधित दस्तावेज, पेंटिंग और डायरी की तस्वीरें ले सकते हैं।

'फांसी टालने के लिए दायर की जा रहीं अर्जियां'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया मामले में दोषियों से जुड़े दस्तावेज उनके अधिवक्ता को अदालत में सौंप दिए गए। पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने कहा कि अब दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। यह आदेश अदालत ने दोषियों की उस अर्जी का निपटारा कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था तिहाड़ जेल प्रशासन दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहा है। इसके चलते उन्हें अपनी याचिका दायर करने में देर हो रही है।

तिहाड़ जेल प्रशासन दोषी विनय द्वारा बनाई गई 10 पेंटिंग, स्केच, 10 पन्नों की दरिंदा शीर्षक की किताब और अन्य दस्तावेज लेकर अदालत पहुंचा। तिहाड़ की तरफ से लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि दोषियों के अधिवक्ता ने जो भी दस्तावेज मांगे, उन्हें उपलब्ध कराए गए। इस तरह की अर्जी दायर कर दोषी सिर्फ देर करने की तरकीबें अपना रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया कानून को हराने के लिए चल रही है। दोषी जिस-जिस जेल में रहे, वहां से उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज सहेजे गए थे, वह सब दे दिए गए हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

1955 में सर्वे ऑफ इंडिया में संविधान की पहली 1000 प्रतियां छापी गई थीं। संविधान छापने वाली इन विशालकाय लिथोग्राफ मशीनों को अब नीलाम किया जा रहा है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 26 जनवरी 2020

प्रशांत किशोर तय नहीं करेंगे कि बिहार में क्या होगा : ललन

राज्य ब्यूरो, पटना

जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शुक्रवार को प्रशांत किशोर द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर लगातार किए जा रहे विरोध वाले ट्वीट पर तल्ख अंदाज में टिप्पणी की। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में क्या होगा यह प्रशांत किशोर नहीं, मुख्यमंत्री तय करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को यह दायित्व कहां दिया है कि हर मसले पर वह बताएं कि बिहार में क्या होगा और क्या नहीं?

ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग राजनीति भी करते हैं और कारोबार भी। जब दोनों मिल जाते हैं तो इस तरह का घालमेल हो जाता है। कोई यह तो बताए कि सीएए और एनआरसी के किस बिंदु पर विरोध है। प्रशांत किशोर विरोध कर रहे है तो यह उनकी समझ है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक पुराने वीडियो को प्रशांत किशोर द्वारा अपने ट्वीट के साथ टैग किए जाने पर ललन सिंह से प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सुशील मोदी के साथ हम लोग एनडीए में सत्रह साल से हैं। मजबूती से गठबंधन चला है। प्रशांत को आए कितना दिन हुआ है। पवन वर्मा पर सीएम के वक्तव्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तो शुभकामना भी दे दी है। चार पैर वाले को बांध कर रख सकते हैं पर दो पैर वाले को थोड़े ही बांध कर रखा जा सकता है।

राजीव रंजन सिंह। (फाइल)

प्रशांत किशोर। (फाइल)

स्वार्थी लोग पार्टी की छवि खराब करने में लगे हैं : संजय झा

जदयू के वरिष्ठ नेता व जल संसाधन मंत्री संजय झा ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा का नाम लिए बगैर ट्वीट के माध्यम से इन दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि स्वार्थी किस्म के लोग अब पार्टी की छवि को बर्बाद करने में लगे हैं पर इसमें कभी सफल नहीं होंगे। ऐसे लोगों ने पार्टी के विश्वास और पार्टी के भीतर मिले आदर का अपमान किया है।

निखिल ने भी किया पीके पर हमला

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं पर प्रशांत किशोर की हर टिप्पणी का हम कड़ा प्रतिवाद और निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा सुशील मोदी पर हमला करते हुए किए गए ट्वीट पर गौर करें तो हकीकत में इशारे में यह नीतीश कुमार पर हमला है। निखिल ने कहा, प्रशांत के शुरुआती बयानों से लगा था कि वे सिर्फ वर्बल डायरिया से पीड़ित है लेकिन जांच करने पर पता चला है कि उनको इंटेलेक्चुअल कॉन्सटिपेशन हो गया है। ऐसे में इलाज के अभाव में वह अनर्गल बयानबाजी करने लगे हैं।

विजयवर्गीय के बयान से शुरू हुई 'पोहा' राजनीति

नईदुनिया, इंदौर

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद इंदौर में 'पोहा' राजनीति शुरू हो गई। शनिवार को कांग्रेसियों ने शहर के राजवाड़ा पर अभियान चलाकर जो व्यक्ति पोहे खाते मिला, उसे सम्मान पत्र दिया। इसी दौरान मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने तो विजयवर्गीय को रॉ और सीबीआइ का प्रमुख बनाने की सलाह दे डाली।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक खंडेलवाल और प्रवक्ता गिरीश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राजवाड़ा पर पोहा सम्मान पत्र अभियान चलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा नेता अब खाने के नाम पर भी देश को बांटने में लग गए हैं। विजयवर्गीय के बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने दुकानों पर पोहा खाने वाले लोगों को ढूंढ़ा। जो पोहे खाते मिला, उससे कहा कि विजयवर्गीय के बयान के बाद भी आपका पोहा प्रेम बरकरार है, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों को सम्मान पत्र भी दिया।

दो दिन पूर्व विजयवर्गीय ने कहा था कि उनके पुत्र की शादी के लिए वह इंदौर स्थित अपने घर रंग-रोगन करा रहे थे। कुछ बांग्लादेशी मजूदर थे, उनके पोहे खाने के अंदाज से उन्हें उनके बांग्लादेशी होने का पता चला था। बकौल विजयवर्गीय उन्हें इन मजदूरों को लाने वाले ठेकेदार ने बताया कि ये बांग्लादेशी हैं और रात में पोहा खाकर ही सोते हैं।

कैलाश विजयवर्गीय। (फाइल)

वर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल को भी घेरा

मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विजयवर्गीय के साथ ही अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पर भी निशाना साधा। सिब्बल ने बीते दिनों कहा था कि सीएए लागू करने से कोई राज्य इन्कार नहीं कर सकता। इस पर वर्मा ने कहा कि सिब्बल से कोई पूछ नहीं रहा, फिर वे बोल क्यों रहे हैं? संघीय ढांचे में हर प्रदेश को अपनी स्थिति के हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार है।

भाजपा महासचिव बचा लेंगे करोड़ों रुपये : वर्मा

विजयवर्गीय के बयान को लेकर मप्र के लोक निर्माण मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी गुजारिश है कि कैलाश विजयवर्गीय को सीबीआइ और रॉ की कमान सौंप दें। वे वीआइपी सुरक्षा पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये वे बचा सकेंगे, क्योंकि वे सूंघकर और खाने की स्टाइल से ही अपराधियों-दुश्मनों को पहचान लेंगे।

न्यूज गैलरी

अखिलेश सम्मान से बुलाएंगे तो गठबंधन को तैयार : शिवपाल

मैनपुरी : प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अखिलेश अगर सम्मान से बुलाते हैं तो वह 2022 के चुनाव में गठबंधन के लिए तैयार हैं। शनिवार को मैनपुरी के करहल कस्बा में वह एक कार्यक्रम में आए थे। 2022 में विधानसभा चुनाव के समय किसी अन्य दल से गठबंधन के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि जो भी दल मेरा सम्मान करेगा, उसके साथ प्रसपा गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। सीएए पर कहा कि भाजपा को इस कानून को बनाने से पहले राजनीतिक दलों के अलावा जनता से भी राय लेनी चाहिए थी। (जासं)

आज अमृतसर से शुरू होगी समरसता सोशल मिशन यात्रा

अमृतसर : अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच एवं इंडो-नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में भारत, नेपाल व भूटान की ओर से समरसता सोशल मिशन यात्रा का 26 जनवरी को गुरु नगरी से शुभारंभ किया जा रहा है। शनिवार को अमृतसर पहुंचे नेपाल के उपराष्ट्रपति के विशेष सलाहकार महावीर प्रसाद टोरडी ने पत्रकारों को बताया कि भारत, नेपाल व भूटान की संस्कृति में ज्यादा भिन्नता नहीं है। इसके तहत 26 जनवरी को श्री हरिमंदिर साहिब से त्रिराष्ट्र समरसता सोशल मिशन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। (जासं)

जमीनी हकीकत ▶ निकाय चुनाव को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कराया आतंरिक सर्वे

माकपा ने माना-बंगाल में उससे ज्यादा मजबूत हुई है भाजपा

रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही असली लड़ाई का उल्लेख

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसे देखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने अपनी शक्ति आंकने के लिए पार्टी स्तर पर आंतरिक सर्वे कराया है, लेकिन जो रिपोर्ट मिली है, उसे देख पार्टी नेतृत्व काफी चिंतित है। माकपा नेताओं की बेचैनी का प्रमुख कारण भाजपा का तेजी से विस्तार है। सर्वे के मुताबिक भाजपा ने माकपा को पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि उत्तर कोलकाता व जादवपुर जैसे क्षेत्र में जिसे कभी लालदुर्ग कहा जाता था, वहां भी माकपा की हालत दयनीय है।

माकपा की आतंरिक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उत्तर कोलकाता में पकड़ काफी कमजोर हो चुकी है, जबकि भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है। इसका मानसिक दबाव माकपा नेताओं-कार्यकर्ताओं पर भी साफ दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोलकाता के अधिकांश इलाकों जैसे बागबाजार, श्यामबाजार और गिरीश पार्क इलाकों में तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई सीधे-सीधे भाजपा से दिख रही है। बड़ाबाजार और उससे सटे वार्डों में भी तृणमूल को भाजपा ही टक्कर देती दिख रही है। बेलेघाटा और मानिकतल्ला बस्ती इलाकों के वोट पहले केवल माकपा को ही मिलते थे, लेकिन अब वहां भी भाजपा ने सेंधमारी कर दी है। कोलकाता में तत्काल चुनाव हो गए, तो माकपा की रिपोर्ट में 107 से 133 नंबर तक के वार्डों में भाजपा की जीत निश्चित दिख रही है।

जादवपुर, गार्डेनरिच और बेहला आदि इलाकों में तृणमूल मजबूत दिख रही है, क्योंकि उक्त इलाकों में अल्पसंख्यक मतदाता एक्स फैक्टर हैं, जो तृणमूल की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन, यहां भी लड़ाई भाजपा-तृणमूल के बीच ही दिख रही है। कभी वाममोर्चा के लिए सख्त घाटी रहे जादवपुर में भी लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक समीकरण बदला हुआ दिखा, क्योंकि वहां भाजपा का वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। जादवपुर के 107 और 108 नंबर वार्ड में भाजपा को 49.49 फीसद वोट मिले थे, जबकि तृणमूल को 45.8 फीसद। 111 और 112 नंवर वार्ड में भाजपा ही आगे दिख रही है। यहां 49.12 फीसद वोट मिल सकते हैं, जबकि तृणमूल को 47.8 फीसद। सीएए और एनआरसी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन के बावजूद जादवपुर में भाजपा के बढ़ते जनाधार देख माकपा नेता भी आश्चर्यचकित हैं।

बनाई नई रणनीति

आत्ममंथन के बाद लोकसभा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए माकपा नेताओं ने नई रणनीति बनाई है। 17 वामपंथी दलों के साथ गठबंधन करने वाली माकपा अब कांग्रेस के साथ भी समझौते को और मजबूत कर आगे बढ़ना चाह रही है। माकपा के कोलकाता जिला सचिव कल्लोल मजूमदार ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन कर कांग्रेस के साथ सीट समझौते को लेकर चल रही बातचीत की जानकारी भी दी है।

जीत को लेकर अपने-अपने दावे

प्रत्याशी चयन को लेकर भी माकपा काफी सतर्क दिख रही है। शिक्षित और अच्छी छवि वाले नेताओं को विशेष तरजीह दी जा रही है। नए चेहरों पर भी दांव खेलने की योजना है। हालांकि, माकपा नेता कहते दिख रहे हैं कि निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल और वाम मोर्चा-कांग्रेस ही लड़ाई में हैं। भाजपा कहीं भी नहीं टिक रही। माकपा नेता शमिक लाहिड़ी का कहना है कि भाजपा किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाएगी। वहीं, भाजपा अलग जीत की ताल ठोक रही है। उधर, कोलकाता के मेयर व मंत्री फिरहाद हकीम माकपा-भाजपा को महत्व नहीं दे रहे। उनका दावा है कि जन विरोधी नीतियों के चलते राज्य की जनता भाजपा-कांग्रेस और वाममोर्चा, तीनों को नकार देगी और फिर से तृणमूल ही सत्ता पर काबिज होगी।

मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए हैं नौकरशाह

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता से बेदखल हुई भाजपा के खिलाफ इन दिनों दो-दो मोर्चे खुले हुए हैं। राजगढ़ जिले के थप्पड़कांड के खिलाफ हल्ला बोलने निकली भाजपा की सियासी लड़ाई तो कमलनाथ सरकार के खिलाफ चल ही रही है, पर पार्टी नेताओं के बचकाने बयान से उसे दूसरे मोर्चे पर नौकरशाहों का विरोध झेलना पड़ रहा है। राजगढ़ की महिला कलेक्टर के खिलाफ पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के आपत्तिजनक बयानों ने भाजपा को ही बैकफुट पर ला दिया है। इस मामले में कमलनाथ सरकार अपनी कूटनीति में सफल रही। मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए फ्री हैंड से सारी अफसरशाही भाजपा के खिलाफ खड़ी हो गई है।

प्रदेशाध्यक्ष के पद को लेकर पार्टी के ही नेताओं के बीच अंदरूनी सियासत चल रही है। इस बीच कांग्रेस सरकार से लड़ाई में वह जितने कदम आगे बढ़ती है, नेताओं की बदजुबानी से उसे उतना ही पीछे हटना पड़ता है। दरअसल, कांग्रेस सरकार ने जब से माफिया और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, तभी से अफसरशाही के साथ भाजपा के संबंध बिगड़े। अब राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को थप्पड़ क्या जड़े, अफसरशाही के साथ भाजपा का नया पंगा खड़ा हो गया।

> अफसरशाही हमारी लोकतांत्रिक भावनाओं के महत्व को समझती है। जहां तक कुछ अफसरों की बात है तो उन्हें राजनीतिक टकराव की स्थितियों में कांग्रेस का टूल नहीं बनना चाहिए।
>
> – डॉ. दीपक विजयवर्गीय, मुख्य प्रवक्ता, भाजपा मप्र

राजगढ़ में 22 जनवरी को मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने जो भाषणबाजी की, उससे अफसरशाही आगबबूला हो गई। भार्गव ने कहा था कि 'अरे मेडम, जिस संविधान के तहत यूपीएससी से आपकी नियुक्ति हुई है, उसी संविधान संशोधन का औचित्य हमारे कार्यकर्ता समझा रहे थे। ये संविधान नहीं होता तो आप घर में बैठकर रोटी बना रही होतीं, चूल्हा-चौका कर रही होतीं।' इस बयान ने अफसरशाही को 'लाल' कर दिया। उधर, बद्रीलाल यादव की अशोभनीय टिप्पणी ने आग में घी का काम किया। उनका बयान महिलाओं के बीच में भी अच्छा नहीं माना गया।

आइएएस अफसरों ने खूब निकाली भड़ास : थप्पड़ कांड के बाद सोशल मीडिया पर भी आइएएस अफसरों ने खूब भड़ास निकाली। उन्होंने नेताओं को डकैत और घपलेबाज तक कहा। आइएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष आइसीपी केसरी ने प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। इसके बाद से भाजपा और अफसरों में खटास और बढ़ गई।

असम में सरकारी नौकरी के लिए 10वीं तक असमी पढ़ना अनिवार्य

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि राज्य सरकार की नौकरी के लिए केवल वे ही आवेदन करने के योग्य होंगे जिन्होंने 10वीं तक असमी की पढ़ाई की है। शिक्षा मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि बराक घाटी के तीन जिलों और बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी जिले (बीटीएडी) को छोड़ शेष सभी क्षेत्रों में यह नियम लागू रहेगा। बराक घाटी के तीन जिलों और बीटीएडी में क्रमशः बांग्ला और बोडो के संबंध में यही क्लाउज लागू होगा।

सरमा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सभी माध्यम के स्कूलों में असमी को अनिवार्य विषय बनाने का फैसला ले लिया है। इस नए नियम को सम्मिलित करते हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे उनके दो बच्चे असम में राज्य सरकार की नौकरी के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि अपने स्कूल में वे असमी नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर 3000 करोड़ खर्च करेगी।

मैं किसके साथ, दो फरवरी तक करें इंतजार : प्रदीप यादव

जागरण संवाददाता, दुमका

- विधायक ने कहा, मंत्री बनाने का अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास
- फिर रघुवर दास के पांच वर्षों के कार्यकाल में क्यों रिक्त रहा मंत्री का एक पद

झाविमो विधायक दल के नेता पद से हटाए गए पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि जिस जगह जनता की भलाई होगी, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। वह किस दल का दामन थामेंगे यह जानने के लिए दो फरवरी तक इंतजार करें, पर्दा उठ जाएगा। वह शनिवार को मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से गठबंधन का दौर चला है, शीर्ष नेतृत्व को सरकार चलाने में कठिनाई हुई है। नेतृत्वकर्ता को अपने कुनबे को संभालकर रखने में पसीना भी छूटता है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हर नेता विधायक बनना चाहता है। मंत्री बनाना या न बनाना यह मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। ऐसे मंत्री की बात कौन करे, राजनीति में कदम रखने वाला हर कोई मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने की चाहत रखता है। विधायक दल के नेता पद से हटाए जाने की बात पर उन्होंने दो टूक कहा कि इसका उत्तर हमें पद से मुक्त करने वाले से पूछा जाना चाहिए।

प्रदीप के कांग्रेस में शामिल होने पर विधायक इरफान अंसारी द्वारा इस्तीफा दिए जाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि यह इरफान अंसारी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। उन्होंने इस बात को भी सिरे से खारिज किया कि उनके अथवा बंधु तिर्की की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि रघुवर दास से पूछा जाना चाहिए कि पूरे पांच साल तक सरकार चलाने के बाद भी मंत्री के एक रिक्त पद को वे क्यों नहीं भर सके।

झाविमो विधायक प्रदीप यादव व पार्टी से निष्कासित विधायक बंधु तिर्की का कांग्रेस में शामिल होना लगभग तय है, लेकिन इसकी तारीख कानूनी अड़चनों की समाप्ति के बाद ही तय होगी। समस्या प्रदीप यादव के साथ अधिक है। उन्हें पार्टी ने विधायक दल के नेता से हटाया जरूर है, लेकिन पार्टी स्तर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर प्रदीप यादव ने भी चुनौती दी है और कहा है कि विधायक दल के नेता को विधायक दल की बैठक में हटाया जा सकता है। इससे प्रतीत हो रहा है कि दोनों गुट कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति में प्रदीप यादव अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उन्हें दलबदल कानून के तहत कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।

गडकरी ने शिवसेना पर लगाया भाजपा के साथ विश्वासघात करने का आरोप

नागपुर, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि भाजपा पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हारी नहीं बल्कि शिवसेना ने उसके साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने न केवल अपने सहयोगी को छोड़ा बल्कि अपनी विचारधारा भी छोड़ दी।

नागपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, 'मैं नहीं समझता कि भाजपा चुनाव हार गई। शिवसेना ने हमारा साथ और अपनी विचारधारा को छोड़ दिया। भाजपा चुनाव हारी नहीं बल्कि उसके साथ विश्वासघात किया गया।' भाजपा और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था और उन्होंने क्रमशः 105 एवं 56 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। लेकिन शिवसेना ने भाजपा के साथ तीन दशक पुराना संबंध तोड़ लिया क्योंकि भाजपा ने उससे मुख्यमंत्री का पद साझा करने से इन्कार कर दिया।

शिवसेना ने राकांपा और कांग्रेस से हाथ मिला लिया एवं उद्धव ठाकरे की अगुआई में सरकार बनाई। हाल के जिला परिषद चुनाव नतीजे पर गडकरी ने कहा कि भाजपा को अधिक वोट फीसद मिलने चाहिए थे। उन्होंने कहा, 'लेकिन हमारी ताकत नागपुर ग्रामीण में जस की तस है और हमारे विरुद्ध जो एक साथ आए, वे भी हमारी ताकत से डरे हुए हैं। भले ही वे साथ आ जाएं लेकिन हम उन्हें हरा देंगे।'

नागपुर में शनिवार को खद्दर क्रीड़ा महोत्सव के समापन पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्रिकेट में हाथ आजमाए। इस दौरान उन्होंने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (तस्वीर में नही हैं) को गेंदबाजी की। इस मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस (बाएं) भी मौजूद रहे। प्रेट्र

राउत ने की घोषणा सात मार्च को अयोध्या जाएंगे उद्धव ठाकरे

मुंबई, प्रेट्र : सरकार के सौ दिन पूरे होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सात मार्च को अयोध्या जाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को यह घोषणा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव की यह पहली अयोध्या यात्रा होगी।

राउत ने ट्वीट कर कहा, 'अयोध्या में जल्लोष! सात मार्च, 2020' बाद में पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा, 'मुख्यमंत्री सत्ता में सौ दिन पूरे होने के मौके पर अयोध्या जाएंगे। देशभर के हजारों शिवसैनिक भी वहां मौजूद होंगे।' उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अयोध्या में रामलला की पूजा-अर्चना करेंगे और सरयू नदी के तट पर आरती भी करेंगे।

शिवसेना सांसद ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की यह यात्रा प्रतिबद्धता और आस्था का मामला है और इसके कोई भी राजनीतिक मायने नहीं हैं। जब उनसे भाजपा द्वारा की जा रही आलोचना के बारे में पूछा गया जो कहती है कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी अपने साथ अयोध्या लेकर जाना चाहिए, राउत ने कहा कि कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने राम मंदिर मसले पर अदालत के फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने कहा, 'भाजपा जो कहती है हम उस पर ध्यान नहीं देते।'

विचार

संघ प्रमुख ने कहा, समाज को तोड़कर विपरीत संवाद खड़ा करने का किया जा रहा प्रयास, उन्नत खेती के लिए की पांच नियमों का पालन करने की अपील

विकृतियों से टूट रहा सामाजिक तानाबाना : भागवत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि जात-पात, विषमता, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक विकार जल्द से जल्द समाप्त होने चाहिए। कुछ विकृतियों की वजह से न केवल सामाजिक तानाबाना टूटा है बल्कि समाज को तोड़कर विपरीत संवाद खड़ा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में विकृतियों को समाप्त करना, समाज का मन बदलना और विपरीत संवाद को समाप्त कर सामाजिक समरसता कायम करना स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी है। सामाजिक अहंकार और हीनता के भाव पर भी तत्काल विराम लगना चाहिए।

वह शनिवार को आरएसएस के उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र के स्वयंसेवकों की बैठक के दूसरे दिन सामाजिक समरसता विषय पर चर्चा कर रहे थे। बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र कार्यकारिणी, अवध, काशी, गोरक्ष, कानपुर प्रांत टोली, प्रांत कार्यकारिणी, गतिविधियों (पर्यावरण, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, धर्म जागरण, समग्र ग्राम विकास व गो सेवा) की प्रांत टोली मौजूद रही। संघ प्रमुख ने कहा कि कार्यकर्ता बिना किसी प्रचार व शासन सत्ता के सहयोग के समाज के सज्जन लोगों को साथ मिलाकर परिवर्तन की गतिविधियों में जोड़ने का काम करें। ऐसा माहौल बनाएं कि पूरा समाज भेदभाव को भुलाकर समरसता के भाव से खड़ा हो। उन्होंने पौधारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने के साथ जैविक खेती को भी प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।

गोरखपुर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र की कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करने के दौरान सर संघचालक मोहन भागवत (बाएं) और साथ में हैं पूर्वी क्षेत्र के संघ संचालक वीरेंद्र पराक्रमादित्य। सौजन्य : आरएसएस

जैविक खेती को अपनाने पर जोर

भागवत ने आदर्श और उन्नत खेती के लिए स्वच्छता, स्वाध्याय, तप, सुधर्म और संतोष के पांच नियमों का पालन करने की अपील की। स्वच्छता के तहत गांव को साफ रखने, स्वाध्याय के अंतर्गत भारतीय पद्धति का अध्ययन करने, तप की अवधारणा में जमीन को भगवान मानकर सेवा करने, सुधर्म का पालन करने के साथ अच्छे परिणाम के लिए संतोष अर्थात धैर्य पूर्वक जैविक खेती को अपनाने की बात कही।

उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक धामी की पार्टी छोड़ने की धमकी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी घोषित होते ही विवाद खड़ा हो गया है। धारचूला विधायक हरीश धामी ने तल्खी दिखाते हुए नई प्रदेश कमेटी में सौंपे गए प्रदेश सचिव के दायित्व से इस्तीफा दे दिया। साथ में पार्टी छोड़ने की धमकी दे डाली है। उधर, इस विवाद से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह सकते में हैं। धामी का नाम विशेष आमंत्रित सदस्य सूची से काटकर प्रदेश सचिव के तौर पर शामिल करने से खफा प्रीतम सिंह ने कहा कि यह राजनीतिक साजिश है। सूची में ऐसा बदलाव करने वाले का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। वह इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल से भी बात करेंगे।

पहले विधायक धामी के तल्ख रुख और फिर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की सूची में उनकी जानकारी के बगैर फेरबदल पर आपत्ति पार्टी में नया तूफान उठने के संकेत दे रही है। नई प्रदेश कमेटी में 98 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। प्रदेश सचिव की सूची में सबसे आखिर में हरीश धामी का नाम है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश समेत पार्टी के कुल 11 में से नौ विधायक विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। दो बार के विधायक और कांग्रेस से लंबे से जुड़े धामी को प्रदेश कमेटी में अपनी स्थिति नागवार गुजरी है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन में दिए गए पद से वह इस्तीफा दे रहे हैं। सोमवार को इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह तक पहुंच जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इसी माध्यम यानी सोशल मीडिया के जरिए ही वह कांग्रेस छोड़ने की तारीख की घोषणा भी करेंगे। धामी की पोस्ट से प्रदेश कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया।

10 वीं तक असमी की पढ़ाई करना अनिवार्य कर दिया गया है असम में सरकारी नौकरी पाने के लिए। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत विस्व सरमा ने कहा कि बराक घाटी के तीन जिलों और बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी जिले (बीटीएडी) को छोड़ शेष सभी क्षेत्रों में यह नियम लागू रहेगा।

बाहर किए जाएं बांग्लादेश व पाक के मुस्लिम घुसपैठिए : शिवसेना

दिया बयान ▸ घुसपैठियों के मसले पर दिया मोदी सरकार को समर्थन

हिंदुत्व का रुख करने और नया झंडा अपनाने के लिए मनसे पर साधा निशाना

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को देश से बाहर करने के मुद्दे पर मोदी सरकार को समर्थन की घोषणा करने के दो दिन बाद शिवसेना ने शनिवार को कहा कि इन देशों से आए मुस्लिम घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए।

मुखपत्र 'सामना' में शिवसेना ने कहा, 'पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन यह देखना मनोरंजक है कि एक पार्टी इसके लिए अपना झंडा बदल रही है। दूसरा, दो झंडे रखना दिमागी भ्रम को दर्शाता है। राज ठाकरे ने 14 साल पहले मराठी के मसले पर अपनी पार्टी बनाई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वह हिंदुत्व की ओर रुख कर रही है।' राज ठाकरे ने गुरुवार को अपनी पार्टी का नया झंडा लांच किया था। भगवा रंग के इस झंडे में छत्रपति

शिवाजी महाराज के समय इस्तेमाल की जाने वाली राजमुद्रा अंकित है। राज ठाकरे ने स्पष्ट किया था कि इस झंडे का इस्तेमाल पार्टी चुनावों के दौरान नहीं करेगी।

इस पर तंज कसते हुए शिवसेना ने कहा, 'सावरकर और बालासाहब की हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन हम बड़े दिल वाले हैं और हिंदुत्व समर्थक रुख अपनाने वालों का स्वागत करते हैं। भले ही विचारधारा उधार ली हुई है, लेकिन है तो हिंदुत्व समर्थक। अगर आपको लगता है कि आप यह कर सकते हैं तो जरूर कीजिए।'

पार्टी का आगे कहना है, 'शिवसेना मराठी के मुद्दे पर पहले ही काफी काम कर चुकी है, इसीलिए मनसे को मराठियों से कोई समर्थन नहीं मिला। इस बात को लेकर आलोचना की जा रही है कि भाजपा के कहने पर राज ठाकरे ने हिंदुत्व की ओर रुख किया है।' संपादकीय के मुताबिक, 'शिवसेना ने महाराष्ट्र में कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इसका यह मतलब नहीं है कि पार्टी ने अपनी विचारधारा छोड़ दी है। भाजपा महबूबा मुफ्ती समेत किसी से भी हाथ मिला सकती है, लेकिन अगर दूसरे इसी तरह का राजनीतिक कदम उठाएं तो यह पाप बन जाता है। भले ही तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग-अलग है, लेकिन उनमें इस बात पर सहमति है कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए चलाई जाएगी। भाजपा जो पांच साल में नहीं कर पाई, उसे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार 50 दिनों में हासिल कर चुकी है।'

राज ठाकरे के उस बयान पर कि सरकार का हिस्सा बनने के लिए शिवसेना ने अपना रंग बदल लिया है, पार्टी ने कहा, 'जो यह कहते हैं उन्हें अपने चेहरों पर लगे नकाबों और बहुरंगी मेकअप को देखना चाहिए। भाजपा ने 2014 और 2019 में अपना रंग बदला। लेकिन कांग्रेस और राकांपा से गठबंधन के बावजूद शिवसेना नहीं बदलेगी।'

मोदी-शाह पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने पर थाने में हंगामा

नईदुनिया, बिलासपुर: सीएए व एनआरसी को लेकर देशभर में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बखेड़ा हो गया। कोतवाली थाने में शनिवार को जमकर बवाल हुआ। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद मामला शांत हुआ।

सीएए लागू करने को लेकर शहर में भी पक्ष और विपक्ष में विरोध-प्रदर्शन का दौर चल रहा है। रिवरव्यू व ईदगाह चौक पर लोग एकजुट होकर नारेबाजी कर अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। इस बीच शनिवार को मसानगंज निवासी युवक ने फेसबुक पर पोस्ट कर बवाल मचा दिया। युवक ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभद्र व आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया। इस पोस्ट में भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल व शिवसेना के बारे में भी आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं।

इसकी भनक लगते ही भाजपाइयों में आक्रोश फूट पड़ा। वे नारेबाजी करते हुए कोतवाली थाने पहुंच गए। थाने का घेराव करते हुए भाजपाइयों ने आरोपित युवक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की।

सीआरपीएफ को मिले 76 वीरता पदक

नई दिल्ली, एजेंसियां : जम्मू-कश्मीर पुलिस के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) को सबसे ज्यादा 76 वीरता पदक मिले हैं, इनमें एक राष्ट्रपति पुलिस पदक भी शामिल है। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो उत्पल रंभा को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक (पीपीएमजी) से नवाजा गया है। रंभा जून 2018 में झारखंड में माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे।

नरेश कुमार को छठीं बार वीरता पदक : पदक पाने वालों में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट नरेश कुमार भी शामिल हैं। इन्हें छवीं बार वीरता पदक मिला है। नरेश कुमार श्रीनगर में तैनात सीआरपीएफ के क्विक एक्शन टीम (क्यूएटी) में तैनात थे, जो आतंकवाद रोधी अभियान के लिए जानी जाती है। 34 साल के नरेश कुमार कश्मीर में पांच साल की तैनाती के दौरान कई आतंकरोधी अभियान में शामिल हुए, जिनमें 50 आतंकवादी मार गिराए गए थे।

सीआइएसएफ के 29, आइटीबीपी के 15 कर्मियों को पुलिस सेवा पदक : औद्योगिक सुरक्षाबल (सीआइएसएफ) के 29 कर्मियों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के 15 कर्मियों को विभिन्न पुलिस सेवा पदकों से नवाजा गया। पदक प्राप्त करने वालों में सीआइएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट विष्णु स्वरूप और सहायक कमांडेंट अब्दुस सलाम और आइटीबीपी के कमान में दूसरे नंबर की रैंक के अधिकारी रतन सिंह सोनल शामिल हैं।

सोनल जाने-माने पर्वतारोही हैं जो कई बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुके हैं। उन्होंने पिछले साल उत्तराखंड में एक पर्वत चोटी के पास फंसे सात लोगों के शवों को निकालने के अत्यंत मुश्किल अभियान के दौरान आइटीबीपी के पर्वतारोहियों की टीम का नेतृत्व किया था।

चिदंबरम को गिरफ्तार करने वाले सीबीआइ अफसर को भी पदक : सीबीआइ के 28 अधिकारियों को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। इनमें कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए दीवार फांद कर उनके घर में घुसने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के डिप्टी एसपी रामस्वामी पार्थसारथी भी शामिल है। आइएनएक्स मीडिया मामले में उन्होंने चिदंबरम के बेटे कार्ति को भी गिरफ्तार किया था।

छह सैन्य कर्मियों को शौर्य चक्र

देश में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ अभियानों में बहादुरी का परिचय देने वाले सेना के छह सैनिकों को शौर्य चक्र दिया गया है। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा, मेजर के बिजेंद्र सिंह, नायब सूबेदार नरेंदर सिंह और नायक नरेश कुमार तथा सिपाही कर्मदेव उरांव शामिल हैं। नायब सूबेदार सोमबीर को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। पिछले साल फरवरी में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सोमबीर शहीद हो गए थे। सेना के अधिकारी ने बताया कि सेना के उत्तरी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह समेत 19 उच्च अधिकारियों को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 151 सेना मेडल और आठ युद्ध सेवा मेडल की घोषणा भी की गई है।

पद्मश्री पाने वालों में कई गुमनाम नायक

नई दिल्ली, प्रेट्र : चंडीगढ़ स्थित पीजीआइ अस्पताल के बाहर मरीजों और उनके साथ आए लोगों को निःशुल्क भोजन कराने वाले जगदीश लाल आहूजा, 25,000 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाले फैजाबाद के मुहम्मद शरीफ, मुस्लिम भजन गायक मुन्ना मास्टर और असम में हाथियों के चिकित्सक कुशल कंवर सरमा उन गुमनाम नायकों में शामिल हैं जिन्हें इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।

लंगर बाबा के नाम से प्रसिद्ध जगदीश लाल अहूजा, पत्नी निर्मल के साथ। हरप्रवेश सिंह

तमिलनाडु के 65 वर्षीय दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता एस रामकृष्णन की फाइल फोटो।

सम्मान पाने वालों में जम्मू-कश्मीर के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद टाक भी शामिल हैं जो दो दशक से दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। वह अनंतनाग और पुलवामा के 40 गांवों में 100 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अन्य सहायता मुहैया करा रहे हैं। औपचारिक शिक्षा नहीं लेने के बावजूद पौधों की विविध किस्मों के विशाल ज्ञान के कारण 'वन की विश्वकोष' उपाधि से प्रख्यात कर्नाटक की 72 वर्षीय तुलसी गौड़ा को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया है। पिछले चार दशक से पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदराज के इलाकों में शिक्षा और पाठन संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे और 'अंकल मूसा' के नाम से विख्यात अरुणाचल प्रदेश के सत्यनारायण मुंदायूर, 1984 भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की खातिर लड़ाई लड़ने वाले अब्दुल जब्बार उर्फ 'भोपाल की आवाज' (मरणोपरांत) और राजस्थान में स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाली दलित सामाजिक कार्यकर्ता ऊषा चौमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सूखाग्रस्त हिवरे बाजार में भूजल में सुधार करने के लिए अहमदनगर (महाराष्ट्र) के प्रख्यात पोपाटाराव पवार, गरीबों को किफायती शिक्षा देने में मदद करने वाले कर्नाटक के 64 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता हारेकला हाजब्बा, दूरस्थ सुंदरबन में मरीजों का उपचार करने वाले बंगाल के चिकित्सक अरुणोदय मंडल, केवल जैविक तकनीक के प्रयोग से ओडिशा में बंजर भूमि को वन क्षेत्र में तब्दील करने वाले गांधीवादी राधा मोहन और उनकी पुत्री साबरमती को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। हल्दी की खेती संबंधी मुहिम चलाने वाले मेघालय के आदिवासी किसान ट्रिनिटि साइऊ, असम की बराक घाटी में कैंसर मरीजों का उपचार करने वाले चेन्नई के चिकित्सक रवि कन्नन, तमिलनाडु में चार दशक से अधिक समय से 14,000 से अधिक दिव्यांग लोगों के पुनर्वास में मदद करने वाले दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता एस. रामाकृष्णन को भी यह पुरस्कार दिया गया। इनके अलावा सरकार ने राजस्थान में 50,000 पौधे लगाने वाले 68 वर्षीय पर्यावरणविद् सुंदरम वर्मा, राज्य के मुस्लिम भजन गायक मुन्ना मास्टर, पिछले 35 साल से लोगों का निःशुल्क उपचार कर रहे उत्तराखंड के 81 वर्षीय चिकित्सक योगी ऐरन, कृषि-जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए विश्वविख्यात आदिवासी महिला राहीबाई सोमा पोपेरे को भी पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है।

न्यूज गैलरी

सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकता है तेलंगाना

हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को कहा कि राज्य की विधानसभा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है, जैसा कि हाल में कुछ अन्य राज्यों ने किया है। राव ने कहा कि वह पहले ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस सिलसिले में बात कर चुके हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सीएए का विरोध करने के लिए वे क्षेत्रीय पार्टियों और मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन भी बुला सकते हैं। राव ने बताया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) अपनी नीति और प्रकृति में पंथनिरपेक्ष है और इसने सीएए का विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले माह टीआरएस ने संसद में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मतदान किया था। (प्रेट्र)

उप्र में प्रदर्शन करने वाले 100 से अधिक पर एफआइआर

लखनऊ : लखनऊ के घंटाघर पर चल रहे प्रदर्शन के नौवें दिन 10 को नामजद करते हुए सौ से अधिक प्रदर्शनकारियों पर ठाकुरगंज थाने में एफआइआर दर्ज की गई। इनमें से आठ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें दिल्ली के जामिया नगर से प्रदर्शन का नेतृत्व करने आए सैयद मोहम्मद फैजान इलाही, सआदतगंज के कैंपवेल रोड निवासी सैयद दानिश, सआदतगंज निवासी तारिक, गढ़ीपीर खां निवासी रेहान, चौपटिया नसीम, दुबग्गा निवासी मोहिद नदीम, सआदतगंज निवासी लईक अहमद व पीजीआइ निवासी सपा कार्यकर्ता पूजा शामिल हैं। (जासं)

इन्कार पर बर्खास्त हो सकती है राज्य सरकार : कोकजे

जबलपुर : विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व न्यायाधिपति विष्णुराव सदाशिव कोकजे ने सीएए को लेकर कहा कि संसद से पारित कानून को कोई भी राज्य लागू करने से इन्कार नहीं कर सकता है। ऐसी सरकारें सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रही हैं। यदि कानून को लागू करने से कोई इन्कार करता है तो उस राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ये संवैधानिक संकट जैसी स्थिति होगी। कोकजे जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। (नईदुनिया)

केरल के राज्यपाल ने कहा, मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाना है तो लाए कांग्रेस

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा है कि कांग्रेस यदि विधानसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहती है तो लाए। उसका स्वागत है। उनकी यह टिप्पणी केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने राज्यपाल को वापस बुलाए जाने का प्रस्ताव लाने की बात कही थी।

संशोधित नागरिकता कानून पर राज्य विधानसभा में अपने खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की कांग्रेस की योजना का स्वागत करते हुए राज्यपाल ने शनिवार को कहा कि वह संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। कांग्रेस की योजना के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, 'हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। मैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख हूं। सरकार को सलाह देना, परामर्श देना, प्रेरित करना और आगाह करना मेरा कर्तव्य है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार यह मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है।' राज्यपाल के अनुसार सरकार के

आरिफ मुहम्मद खान। फाइल

साथ उनका कोई टकराव नहीं है। उन्होंने कहा, 'विचार अलग हो सकते हैं लेकिन इसे टकराव नहीं कहा जा सकता।'

बजट सत्र के पहले दिन संबोधन में विधानसभा द्वारा पारित सीएए विरोधी प्रस्ताव पर राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने सरकार को केवल यह बताया था कि उन्हें दिए 'दस्तावेज की सामग्री में कैसे सुधार किया जाए।' राजभवन के एक अधिकारी ने कहा, 'नीति संबोधन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान में भाषण राज्य के विकासात्मक आयामों के बारे में होना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, राज्यपाल की यह राय है कि चूंकि नागरिकता कानून राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है तो विधानसभा में इसका उल्लेख करना सही नहीं था।'

कांग्रेस नेता चेन्निथला ने कहा था कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन को नोटिस सौंप विधायी कामकाज के नियम 130 के तहत प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने राज्यपाल पर शीतकालीन सत्र के दौरान नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 के खिलाफ राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने का आरोप लगाया।

चेन्निथला ने कहा, 'केरल विधानसभा में भाजपा के एकमात्र सदस्य ने भी सीएए के खिलाफ विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं किया, लेकिन राज्यपाल ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि यह असंवैधानिक है।'

लोहरदगा में तीसरे दिन भी कर्फ्यू, गुमला रहा बंद

जागरण संवाददाता, लोहरदगा

तीन दिन पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में निकले जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के कारण शनिवार को भी लोहरदगा में लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रहा। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। पुलिस के साथ ही अर्द्धसैनिक बल के जवान भी चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं। घटना के विरोध में गुमला में बंद का व्यापक असर रहा। लोहरदगा में घटना के बाद से जिले में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। रोज अलग-अलग क्षेत्रों से तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। इससे निपटने में भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति से लोहरदगा पुलिस प्रशासन को थोड़ी राहत मिली है, जिले में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस महानिरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने कहा कि घटना की जांच के लिए एसआइटी गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

हिरासत में लिए लोगों से हो रही पूछताछ

उपद्रव फैलाने के संदेह में लोहरदगा पुलिस प्रशासन ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।

गुदड़ी नरसंहार में प्रयुक्त दो कुल्हाड़ियां बरामद

जासं, सोनुवा (पश्चिमी सिंहभूम) : पुलिस ने गुदड़ी प्रखंड के बुरुगुलीकेरा गांव में हुई सात लोगों की हत्या की जांच के लिए गठित एसआइटी के सहयोग के लिए रांची से एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी) की टीम बुरुगुलिकेरा पहुंची। टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दो कुल्हाड़ियों को शनिवार को बरामद किया।

छह महीने में काटे थे 10.57 लाख रुपये के रेल टिकट

रजनीश, भागलपुर

ई-टिकट से हवाला के जरिये आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार मो. इमरान बड़ा शातिर निकला। पूछताछ में इमरान ने कई अहम जानकारी दी हैं। गुलाम मुस्तफा के अलावा देश के कई राज्यों में सक्रिय पैनल सेलर से भी इसके रिश्ते अच्छे रहे हैं। आरपीएफ की जांच में पता चला है कि इमरान ने 46 फर्जी आइडी से छह महीने में 10.57 लाख रुपये के 735 टिकट काटे थे। उसके पास कई बैंकों के कार्ड भी मिले हैं। इमरान की तरह ऐसे कई और बुकिंग एजेंट है जो इस तरह का धंधा संचालित कर रहे हैं। इस धंधे में और लोगों का पर्दाफाश करना आरपीएफ के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस अवैध धंधे में कई और के नाम जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।

दरअसल, आरपीएफ ने भागलपुर से गिरफ्तार मो. जुनैद रजा और मो. इमरान को रिमांड पर लिया था। रिमांड पर कड़ाई से पूछताछ के दौरान जुनैद से तो कोई खास इनपुट नहीं मिला। पर, मो. इमरान ने कई राज खोले हैं। मो. इमरान इस धंधे का माहिर खिलाड़ी है। इमरान के जिस लैपटॉप को आरपीएफ ने जब्त किया है। उस लैपटॉप से इमरान के साथ इन कंप्यूटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कंप्यूटर को जोड़कर काम करने की बात सामने आई है। इमरान ने बताया है कि वह किस तरह से ई-टिकट काटता था।

मुंबई, बेंगलुरु, सहित कई राज्यों के पैनल सेलर से संबंध : इमरान का मुस्तफा के साथ-साथ बिहार के अलावा मुंबई, यूपी, दिल्ली, बेंगलुरु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर सहित देश के कई राज्यों में सक्रिय पैनल सेलर (ई-टिकट सरगना) से संबंध है। पैनल सेलर ई-टिकट के अवैध धंधे से जुड़े लोगों का ग्रुप है। इमरान ने बताया कि वह आने-जाने के लिए बंगाल या पटना से फ्लाइट लेता था।

बहुत तेज काम करता था सॉफ्टवेयर : इमरान जिस सॉफ्टवेयर से ई-टिकट काटता था उसकी स्पीड आइआरसीटीसी के सॉफ्टवेयर से हजार गुणा से ज्यादा तेज है। इमरान ने बताया कि पैनल सेलर के पास ऐसी व्यवस्था है जो उसे पता रहता था कि किस बैंक का लिंक तेजी से काम करेगा।

नेपाल भागे मुस्तफा के कई गुर्गे

चंद्रशेखर, पटना

अवैध ई-टिकटों की कमाई से टेरर फंडिंग का पर्दाफाश होने के बाद नेपाल से गिरोह चला रहे बस्ती के मास्टरमाइंड हामिद अशरफ उर्फ हामिद अंसारी के बिहार में रहने वाले अधिकांश गुर्गों ने गिरफ्तारी के डर से नेपाल अथवा अन्य शहरों में शरण ले रखी है। हामिद के दाहिने हाथ मो. मुस्तफा की गिरफ्तारी के बाद बिहार और झारखंड में इनके गिरोह से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है।

आरपीएफ की विशेष टीम की मानें तो ई-टिकट के काले कारोबारी मो. मुस्तफा के लिए काम करने वालों में सबसे अधिक भागलपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, रक्सौल, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा, मुंगेर, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, बेगूसराय, किशनगंज, पूर्णिया के लोग हैं। इसके अलावा गिरिडीह, रांची, धनबाद जिले के सदस्य भी हैं। सीतामढ़ी निवासी मनोज की गिरफ्तारी के लिए आरपीएफ की टीम जब तक उसके घर पहुंचती वह फरार होकर नेपाल पहुंच चुका था। समस्तीपुर निवासी मो. तबरेज व एक अन्य भी गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हैं। सीतामढ़ी निवासी मनोज मुस्तफा व हामिद से काफी जुड़ा हुआ था। मनोज व तबरेज हर महीने करोड़ों रुपये नेपाल में बैठे सरगना हामिद को हवाला के जरिए पहुंचाते थे। मो. मुस्तफा से कनेक्शन की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ की टीम ने अरवल जिले के एक गांव में शुक्रवार को छापेमारी की। लेकिन उसका करीबी पहले ही फरार हो चुका था। वह मुस्तफा के काले धन को सफेद करने में मदद तो करता ही था बिहार से मोटी रकम हवाला के जरिए दुबई भी भेजता था।

हैलो-हाय छोड़िये, जय हिंद बोलिये ...अरुणाचल से सीखिये

रविवार विशेष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालही में 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश की एक प्रेरक विशेषता का जिक्र किया था। यह जिक्र वह इससे पहले 2015 और फिर 2018 में भी कर चुके थे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत का एक ऐसा राज्य है, जहां लोग मिलते हैं तो जय हिंद कहकर एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं ...। इसे समझने के लिए हमने अरुणाचल का रुख किया। पाया कि मोदी जी ने जो कहा, सच ही कहा ...। कमाल का जज्बा। विशुद्ध राष्ट्रवाद। कहीं कोई मिलावट नहीं। एकदम खालिस और शतप्रतिशत शुद्ध ...। ईटानगर से संवाद सहयोगी मनोज सिंह के साथ कोलकाता से जागरण संवाददाता विशाल श्रेष्ठ की रिपोर्ट

हम भारत की उस धरा, उस राज्य के निवासी हैं, जहां उगते सूर्य की पहली किरण दस्तक देती है। इसीलिए तो इसे अरुणाचल कहा गया है। भले ही हमारी विभिन्न समुदायों, जातियों और बोलियों के रूप में भी पहचान है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम भारतवंशी हैं। हम हिंदी हैं, हिंदुस्तानी हैं। आप अरुणाचल में कहीं भी जाएं, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो 'जय हिंद' कहकर एक-दूसरे का अभिवादन करना अपनी शान समझते हैं...। राजधानी ईटानगर से चंद किलोमीटर दूर स्थित चीन की सीमा से सटे कस्बे के रहने वाले फुरपा सेरिंग ने बेहद गर्व से यह बात कही।

फुरपा ने इसके पीछे का कारण भी बताया। बोले, चूंकि अरुणाचल चीन से सटा हुआ है, भारतीय फौजी यहां तैनात रहते हैं। वे एक-दूसरे का अभिवादन बड़े ही जोश के साथ जय हिंद कहकर करते हैं। उनका यह जोश हमें भी देशप्रेम से भर देता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने उनसे प्रेरित होकर जय हिंद को आम बोलचाल में अपना लिया। देश के अन्य स्थानों से जो लोग यहां आते हैं, हम उनका भी स्वागत जय हिंद, भारत माता की जय और वंदे मातरम कहकर करते हैं। दरअसल हम जताना चाहते हैं कि हम भी भारतीय हैं...।

ईटानगर हो या छोर पर बसा गांव मॉनबांग, या फिर तवांग, हम जहां भी गए, अरुणाचलवासियों का यह जज्बा और अंदाज देख देशप्रेम से भर उठे। आज अरुणाचल प्रदेश में 'जय हिंद' अभिवादन संस्कृति का पर्याय बन चुका है। यह संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत के रूप में स्थानांतरित हो रहा है। कमाल का जज्बा। विशुद्ध राष्ट्रवाद। कहीं कोई मिलावट नहीं। एकदम खालिस और शतप्रतिशत शुद्ध।

ईटानगर निवासी कीपा बाबा ने कहा, मैंने भी अपने पूर्वजों और फिर फौजी भाइयों से जय हिंद बोलना सीखा। जय हिंद हमारे लिए सम्मानसूचक शब्द है। ऐसा नहीं है कि हम अन्य अभिवादनों को उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जब किसी के प्रति अधिक सम्मान जताना चाहते हैं तो निश्चित ही जय हिंद कहकर ही अभिवादन करते हैं। प्रदेश के क्रा दादी जिले में चीन की सीमा से सटे टाली इलाके के रहने वाले तकशिंग तायेम कहते हैं, मेरे तो माता-पिता भी जय हिंद कहकर ही एक-दूसरे का अभिवादन करते थे। जय हिंद हमारी फौज का नारा है। यह सुदूर बसे हम लोगों को भारत के दिल से जोड़ता है...।

- अरुणाचल के लोगों के लिए 'जय हिंद' कहना विरासत और संस्कृति का हिस्सा
- उगते सूरज की भूमि में निखर रही 'जय हिंद' की छटा

किपा बाबा। सौ. अरुणाचल सरकार

ताकशिंग तायेम।

फुरपा सेरिंग।

तिरंगा थामें अरुणाचल की महिलाओं की फाइल फोटो।

'जय हिंद' हमारे खून में : मुख्यमंत्री खांडू

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दैनिक जागरण से कहा, अरुणाचल 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध की युद्धभूमि रहा है। उस समय यहां भारतीय सेना की मौजूदगी से हिंदी और जय हिंद की शुरुआत हुई थी। सेना में कुली के काम के लिए सैकड़ों स्थानीय लोगों की भर्ती की गई थी, जिन्हें बातचीत करने के लिए हिंदी सीखनी पड़ी थी। सेना ने यहां स्वास्थ्य, शिक्षा व आधारभूत संरचना संबंधित संस्थान निर्मित किए थे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए हिंदी सीखना-समझना आसान हो गया था। फौजी हिंदी में बातचीत करते थे और जय हिंद कहकर अभिवादन करते थे। इससे स्वाभाविक तौर पर स्थानीय लोगों में भी जय हिंद कहने की प्रवृत्ति पैदा हुई, जो अब यहां का शिष्टाचार बन चुकी है। विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के गांवों में, वहां इसे लेकर जोश कहीं अधिक दिखता है। आज अरुणाचल का हर नागरिक हिंदी बोल पाने की अपनी योग्यता को लेकर गर्व की अनुभूति करता है। जय हिंद हर अरुणाचल वासी के खून में है।

पेमा खांडू।

अपना अरुणाचल...

अरुणाचल प्रदेश की आबादी 14 लाख से थोड़ी कम है। यह 26 आदिवासी जातियों व 256 उप जातियों का घर है, जो लगभग 90 स्थानीय भाषाएं बोलते हैं। इस विविधता के बीच भी हिंदी राज्य की सामान्य भाषा के रूप में उभरी है। यह संपर्क भाषा भी है, जो प्रशासनिक इकाइयों को बांधती है। राज्य के 90 फीसद से अधिक लोग हिंदी में बातचीत करते हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

1.51 करोड़ रुपये का जुर्माना 2019 में रेलवे ने सिर्फ टिकट चेकिंग से ही वसूला है। रेलवे ने यह जुर्माना 22,680 उन यात्रियों से वसूला, जो बिना टिकट के ही यात्रा कर रहे थे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 26 जनवरी 2020

कुछ बरसों से टूट गया हूं, खंडित हूं, वादी तेरा बेटा हूं मैं, पंडित हूं...

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल

ईश्वर शर्मा, जयपुर

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने आए फिल्म 'शिकारा' के निर्माता-निर्देशक और विस्थापित कश्मीरी पंडित विधु विनोद चोपड़ा का दर्द दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से चर्चा में फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में मैंने 30 साल पुराने विस्थापन के दर्द को व्यक्त करने की कोशिश की है। मुझे लगता है हर कश्मीरी पंडित अपनी घाटी से फिर कहना चाहता है- 'कुछ बरसों से टूट गया हूं, खंडित हूं, वादी तेरा बेटा हूं मैं, पंडित हूं...।'

चोपड़ा ने कहा, '19 जनवरी 1990 की वह भयानक रात मुझ सहित उन चार लाख कश्मीरी पंडितों को याद है, जिन्हें अपना घर, खेत, सेब के लहलहाते बगीचे, आंगन, यादें...सब छोड़कर भागना पड़ा था। उस रात आवाज गूंजी थी कि 'कश्मीरी पंडितों घर छोड़ दो, वरना खुदा को प्यारे हो जाओगे। उस दर्द में मेरा दर्द भी शामिल है।

कई शाहीन बाग कम पड़ेंगे : विधु विनोद चोपड़ा ने एक प्रश्न के जवाब में कहा- 'बेजा मुद्दों के लिए लोग शाहीन बाग जैसे धरने खड़े कर देते हैं, मगर कश्मीरी पंडितों के दर्द को कहने के लिए कई शाहीन बाग कम पड़ेंगे।' चोपड़ा ने कहा कि तब 87,000 लोगों के मारे जाने का सरकारी आंकड़ा सामने आया था, हकीकत में इससे कहीं अधिक करीब दो लाख लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए हटा दिए जाने की प्रशंसा करते हुए विधु विनोद ने कहा- '30 साल में यह एकमात्र ऐसी साहसी सरकार आई, जिसने यह कर दिखाया।'

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते फिल्म निर्माता-निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा (बीच में)। जागरण

भाई ने 200 रुपये देकर कहा था- जा सपने सच कर ले

अपना संघर्ष बयां करते चोपड़ा ने कहा- 'मेरे पिता गरीब कश्मीरी पंडित थे। उनके पास हमें खिलाने तक का पैसा नहीं था तो हमारे सपने कैसे पूरे करते। मेरे बड़े भाई ने मुझे 200 रुपये देकर कहा था, 'जा अपने सपने सच कर ले। मैं वही पैसा लेकर निकल पड़ा और आज इस मुकाम पर हूं।'

कश्मीर में फिल्म यूनिवर्सिटी खोलूंगा

चोपड़ा ने कहा, 'अब ऐसा कश्मीर चाहता हूं जहां प्रत्येक कश्मीरी पंडित फिर अपने घर लौट सके। ऐसा स्वर्ग से सुंदर कश्मीर जहां विवाद की बजाय संवाद हो। जिस दिन ऐसा होगा, मैं वहां अपनी फिल्म यूनिवर्सिटी खोलूंगा।'

सिर्फ सरकार सब कुछ नहीं कर सकती लोगों को भी बदलना होगा : अमिताभ कांत

राज्य ब्यूरो, जयपुर: नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि शहरों को स्वच्छ करने के लिए सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। लोगों को भी आगे आना होगा। इंदौर और भोपाल जैसे शहरों ने यह कर दिखाया है।

अमिताभ कांत जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन शनिवार को 'स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत' विषय पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने का अभियान नहीं था। इसने लोगों की सोच में बदलाव किया है और ग्रामीण भारत में इसका जबरदस्त प्रभाव देखा भी जा सकता है। जहां तक शहरों की बात है तो सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने से काम नहीं होगा, लोगों की सोच भी स्मार्ट होनी चाहिए। पांच साल पहले इंदौर गंदा शहर था और आज पूरे देश ही नहीं दक्षिण एशिया में सबसे साफ शहर है। उन्होंने कहा कि 70 साल में हमने सिर्फ ग्रामीण भारत के लिए योजनाएं बनाई, जबकि सच्चाई यह है कि लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं और हमारे यहां शहरीकरण बहुत अव्यवस्थित रहा है। यह पहली सरकार है, जिसने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में सोचा और शहरों की रैंकिंग ने बड़ा असर डाला है।

सत्र में जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को हमने राजनीतिक इच्छाशक्ति, लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक वित्त और संस्थाओं के साथ साझेदारी के दम पर चलाया है। अब जलजीवन मिशन को भी बड़ी चुनौती के रूप में हमने लिया है और इसे भी एक जनआंदोलन के रूप में चलाएंगे।

कोहली और मोदी ने क्रिकेट एवं सियासत के कायदे बदल दिए

जासं, जयपुर: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शनिवार को 'क्रिकेट: द स्पिरिट ऑफ द गेम' सत्र में क्रिकेट से लेकर राजनीति तक पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान क्रिकेट, नोटबंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर एवं पत्रकार राजदीप सरदेसाई में बातचीत हुई। सत्र में कहा गया कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने क्रिकेट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासत के कायदे बदल दिए।

सत्र में चर्चा हुई कि क्रिकेट का एक दौर वह था, जिसमें टेस्ट मैच हुआ करते थे और अब टी-20 हो रहे हैं। क्रिकेट के बदलते स्वरूप में कैसे लोगों की सोच बदली है। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि चाहे कुछ भी बदल जाए खेल गेंद बल्ले का ही रहेगा। राजदीप ने कहा कि जब एक खिलाड़ी को 10 करोड़ में खरीदा गया तब कपिल ने कहा था कि हमने क्रिकेट के लिए कितना किया व बेहतर करने पर भी एक करोड़ ही मिले थे।

न्यूज गैलरी

गुजरात में 11 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में गैरकानूनी रूप से रह रहे 11 बांग्लादेशियों को शनिवार को हिरासत में लिया गया। गुजरात पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने बताया कि इशानपुर में चंदोला झील के पास बनी बस्ती से इन्हें हिरासत में लिया गया है। एसओजी के सहायक पुलिस आयुक्त बीसी सोलंकी ने कहा, 'पुलिस अब उन्हें बांग्लादेश निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।' उन्होंने कहा, '11 बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे थे और यहां मजदूरी कर रहे थे।' सोलंकी ने कहा, 'हिरासत में लिए गए लोग भारतीय नागरिक होने का कोई भी दस्तावेज मुहैया नहीं करा पाए। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं वे किसी आपराधिक गतिविधि में तो शामिल नहीं थे।' (प्रेट्र)

बांदीपोरा में हिजबुल व लश्कर के सात ओजीडब्ल्यू दबोचे

श्रीनगर: उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में गणतंत्र दिवस पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मौका तलाश रहे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के सात ओवरग्राउंड वर्करों (ओजीडब्ल्यू) को शनिवार सुरक्षाबलों ने पकड़ लिया। इनमें पास से हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि गणतंत्र दिवस पर बांदीपोरा में आतंकी संगठन बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में हैं। आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए मुखबिरों का जाल बिछाया गया। इस दौरान कुछ सुराग लगे फिर छापेमारी शुरू की गई। (राब्यू)

मुठभेड़ में जैश के कमांडर समेत तीन ढेर

बड़ी कामयाबी ▶ सुरक्षाबलों का दावा-आतंकियों के सारे बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं

त्राल में 11 घंटे चली मुठभेड़ में मारे गए आतंकी, दो जवान भी घायल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

गणतंत्र दिवस पर घाटी में एक बड़े आत्मघाती हमले की साजिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम बना दिया। दक्षिण कश्मीर के त्राल में शनिवार को 11 घंटे चली एक भीषण मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मोहम्मद के कुख्यात कमांडर कारी यासिर समेत तीन आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए अन्य दो आतंकियों में आत्मघाती बुरहान शेख और पाकिस्तानी आतंकी मूसा भी बताया जा रहा है। मुठभेड़ में दो सैन्यकर्मी भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों पर भीड़ ने पथराव भी किया, जिसपर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन पुलिस या किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की।

अधिकारियों ने बताया कि जैश कमांडर कारी यासिर अपने साथियों के साथ गणतंत्र दिवस पर अवंतीपोरा और उसके साथ सटे इलाकों में हमले करने वाला था। इसलिए वह गत मंगलवार को खियू इलाके में अपने साथियों संग बैठक के लिए आया था। सुरक्षाबलों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने उसी समय आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। कारी यासिर उस समय घेराबंदी तोड़ भाग निकला था। इस दौरान दो सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए थे। अगले दिन बुधवार को करीब दो किलोमीटर आगे नगीनदर में सुरक्षाबलों ने जैश आतंकियों को दोबारा घेर लिया था और एक आतंकी सैफुल्ला मारा गया था।

पुलवामा हमले में भी शामिल था कारी : कारी यासिर बीते साल 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के वाहन पर हुए आत्मघाती हमले की साजिश में भी शामिल था। हमले में 40 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हुए थे। वर्ष 2016 से कश्मीर में सक्रिय कारी को आत्मघाती आतंकियों के रिक्रूटर के तौर पर भी जाना जाता है।

त्राल में मुठभेड़ के बाद प्रेस कांफ्रेंस के दौरान चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों (बीच में), साथ में कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार (दाएं)। एएनआइ

नागरिकों को बचाते हुए दो जवानों को लगी गोली

आतंकी जिस मकान में छिपे थे, वहां रहने वाले नागरिकों को सुरक्षाबलों ने आतंकियों की गोलियों की बौछार के बीच सुरक्षित बाहर निकाला। इसी दौरान दो सुरक्षाकर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए। आतंकियों को आत्मसमर्पण का कई बार मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने गोलाबारी जारी रखी। सुबह सात बजे शुरू हुई मुठभेड़ शाम छह बजे तक चली, जो कि तीनों आतंकियों के मारे जाने के साथ समाप्त हुई।

तीन आतंकियों के ढेर होते ही घाटी में जैश का सफाया

सेना की चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने और आइजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पत्रकारवार्ता में कहा कि पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में जैश के नेतृत्व को लगभग समाप्त कर दिया था। कारी यासिर का गुट किसी तरह बचा था जो अपना नेटवर्क भी बढ़ाने की कोशिश में था। खैर, आज हम कह सकते हैं कि जैश का सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि हिजबुल मुजाहिद्दीन सहित आतंकियों के सभी बड़े कमांडर चाहे स्थानीय हो या फिर पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। अल-बदर और लश्कर-ए-तैयबा भी कश्मीर में लगभग समाप्त हो चुके हैं। वहीं, घाटी में सक्रिय आतंकियों पर आइजीपी ने कहा कि 125 आतंकी रहे हैं। यह भी जल्द मारे जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे।

कश्मीर में बदलते हालात के साथ बदल गए 'उमर'

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ पूर्व सीएम की बढ़ी दाढ़ी और झुर्रियां, फिर भी कोई शिकन नहीं

▶ परिचित ने ही ट्विटर पर वायरल की उमर अब्दुल्ला की तस्वीर

सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला फिर ट्विटर पर छाए हैं। इस बार कारण उनका ट्वीट नहीं बल्कि उनकी तस्वीर है। यह तस्वीर उनके किसी परिचित ने ही वायरल की है। तस्वीर में उमर की बढ़ी दाढ़ी और चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आती हैं, लेकिन कोई शिकन नहीं है। तस्वीर में वह चिरपरिचित अंदाज में मंद-मंद मुस्कुराते हिमपात का मजा लेते नजर आते हैं।

पांच अगस्त से हिरासत में : नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष और एकीकृत जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गत वर्ष पांच अगस्त से एहतियातन हिरासत में हैं। पहले वह अपने घर से दो किलोमीटर आगे हरि निवास में एहतियातन हिरासत में रखे गए थे। कुछ दिन पूर्व उन्हें उनके घर के पास सरकारी बंगले में स्थानांतरित करने की सूचना है। उन्हें और उनके पिता और कश्मीर के 500 अन्य राजनीतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के मद्देनजर एहतियातन हिरासत में लिया था। हालांकि अधिकांश नेताओं को रिहा किया जा चुका है।

आसानी से पहचाने नहीं जा रहे : डिजायनर कपड़ों के शौकीन उमर अब्दुल्ला ने पांच अगस्त से पहले कभी दाढ़ी नहीं रखी थी। हिरासत में उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी और उनकी यह तस्वीर भी वायरल हुई थी। उनकी जो तस्वीर अब वायरल हुई है। उसमें उन्हें आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। वह किसी बुजुर्ग की भांति नजर आते हैं। सिर पर ऊनी टोपी पहने उमर ने दाढ़ी को पूरी तरह बढ़ा लिया है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही तस्वीर गत दिनों श्रीनगर में हुए हिमपात के दौरान की है। यह तस्वीर उनसे मिलने आए एक निकट संबंधी ने ली है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तस्वीर। ट्विटर

अफसरों ने मंत्रियों को अदालत के निर्देशों का दिया हवाला

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

अधिकारियों ने मंत्रियों को यह भी बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अन्य मामलों में निर्देश हैं कि राज्य की किसी एजेंसी द्वारा जांच के बाद उसी मामले की जांच का काम राज्य की ही किसी अन्य एजेंसी को नहीं दिया जा सकता। माना जा रहा है कि पवार के निर्देश पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की एक घटक राकांपा इस मामले में विशेष रुचि ले रही है। कांग्रेस को मजबूरी में उसका साथ देना पड़ रहा है। जबकि फड़नवीस सरकार में गृह राज्यमंत्री रहे शिवसेना नेता दीपक केसरकर इस मामले में पुलिस की जांच को सही ठहराते दिख रहे हैं। शिवसेना की स्थिति इस मामले में सांप-छछूंदर जैसी हो रही है। फड़नवीस सरकार में कनिष्ठ सहयोगी होने के बावजूद उस समय वह गृह मंत्रालय में भागीदार थी। हालांकि उनके नेता उद्धव ठाकरे की कोई प्रतिक्रिया इस मामले में अब तक नहीं आई है। हालांकि शरद पवार आरोप लगा रहे हैं कि एसआइटी की जांच होने पर निर्दोष लोगों को फंसाए जाने की पोल खुल जाने का खतरा था इसलिए जांच अचानक एनआइए ने अपने हाथ में ले ली। लेकिन इस मामले का एक पहलू यह भी है कि मामला एनआइए के हाथ में जाने के बाद अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा नक्सल समर्थक गौतम नवलखा अब जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ सकता है। उसके संबंध कश्मीरी आतंकियों से बताए जाते हैं। एनआइए जांच में यदि कश्मीरी आतंकियों और नक्सलियों के बीच गठजोड़ उजागर हो सका तो सीएए और एनआरसी के विरोध में खड़े किए गए आंदोलन की हवा निकलते भी देर नहीं लगेगी।

राहुल का मोदी सरकार पर तंज

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भीमा-कोरेगांव मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अपने हाथ में लेने को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'जो भी मोदी-शाह के नफरत के एजेंडे का विरोध करता है, वह शहरी नक्सली हो जाता है।' राहुल ने कहा, 'भीमा-कोरेगांव प्रतिरोध का प्रतीक है जिसे सरकारी एनआइए की कठपुतलियां कभी मिटा नहीं सकते।'

एनआइए की कार्रवाई में हो सकता है विलंब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ भीमा-कोरेगांव मामले में पूरी गोपनीयता बरत रही एजेंसी

▶ फैसले को अदालत में चुनौती दिए जाने की आशंका

भीमा कोरेगांव मामले में केस ट्रांसफर होने के बाद भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) पूरी गोपनीयता बरत रही है। एनआइए को आशंका है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे को अदालत में घसीटा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री समेत राकांपा सुप्रीमो शरद पवार के बयान से इस आशंका की पुष्टि होती है।

दरअसल, मुंबई से तमाम दलों और उसके राजनेताओं की प्रतिक्रिया आने के बावजूद शुक्रवार को एनआइए और गृह मंत्रालय दोनों ने चुप्पी साध ली थी। शनिवार को भी गृह मंत्रालय ने सिर्फ केस एनआइए को ट्रांसफर होने की पुष्टि की, लेकिन एनआइए की चुप्पी बरकरार रही। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार एनआइए और गृह मंत्रालय को आशंका है कि इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में सरकार या एजेंसी की ओर से किसी भी आधिकारिक बयान का इस्तेमाल अदालत में किया जा सकता है। इसीलिए दोनों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। दरअसल, एनआइए कानून के अनुसार एनआइए को आतंकी और नक्सलियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार है।

लेकिन भीमा कोरेगांव मामला सीधे तौर पर नक्सलियों से न जुड़ा होकर शहरी नक्सलियों से जुड़ा है जो सरकार के खिलाफ हिंसा की साजिश रच रहे थे। इस मामले में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की बात और वरिष्ठ नक्सली नेताओं से संपर्क की बात एनआइए की जांच के दायरे में आती है। लेकिन इसके लिए सुबूत के तौर पर सिर्फ कथित शहरी नक्सलियों के बीच ईमेल का आदान-प्रदान है। जाहिर है कि नक्सलियों से उनके संबंध को स्थापित करने के लिए बहुत काम करना बाकी है। एनआइए को जांच सौंपने के पीछे केंद्र सरकार की यही मंशा है।

भारत ने के-4 बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरी बार किया परीक्षण

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित समुद्र तट से दूसरी बार के-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पनडुब्बी से दागी जा सकने वाली इस शक्तिशाली मिसाइल का एक सप्ताह के भीतर यह दूसरा सफल परीक्षण है। इसे भारतीय नौसेना के कौशल को बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है। 3,500 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल की जद में पाकिस्तान के करीब-करीब सभी हिस्से और चीन के कई हिस्से आ सकते हैं। इसे अरिहंत श्रेणी की परमाणु क्षमता से संपन्न पनडुब्बियों में तैनात किया जाना है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गत रविवार को भी के-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल अरिहंत ही एक ऐसी परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी है, जो परिचालन में है। के-4 उन दो अंडरवाटर मिसाइलों में से एक है, जिन्हें भारत नौसेना के लिए तैयार कर रहा है।

बिहार के कॉलेज में बुर्का पहनने पर रोक से विवाद

जागरण संवाददाता, पटना

▶ जेडी वीमेंस कॉलेज प्रशासन ने कहा, तय ड्रेस पहननी ही होगी

बिहार के जेडी वीमेंस कॉलेज में छात्राओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाने का आदेश शनिवार को दिनभर सुर्खियों में रहा। नतीजतन 24 घंटे के अंदर कॉलेज प्रशासन ने नोटिस से बुर्का शब्द हटा दिया। हालांकि ड्रेस कोड को लेकर अब भी कॉलेज प्रशासन का सख्त निर्देश है कि तय ड्रेस कोड (लाल कुर्ती, सफेद सलवार और दुपट्टा) के अलावा कुछ भी पहनने पर कार्रवाई होगी और 250 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

दरअसल, जेडी वीमेंस कॉलेज की कई छात्राएं ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रही थीं। कई छात्राएं तय ड्रेस के अलावा रंग-बिरंगे कपड़े तो कई बुर्का या नकाब पहनकर कॉलेज आती थीं। कॉलेज प्रशासन ने इसको लेकर कई बार आपत्ति जताई और आखिर में शुक्रवार को नोटिस चस्पा कर दिया। छात्राओं को निर्देश दिया गया कि- 'शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस में ही परिसर में प्रवेश करें। इसके साथ ही परिसर एवं क्लासरूम में बुर्के का उपयोग वर्जित है। निर्धारित पोशाक में नहीं पाए जाने की स्थिति में उन्हें 250 रुपये का दंड देना होगा।' इसके बाद शनिवार को मीडिया की सुर्खियां बनने और कई छात्राओं की आपत्ति के बाद कॉलेज प्राचार्या ने नया निर्देश चिपका दिया। इसमें से सिर्फ बुर्का शब्द हटा दिया गया है, बाकी आदेश हूबहू है। इस बाबत कॉलेज की शिक्षिका वीणा अमृत ने बताया कि अगर किसी के लिए बुर्का या कोई भी ऊपरी वस्त्र पहनना अनिवार्य है, तो वे पहनें मगर कॉलेज परिसर में आकर उसे बदल लें। क्लासरूम और कॉलेज परिसर में सभी को हर हाल में ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है।

जेडी वीमेंस कॉलेज की प्राचार्या प्रो. श्यामा राय ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई भी आदेश वापस नहीं लिया गया है। बस बुर्का शब्द हटा दिया है। अगर कोई लड़की कॉलेज ड्रेस में नहीं आती है तो उससे 250 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।

उपराज्यपाल फहराएंगे तिरंगा

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। वहीं, श्रीनगर में उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में तिरंगा फहराएंगे। लेह में मुख्य समारोह पोलो मैदान में होगा जहां उपराज्यपाल आरके माथुर ध्वजारोहण करेंगे।

पहली बार चेयरमैन फहराएंगे तिरंगा : राष्ट्रीय पर्व पर शहरों के साथ गांवों में भी तिरंगों की धूम रहेगी। सभी 307 बीडीओ कार्यालयों में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन तिरंगा फहराएंगे। जम्मू-कश्मीर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी सलामी लेंगे।

गणतंत्र दिवस के चलते इंटरनेट फिर बंद : पांच महीने बाद शनिवार की सुबह बहाल हुई इंटरनेट सेवाएं शाम होते ही फिर बंद हो गई। अधिकारियों का कहना है कि गणतंत्र दिवस समारोह के जश्न में किसी तरह की खलल ने पड़े। इसे देखते हुए एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है।

बयान से मुकरने पर दुष्कर्म पीड़िता पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

जागरण संवाददाता, एटा : दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता आरोपित पर लगाए आरोप से मुकर गई। अदालत से कहा कि जिसने दुष्कर्म किया, वो यह युवक नहीं है। संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने आरोपित को बरी कर दिया, जबकि झूठा बयान देने पर पीड़िता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। मामला 28 सितंबर 2017 का है। आरोप है कि युवती को रास्ते में एक युवक ने पकड़ लिया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया। अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान युवती अपने आरोप से मुकर गई। जिस युवक को जेल भिजवाया, उसी के पक्ष में गवाही दे दी। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम रीमा मल्होत्रा ने फैसला देते हुए आरोपित को दोषमुक्त कर दिया, जबकि युवती के खिलाफ झूठी गवाही देने पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए।

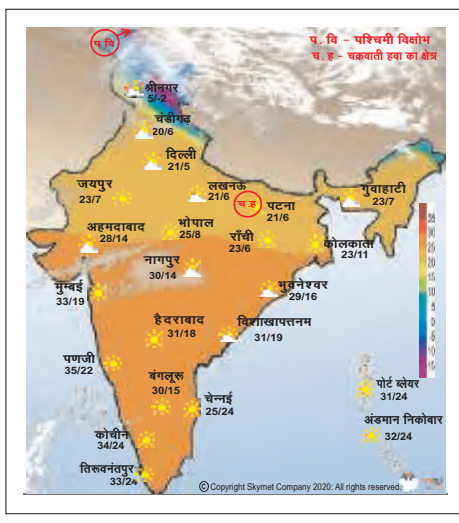

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व बर्फबारी होगी। दिन के तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली सहित मैदानी भागों में ठंडी सुबह में हल्का कोहरा व कुहासा रहेगा। आंशिक बादलों के साथ दिन सुहावना बना रहेगा। पश्चिम राजस्थान में हल्की वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/20/आंबा	अहमदाबाद	26/14/आंबा
कोलकाता	24/11/सा	बड़ोदा	28/09/सा
चेन्नई	30/19/आंबा	नागपुर	30/15/आंबा
हैदराबाद	31/19/सा	इन्दौर	26/12/आंबा
बंगलूरू	31/16/आंबा	राँची	24/07/व
त्रिवेन्द्रम	33/25/सा	पटना	22/05/आंबा
गुवाहाटी	25/15/आंबा	जमशेदपुर	26/09/आंबा
गंगटोक	10/03/सा	पुणे	30/17/आंबा

साप्ताहिक राशिफल

रविवार 26 जनवरी, 2020 से शनिवार 01 फरवरी, 2020 तक

पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,आ)
व्यापारिक नौकरी उद्योग के कार्य में सहयोग से सफलता, धनागम में देरी, कार्य क्षेत्र में अवरोध, विदेश व्यापार में अवरोध, सुख साधन सीमित, संतान से अनबन, चयन में देरी, प्रणय में सुख, रक्षा कार्य में अवरोध, राज्य पक्ष से सावधान, व्यय अधिक, शुभ अंक 5

वृष (इ,ऊ,ए,ओ,पा,वी,वू,वे,वो)
व्यापारिक, उद्योग, नौकरी के कार्य में सफलता, अर्थ साधन सीमित, दिनचर्या व्यस्ततम, विदेश से समाचार, चिंता, निर्माण कार्य में अवरोध, संतान से सहयोग, अध्ययन में रूचि, खान-पान पर ध्यान दें, वायु विकार की वृद्धि, प्रणय में सुख, यात्रा में सावधानी, शुभ अंक 6

मिथुन (का,की,कू,घ,ड,छ,के,को,हा)
व्यापारिक, नौकरी, उद्योग के कार्य में सहयोग से सफलता, धन साधन में प्रयास, सामाजिक कार्य में यश, विदेश कार्य में अवरोध, चिंताग्रस्त, भवन कार्य में अवरोध, संतान से अनबन, चयन में देरी, वाद-विवाद से बचें, जीवन साथी का मिलन, अधिकारी से सावधान, शुभ अंक 7

कर्क (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो)
व्यापारिक, उद्योग, नौकरी के कार्य में सहयोग से सफलता, अर्थ साधन सीमित, निर्णय सलाह से करें, कार्य की गति धीमी, सन्तान से चिंतित, अध्ययन में रूचि, क्रोध पर नियन्त्रण, मित्र से सहयोग, जीवन साथी का मिलन, रक्षा साधन कार्य में देरी, राजनैतिक अपयश, शुभ अंक 8

सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)
नौकरी, उद्योग, व्यापार के कार्य में प्रगति, धनागम के प्रयास सीमित, साझेदारी में सावधानी, कार्यक्षेत्र में स्थिति कमजोर, साधनों की सीमित स्थिति, संतान से अनबन, अध्ययन में एकाग्रता, शत्रुपक्ष से सावधान, दाम्पत्य में सुख, राज्यपक्ष से सावधान, बैंक कार्य में प्रगति, शुभ अंक 9

कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)
व्यापारिक, नौकरी, उद्योग के कार्य में प्रयास से सफलता, अर्थ साधन सीमित, सलाह से निर्णय करें, कार्यक्षेत्र में साधनों की कमी, भावुकता से बचें, पारिवारिक धन का सहयोग, साधनों की पूर्ति, संतान का सहयोग, शत्रुपक्ष प्रभावी, धर्म में रूचि, राज्य पक्ष से सावधान, शुभ अंक 9

तुला (रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, भूमि भवन कार्य में अवरोध, संतान से चिंतित, मित्रों से सावधान, ससुराल से सहयोग, राजनैतिक कार्य में अपयश, अधिकारी से सावधान, यंत्र स्थापन में देरी, शुभ अंक 2

वश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, अर्थ साधन कमजोर, आत्म विश्वास की कमी, धन निवेश में सावधानी, विदेश कार्य में देरी, चिंता योग प्रभावी, संतान से सहयोग, शत्रु पक्ष प्रभावी, प्रणय में सुख, अधिकारी से सावधान, कार्यों की गति सीमित, व्यय अधिक, शुभ अंक 2

धनु (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फा,ढा,भे)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सहयोग से सफलता, अर्थ साधन कमजोर, धन के निवेश में सावधानी, साझेदारी में तनाव, चिंता, आत्म विश्वास की कमी, कार्यों की गति धीमी, संतान से सहयोग, चयन में अवरोध, रक्त विकार का योग, रक्षा कार्य में अवरोध, शुभ अंक 4

मकर (भो,जा,ज,खी,खू,खे,खो,गा,गी)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में अर्थ साधन अच्छा, धन के लेन-देन में सावधानी, चिंता का समाधान, विशेष व्यक्ति से मिलन, स्त्रीपक्ष से सहयोग, वाहन भवन योग, संतान की चिंता, अध्ययन में एकाग्रता, मित्रों से सहयोग, प्रणय में मधुरता, व्यय अधिक, शुभ अंक 5

कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सा,दा)
नौकरी, व्यापार, उद्योग के कार्य में सफलता, अ

महाग्रंथ : संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरह लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉ राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया।

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

हमारा संविधान सबका अभिमान

देश को उसका सबसे पवित्र ग्रंथ समर्पित करते हुए उसके निर्माता बाबा भीमराव आंबेडकर ने कहा था, कि यह ऐसी किताब है जो युद्धकाल में भी देश की रक्षा करेगी और शांतिकाल के लिए प्रासंगिक होगी। सात दशक हो गए देश में संविधान को लागू हुए। बड़ी-बड़ी संवैधानिक जटिलताएं खड़ी हुई। लोकतांत्रिक मूल्य संकट में नजर आए। प्राकृतिक आपदाएं आईं। पड़ोसी देशों से जंग हुई। आपातकाल का काला अध्याय भी देखा। मगर संविधान अक्षुण्ण रहा। अपने नियमों-उपबंधों के कवच से देश को हर प्रतिकूल हालात से उबारता रहा। कोई भी सरकार, कितने ही प्रचंड बहुमत से क्यों न आई हो, मजाल कि उसने इसके मूल स्वरूप या आत्मा से छेड़छाड़ करने की जुर्रत की हो। हर बीते दिन के साथ यह किताब लोकतंत्र को और मजबूत करने के साथ पुष्पित-पल्लवित करती रही। किसी से विवाद होने की स्थिति में आज भी हम उसे 'कोर्ट' में देख लेने की बात कहते हैं। ये वही कोर्ट है जो हर चीज का संवैधानिक दायरा तय करता है। उसके हर फैसले में आधार संविधान ही होता है। हाल ही में देश में एक विमर्श तेजी से उभर रहा है कि सरकार अनुच्छेद 370, 35 ए और अन्य तमाम नए कानूनों को बनाकर-संशोधित कर संविधान की मूल आत्मा से छेड़छाड़ कर रही है। उसके स्वरूप को खत्म कर रही है। न्यायपालिका इन आरोपों के संविधान सम्मत होने या न होने को तय करने के लिए बैठी है। हम भारत के नागरिक हैं। हमें अपने संविधान पर पूरा भरोसा है। उससे छेड़छाड़ किए जाने की कोई आशंका हमारे मन में नहीं उपज सकती। क्योंकि पिछले 70 साल से हम संविधान को जीते आए हैं और हर उस आशंका को उसने निर्मूल साबित किया है जो हम लोगों के दिलोदिमाग में पैबस्त करने को आतुर थी। ऐसे में जब भारत अपना **71वां गणतंत्र दिवस** मना रहा हो तो भारतीय संविधान की पवित्रता और देश को विविधता के साथ एकता के सूत्र में जोड़े रखने वाले उसके महात्म्य की पड़ताल आज बड़ा मुद्दा है।

दृढ़ और लचीला

भारतीय संविधान अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। संविधान की ऐसी ही कुछ विशेषताएं हैं, जो उसे देश के समक्ष उपजी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने में सक्षम बनाती हैं। भारत के नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को उन्हें जानना चाहिए।

विशिष्ट खूबी

भारतीय संविधान संसद को शक्ति देता है कि वह इसके कई प्रावधानों को साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकता है। संविधान में कुछ ही ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें राज्य विधानसभाओं द्वारा समर्थन की आवश्यकता होती है। संविधान के शेष प्रावधानों को केंद्रीय संसद के एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी प्रत्येक सदन के कम से कम दो-तिहाई सदस्य उपस्थित और मतदान करते हैं। संसद को कानून द्वारा संविधान के प्रावधानों को पूरक करने की शक्ति भी दी गई है।

मूलाधिकार और संवैधानिक उपचार

भारतीय संविधान भाग तीन में कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे समानता का अधिकार, विशेष स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और इसी तरह दूसरे अधिकार भी हैं। ये सभी अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। हालांकि ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं और ये उचित प्रतिबंधों के अधीन आते हैं। मूल रूप से, संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44 वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया और अब यह एक कानूनी अधिकार है।

मौलिक कर्तव्य

42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भाग चार-ए में अनुच्छेद 51-ए के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ये कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं और इन कर्तव्यों को लागू करना नागरिकों का नैतिक दायित्व है।

स्वतंत्र न्यायपालिका

हमारे संविधान में संघ के साथ-साथ राज्यों के लिए न्यायालयों की एकल एकीकृत प्रणाली है जो कि संघ और राज्य दोनों के कानूनों की व्यवस्था करती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरी व्यवस्था का नेतृत्व करता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधीन, अन्य अदालतों का अनुक्रम होता है। हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

भारत में मताधिकार ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में बहुत व्यापक है। भारत में 18 साल से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता इत्यादि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना मतदान करने का अधिकार प्राप्त है।

सरकार का संसदीय स्वरूप

हमारे संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की शुरुआत की। यद्यपि संसदीय सरकार के ब्रिटिश रूप को अपनाया गया था, बावजूद इसके वंशानुगत शासक की नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी जा सकती थी क्योंकि भारत एक गणराज्य बन गया था। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल व्यवस्था है, जिसमें दो सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट पृथक्करण नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है।

एकल नागरिकता

आमतौर पर संघीय राज्य के नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती है क्योंकि सरकार के दो मंच होते हैं, लेकिन संघीय राज्य के बावजूद भी भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता दी गई है। भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल और समान नागरिकता प्रदान करता है। भारत में राज्य नागरिकता की कोई अवधारणा नहीं है। भारत में कोई भी राज्य किसी भी नागरिक को उसके जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके अलावा, भारत में, किसी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने या कुछ स्थानों को छोड़कर भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने का अधिकार है।

आपातकालीन प्रावधान

राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को असामान्य स्थितियों से निपटने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। जब भी आपातकाल लगाया जाता है तो केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और राज्य अधीनस्थ हो जाते हैं। भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है तो हमारे संविधान में सुरक्षा के उद्देश्य से आपातकालीन प्रावधान हैं। हमारे संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं इनमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल शामिल हैं।

सामाजिक समानता

भारतीय संविधान का भाग तीन में जिसमें मौलिक अधिकार भी हैं, का उद्देश्य राजनीतिक समानता के साथ सामाजिक समानता प्रदान करना है। हमारे मूल मौलिक अधिकारों के अलावा हमारा संविधान किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है और इस बात की पैरवी करता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी सार्वजनिक स्थान तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा।

अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान

हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हैं। यह न केवल संसद और राज्य विधानमंडल में उनके लिए सीटों को आरक्षण प्रदान करता है बल्कि उन्हें विशेष अधिकार भी प्रदान करता है। संविधान उन्हें मौलिक अधिकारों के तहत विभिन्न अवसर प्रदान करता है।

समझें मर्म

भारतीय संविधान अपने आप में अनूठा है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के साथ ही ऐसी कई बातें हैं, जो आपको रोमांचित करने के साथ गर्व से भी भर देंगी।

दो भाषाओं में संविधान की मूल कॉपियां : भारतीय संविधान वास्तविक रूप में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। इस हॉल को उस वक्त कांस्टीट्यूशन हॉल के नाम से जाना जाता था।

हस्तलिखित मूल प्रतियां : हिंदी और अंग्रेजी की दोनों मूल प्रतियां हस्तलिखित हैं। इस तरह से यह दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान भी है।

प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिपिबद्ध किया संविधान : संविधान को लिपिबद्ध करने का सौभाग्य मिला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। उन्होंने होल्डर और निब की सहायता से इटैलिक स्टाइल में कैलिग्राफी के साथ संविधान को लिखा। यह देहरादून में छपा और सर्वे ऑफ इंडिया ने फोटोग्राफ किया।

शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया : संविधान की मूल प्रति को शांति निकेतन के कलाकारों ने आचार्य नंदलाल बोस के निर्देशन में सजाया था। वे महात्मा गांधी के काफी निकट थे। प्रस्तावना के पृष्ठ को बी राम मनोहर सिन्हा ने बनाया था।

कहां है मूल प्रतियां : संविधान की हिंदी और अंग्रेजी में लिखी मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी गयी है। इन प्रतियों को हीलियम से भरे पात्रों में रखा गया है।

संविधान के पहले ड्रॉफ्ट में 2000 संशोधन : संविधान के पहले ड्रॉफ्ट के तैयार होने के बाद इस पर बहस हुई और करीब 2000 संशोधन के बाद मूल संविधान सामने आया।

26 नवंबर 1949 को सामने आया था वर्तमान स्वरूप : संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। आखिरी सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर को इसका फाइनल ड्रॉफ्ट तैयार हुआ।

पौराणिक आराध्यों का जिक्र : संविधान की मूल प्रतियों में हमारे पौराणिक और धार्मिक पात्रों को भी उकेरा गया है। भगवान राम, कृष्ण और शिव को चित्रित किया गया है। इसके साथ ही उपदेश देते भगवान बुद्ध को भी शामिल किया गया है।

जनमत

हां 1% | नहीं 99%

क्या प्रचंड बहुमत से चुनी गई सरकार हमारे संविधान की मूल आत्मा से खिलवाड़ करने में सक्षम है?

हां 3% | नहीं 97%

क्या हालिया हालात से उपजे इस सवाल से आप सहमत हैं कि केंद्र सरकार संविधान के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ कर रही है?

आपकी आवाज

किसी को भी संविधान के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। - **सारिक हुसैन।**

संविधान और देश की मूल आत्मा एक ही है। बड़े से बड़े राजतंत्र में भी इस आत्मा से खिलवाड़ सफल नहीं हुए, तो लोकतंत्र में कैसे होंगे? भारी से भारी मतों से चुनी गई सरकारें जनता व देश की मालिक नहीं, प्रतिनिधि होती हैं। वर्तमान सरकार इसी बात पर अमल कर रही है। **-गौरीशंकर अंतज।**

किसी भी संविधान की रचना उस देश को सुनियोजित, सुविकसित, शक्तिशाली और सरकार एवं नागरिकों के मध्य स्पष्ट संबंधों के साथ ही सभी पक्षों को अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित करने के लिए होती है। देश हित के निर्णय संविधानसम्मत हों। **-अमन कुमार।**

हर मर्ज की दवा है हमारा पवित्र ग्रंथ

हमारा संविधान इतना कमजोर नहीं है कि तात्कालिक मुद्दों पर सवालों के कठघरे में आ जाए। इसमें हर परिस्थिति से निपटने का रास्ता है। बड़ी बड़ी बहस हों या जटिल परिस्थितियां, हर स्थिति का निवारण इसमें छिपा है।

-सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ

भारत का संविधान बहुत मजबूत है। लोकतांत्रिक देश होने के कारण हमारे संविधान में अपनी बात रखने व असहमति जाहिर करने का भी अधिकार मिला हुआ है। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों का राज होता है। जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं अपने ऊपर राज करती है। इसलिए लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन होते हैं। लोकसभा में जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जबकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यों के प्रतिनिधियों और लोगों के प्रतिनिधियों ने दो तिहाई बहुमत से निर्णय लेकर कोई कानून बनाया है तो उसे देश के हर नागरिक को मानना होगा। लेकिन किसी कानून या संसद के किसी निर्णय के विरोध में अगर कुछ हजार लोग सड़कों पर एकत्र होकर चक्का जाम करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं तो यह गलत है। दरअसल, ये लोग अपने निहित स्वार्थों के कारण व राजनीतिक कारणों से खुद को देश का 'हम' समझने लगते हैं। यह गलत है। जो लोग दंगा फसाद कर रहे हैं वे भारत के लोगों के प्रतिनिधि नहीं हैं। देश में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है। संसद ने जो कानून बनाया है उससे आप सहमत नहीं हैं तो उसका विरोध कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं उन्होंने अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून को सभी को मानना पड़ेगा। अगर आप सहमत नहीं हैं तो शांतिपूर्ण आंदोलन व संवैधानिक विरोध कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं।

अगर देश में ऐसी चर्चा चल रही है कि संविधान की मूल आत्मा को खत्म किया जा रहा है तो वो लोग जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि ऐसे लोग समस्याओं पर बात नहीं कर रहे बल्कि राजनीति कर रहे हैं। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है। देश में इस समय गर्म मुद्दों से वो बिलकुल खतरे में नहीं है।

सच बात तो यह है कि हमारे देश ने आपातकाल का भी दौर देखा है तब भी हमारा संविधान सामयिक था। विषम परिस्तिथियों में हल और न्याय के लिए संविधान में हमेशा विकल्प मौजूद रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर देशों के संविधानों पर घनघोर विमर्श हुए, सवाल खड़े किए गए या फिर अंततः उन्हें बदला गया। भारत का संविधान इकलौता ऐसा संविधान था जिसे नहीं बदला गया। उसे सार्वजनिक मंच पर स्वीकृति मिली और वो अब भी 70 सालों से कायम है। जानना चाहेंगे क्यों? तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत का संविधान एकीकरण और अखंडता का सशक्त माध्यम साबित हुआ। यह मौलिक अधिकारों की बात करता है। इसी संविधान में सभी संप्रदायों का ध्यान रखा गया है। सभी जाति, धर्मों को शामिल करते हुए देश को संगठित किया है। हर भाषा की इसमें जगह है। मानवाधिकार भी शामिल हैं और आपातकालीन स्थितियों का भी हल छिपा है। समय-समय पर जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन भी हुए। अभी तक हमारे संविधान में 104 संशोधन हुए हैं। आखिरी संशोधन इसी साल 22 जनवरी को किया गया। तीन साल से कम समय में तैयार इस संविधान की ताकत को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इसमें सभी मतों का समावेश है। असल में यह एकीकरण और देश की पहचान है। शायद इसीलिए विभिन्न पक्ष खुद को इसमें शामिल पाते हैं। कठिन समय में इसकी परिपूर्णता पता चलती है और अपराधी इसकी ताकत की दुहाई देते हैं।

पहले खुद तो संवैधानिक बनिए

संविधान के कुछ अनुच्छेदों को हटाने और कुछ नए कानून बनाने को लेकर एक वर्ग आकुल हुआ पड़ा है। दुहाई तो वो संविधान बचाने की दे रहा है, और हरकतें उसकी संवैधानिक नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाने वाली हैं।

योगेंद्र नारायण, पूर्व महासचिव, राज्यसभा

अनुच्छेद 370, 35 ए को हटाने और नागरिकता संशोधन कानून को बनाने जैसे कुछ कदमों से समाज के एक तबके की तथाकथित व्याकुलता, विरोध प्रदर्शनों और अशांति ने पूरे देश को प्रभावित किया है। ये संवैधानिक कदम विपक्षी राजनीतिक संगठनों द्वारा ऐसे रंगे गए हैं, जैसे यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित करने का प्रयास कर रही है और यह कानून संविधान की भावना के अनुरूप न होकर साफ तौर पर असंवैधानिक है।

विरोध-प्रदर्शन के दौरान ऐसे लोग खुद न केवल संविधान की भावना बल्कि उसके बुनियादी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बात और है कि अपने इस कदम को वे संविधान सम्मत मान रहे हैं। संविधान निश्चित रूप से सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है लेकिन कहता है कि ऐसी स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा की कीमत पर नहीं हासिल हो सकती है। संविधान सभी नागरिकों को आंदोलन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन महीनों से सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा किए आंदोलनकारी आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह संविधान के मूलभूत कर्तव्यों से जुड़े अनुच्छेद 51-ए की भावना के सर्वथा प्रतिकूल है। आंदोलनकारियों और हिंसक प्रदर्शन करने वालों को अनुच्छेद 51 ए के तहत अपने मौलिक कर्तव्य को याद रखना चाहिए। साथ ही हिंसा को रोकना चाहिए और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। यदि कुछ लोगों को यह लगता है कि सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए तमाम कदम संविधान सम्मत नहीं हैं या वे संविधान की भावना का उल्लंघन करते हैं तो उनके पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का संवैधानिक अधिकार है। अदालतें ऐसे मामलों में अंतिम मध्यस्थ हैं। हकीकत यह है कि इन वर्गों के लोगों को लगता है कि वे सही हैं और दूसरे गलत हैं। संविधान उन्हें सड़कों पर मुद्दों को सुलझाने का विशेषाधिकार नहीं देता है। इस रवैये से देश में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को हाथ मिलाना चाहिए और ऐसी असंवैधानिक गतिविधियों के लिए अपना समर्थन वापस लेना चाहिए।

संविधान में इन मामलों को सुलझाने के लिए कई और रास्ते हैं। केरल ने यह रास्ता दिखाया है। राज्य ने केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल कर नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बाध्यता और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इसे अंतरराज्यीय विवाद के रूप में अनुच्छेद 131 के तहत व्यवहार करने की बात कही है। संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वह राज्यों और केंद्रों के बीच के विवादों का निपटारा कर सके। अन्य राज्य जो इन कानूनों का विरोध करते हैं उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करनी चाहिए।

हमारा संविधान काफी सोच विचार के बाद अस्तित्व में आया। इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए इसमें प्रावधान हैं। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि हम संविधान का अक्षरशः और आत्मा दोनों से अनुसरण करें। हमारा ढांचा संघीय है और विभिन्न विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संसद और राज्यों दोनों को दी गई है। केंद्रीय सूची की संख्या 69 के तहत, केंद्र सरकार कानूनी और संवैधानिक रूप से जनगणना करा सकती है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जिसका एक अंग है। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र द्वारा बनाए हर कानून को इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकारों को कार्यकारी शक्तियां मिली हुई हैं। इसके साथ ही पूर्व में प्रचलित कानून भी राज्य में लागू होंगे। पूर्व में उल्लेख है कि केंद्र अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल राज्य को निर्देश देने में कर सकता है। यह पहले से ही समझा जा सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून का एक हिस्सा है और यह संविधान में संशोधन नहीं है। यदि विपक्षी पार्टियां सत्ता में आती हैं तो वे इस कानून में बदलाव कर सकती हैं।

याद रखें कि सत्तारूढ़ दल के पास उच्च सदन में बहुमत नहीं था। यदि विपक्ष एकजुट होता तो वे विधेयक को कानून बनने से रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने इस विधेयक को पारित होने दिया और अब सड़कों पर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। यह किसी भी मायने में संवैधानिक नैतिकता नहीं है। आंदोलनकारियों को मेरा सुझाव है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए और तब तक इस संबंध में सभी आंदोलन स्थगित कर देने चाहिए। संविधान को हमें यह सम्मान देना चाहिए जिसका हम पर ऋण है।

मूल आत्मा व ढांचे में बदलाव असंभव

संविधान ने बहुत कुछ झेला है। प्राकृतिक आपदाओं की लंबी फेहरिस्त, दंगे, संसद पर हमले के बाद भी अडिग है। दो-दो प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है, इसके बाद भी संविधान पूरी मजबूती से देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। यही संविधान की ताकत है।

-एसके शर्मा, संविधान विशेषज्ञ

जो लोग यह सोच रहे हैं कि संविधान बदला जा सकता है, वे या तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, या फिर उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है। कोई भी ताकत हमारे संविधान के मूल स्वरूप को नहीं बदल सकती। संविधान को देश की संसद भी नहीं बदल सकती। अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि संसद भारत के संविधान में बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संशोधन 103 बार किया भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार उसे भी नहीं है। संविधान का मूल ढांचा संघीय व्यवस्था, प्रजातंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता है।

लोग बिना वजह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। जब देश की संसद ही मूल ढांचे को बदल नहीं सकती, तो फिर से देश को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कहां से खड़ी हो गई। ये सभी बातें पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण हैं। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी बातों से लगता है कि उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाए जाने का इससे कोई संबंध नहीं है। तीन तलाक का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का अपना एजेंडा है, वह बहुमत लेकर आती है। उन्हें क्या काम करना होता है, चुनाव के समय बाकायदा अपने घोषणा-पत्र में जनता के सामने रखती हैं। केंद्र सरकार अब अपने घोषणा-पत्र में कही गई बातें अमल में ला रही है। अब जिन लोगों को लग रहा है कि सरकार के ये कदम संविधान की मूल भावना, मूल आत्मा और मूल ढांचे को बदलने वाले हैं, वे गलत हैं।

भारत के संविधान में अनुच्छेद पांच से 13 तक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नागरिकता देने या न देने का अधिकार भारत की संसद को है। इसके लिए वह कानून बना सकती है। यह संघ का कार्यक्षेत्र है, इसमें राज्य सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। संविधान में एक नागरिक बिल पहले से था, केंद्र सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया, इसका नाम नागरिक संशोधन बिल हो गया। इसमें यह किया गया कि तीन देशों से जो लोग प्रताड़ित होकर आएंगे, उन्हें चाहे तो केंद्र सरकार नागरिकता दे सकेगी। इसमें सिर्फ एक लाइन का प्रावधान है। इस पर सारा बवाल खड़ा हुआ है। कुछ राज्य सरकारें यह कह रही हैं कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। संसद के दोनों सत्रों ने कानून पास किया है, उन दोनों सत्रों में सभी प्रदेशों के सांसद और प्रतिनिधि भी हैं। उन्होंने भी इसके लिए वोट दिया है। अब ये कानून बन गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिसूचित होकर लागू हो गया है। अब कहा जा रहा है कि इसे वापस ले लो। उनके पास बहुमत था, उन्होंने लागू कर दिया। इसे वापस करने के दो ही तरीके हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट यह कहें कि यह संविधान के खिलाफ है। दूसरा, विपक्ष बहुमत लेकर आए और वे इसे फिर से बदल दें। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अमेरिका के संविधान में 200 वर्षों में 27 बार संशोधन किया गया है, जबकि भारत के संविधान में 70 वर्षों में 103 बार संशोधन किया गया है। संविधान ने बहुत कुछ झेला है। प्राकृतिक आपदाओं की लंबी फेहरिस्त, दंगे, संसद पर हमले के बाद भी अडिग है। दो-दो प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है, इसके बाद भी संविधान पूरी मजबूती से देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। यही संविधान की ताकत है।

(लोकेश चौहान से बातचीत पर आधारित)

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 26 जनवरी 2020

दैनिक जागरण

प्रत्येक नागरिक की सार्थक भूमिका से ही गणतंत्र सफल होता है

हम भारत के लोग

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह जो रेखांकित किया कि हमारे संविधान ने एक स्वाधीन लोकतंत्र के नागरिक के रूप में हम सब को कुछ अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी प्रदान की है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना समय की मांग है। जिम्मेदारी की यह भावना केवल न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहने को ही नहीं कहती, बल्कि यह भी अपेक्षा रखती है कि गण के तंत्र के रूप में हम परिपक्व नागरिकों सरीखा व्यवहार करें। इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि देश ही नहीं, दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। जब दुनिया भारत को एक ऐसे उभरते हुए देश के रूप में देख रही हो जो विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने में सक्षम है तब फिर इसका कोई मतलब नहीं कि संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल होता हुआ दिखे। दुर्भाग्य से आज ऐसा ही हो रहा है। इसके चलते न केवल भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है, बल्कि कुछ दुराग्रही शक्तियों को अनावश्यक उपदेश देने का अवसर भी मिलता है। गणतंत्र के रूप में सात दशक के लंबे सफर को तय करने वाले भारत को देश-दुनिया के मामले में विवेकपूर्ण राष्ट्र के रूप में आचरण करते हुए दिखना ही चाहिए। निःसंदेह भारत की ऐसी छवि तभी निर्मित होगी जब हम भारत के लोग धीर-गंभीर आचरण का परिचय देंगे।

चूंकि हमारा संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है इसलिए जनता का नीर-क्षीर आचरण कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है। हमारा संविधान हर किसी को अपनी बात कहने की अनुमति देता है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि इस अधिकार का इस्तेमाल भोंडे तरीके से किया जाए। किसी भी मसले पर सहमति और असहमति व्यक्त करने का एक तरीका होता है। यह ठीक नहीं कि जब-तब ऐसी प्रतीति कराई जाए कि हम भारत के लोगों को अभी यह तरीका सही तरह से सीखना शेष है। इससे इन्कार नहीं कि एक गणतंत्र के रूप में हम वह सब कुछ हासिल नहीं कर सके हैं जो हमारे साथ ही स्वतंत्र हुए अनेक देशों ने हासिल कर लिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी तमाम उपलब्धियों की अनदेखी कर दें। दुर्भाग्य से कुछ लोग यही कर रहे हैं। उनका नकारात्मक रवैया एक तरह के रुदन में बदल गया है। इस मानसिकता से कभी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तभी सही दिशा में आगे बढ़ते हैं जब वे सकारात्मक भाव से लैस होकर आगे बढ़ते हैं। यही भाव हर तरह की समस्याओं के समाधान की कुंजी प्रदान करता है।

कार्यप्रणाली में सुधार

लोग इसी उद्देश्य से सरकार चुनते हैं कि उन्हें राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसमें हिमाचल प्रदेश भी कोई अपवाद नहीं है। सरकार भी जनता की समस्याओं के हल का हरसंभव प्रयास करती है। इसके लिए कई योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लेकिन जब योजनाओं को लागू करने वाले ही गंभीर न हों तो स्थिति सुखद नहीं होती। योजना का जनता को तो अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, बल्कि सरकार को लोगों के रोष का सामना अवश्य करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन 1100 नंबर टेलीफोन पर कोई भी व्यक्ति समस्या को दर्ज करवा सकता है। यहां से यह समस्या संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास हल के लिए भेज दी जाती है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि हेल्पलाइन पर आने वाली समस्या का हल प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके बावजूद शिकायत पर बिना कोई कार्रवाई किए बंद कर दिया जाना गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जब से यह हेल्पलाइन शुरू हुई है तब से 50 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन शिकायतों में से साढ़े 28 हजार से अधिक का निपटारा कर दिया गया है। निःसंदेह यह हेल्पलाइन प्रदेशवासियों के लिए काफी राहत प्रदान कर रही है। इससे लोगों को जहां सरकारी कार्यालयों से चक्कर लगाने से छुटकारा मिल गया है वहीं समय की बचत हो रही है। जनहित की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कड़ी कर्मचारी व अधिकारी हैं। उन्हीं की कार्यशैली तय करती है कि योजना सफल होगी या नहीं। अधिकारियों व कर्मचारियों का दायित्व है कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन करें व समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाएं। इस हेल्पलाइन पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। सुखद यह है कि समय-समय पर मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसे ईमानदारी से निभाया जाना चाहिए। यदि जनहित का मामला है तब यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सभी को चाहिए कि जो भी योजना बनाई जाती है वह धरातल पर लागू हो और उसका लाभ पात्रों तक पहुंचे।

सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का जिम्मा कर्मचारियों पर है। उनकी सुस्ती योजना के उद्देश्य के लिए घातक हो सकती है

संवैधानिक स्वतंत्रता का मनमाना इस्तेमाल

संजय गुप्त

यह हैरान करता है कि असहमति के नाम पर हिंसा करने और भड़काऊ बयान देने वाले भी संविधान की आड़ लेने में सफल हैं

समस्त देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की बधाई। यह सचमुच बधाई का भी अवसर है और इस पर गौर करने का भी कि इस गणतंत्र दिवस पर नए भारत की एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। गणतंत्र दिवस अन्य अनेक बातों के साथ संविधान की याद प्रमुखता से दिलाता है। दुर्भाग्य से इसी संविधान का हिस्सा बना था अनुच्छेद 370। इसे हटाए जाने के बाद ही देश इससे अवगत हो पाया कि वास्तव में इस संवैधानिक प्रावधान के जरिये शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर एक तरह से तोहफे में दे दिया गया, क्योंकि नेहरू ऐसा ही चाहते थे। बीते सात दशकों में देश को यही बताया गया कि इसे हटाना बहुत मुश्किल है और यह तो एक तरह से स्थाई प्रावधान ही है। इस तरह की दलीलें इसके बावजूद दी जाती रहीं कि अनुच्छेद 370 का सहारा लेकर कश्मीरी आवाम में अलगाव की भावना भरी जा रही है। चूंकि सारा जोर अलगाव पैदा करने वाले अनुच्छेद 370 को उपयोगी बताने का था इसलिए इसकी अनदेखी की जाती रही कि कैसे वहां संसद से पारित तमाम महत्वपूर्ण कानून लागू नहीं हो पा रहे और किस तरह वहां के दलितों के अधिकारों को कुचला जा रहा। यह आश्चर्यजनक है कि अनुच्छेद 370 के अलगाववाद का पर्याय और संविधान की मूल भावना के खिलाफ साबित होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उसे हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। क्या इस रवैये को संविधानसम्मत कहा जा सकता है? यह तो गनीमत रही कि अनुच्छेद 370 को अस्थाई दर्जा दिया गया, अन्यथा उसे हटाना और कठिन होता।

आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम भारतवासी यह कह सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर वैसे ही भारत का अभिन्न अंग है जैसे देश के अन्य राज्य। मोदी सरकार अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इस कोशिश में है कि कश्मीर न केवल देश की मुख्यधारा से जुड़े, बल्कि वहां की समस्याओं का तेजी से निराकरण भी हो। इसके लिए वह अपने मंत्रियों को जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग जिलों में भेज रही है। पता नहीं क्यों विपक्ष को ऐसे तौर-तरीके रास नहीं आ रहे हैं। वह यह देखने से इन्कार कर रहा है कि 5 अगस्त यानी अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई है। क्या यह उल्लेखनीय नहीं? विपक्ष के ऐसे नकारात्मक रवैये के कारण ही आम जनता से उसे अहमियत नहीं दे रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के मामले में भी है।

विपक्ष के तमाम दुष्प्रचार के बाद भी सरकार सीएए के अमल के प्रति अडिग है। उसे अडिग रहना भी चाहिए, क्योंकि यह कानून शरणार्थी रूप में रह रहे उन अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए थे। आखिर इन प्रताड़ित लोगों को राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या यह सच नहीं कि नेहरू, पटेल सरीखे संविधान निर्माताओं और खुद गांधी जी ने यह कहा था कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जब चाहें भारत आ सकते हैं?

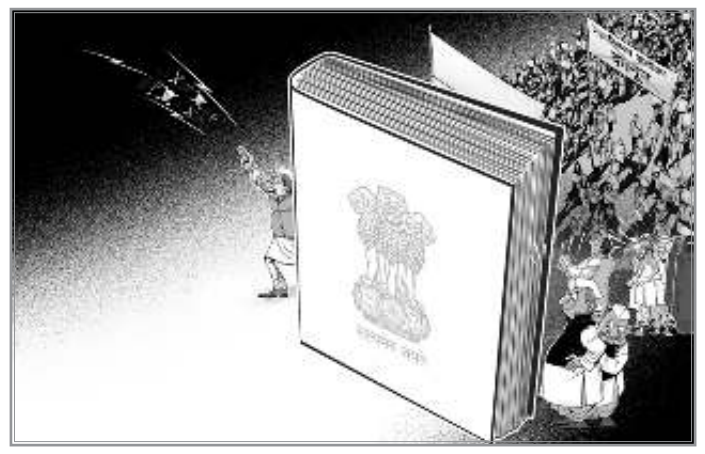

अवधेश राजपूत

विपक्ष ने सीएए के साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अर्थात एनआरसी का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। एनपीआर हर दस वर्ष में जनगणना के तहत की जाने वाली कवायद है। आखिर इस संविधानसम्मत प्रक्रिया के विरोध का क्या औचित्य? हास्यास्पद यह है कि एनपीआर तैयार करने का विरोध करने वाले खुद को संविधान का हितैषी बता रहे हैं। यह संविधान का हवाला देकर जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं। विपक्षी दल सीएए के खिलाफ विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करने का काम यह जानते भी हुए कर रहे हैं कि वे संसद से पारित कानून को लागू करने से इन्कार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर संविधान की दुहाई देकर उसकी धज्जियां उड़ाने वाले ही सरकार पर यह दोष मढ़ रहे हैं कि वह संविधान के खिलाफ काम कर रही है। विपक्षी दल एक ओर इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचे हैं और दूसरी ओर दुष्प्रचार का सहारा लेकर उसका सड़क पर विरोध भी कर रहे हैं। क्या यह संविधानसम्मत आचरण है?

जहां तक प्रस्तावित एनआरसी की बात है, जिम्मेदार देश वही है जो यह सुनिश्चित करे कि उसके यहां रह रहे लोगों में कौन उसके नागरिक हैं और कौन नहीं? अगर मोदी सरकार भी यह करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? क्या यह वही काम नहीं जो कांग्रेस शासन के समय करने की पहल की गई थी? आखिर अपने नागरिकों की पहचान पुख्ता करना गैर संवैधानिक कैसे है? क्या दुनिया के जिन देशों ने यह काम किया है वे लोकतांत्रिक देश नहीं?

इन दिनों संविधान की प्रस्तावना का जिक्र खूब हो रहा है और इस दौरान संविधान की प्रस्तावना में दर्ज सेक्युलरिज्म को बढ़चढ़कर रेखांकित किया जा रहा है। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन क्या इसकी अनदेखी कर दी जाए कि संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द आपातकाल के दौरान थोपे गए? सेक्युलरिज्म शब्द का जैसा घोर दुरुपयोग किया गया है उसकी दूसरी मिसाल मिलनी मुश्किल है। इसी तरह यह भी जगजाहिर है कि समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की राजनीति को पोषित किया गया। क्या राजनीतिक दलों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह चलाना संविधान की भावना के अनुरूप है?

यह देखना दयनीय है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर लोगों और खासकर मुसलमानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हर तरह के छल-कपट का सहारा लिया जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि इस छल-कपट में मीडिया का भी एक हिस्सा शामिल है। यह समझ आता है कि विदेशी मीडिया दुराग्रह से ग्रस्त है, लेकिन आखिर इसका क्या मतलब कि भारतीय मीडिया का भी एक हिस्सा इस हद तक दुराग्रही हो जाए कि झूठ का सहारा लेने से बाज न आए?

यह विडंबना ही है कि जो दल संविधान के दिशा निर्देशक तत्वों में शामिल समान नागरिक संहिता का विरोध करने में आगे रहते हैं वही भाजपा पर यह तोहमत मढ़ने में सक्रिय रहते हैं कि वह इस संहिता की बात कर संविधान तोड़ने और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रही? इन्हीं दलों ने तीन तलाक को बनाए रखने की पुरजोर वकालत की थी। यह हैरान करता है कि असहमति के नाम पर हिंसा करने और भड़काऊ बयान देने वाले भी संविधान की आड़ लेने में सफल हैं। इससे भी हैरानी की बात यह है कि प्रणब मुखर्जी जैसे नेता इस विध्वंसक असहमति को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला काम करार दे रहे हैं। ऐसी दलीलें तो संविधान की आड़ में संविधान को चोट पहुंचाने वालों को बल ही प्रदान करेंगी।

response@jagran.com

गणतंत्र की समृद्ध परंपरा

शक्ति सिन्हा

कुछ लोग गणतंत्र को अंग्रेजों की देन बताते हैं। यह सच नहीं। प्राचीन भारत में कई गणतंत्रों का अस्तित्व था

हम भारतीयों को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व है और होना भी चाहिए। इसके साथ ही हम इस पर भी गर्व करें कि हम किसी प्रक्रिया के जरिये नहीं, बल्कि मूल रूप से लोकतंत्र हैं। चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं। यह वास्तव में गणतंत्र ही है जो एक लोकतंत्र को जीवन एवं आकार देता है। गणतंत्र का अर्थ ही है विधिसम्मत शासन यानी कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं। एक लोकतांत्रिक गणराज्य में सरकार एक साधन है जो समाज की सेवा में रत है, जो संप्रभु है। कुछ लोग गणतंत्र को अंग्रेजों की देन बताते हैं। यह सच्चाई से काफी दूर है। तथ्य यही है कि भारत के विभिन्न हिस्सों पर अलग-अलग गणराज्य शासन कर रहे थे। उनकी संरचनाएं एकसमान नहीं थीं, लेकिन उनकी जवाबदेही थी। शासक निरंकुश तरीके से निर्णय नहीं ले सकते थे। वे नियमों से बंधे हुए थे।

वैशाली का लिच्छवी प्राचीन गणराज्यों में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था। यह उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश के काशी और कोसल भी उससे लगे हुए थे। वास्तव में लिच्छवी 25 से अधिक गणराज्यों का संघ था। कपिलवस्तु के पूर्व में कोलिय का रामाग्राम गणराज्य था। त्रिपिटक बताते हैं कि बुद्ध द्वारा मध्यस्थता कराने से पहले गणराज्य एक दूसरे के साथ संघर्षरत रहते थे। मिथिला गणराज्य, जो तराई से गंगा की ओर बढ़ा, विदेह में स्थित था। तराई क्षेत्र में एक और गणराज्य कोल्लंगा में घ्वात्रिकों का गणराज्य था। मिर्जापुर के पास वाराणसी के दक्षिण में सूर्यसमागिरि में भाग्य गणतंत्र था।

सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब अस्माक गणराज्य और अन्य गणराज्यों ने उसका डटकर विरोध किया। हालांकि मगध साम्राज्य के उदय के साथ पहले नंद वंश और बाद में मौर्यों के तहत, इनमें से अधिकांश गणराज्यों ने कई राज्यों के साथ-साथ अपनी स्वतंत्रता खो दी। फिर भी यह भारतीय गणराज्यों का अंत नहीं था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वे फिर से फैल गए। गुप्त वंश के उदय के साथ अधिकांश गणराज्यों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो दिया था, लेकिन सरकार का स्वरूप कुछ हद तक बना रहा। गणराज्यों के भी तीन प्रकार थे। पहला शुद्ध गण थे, जिसमें प्रशासन में कुल वयस्क-आबादी भाग लेती थी। दूसरा, अभिजात वर्ग या शुद्ध कुल, जिसमें केवल कुछ चुनिंदा परिवार प्रशासन में भाग लेते थे और तीसरा मिश्रित जिसमें लोकतंत्र, कुल और गण का मिश्रण था। प्रशासनिक रूप से इन राज्यों को दो रूपों में आयोजित किया गया- या तो एकात्मक या संघीय। गणतंत्र के केंद्र में सभा थी। इसमें पूरी वयस्क आबादी या कुछ स्थानों पर परिवारों के प्रमुख शामिल थे। कुछ राज्यों में सभाओं ने अपने स्थानीय प्रशासन की देखभाल के लिए व्यापक स्वायत्तता का आनंद लिया और पूरे राज्य से संबंधित मामलों का फैसला सभी सदस्यों द्वारा किया गया जबकि अन्य में पूरे राज्य को संचालित करने की शक्तियां एक निर्वाचित कार्यकारी को सौंपी गईं। इस निर्वाचित निकाय को आमतौर पर समिति के रूप में जाना जाता था। समितियों के लिए चुनाव मौजूदा स्वरूप वाले नहीं थे। लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाता था। समिति कार्यकारी का गठन करती थी जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर राज्य का संचालन करती थी। समिति के प्रमुख को कभी-कभार राजा कहा जाता था, लेकिन न तो वह और न ही कोई पदाधिकारी अपने बेटों को पदस्थ कर सकते थे। इसमें उत्तराधिकार पूरी तरह गायब था।

तब भारतीय गणतंत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या थे? राजा के दैवीय अधिकारों का कोई संकेत नहीं है। यहां तक कि वंशानुगत राजा को अपने शासन को बनाए रखने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता थी। राज्य का मौलिक कर्तव्य था-धर्म, न्याय और संविदा इत्यादि को बनाए रखना। इससे यही आभास होता है कि गणराज्यों को लेकर हमारी अपनी एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें उस पर ध्यान देकर सबक लेने होंगे। यदि कोई राजनीतिक प्रणाली अपनी मिट्टी से जुड़ी है तो उसकी सफलता की संभावनाएं स्वयं बढ़ जाती हैं ।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन

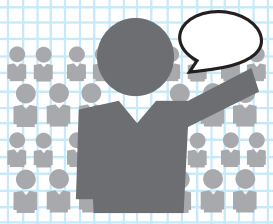

(सीएए का समर्थन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की हिस्सेदारी)

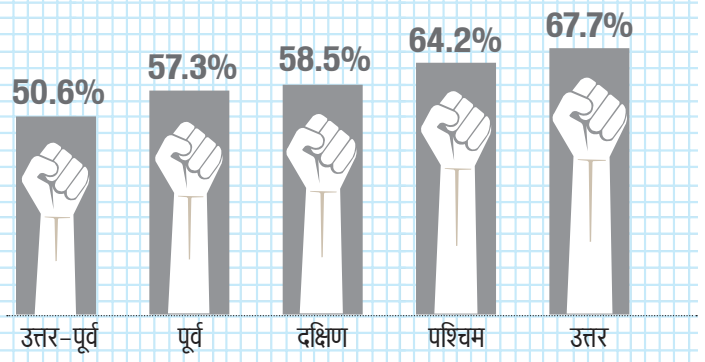

स्रोत : आइएएनएस-सीवोटर जनमत सर्वेक्षण

ऊर्जा

मोक्ष के मार्ग

शास्त्रों में जीवन के चार उद्देश्य-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष का द्वार खोलती है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। उसी प्रकार बौद्ध ,जैन और मीमांसकों में भी मोक्ष की चर्चा है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा के निवर्तन तथा निर्मल ज्ञान की उत्पत्ति ही मोक्ष है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म से उत्पन्न आवरण के नाश से जीव का ऊपर उठना ही मोक्ष है। वहीं मीमांसकों के अनुसार वैदिक कर्म द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण (मोक्ष) प्राप्ति के लिए जीवनपर्यंत साधना की। भगवान महावीर को भी कैवल्य (मोक्ष) प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी।

मोक्ष प्राप्ति के कई साधन हैं। इनमें वाणी, संयम, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तप, अध्ययन, एकांतवाद, जप और समाधि मुख्य हैं। भारतीय दर्शन केवल मोक्ष की सैद्धांतिक चर्चा ही नहीं, बल्कि उसके व्यावहारिक उपाय भी बताता है। सभी भारतीय दर्शन बंधन और मोक्ष संबंधी विचार से सहमत हैं। यदि कोई अपवाद है तो वह है-चार्वाक दर्शन जो घोर नास्तिक और भौतिकवादी दर्शन है। कुछ लोग समझते हैं मोक्ष मरने के बाद ही मिलता है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि मोक्ष देने वाले ज्ञान का स्वरूप भारतीय दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है, किंतु लक्ष्य सभी का एक है और वह है जीव को बंधनों से मुक्त करना। इस लक्ष्य को अनेक साधनों से निरंतर अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता हैं। कर्म करते हुए व्यक्ति को अनेक बंधनों को काटना पड़ता है, जिनमें लोभ, मोह व अहम् तीनों प्रमुख हैं। वास्तव में इन तीन दुष्प्रवृत्तियों से मनुष्य जीवन में छुटकारा पा लेना ही मोक्ष है जिसके लिए कर्ममार्ग और ज्ञानमार्ग का रास्ता अनेक दार्शनिक प्रणालियों ने अपनाया है। इन तीनों दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा मनुष्य के जीवन को सार्थक सिद्ध करने में सहायता करता है।

शिवांशु राय

अंतरिक्ष की दिशा में एक और कदम

मुकुल व्यास

महिला रोबोट व्योममित्र के जरिये अंतरिक्ष में इसरो के पहले मानव मिशन की सफलता के लिए जमीन तैयार की जाएगी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मानवरहित और मानवीय अंतरिक्ष मिशन से जुड़े सुरक्षा पहलुओं की जांच के लिए एक महिला रोबोट विकसित किया है। इसे 'व्योममित्र' नाम दिया गया है। यह अर्धमानव रोबोट प्रोटोटाइप है जिसे इस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका मकसद वर्ष 2022 में इसरो के मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए आधार तैयार करना है। यह एक ह्यूमेनॉइड रोबोट है जो मनुष्य सरीखा दिखता है। व्योममित्र को हाफ-ह्यूमेनॉइड भी कहा जा रहा है, क्योंकि उसका सिर्फ ऊपरी शरीर है। रोबोट की तरह ही ह्यूमेनॉइड के कार्य कंप्यूटर सिस्टम से निर्धारित किए जाते हैं जिससे वह जुड़ा होता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ और रोबोटिक्स के क्षेत्रों में हाल में हुई प्रगति के बाद विविध कार्यों के लिए ह्यूमेनॉइड रोबोट का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। इसरो वर्ष 2022 तक मनुष्य को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। वह भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित उड़ान और वापसी के लिए मॉड्यूल और रॉकेट सिस्टम विकसित कर रहा है। अभी जिन देशों ने भी मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा है, उन्होंने अंतरिक्ष से वापसी के सिस्टम को परखने के लिए पहले जानवरों का प्रयोग किया था।

भारत अपने अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जीएसएलवी मार्क थ्री रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। इसरो इस रॉकेट की दक्षता को जांचने के लिए ह्यूमेनॉइड रोबोट का प्रयोग करेगा। इस रोबोट को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की रोबोटिक्स प्रयोगशाला में विकसित किया जा रहा है। जीएसएलवी मार्क थ्री रॉकेट को मनुष्य की यात्रा के लिए सुरक्षित बनाने के लिए उसमें कई तरह के सुधार किए जा रहे हैं। मनुष्य के लिए उपयुक्त रॉकेट के साथ पहली मानवरहित उड़ान दिसंबर 2020 में निश्चित की गई है। इसरो को अपनी अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए रोबोटिक सिस्टम निर्मित करने का अच्छा खासा अनुभव है। पिछले वर्ष सितंबर में चंद्रयान-2 मिशन के लिए प्रयुक्त विक्रम लैंडर सिस्टम में दूरियों का अनुमान लगाने और गति आदि के लिए एआइ तकनीकों का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रोबोट पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षित यात्रा के लिए विकसित मॉड्यूल में विभिन्न सिस्टम की जांच करेगा।

व्योममित्र रोबोट टार्स टाइप के एआइ और रोबोटिक्स सिस्टम का बहुत ही बुनियादी रूप है। व्योममित्र के कार्यों में अंतरिक्ष यात्री के मॉड्यूल में लगे उपकरणों का संचालन, धरती स्थित सिस्टम से भेजी जाने वाली कमांड को ग्रहण करना और उसका पालन करना शामिल है। यह रोबोट अंतरिक्ष यात्रा के दौरान और वापसी के समय मॉड्यूल में उष्मा के विकिरण के स्तर और अन्य परिवर्तनों की सूचना पृथ्वी पर भेजेगा। भविष्य में यह रोबोट अंतरिक्ष यात्री के सहयोगी के रूप में भी काम करेगा।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

दलाल है कि मानता नहीं

मोदी सरकार आने के बाद से ही मंत्रालयों में दलालों का प्रवेश बंद है और बिना किसी शिकायत के सर्विलेंस के आधार पर दिल्ली के कई दलाल सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इसके बावजूद लुटियन दिल्ली में दलालों की सक्रियता पूरी तरह रुकने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता के गलियारे में आजकल एक ऐसे दलाल की चर्चा है जो चंदा कोचर मामले में फंसे बड़े लोगों को राहत दिलाने का दावा कर रहा है। इस दलाल का रिश्ता फिल्मी दुनिया से भी बताया जाता है। भले ही खुद चंदा कोचर को अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई हो और ईडी ने उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली हो। बताया जाता है कि यह दलाल इन दिनों इस मामले में फंसे कई बड़े लोगों के बीच घूम रहा है और जांच एजेंसी के एक शीर्षस्थ अधिकारी से अपनी नजदीकियों का हवाला देकर उन्हें जांच के शिकंजे से पूरी तरह मुक्त करने का दावा कर रहा है। उसकी कारगुजारियों की चर्चा कुछ एजेंसियों तक पहुंच भी चुकी है। जाहिर है एजेंसियों ने उसकी हर हरकत पर नजर रखना शुरू भी कर दिया है।

बाबा का ठहाका योग

योग में पारंगत होने के साथ ही बाबा रामदेव की हाजिरजवाबी भी लाजवाब है। शुक्रवार को उन्होंने इसका अहसास भी कराया। उनकी हाजिरजवाबी ने लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। हुआ यह कि बाबा रामदेव संवाद 2020 में शामिल होने पहुंचे थे, तभी किसी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बाबा से सवाल कर डाला। फिर क्या था, बाबा पूरे रंग में आ गए। बाबा ने कहा कि इस जन्म में मुझसे तो आबादी बढ़ने का कोई खतरा नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें ही विचार करने की जरूरत है। फिर क्या था, पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। हालांकि उन्होंने उन लोगों को जरूर समझाइश दी, जो दो से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों के अधिकार भी खत्म होने चाहिए।

अनोखा समर्थन...

किसी का फैन होना अलग बात है और किसी मुद्दे पर उसका समर्थन करना अलग, लेकिन जब ये दोनों ही बातें किसी एक व्यक्ति से जुड़ जाएं तो वह कुछ भी कर सकता है। हाल ही में अपनी फिल्म छपाक के रिलीज होने से पहले दीपिका पादुकोण जेएनयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचीं तो उसके बाद उनकी फिल्म के बहिष्कार के स्वर भी बुलंद हुए। लेकिन बताते हैं कि रालोद नेता जयंत चौधरी ने दीपिका को सपोर्ट करने का अनोखा ही अंदाज चुना। उन्होंने पूरा का पूरा सिनेमाहॉल बुक करा डाला जहां उन्होंने अपने परिवार और समर्थकों के साथ छपाक फिल्म देखी।

हड़बड़ी में गड़बड़ी

दर्जनों श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेटने की हड़बड़ी में बाबुओं ने तमाम ऐसी गलतियां कर दी हैं जिन्हें देखकर किसी दिमागदार आदमी का माथा भी चकरा जाएगा। वह तो भला हो विपक्ष का जिसके दबाव में सरकार को वेतन संबंधी पहली श्रम संहिता के पास होने के बाद औद्योगिक संबंध तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित दो श्रम संहिताओं को स्थायी संसदीय समिति के हवाले करना पड़ा। सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी स्थायी समिति ने सभी पक्षों से अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज कराने को कहा है। अब तक अनेक संगठन और व्यक्ति समिति को अपने अपने हिसाब से संहिता की खामियों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन रेलवे की प्रमुख यूनियन ऑल इंडिया रेलमेंस फेडेरेशन ने जिस खामी की ओर ध्यान दिलाया है वह खासी गंभीर है। यूनियन ने समिति को बताया है कि संहिताओं में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आइएलओ के साथ भारत की संधियों और घोषणाओं का उल्लंघन किया गया है। यदि इन्हें दुरुस्त नहीं किया गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हो सकती है। संहिताओं में और भी कई खामियां हो सकती हैं, जिनके अध्ययन के लिए समिति को कम से कम छह सप्ताह का समय देना चाहिए।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1.95 तौलिये और 81,736 बेड शीट समेत अनेक सामान भारतीय रेल में यात्रा के दौरान गायब हुए वर्ष 2018 में, आइआरसीटीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार।

आजकल

कुंठित मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन

अनंत विजय
anant@nda.jagran.com

नसीरुद्दीन शाह ने हाल में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर पर कई तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए उन्हें जोकर और खुशामदी व्यक्ति कहा और उनके खून को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। ऐसे में वर्ष 2014 में नसीरुद्दीन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक 'एंड दैन वन डे' के तथ्यों को समझना जरूरी है जिसे लगभग उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा है। हालांकि इसमें बड़ी बेबाकी से अपने बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन इस तरह के बयान से आज उन्होंने स्वयं को ही हास्यास्पद बना दिया है

अनुपम खेर। फाइल फोटो।

नसीरुद्दीन शाह। फाइल फोटो।

हिंदी फिल्मों के इतिहास में सलीम-जावेद की ऐतिहासिक जोड़ी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। डेढ़ दशक तक एक साथ फिल्में लिखने वाली जोड़ी जिसने 'शोले', 'दीवार', 'जंजीर' और 'डॉन' जैसी सुपर हिट फिल्में लिखीं। वर्ष 1981 में ये जोड़ी टूटी और दोनों अलग हो गए। बताया गया कि दोनों में मनभेद हो गया था जिसकी वजह से वे अलग हो गए। सलीम-जावेद के बीच मतभेद तो स्क्रिप्ट को लेकर भी होते रहते थे और दोनों घंटों माथापच्ची करते थे। फिल्म 'दीवार' का वो प्रसिद्ध संवाद 'मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है' के जवाब में यह लिखना कि 'मेरे पास मां है' को लेकर भी दोनों के बीच घंटों चर्चा हुई थी। सलीम खान ने कहीं लिखा भी है कि इस वाक्य पर पहुंचने के लिए दोनों ने मिलकर करीब पचास ड्राफ्ट फाड़े थे, तब जाकर ये पंक्ति निकल कर आ पाई थी।

पिछले करीब 39 वर्षों से सलीम खान और जावेद अख्तर की राय किसी मुद्दे या व्यक्ति पर एक रही हो ऐसा सार्वजनिक रूप से एक बार ही सामने आ पाया है। वह व्यक्ति हैं फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। कुछ दिनों पहले एक साहित्य उत्सव में जावेद अख्तर ने नसीर के बारे में कहा था, 'नसीर साहब को कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं पसंद है, अगर कोई पसंद हो तो उसका नाम बताएं कि यह आदमी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि सक्सेसफुल है। मैंने तो आज तक सुना नहीं। वह दिलीप कुमार की आलोचना करते हैं, अमिताभ बच्चन को क्रिटिसाइज करते हैं, हर आदमी जो सक्सेसफुल है वह उनको भला नहीं लगता।' जावेद साहब ने यह तब कहा था जब नसीर ने राजेश खन्ना को औसत कलाकार कहकर मजाक उड़ाया था। उसी समय सलीम खान ने भी नसीरुद्दीन शाह को कुंठित और कड़वा व्यक्ति कहा था। इस पर सलीम-जावेद सहमत थे कि नसीरुद्दीन शाह कुंठित हैं। आप समझ सकते हैं कि यह मुद्दा कितना अहम होगा जिस पर सलीम खान और जावेद अख्तर एक बार फिर से सलीम-जावेद नजर आते हैं या यह बात सत्य के कितने करीब होगी जिस पर चार दशक तक एक दूसरे से दूरी रखनेवाले दो लेखक एक राय रख पाते हैं।

नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर के बारे में अनाप-शनाप बोलकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। नसीर ने कहा कि अनुपम खेर जोकर हैं और उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। खुशामद उनके स्वभाव में है। नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर के खून को भी सवालों के घेरे में लिया और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। अनुपम खेर ने चंद घंटों में ही नसीर को आईना दिखा दिया। लेकिन जिस तरह की शब्दावली का उपयोग नसीरुद्दीन शाह ने किया वह निहायत घटिया है और वह नसीर के संस्कारों पर भी सवाल खड़े करती है। मैंने जब नसीरुद्दीन शाह का अनुपम को लेकर दिया बयान सुना तो उनकी पुस्तक का एक प्रसंग ध्यान आया। पुस्तक का नाम है- एंड दैन वन डे। यह पुस्तक 2014 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक नसीरुद्दीन शाह की लगभग आत्मकथा है, हालांकि इसको संस्मरण के तौर पर पेश किया गया है। इसमें नसीर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रहने के दौरान के स्वयं से जुड़े प्रसंगों को विस्तार दिया है। इसके एक अध्याय 'द वूमेन विद द सन इन हर हेयर' में उन्होंने स्वीकार किया है कि वहां उनको अपने से करीब पंद्रह साल बड़ी पाकिस्तानी लड़की परवीन से इश्क हो गया। इश्क की इस पूरी दास्तां को पढ़ने के बाद कहीं प्रत्यक्ष और कहीं परोक्ष रूप से नसीर ने यह लिखा है कि उस वक्त परवीन उनकी जरूरत थी। उनके अंदर विश्वास पैदा करने में, उनको गढ़ने में परवीन ने अहम भूमिका निभाई। नसीरुद्दीन और परवीन का इश्क परवान चढ़ने लगा था और नसीर हर दिन यह महसूस करने लगे थे कि परवीन उनके लिए और उनके करियर के लिए कितनी अहम है। परवीन उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डॉक्टरी पढ़ रही थी और नसीर रंगकर्म की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते थे। उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी जो परवीन ने उन्हें दिया। इस सहारे को दोनों ने सहमति से रिश्ते में बदलने की बात सोची और दोनों ने शादी कर ली।

दोनों का दांपत्य जीवन ठीक-ठाक चल रहा था। दोनों की शादी के दस महीने के अंदर ही परवीन ने एक बेटी को जन्म दिया। इस बीच नसीर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली पहुंच गए थे। परवीन अलीगढ़ में रह रही थी और नसीर दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अपने करियर को परवान चढ़ाने में लगे थे। नसीर ने अपनी इस किताब में माना है कि दिल्ली में रहने के उस दौर में वह बेहद असुरक्षित महसूस करते थे जिस कारण उनका यह रिश्ता लंबा नहीं चल पाया। दिल्ली में रहनेवाले नसीर की प्राथमिकताएं बदल गई थीं, दोस्त भी। नए रिश्ते भी पनपने लगे थे। नसीर को लगने लगा था कि उनके करियर में शादी और बच्चे दोनों बाधा हो सकते हैं। अपने करियर को तमाम रिश्तों पर प्राथमिकता देनेवाले नसीर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचने के बाद शादी और बच्चा दोनों बोझ लगने लगे थे, लिहाजा उन्होंने परवीन से दूरी बनानी शुरू कर दी। नसीर का यह रुख उसके व्यवहार में भी दिखने लगा था। उन्होंने अलीगढ़ जाना कम कर दिया था, परवीन के पत्रों के उत्तर देने कम कर दिए थे। जब परवीन उनसे मिलने दिल्ली आई तब भी नसीर ने बहुत बेरुखी से उनसे बातचीत की। परवीन ने नसीर से प्रार्थना की कि एक बार फिर से पति-पत्नी के रिश्ते को हरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नसीर का रुख नकारात्मक ही रहा। वह इस शादी से मुक्ति चाहने लगे थे। उनके सामने करियर का जो नया द्वार खुल रहा था उसमें शादीशुदा जिंदगी उनको बोझ और बाधा दोनों लगने लगी थी। इस तरह की सोच जब किसी व्यक्ति के मानस में अंकुरित होती है तो फिर वह रिश्ते की परवाह कहां करता है। दोनों अलग हो गए। थोड़े समय के बाद पाकिस्तानी महिला परवीन अपनी बच्ची को लेकर लंदन चली गई और फिर नसीर बारह वर्षों तक उससे नहीं मिल सके। नसीर को बारह वर्षों तक अपनी बेटी की भी याद नहीं आई। जब पुस्तक लिखी या जब करियर के शीर्ष पर पहुंच गए तो याद सताने लगी। नसीरुद्दीन शाह ने अभिनेत्री रत्ना पाठक से दूसरी शादी की। उसका जिक्र करते हुए भी वह यह कह जाते हैं कि रत्ना एक मजबूत स्त्री है जिसने नसीर को कई बार संभाला।

कमाल है इस कलाकार का, इनको प्रेम उसी स्त्री से होता है जिसमें उनको संभालने की संभावना नजर आती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह नसीर के व्यक्तिगत संदर्भ लगें और इन सबका उल्लेख अनुचित। लेकिन जब व्यक्ति अपना जीवन सार्वजनिक तौर पर खोलता है या किसी संदर्भ या पुस्तक में उसकी जिंदगी खुलती है तभी उसकी मुकम्मल तस्वीर बनती है। नसीर की इस किताब में कई ईमानदार प्रसंग भी हैं, लेकिन इसी पुस्तक के कई प्रसंग उनकी सोच, उनकी मानसिकता, अपनी करियर की सीढ़ी के तौर पर रिश्तों का इस्तेमाल करने की उनकी प्रवृत्ति भी खुलकर सामने आ जाती है। ऐसा इंसान जब दूसरों को जोकर, खुशामदी या चापलूस कहता है या दूसरों के खून के बारे में बात करता है तो सही में लगता है कि वह कुंठित हो चुका है। सही तो जावेद अख्तर भी प्रतीत होते हैं कि नसीर किसी सफल आदमी की तारीफ नहीं कर सकते। आज अनुपम खेर बेहद सफल हैं, अमेरिका में मिले काम की वजह से उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अभिनेता के तौर पर मान्यता मिल रही है, वहीं नसीर मुंबई में बैठकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कभी उनको अपने बच्चों की फिक्र होती है, कभी वह राजेश खन्ना को कोसने लगते हैं। कुंठा का सार्वजनिक प्रदर्शन किसी गंभीर कलाकार को किस कदर हास्यास्पद बना देती है, नसीर इसकी जीती जागती मिसाल बनकर रह गए हैं।

गणतंत्र दिवस

देशभक्ति और नागरिक बोध

डॉ. अजय खेमरिया

'हमें आजादी के आंदोलन में संघर्ष या शहादत का अवसर नहीं मिला इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन हमें भारत के लिए जीने का अवसर आज उपलब्ध है,' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर यह कहते हैं। इसके पीछे मूल वजह पिछले सात दशकों में लोकजीवन के वे नैराश्य भरे अनुभव हैं जो देशवासियों के नागरिक बोध पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे हैं। हमने गणतंत्रीय और संप्रभु राजव्यवस्था को अपनाया, लेकिन इसके लिए मूल संविधान में नागरिक उत्तरदायित्व के प्रावधान नहीं किए। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 (क) जोड़कर पहले 10 और अब 11 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। भारत के लोकजीवन में नागरिकों के अधिकारों को लेकर बहस होती रहती है। पिछले कुछ वर्षों में अभिव्यक्ति की आजादी और इससे संबंधित अधिकारों को लेकर एक वर्ग द्वारा ऐसा माहौल निर्मित किया जाता रहा है मानो राजव्यवस्था नागरिक अधिकारों को कुचलने में लगी है।

क्या कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बगैर नागरिक बोध के सफल हो सकती है? क्या सिर्फ राज्य प्रायोजित अनुदान और सुविधाओं के उपभोग से कोई राज्य लोक कल्याणकारी ध्येय को प्राप्त कर सकता है? वर्ष 1950 से भारतीय लोकजीवन का सिंहावलोकन हमें इस चिंतन की ओर उन्मुख करता है कि क्या भविष्य का भारत अपने नागरिकों की कर्तव्य विमुखता की नींव पर खड़ा होकर उस वैश्विक स्थिति को हासिल कर पाएगा जिसकी कल्पना संविधान बनाने वाले पूर्वजों ने की थी।

हमारी गैर जवाबदेह लोक चेतना को जापान के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। कुछ वर्ष पूर्व एक भारतीय शिक्षक जापान यात्रा पर थे। वहां उन्होंने देखा कि टोकियो में एक बुजुर्ग ट्रेन की सीट के फटे हुए हिस्से की सिलाई कर रहे हैं। भारतीय शिक्षक ने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह एक रिटायर्ड शिक्षक हैं और यह सोचकर सीट की सिलाई कर रहे हैं कि कोई विदेशी अगर इस ट्रेन में सफर करेगा तो उसके मन में जापान की क्या छवि बनेगी? अंदाजा लगा सकते हैं कि जापानी चरित्र में किस उच्च कोटि की राष्ट्रीयता का तत्व विद्यमान है। इसके उलट आइआरसीटीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2018 में हमारी ट्रेनों से 1.95 लाख तौलिया, 81,736 बेड शीट, 55 हजार तकिया कवर, सात हजार कंबल आदि गायब हो गए। भारतीय रेल भी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। संविधान का मूल कर्तव्य संख्या नौ कहता है कि 'हम सभी को अपने राष्ट्रीय स्मारक और संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए।'

जापानी नागरिक बोध को दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जा सकता

प्रतीकात्मक फोटो।

है। वह ऐसे नागरिकों का राष्ट्र है जो द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी के बाद आज तकनीकी और राष्ट्रीय उत्पादन के मामले में अव्वल बन चुका है।

बेशक भारत ने सात दशकों में हर क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन उपलब्ध मानव और प्राकृतिक संपदा की तुलना में यह अन्य देशों से काफी कम है। इसका कारण हमारे चेतन में राष्ट्रीयता के प्रधान तत्व की कमी है। हम अटारी वाघा बॉर्डर पर जब परेड देखते हैं तो देशभक्ति के उन्मादी ज्वार में डूब जाते हैं। वहां से लौटते हैं तो ढेर सारा कचरा ट्रेन में अपनी सीट के नीचे छोड़ आते हैं। ऐसे बीसियों उदाहरण हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि हमारी चेतना में राष्ट्रीय दायित्व बोध आज भी स्थाई भाव नहीं बना सका है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

ट्वीट-ट्वीट

यह बहुत गर्व की बात है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले 286 गैलेंट्री अवॉर्ड में से 105 जम्मू-कश्मीर पुलिस के खाते में जा रहे हैं। कभी हार ना मानने वाले जज्बे वाली जम्मू-कश्मीर पुलिस सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ उस छद्म युद्ध से निपटने में जुटी है जो हम पर थोपा गया है।
इम्तियाज हुसैन@hussain_imtiyaz

शाहीन बाग में पत्रकारों के साथ जो हुआ वह बेहद शर्मनाक है। आपको किसी से बात करनी है कीजिए, न करनी हो, न कीजिए, पर आपके बीच पहुंचे एक पत्रकार को अपना काम करने से भला कैसे रोक सकते हैं ? इस वाकये की जितनी निंदा की जाए उतना कम है।
समीर अब्बास@TheSamirAbbas

लोकतंत्र कभी परफेक्ट नहीं होता। उसमें सुधार की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है। हमें अपने लोकतंत्र को बेहतर बनाना है तो भ्रष्टाचार और वोट खरीदने जैसी कई बुराइयां दूर करनी होंगी। ऐसा संभव होने पर लोकतंत्र के प्रति आस्था और बढ़ेगी।
जयप्रकाश नारायण@JP_LOKSATTA

अमेरिकी उद्यमी जॉर्ज सोरोस कथित लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण पर एक अरब डॉलर निवेश करेंगे। इसे आप भारत, चीन जैसे देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करने की कवायद कह सकते हैं। उन्नीसवीं सदी के विचारक भी उपनिवेशवाद को जायज ठहराने के लिए यही भाषा बोलते थे।
संजीव सान्याल@sanjeevsanyal

कंगना रनोट को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर दिली मुबारकबाद। वह कमाल की अभिनेत्री होने के साथ ही बहादुर इंसान भी हैं जो कभी अपनी बात कहने से हिचकती नहीं हैं। खासतौर से जब मसला राष्ट्रवाद का हो तो वह चुप नहीं बैठती हैं।
अशोक पंडित@ashokepandit

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर पर निशाना साध कर अपनी फजीहत कराई?

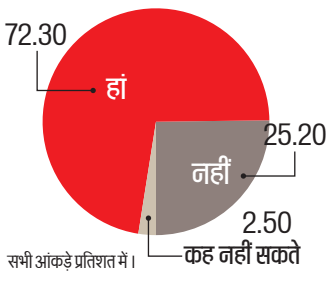

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आइएमएफ प्रमुख द्वारा देश में आर्थिक सुस्ती को अस्थायी बताना भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसे का सूचक है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

'आजादी' के घोष का गूंज रहा हो मंत्र,
फिर तो है बेकार यह भारत का गणतंत्र।
भारत का गणतंत्र न अब तक जिनको भाया,
है जश्न-ए-शाहीन जा रहा वहीं मनाया!
चाह रहे जो लोग देश की हो बर्बादी,
चौराहों पर आज मांगते वे 'आजादी'।
– ओमप्रकाश तिवारी

रचनाकर्म

दिल्ली की भूली-बिसरी बावलियां

संजीव कुमार झा

दिल्ली सदियों से सत्ता का केंद्र रही है। आक्रांताओं ने इसे कई बार लूटा, लेकिन नव निर्माण की इसकी जिजीविषा इसे हर बार नए सिरे से, नए कलेवर में बसाया है। इसमें उन शासकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने दिल्ली को बेहतर शहर बनाने और उसके बाशिंदों को आधुनिक सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बेहतर तकनीकों का उपयोग किया। इनमें जल संरक्षण की दिशा में किए गए उपाय प्रमुख रहे, क्योंकि जीवन के लिए जल और वायु नितांत मौलिक जरूरतें हैं। इसलिए दुनिया की सभी प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों और जल संसाधनों के समीप हुआ। इन सभ्यताओं के अवशेषों में जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन के बेहतरीन प्रमाण मिलते हैं। पिछले दो हजार वर्षों का ही इतिहास देखें, तो दुनिया भर में तत्कालीन शासकों ने अपनी राजधानियों और राज्यों के लिए जल-प्रबंधन के जितने उपाय किए, वे अपने आप में मिसाल हैं। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण पर काम करने वाले फोटोग्राफर विक्रमजीत सिंह रूपराई की किताब 'बावलीज' भारत की आजादी के पहले दिल्ली के कुछ शासकों द्वारा निर्मित और संरक्षित जल-स्रोत बावलियों की जानकारी का ऐसा संकलन है, जो जल प्रबंधन और आपूर्ति के संकट से जूझ रही स्थानीय सरकार के अलावा इन विषयों पर काम करने वालों के लिए अनमोल खजाना साबित हो सकता है।

पिछले करीब 1,500 वर्षों में एशिया में राजाओं ने जल-संरक्षण व प्राकृतिक अभाव के दिनों में उसके उपयोग के लिए बावलियों के निर्माण का तरीका अपनाया। उन्होंने ऐसे कुएं बनवाए, जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थीं। इनमें कुछ बावलियों का निर्माण राजाओं-महाराजाओं ने निजी उपयोग के लिए, तो कई का आम जनों के उपयोग के लिए करवाया था।

रूपराई ने दिल्ली की बावलियों में कोटला फिरोजशाह बावली, लालकिला बावली, हजरत निजामुद्दीन बावली, उग्रसेन की बावली, मुनीरका बावली, गंधक की बावली, पुराना किला बावली, राजों की बावली, लोहारहेड़ी बावली, मेहरबां आगा की बावली, दरगाह ख्वाजा की बावली समेत ढाई दर्जन से ज्यादा उन बावलियों के इतिहास और वर्तमान पर प्रकाश डाला है, जिनमें से अधिकतर का पता तो दिल्ली में ही पले-बढ़े लाखों बाशिंदों को भी नहीं होगा। अफसोस की बात यह कि इनमें से कई बावलियां लुप्त हो चुकी हैं, तो कई लुप्तप्राय हैं। खारी बावली आज देश के एक बड़े होलसेल मार्केट के रूप में विख्यात है। बहुत कम लोगों को पता है कि उस घने बाजार में जमीन के नीचे कभी जल भंडारण-संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण रही एक बावली मृत पड़ी है। अब वह यहां ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। दिल्ली के दिल में बसे कनॉट प्लेस के करीब बाराखंबा रोड और कस्तूरबा गांधी मार्ग के बीच हेलीलेन में स्थित दिल्ली की मशहूर बावलियों में से एक उग्रसेन की बावली को वर्तमान पीढ़ी के ज्यादातर लोग आमिर खान अभिनीत फिल्म 'पीके' के बाद से जानने लगे हैं। इसमें 108 सीढ़ियां हैं। दिलचस्प यह कि सूरज से पृथ्वी की दूरी भी सूरज के व्यास का लगभग 108 गुना और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी चंद्रमा के व्यास का करीब 108 गुना है। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से 108 उपनिषद हैं और नाट्य शास्त्र के मुताबिक, हाथ और पैर की 108 तरह की गतियां होती हैं। शास्त्रों के मुताबिक इंसान के झूठ और इच्छाओं की संख्या भी 108 होती है। रूपराई का यह संकलन दिल्ली की हर बावली के निर्माण, उससे जुड़े कथानक और उसकी मौजूदा स्थिति के बारे में ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों का पिटारा है।

'दिल्ली हैरिटेज टॉप-10' सीरीज की यह पुस्तक वर्तमान और भविष्य में जल संकट से निपटने में इन बावलियों की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करती है। लेखक का मानना है कि यदि इन बावलियों का पुनरुद्धार कर उपयोग में लाया जाए, तो दिल्ली में जल संकट को खत्म किया जा सकता है।

इस किताब में दिल्ली के शासकों द्वारा बनवाई गई उन भूली-बिसरी बावलियों का वर्णन किया गया है, जिससे जल संकट जैसी समस्या का समाधान किया जा सकता है

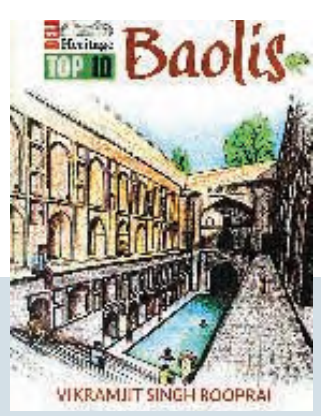

पुस्तक का नाम : बावलीज
लेखक : विक्रमजीत सिंह रूपराई
प्रकाशक : नियोगी बुक्स
मूल्य : 399 रुपये

खादी की तरह सहज बने हिंदी

अजय कुमार राय

जो सौंदर्य वस्त्रों में खादी का है, वही सौंदर्य भाषा में हिंदी का है। वह हिंदी जो पूरे देश में बोली जाती है। उसका लहजा, उसकी शैली कैसी भी हो, किंतु उसकी व्यापकता स्वयंसिद्ध है। हिंदी के इसी सौंदर्यबोध को ओम निश्चल ने अपनी पुस्तक 'भाषा की खादी' में उकेरा है। इसमें उन्होंने हिंदी के महत्व पर अलग तरीके से प्रकाश डाला है। सहज-सरल सबकी जुबान पर चढ़ सके, उस हिंदुस्तानी हिंदी के विस्तार में आने वाली मुख्य बाधाओं को गिनाने के साथ-साथ उनका आसान समाधान भी सुझाया है।

खादी का संबंध हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन से रहा है। हिंदी का संबंध भी स्वतंत्रता, स्वदेशी और राष्ट्रीय स्वाभिमान से रहा है। जैसी सहजता खादी का पर्याय है, वैसे ही सरलता हिंदी का पर्याय है। जिस प्रकार खादी को लोगों ने वस्त्र नहीं, विचार माना था, उसी प्रकार हिंदी भी भाषा नहीं, विचार है। यह विचार है उस स्वदेशी का, जो सिर्फ अपनी भाषा में सोचने से संभव है। यह विचार है उस अहिंसा का, जो हमारी भाषा हमें बचपन में सिखाती है। यह विचार है उस चरखा संस्कृति का, जो हमें स्वावलंबन सिखाती है। यह भी सच है कि जो जितना सरल होता है वह उतना ही विस्तार पाता है। लेखक ने इस पुस्तक के जरिये नीति-नियंताओं और भाषा के उपयोगकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है। अभी देश में दो तरह की हिंदी देखने को मिलती है। एक वह, जिसे आम लोग बोलते-समझते हैं। दूसरी वह, जो विभिन्न सरकारी विभागों-दफ्तरों में होने वाले दैनिक प्रशासनिक कामकाज में प्रयोग होती है। दरअसल, हिंदी ने संविधान सभा में राजभाषा का दर्जा हासिल तो किया, लेकिन इसे अनुशासन के नाम पर ऐसी कठिन तकनीकी शब्दावलियों में बांध दिया गया कि सरकारी कामकाजी स्तर पर यह आमजन को स्वीकार्य न हो सकी। यह समस्या आज भी कायम है। यह किताब हिंदी में आई जटिलता की इस दीवार को गिराकर भाषा में खादी जैसा सौंदर्य विकसित करने का आह्वान करती है। जो लोग इस भाषा से प्रेम करते हैं, उन्हें यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए।

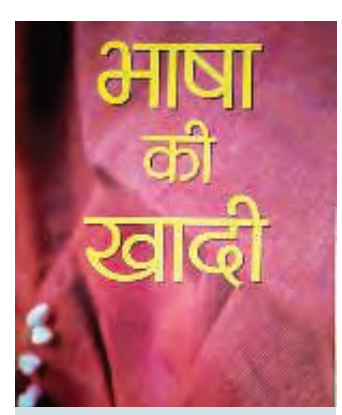

पुस्तक : भाषा की खादी
लेखक : ओम निश्चल
प्रकाशक : ज्ञान गंगा, दिल्ली
मूल्य : 400 रुपये

आशीष व्यास
संपादक, नई दुनिया, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

अति उत्साह से उलझ रहा प्रशासनिक तंत्र

मध्य प्रदेश में एक प्रशासनिक विवाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का बड़ा केंद्र बन गया है! बहस इस बात पर हो रही है कि सम्मान, सहयोग, सत्यनिष्ठा से वंचितों की सेवा का संकल्प लेने वाले प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी संभालते ही 'रूल ऑफ लॉ' को क्यों भूल जाते हैं? क्यों अवसर विशेष पर 'कृत्रिम-किरदार' ओढ़कर अपने ही बनाए 'नियम-कायदे' में ढल जाते हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में कलेक्टर निधि निवेदिता द्वारा भाजपा नेता को थप्पड़ मारने और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा की भीड़ से भिड़ने की घटना इसका ताजा उदाहरण है। मैदान में उतर कर 'शौर्य' प्रदर्शन करने वाली दोनों महिला अधिकारियों का सार्वजनिक आचरण क्या नियम-कानून के दायरे में था, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर मध्य प्रदेश में अब खुली राजनीतिक बहस हो रही है। कांग्रेस सत्तारूढ़ दल की परंपरा को निभाते हुए अधिकारियों के पक्ष में खड़ी है और विपक्षी दल भाजपा प्रदेश में अराजकता के नए दायरों की, नई परिभाषा लिखने में जुटी हुई है। इस बार की बहस और क्रिया-प्रतिक्रिया सिर्फ चौराहों- गलियारों तक सीमित नहीं है। सही-गलत पर मुहर की आस अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। उम्मीद की जाए कि इंदौर हाई कोर्ट में बीते बुधवार लगी याचिका भी इस बात को प्रमाणित करेगी कि लोकसेवकों का आचरण कैसा हो? तर्क-कुतर्क के इस नए कुहासे में यह दलील भी फिर उभरी है कि चर्चा में आने और फिर छा जाने की महत्वाकांक्षाएं, प्रशासनिक अधिकारियों को विचलित कर देती हैं। सोशल मीडिया के जरिये यह संक्रामक 'बीमारी' तेजी से फैलती है और नए या पुराने चेहरों को अलग-अलग कारणों से अपना शिकार बनाती है।

तर्क और प्रमाणों से सुलझाई ईवीएम की चुनौती : मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को चुनौती देने वाले राजनीतिक दलों को संभालने में सफल रहे आइएएस ओपी रावत (सेवानिवृत्त) कहते हैं, 'हर आइएएस को 'रूल ऑफ लॉ' को ध्यान में रखते हुए फैसला लेकर ही लोगों के बीच जाना चाहिए। यदि उद्देश्य स्पष्ट हो और सभी का ध्यान रखकर निर्णय लिया गया हो, तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती है। त्रिपुरा चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर हर पार्टी संदेह कर रही थी। यहां तक कि सत्तारूढ़ पार्टी के मन में भी संशय था। योजनाबद्ध तरीके से सभी पार्टियों से चर्चा की, समझाइश दी और परिणाम आया तो सभी ने स्वीकार भी किया। जहां तक भीड़ की मानसिकता है, तो एक आइएएस की यही खूबी है कि माहौल बिगड़ने से पहले उसे भांप ले। प्रशिक्षण के दौरान हमें सिखाया जाता था, निर्दोष चेहरे को पहचान कर फैसला लें। आज की पीढ़ी के अफसरों (आइएएस) को यह बात सीखना और समझना पड़ेगा।

उज्जैन की घटना से सबक लिया और दतिया को जलने से बचाया : लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के पूर्व निदेशक और मध्य प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आइएएस पद्मवीर सिंह सबसे पहले भीड़ से बातचीत के हिमायती हैं। वे कहते हैं, 'मेरी पहली पोस्टिंग उज्जैन में थी। कॉलेज छात्रों के बीच विवाद का हल निकालने में देरी हुई, नतीजन मामला बिगड़ता चला गया। मैं मानता हूं उस दौरान परिस्थितियों को संभालने में कहीं चूक हुई होगी, तभी मामला इतना बिगड़ गया। उस दिन से तय कर लिया था कि किसी भी मसले का हल सिर्फ बातचीत से ही निकालूंगा। 1984 के दंगे देश भर में जोर पकड़ रहे थे। दतिया कलेक्टर रहते हुए मैंने सारे समाज के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। सुझावों-शिकायतों को सुनने के बाद केवल इतना कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। तब दतिया शांत रहा था। प्रशासनिक अकादमी में भी नवागत आइएएस को इस बात का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि 'सिचुएशन-डिफ्यूज' कैसे की जाए। इस व्यावहारिक प्रशिक्षण में देश भर की कई केस स्टडी के जरिये समस्याओं को सुलझाना बताया जाता है। बावजूद इसके, मध्य प्रदेश में घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, समझ से परे है।'

फिर से लौटते हैं लोक आचरण की मर्यादाओं पर। चूंकि कलेक्टर व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे के शीर्ष प्रतीक होते हैं, इसलिए उनसे मारपीट या अभद्रता पूरी टीम का मनोबल गिरा देती है और इसी दबाव में गलत निर्णय होते चले जाते हैं। आइएएस एसोसिएशन जैसे संगठन राजनीतिक दलों के आचरण पर सवाल खड़े कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन क्या उनसे तुलना करना सही है? क्योंकि राजनीतिक दलों के चंद नकचढ़े नुमाइंदों के बयान अब इसलिए नहीं चौंकाते कि यह पथभ्रष्ट आचरण अब आदत में आ चुका है। लोकलाज तोड़ती लोकसेवकों की कार्यशैली अब चिंता बढ़ाने लगी है। आज यह दोहराया जाना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी यदि आम नागरिक का अधिकार है, तो उसकी रक्षा का दायित्व लोकसेवकों को निभाना ही पड़ेगा।

समृद्धि की राह : कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री कमल नाथ ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश बुलाया था। राज्य सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि प्रदेश में पहली बार वास्तविक निवेश की संभावनाएं जमीन पर उतारी गई हैं। मुख्यमंत्री दावोस में हैं। अपने अनुभव और रिश्ते के आधार पर वे 4,000 करोड़ रुपये का निवेश लेकर आने का दावा कर रहे हैं। उधर, फिल्म सिटी की घोषणा को भी पर्यटन विकास की दिशा में नया कदम माना जा रहा है। विपक्ष चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस को तमाम राजनीतिक उलझनों के बीच प्रदेश के विकास का यह सिरा अभी तो सुलझता हुआ नजर आ रहा है।

20 फीसद बच्चों, जिनकी उम्र दो साल से कम है, के पास ही जन्म प्रमाणपत्र है। यह जानकारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में दी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2015 और 2016 में 68 लाख नवजात शिशु पंजीकृत नहीं किए गए।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 26 जनवरी 2020

जम्मू-कश्मीर

जग रही है विकास की उम्मीद

आमतौर पर देश के लगभग सभी राज्यों के सभी इलाकों में केंद्रीय मंत्री वहां के लोगों की समस्याओं को जानने-समझने और उनका समाधान करने के लिए जाते रहे हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर के मामले में यह बात कुछ हद तक जुदा रही है। उसकी भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों की अब तक की विकटता के कारण वहां ऐसा बहुत कम ही देखा गया कि कोई केंद्रीय मंत्री वहां के लोगों की समस्याओं को जानने-समझने के लिए उनके नजदीक तक पहुंचा हो।

ऐसे में यदि राज्य में केंद्र के मंत्री एक के बाद एक बड़ी संख्या में उनकी सुध लेने के लिए पहुंचें तो फिर लोगों में विकास की उम्मीद जगना स्वाभाविक है। एक सप्ताह में केंद्र से 36 मंत्री जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में गए और वहां विकास कार्यों के उद्घाटन करने के अलावा लोगों की समस्याओं को जानने के लिए उनके साथ सीधा संवाद किया। यह पहली बार था कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री जम्मू-कश्मीर आए और लोगों से रूबरू हुए। सात दिवसीय मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के 60 ब्लॉक में लोगों के बीच गए केंद्रीय मंत्री लोगों को यह संदेश दे गए कि उन्होंने जो समस्याएं उठाई हैं, उनका लेखा-जोखा प्रधानमंत्री को सौंप कर जल्द यहां के विकास को लेकर उनकी उम्मीदों के अनुरूप नीति बनाई जाएगी। यह सर्वविदित है कि केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात तनावपूर्ण रहे हैं और सरकार को कई प्रतिबंध भी लगाने पड़े। अच्छी बात यह है कि कुछ महीने में ही यहां की स्थिति सामान्य होने लगी। यह सुधरे हालात का ही परिणाम है कि पहले सरकार ने कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाए और फिर लैंडलाइन सेवा बहाल की। एक दिन पहले ही मोबाइल इंटरनेट भी शुरू कर दी गई। यह सब सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से किया और यह सुनिश्चित किया कि इस दौरान कहीं पर भी कोई हिंसा न हो। इन सभी कदमों के बीच केंद्रीय मंत्रियों के दौरों ने लोगों में नया विश्वास जगाने का काम किया। लोगों में संदेश गया है कि सरकार उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूल समस्याओं के समाधान के लिए खुद केंद्र से मंत्री आ रहे हैं।

राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति और राजनीतिक दशा के कारण जनता की सुध लेने नेता कम ही उन तक पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है

लेकिन अगर सरकार को लोगों के विश्वास को बरकरार रखना है तो केंद्रीय मंत्रियों के इन दौरों को एक अंतराल के बाद फिर से करवाने की जरूरत है ताकि लोगों ने अपनी जो समस्याएं उन्हें बताई है, उन्हें लगे कि उनका समाधान करवाने के लिए सरकार गंभीर है। अभी तक यह देखा गया है कि मंत्री व अधिकारी एक बार जाने के बाद फिर से सुध लेने के लिए नहीं आते हैं। इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के स्थानीय प्राधिकरणों को भी आपस में तालमेल बनाए रखना होगा ताकि केंद्र से पर्याप्त सहयोग मिलता रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

बंगाल

पांच लाख वाहनों पर बकाया कर

अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि देश के किसी खास इलाके या राज्य में या फिर जिले में बड़ी संख्या में वाहन बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। हालांकि संबंधित विभाग और वाहन मालिकों की मिलीभगत से सबकुछ सामान्य दिखता है। जहां तक बात रोड टैक्स जमा करने की है तो बड़ी संख्या में वाहन मालिक इसकी अदायगी समय पर संबंधित सरकारी एजेंसी को नहीं करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि वह संबंधित सरकारी एजेंसी भी इस दिशा में ठोस कार्रवाई करती हुई नहीं दिखती है ताकि लोग इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ईमानदारी से टैक्स जमा करें।

हालांकि अनेक राज्यों में यह सामने आया है कि वहां बड़ी संख्या में लोगों ने वाहन टैक्स समय से नहीं जमा कराया है, लेकिन बंगाल में इस संबंध में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि राज्य में चलने वाले करीब पांच लाख वाहनों पर कर यानी टैक्स बकाया है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें साढ़े तीन लाख ऐसे वाहन हैं जो समय पर रोड टैक्स नहीं दे रहे हैं। वहीं बिना सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस (सीएफ) लिए हुए डेढ़ लाख गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल के परिवहन विभाग वाहनों और लोगों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। यदि डेढ़ लाख गाड़ियां बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रही हैं, तो यह लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। इसमें निजी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मालवाही गाड़ियां शामिल हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक पांच लाख गाड़ियों पर करीब 500 करोड़ रुपये का कर बकाया हो चुका है। अब ऐसे वाहनों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। यह होना भी चाहिए। हाल ही में इस संबंध में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के बड़े महानगरों में कोलकाता में सड़क दुर्घटनाएं पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई हैं। देश के कई बड़े शहरों में जहां सड़क दुर्घटना की संख्या में लगातार कमी आ रही है, वहीं कोलकाता में इसमें बढ़ोतरी ही हुई है।

प्रतीकात्मक फोटो।

इस बीच राज्य परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को नोटिस भेज कर 31 जनवरी तक बकाया टैक्स भुगतान करने का निर्देश दिया है। यदि इसके बाद भी वे लोग टैक्स जमा नहीं करते हैं तो वाहनों की धड़पकड़ शुरू की जाएगी। परंतु यहां सवाल यह उठ रहा है कि दो-चार दिन या फिर एक-दो माह में पांच सौ करोड़ रुपये का कर बकाया तो हुआ नहीं होगा? यह लंबे समय से चल रहा था तो परिवहन विभाग ने पहले क्यों नहीं कार्रवाई शुरू की? यदि बिना सीएफ के ही सड़कों पर वाहन दौड़ रहे थे तो सरकार के पास यह डाटा ही नहीं होगा कि इनमें से कितने वाहन 15 वर्ष या उससे भी अधिक पुराने हैं? यह एक तरह से 15 वर्ष पुराने वाहनों पर हाई कोर्ट द्वारा लगी रोक के आदेश की भी तौहीन है। सीएफ के बिना चलने वाले वाहन सिर्फ लोगों की जान के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरनाक हैं, क्योंकि वैसे भी कोलकाता और आस-पास के जिलों में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी खराब होने के कगार पर पहुंच चुका है। इनमें से हावड़ा में तो दिल्ली से भी दयनीय स्थिति हो चुकी है। क्या राज्य सरकार को पता नहीं था कि राज्य में अवैध वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पर सरकार का नियंत्रण नहीं के बराबर है। उसे परिवहन कानून के दायरे में लाने के लिए क्यों नहीं पहले ही ठोस कदम उठाए गए? इस पर परिवहन विभाग से लेकर पुलिस तक को गंभीरता से कार्य करना होगा।

झारखंड

शिक्षक पात्रता परीक्षा में देरी

शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में बीते वर्षों के दौरान बीएड की डिग्री के साथ ही सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य कर दिया गया। लिहाजा राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) नियमित रूप से आयोजित हो रही है। 14वीं सीटेट की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे इतर झारखंड में महज दो ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हो पाई है। पिछले चार वर्षों से यह परीक्षा लंबित है। इसका खामियाजा शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हजारों अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। इससे ना केवल राज्य में शिक्षा की स्थिति पर असर पड़ रहा है, बल्कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में भी दिक्कतें बढ़ रही हैं।

हालांकि झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं में देरी कोई नई बात नहीं है। जेपीएससी की छठी सिविल सेवा परीक्षा खुद में उदाहरण है जो पांच वर्ष से लंबित है। इससे जहां एक ओर प्रतिभावान छात्र-छात्राओं में निराशा की भावना पनप रही है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें तो पहली और दूसरी परीक्षा भी समय पर पूरी नहीं हो पाई थी। इसके लिए सिर्फ झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही जिम्मेदार नहीं है। तीसरी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली में संशोधन किया गया, और उसमें भी लंबा समय लगा। एक बार ठोस और सटीक नियमावली नहीं बनने से भी इसमें बार-बार संशोधन करना पड़ा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमित नहीं होने से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी बढ़ती उम्र के साथ जहां हताश हो रहे हैं, वहीं शिक्षकों की कमी का असर स्कूली शिक्षा पर पड़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सरकार राज्य के हित में निश्चित रूप से इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देगी और समय पर परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा। उम्मीद इसलिए भी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गठन के साथ ही तमाम रिक्तियों को भरने का वादा दोहराया है। आवश्यकता है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित नियुक्ति नियमावलियों के शीघ्र गठन, पदों के सृजन तथा आरक्षण रोस्टर निर्धारित करने का। साथ ही समय पर संबंधित एजेंसियों को रिक्तियां भेजने की भी जरूरत है। आवश्यकता इसकी भी है कि संबंधित आयोग और एजेंसी भी समय पर विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करे तथा परीक्षाओं के आयोजन में तेजी लाए। शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू होगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।

प्रतीकात्मक फोटो।

उत्तराखंड

विद्यालयों को मिले पर्याप्त अनुदान

आज देश के विभिन्न राज्यों में स्कूली शिक्षा के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इतना ही नहीं, अनेक अशासकीय विद्यालयों को पर्याप्त अनुदान नहीं मिल पाने के कारण बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। यदि हम बात खास तौर पर उत्तराखंड की करें तो राज्य में अशासकीय विद्यालयों को मान्यता और अनुदान सूची में शामिल करने के बारे में सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो पा रहा है। कक्षा एक से आठवीं तक अशासकीय विद्यालयों को मान्यता देने के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी प्रावधान हैं, इसके बावजूद शिक्षा महकमा ऐसे मामलों को निस्तारित करने में ढुलमुल रवैया अपना रहा है। इसी तरह गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने के लिए करीब 26 मानक तय किए गए हैं। इस संबंध में करीब तीन वर्ष पहले शासनादेश जारी हो चुका है, लेकिन इसका पालन खुद महकमा नहीं कर रहा है। विद्यालयों को पूर्ण अनुदान देने की व्यवस्था से सरकार कदम पीछे खींच चुकी है। इसके स्थान पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रविधान किया गया है। दरअसल राज्य में बड़ी संख्या में अशासकीय विद्यालयों की ओर से सरकार से अनुदान की मांग की जा रही है। तकरीबन सौ विद्यालय कतार में खड़े हैं, जबकि करीब 200 विद्यालयों को अनुदान सूची में सशर्त शामिल किया गया है। अब ये विद्यालय अनुदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर विद्यालयों को अभी तक अनुदान नहीं मिला है। इस बारे में खुद महकमे के भीतर ऊहापोह तो है ही, साथ ही हालात भी निरंतर विकट हो रहे हैं। प्रदेश में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक बड़ी संख्या में खोले गए विद्यालयों पर कम छात्र संख्या की वजह से बंदी की तलवार लटकी है। अब तक कई विद्यालय बंद हो चुके हैं। आश्चर्यजनक तरीके से दूरदराज के सरकारी विद्यालयों में भी छात्र संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों की संख्या में इजाफा होने से सबसे ज्यादा मुश्किलें सरकारी विद्यालयों को ही पेश आना तय है। कभी शिक्षा के प्रसार और उसके स्तर को सुधारने में बड़ा योगदान करने वाले सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों की मौजूदा हालत अच्छी नहीं कही जा सकती। सरकारी अनुदान हासिल कर चुके ये विद्यालय अपने पास मौजूद संसाधनों का बेहतर उपयोग और प्रबंधन में पिछड़ते दिख रहे हैं। इस गंभीर समस्या से शिक्षा महकमा भी वाकिफ है, लेकिन समाधान उसके पास भी नहीं है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री यदि विद्यालयों को आंख-मूंदकर अनुदान देने के पक्ष में नहीं है तो इसकी बड़ी वजह यही है। उच्चस्तरीय बैठक में मानकों को पूरा नहीं करने के बावजूद अनुदान हासिल करने वाले विद्यालयों पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि विद्यालयों को अनुदान देने के बारे में ठोस नीति अमल में लाई जाएगी।

विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने या मान्यता देने में मानकों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इस मामले में सरकार का सख्त रुख अच्छा संकेत है

चिंताजनक : गंगा के पर्यावरण प्रवाह पर खतरे की आहट

जागरण पड़ताल

केदार दत्त, देहरादून

उत्तराखंड में गंगा के पर्यावरण प्रवाह (ई-फ्लो) को लेकर फिलहाल चिंता वाली बात भले न हो, लेकिन गंगा पर बने बांधों से तय मात्रा में पानी छोड़ने पर कंपनियों की ना-नुकुर ने भविष्य के लिए खतरे की आहट दे दी है। बांध संचालक कंपनियां, केंद्र सरकार के उस आदेश से बेचैन हैं, जिसमें गंगा व उसकी सहायक नदियों पर स्थित बांधों से हर साल तीन सीजन में 20 से 30 फीसद पानी छोड़ना अनिवार्य किया गया है। दो कंपनियों एनएचपीसी और एएचपीसीएल ने इसे मानने में हाथ खड़े कर दिए हैं। अन्य कंपनियों ने भी आपत्ति जताई है। इस परिदृश्य के मद्देनजर हरकत में आई सरकार ने केंद्र का ध्यान इस तरफ खींचा है।

गंगा के ऊपरी हिस्से (अपर गंगा बेसिन) में अधिक जलविद्युत परियाजनाओं के कारण डाउन स्ट्रीम में पानी कम होने से उत्पन्न दिक्कतों का नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने संज्ञान लिया। जोर दिया गया कि गंगा के समुचित पर्यावरण प्रवाह (जलीय जीवन के लिए पर्याप्त पानी) के साथ प्रदूषण निवारण के लिए मौसमी भिन्नताओं को बदले बिना गंगा में जल प्रवाह की निरंतरता आवश्यक है। विशेषज्ञ समिति के अध्ययन के बाद जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन) ने नौ अक्टूबर 2018 को एक आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, ऊपरी गंगा बेसिन में नवंबर से मार्च तक 20 फीसद, अक्टूबर, अप्रैल व मई में 25 फीसद और जून से सितंबर तक 30 फीसद जल प्रवाह सुनिश्चित होगा। इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय जल आयोग को नोडल एजेंसी नामित किया गया।

15 दिसंबर, 2019 से अनिवार्य किए गए इस आदेश के बाद उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं संचालित कर रही कंपनियों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। उत्तराखंड जल विद्युत निगम (यूजेवीएन) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कंपनियों का तर्क है कि 20 से 30 फीसद जल प्रवाह छोड़ने पर उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। एनएचपीसी ने इस गाइडलाइन को मानने से इन्कार कर दिया। वहीं, जल आयोग के अनुसार श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर प्रोजेक्ट संचालित कर रही अलकनंदा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि. भी मानकों का पालन नहीं कर रही। दूसरी तरफ, सरकारी व निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी आपत्ति दर्ज कराई कि उन्हें 15 से 20 फीसद तक राजस्व की क्षति होगी।

आठ प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग : केंद्रीय जल आयोग का हिमालयन गंगा डिवीजन वर्तमान में गंगा पर बने आठ हाइड्रो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहा है। हिमालयन गंगा डिवीजन के अधिशासी अभियंता एके सिंघल के अनुसार जिन प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जा रही, उनमें विष्णुप्रयाग, श्रीनगर, मनेरी भाली-प्रथम व द्वितीय, टिहरी, कोटेश्वर, पशुलोक, भीमगौड़ा शामिल हैं। श्रीनगर प्रोजेक्ट को छोड़ अन्य सभी कंपनियां तय मात्रा में पानी छोड़ रही हैं। ऐसे में श्रीनगर प्रोजेक्ट की संचालक कंपनी को निरंतर पांच दिन के अंतराल में नोटिस भेजे जा रहे हैं।

फिलहाल गंगा में नहीं दिक्कत : हिमालयन गंगा डिवीजन के अधिशासी अभियंता सिंघल के अनुसार, फिलहाल गंगा के ई-फ्लो को लेकर दिक्कत वाली बात नहीं है। देवप्रयाग का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि 2018 में 15 से 31 दिसंबर तक वहां गंगा का प्रवाह 645.80 क्यूसेक था। 2019 में इसी अवधि में यह 409.96 क्यूसेक आंका गया, लेकिन इसकी वजह बांधों से कम पानी छोड़ा जाना नहीं बल्कि बारिश कम होना रहा।

सरकार ने केंद्र को भेजा पत्र : यूजेवीएन के एक आला अधिकारी के मुताबिक कंपनियों की आपत्तियों के क्रम में राज्य सरकार की ओर से केंद्र को पत्र भेजा है। इसमें गंगा व उसकी सहायक नदियों पर बने बांधों से जल प्रवाह छोड़ने के मद्देनजर पूर्व में गठित विशेषज्ञ समिति-दो की सिफारिशों पर सहमति जताई गई है। इस समिति ने प्रति माह के हिसाब से जल प्रवाह छोड़ने की सिफारिश की है।

- केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार गंगा व उसकी सहायक नदियों पर बने बांधों से छोड़ा जाना है 20 से 30 फीसद पानी
- एनएचपीसी व एएचपीसीएल का इस गाइडलाइन को मानने से इन्कार, एनएचपीसी के मामले में जांच कमेटी गठित

प्रतीकात्मक

गंगा पर बनी इन बड़ी परियोजनाओं पर पड़ेगा असर

परियोजना	क्षमता (मेगावाट में)
चीला	144
मनेरी भाली-प्रथम	90
मनेरी भाली-द्वितीय	304
टिहरी	1000
कोटेश्वर	400
विष्णुप्रयाग	400
श्रीनगर	330

कमेटी करेगी पड़ताल

यूजेवीएन के प्रबंध निदेशक एसएन वर्मा के मुताबिक एनएचपीसी के पानी छोड़ने से इन्कार करने पर एक समिति गठित की गई है। यह समिति धौलीगंगा व शारदा नदी (टनकपुर) पर एनएचपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जाकर यह देखेगी कि तय मात्रा में वहां से पानी छोड़ा जा सकता है या नहीं। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को इससे अवगत कराया जाएगा।

राज्य में हैं 38 परियोजनाएं

उत्तराखंड में सरकारी और निजी क्षेत्र की 38 जल विद्युत परियोजनाएं वर्तमान में विभिन्न नदियों पर संचालित हैं। इनकी क्षमता 4000 मेगावाट है। इसके अलावा 2357 मेगावाट की 13 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

स्पीच थेरेपी से पहले जाननी होगी मरीज की भाषा

जागरण संवाददाता, लखनऊ

- भाषा डालती है दिमाग की सक्रियता पर प्रभाव

भाषा का प्रभाव दिमाग की सक्रियता पर पड़ता है। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआइ के सेंटर फॉर बॉयोमेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक डॉ. उत्तम कुमार की शोध में यह तथ्य सामने आया है। इसमें यह भी साबित हुआ है कि स्पीच थेरेपी देते समय जानना जरूरी है कि मरीज किस भाषा का जानकार रहा है।

इसके लिए डॉ. उत्तम कुमार ने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जानने वाले लोगों पर अध्ययन किया। इसमें ये तथ्य सामने आए। डॉ. उत्तम कुमार के मुताबिक, हमारा मस्तिष्क न्यूरान्स से बना होता है। इसमें करीब 86 अरब न्यूरान्स होते हैं। वे एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे आप आसान भाषा में ब्रेन सर्किट भी कह सकते हैं। एक तरह से यह मस्तिष्क की नेटवर्किंग है। इस सर्किट के बहुत सारे हिस्से होते हैं। ये मिलकर एक प्रॉसेसर जैसा काम करते हैं। अध्ययन में 20 हिंदी भाषियों को लिया गया, जो अंग्रेजी और उर्दू नहीं जानते थे। इनकी ब्रेन मैपिंग की गई, तो पता चला कि हिंदी पढ़ते समय दिमाग का पृष्ठ भाग यानी ऊपरी हिस्सा ज्यादा सक्रिय रहा। उर्दू पढ़ते समय दिमाग के पृष्ठ भाग यानी ऊपरी हिस्से के साथ निचला हिस्सा भी सक्रिय रहता है। दोनों हिस्से सक्रिय होने से इनके दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ता है।

लखनऊ का संजय गांधी पीजीआइ। फाइल

उर्दू भाषी को ज्यादा देर तक स्पीच थेरेपी देने की जरूरत

अपने अध्ययन डॉ. उत्तम कुमार ने पाया कि पैरालिसिस होने, शब्दों को समझने में दिक्कत होने, सिर में चोट होने पर उर्दू भाषियों की स्पीच थेरेपी आसान नहीं होती। इसलिए अध्ययन के आए नतीजों के बाद इनके लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। हिंदी व अंग्रेजी भाषियों की अपेक्षा इन्हें ज्यादा देर तक स्पीच थेरेपी देनी चाहिए।

चंपावत के बाणासुर किले को पर्यटन हब के रूप में विकसित किए जाने की तैयारी

विनोद कुमार चतुर्वेदी, चंपावत

- किले में रिटेनिंग वॉल, रास्तों और क्षतिग्रस्त भवनों की होगी मरम्मत
- पर्यटन विभाग ने भेजा 80 लाख रुपये का प्रस्ताव

उत्तराखंड में पर्यटन विभाग चंपावत के उपेक्षित पड़े पर्यटक स्थलों को विकसित कर यहां अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना तैयार कर रहा है। इसमें ऐतिहासिक बाणासुर किला भी शामिल है। किले का विकास कर यहां पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए विभाग ने 80 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है।

लोहाघाट-खेतीखान मार्ग पर लोहाघाट से छह किमी दूर कर्णकरायत से एक किमी ऊपर और समुद्र तल से 1900 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित है बाणासुर किला। देवासुर संग्राम से जुड़े इस किले को देखने के लिए प्रतिवर्ष सैकड़ों पर्यटक यहां पहुंचते हैं। बाणासुर किला अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी काफी महत्वपूर्ण है। किले से 360 डिग्री में दूर-दूर तक नजारा देखा जा सकता है। चोटी पर लगभग 90 मीटर लंबे और 20 से 25 मीटर चौड़ाई के आकार में बने हुए किले के अवशेष आज भी मौजूद हैं। किले के पूर्व एवं उत्तर दिशा में हिमालय की धवल श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। नेपाल की चोटियों से लेकर चौखंभा तक की चोटियां भी आसानी से दिख जाती हैं। किले तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। बुनियादी सुविधाएं न होने से यहां अपेक्षा के अनुरूप पर्यटक नहीं आ पाते। पर्यटन विभाग ने किले के विकास की योजना तैयार की है। विभाग यहां व्यू प्वाइंट तैयार करने के साथ रास्तों की मरम्मत, रिटेनिंग वॉल और ऐतिहासिक महत्व के क्षतिग्रस्त भवन अवशेषों की मरम्मत के लिए 80 लाख रुपया खर्च करेगा। जिला पर्यटक अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि इसके साथ ही राजबुंगा किले को विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है।

चंपावत का ऐतिहासिक बाणासुर किला। फाइल

उत्तराखंड में मगरमच्छ, घड़ियाल व ऊदबिलाव गणना 22 फरवरी से

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड में पहली बार होने जा रही मगरमच्छ, घड़ियाल और ऊदबिलाव की गणना का शेड्यूल तय कर दिया गया है। यह गणना 22 से 24 फरवरी को होगी। इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) और विश्व प्रकृति निधि (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की मदद ली जाएगी। महकमे की कोशिश है कि गणना कार्य पूरा होने पर दो सप्ताह के भीतर इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

वर्ष 2008 में कार्बेट टाइगर रिजर्व में मगरमच्छ व घड़ियालों की गणना हुई थी, लेकिन राज्य के अन्य क्षेत्र इससे अछूते रह गए थे, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी इनकी अच्छी-खासी संख्या है। अब महकमे ने पहली बार राज्य स्तर पर मगरमच्छ व घड़ियाल के साथ ही ऊदबिलावों की गणना कराने का निर्णय लिया है। लंबी कसरत के बाद अब इसका शेड्यूल तय कर दिया गया है। राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजीव भरतरी के मुताबिक मगरमच्छ, घड़ियाल व ऊदबिलाव की गणना 22 से 24 फरवरी तक चलेगी। कार्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व के अलावा अन्य संरक्षित क्षेत्रों व वन प्रभागों में इन जलीय जंतुओं की गणना की जाएगी।

पासपोर्ट के लिए फर्जी वेबसाइट्स से बचाने को विदेश मंत्रालय की नई पहल

राज्य ब्यूरो, भोपाल

- आधा दर्जन धोखेबाज वेबसाइट्स के नाम किए जारी

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक नागरिकों को फर्जी वेबसाइट्स से बचाने के लिए नई पहल की है। दरअसल, पासपोर्ट बनाने की आसान व ऑनलाइन प्रक्रिया से दलालों व एजेंटों की लगभग छुट्टी हो गई है, लेकिन वह बाज नहीं आ रहे। उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट से मिलते-जुलते नामों की करीब आधा दर्जन फर्जी वेबसाइट्स बना ली हैं। इनके जरिये आवेदकों को ठग रहे धोखेबाजों के खिलाफ विदेश मंत्रालय ने एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकृत वेबसाइट में कुछ फीचर बदले गए हैं। फर्जी वेबसाइट्स के नाम दर्शाते हुए उनसे सतर्क रहने की समझाइश भी दी है।

विदेश मंत्रालय ने देश के सभी पासपोर्ट कार्यालयों के लिए भी एडवायजरी जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी विभाग (डाईटी) द्वारा भी एडवायजरी जारी की जा रही है। मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि फर्जी वेबसाइट्स के जरिये आवेदकों के साथ ठगी हो रही है। ये फर्जी वेबसाइट्स बतौर प्रॉक्सी साइट्स और प्रॉक्सी एजेंट्स के रूप में काम कर रही हैं। ये पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक लोगों को ठग रहे हैं।

अधिकृत वेबसाइट पर आएगा पहले अलर्ट का मैसेज : ठगी से बचाने के लिए विदेश मंत्रालय ने अपनी अधिकृत वेबसाइट (पासपोर्ट इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन) पर स्थायी रूप से अलर्ट प्रदर्शित कर दिया है। वेबसाइट खोलते ही सबसे पहले यही सूचना दिखती है, उसे बंद करने के बाद ही होम पेज खुलता है।

1500 के बजाये ले लेते हैं 5000-6000 रुपये : मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मिलते-जुलते नाम की वेबसाइट्स पर कोई व्यक्ति गलती से आवेदन कर देता है तो उसके साथ दो तरह से ठगी हो रही है। एक तो संबंधित वेबसाइट 1500 रुपये की अधिकृत फीस के बजाय आवेदक से 5000-6000 रुपये और सारा डेटा लेकर विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन कर अपाइंटमेंट ले लेते हैं। दूसरा यह कि जालसाजों की वेबसाइट पूरे पैसे हड़पकर आवेदकों को अपाइंटमेंट की झूठी तारीख दे देती हैं, इसलिए प्रॉक्सी साइट, प्रॉक्सी एजेंट्स व फर्जी वेबसाइट से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा एसएमएस के जरिये अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं।

जागरूकता ही बचाव : बघेल : भोपाल स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल ने बताया कि जागरूकता ही बचाव है। इसलिए आवेदक अधिकृत वेबसाइट की पुष्टि के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें।

ये हैं फर्जी वेबसाइट्स के नाम : डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंडिया पासपोर्ट डॉट ओआरजी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ऑनलाइन पासपोर्ट इंडिया डॉट कॉम, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पासपोर्ट पोर्टल डॉट इन, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पासपोर्ट-इंडिया डॉट इन, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पासपोर्ट-सेवा डॉट इन।

प्रतीकात्मक

47 वर्ष पुराने नाइकी के स्पोर्ट्स शूज की एक जोड़ी हाल ही में चार लाख 37 हजार 500 डॉलर (करीब तीन करोड़ 12 लाख रुपये) में नीलाम हुई है। यह जूते इसलिए ऐतिहासिक हैं क्योंकि नाइकी के सह संस्थापक बिल बोवरमैन ने स्वयं इसे डिजाइन कर बनाया था।

बाल अधिकारों को चित्रों के माध्यम से उकेरतीं रिया

सुर्खियों में

अंजली राय, भोपाल

सेंट जोसफ को-एड स्कूल की छात्रा रिया जैन ने पांचवीं कक्षा से जब पेंटिंग की शुरुआत की तो कभी सोचा भी न था कि इसके जरिये वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिल सकेंगी, लेकिन आज जब वह 11वीं में हैं तब अपने इस हुनर की वजह से उन्हें कला व संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक लाख रुपये की नकद राशि, टैबलेट, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली रिया जैन अपनी पेंटिंग के जरिये समाज को जागरूक करती हैं। वह अपनी पेंटिंग में बाल अधिकार संरक्षण, बाल विवाह, बाल श्रम, कुपोषण जैसे मुद्दों को बच्चों के जीवन से जोड़ते हुए दर्शाती हैं। रिया ने इस पुरस्कार के लिए 230 प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन किया था। वह अब तक पेंटिंग के लिए 100 पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। इनमें आठ अंतरराष्ट्रीय, 20 राष्ट्रीय और 72 जिला और राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं।

पुरस्कार के बाद उत्साह हुआ दोगुना: रिया ने बताया कि बाल शक्ति पुरस्कार मिलने के बाद अब उत्साह और बढ़ गया है। अब अपनी कला के जरिये समाज को और अधिक जागरूक करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि पेंटिंग के जरिये समाज में हो रहे बदलाव और अन्याय को एक कलाकार ही बखूबी उभार सकता है।

अभिभावकों का मिलता है सहयोग: रिया ने बताया कि उनके पिता श्रेयांश जैन कारोबारी हैं और मां रजनी जैन गृहिणी। दोनों से उन्हें काफी सहयोग मिलता है। उन्हें निबंध लेखन में भी राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिल चुका है। वह कहती हैं कि अभिभावकों ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उनका मानना है कि अभिभावकों को कभी भी बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें बच्चों को अपनी दिशा में आगे बढ़ने देना चाहिए।

बनाया है एक बहुपयोगी छाता: रिया ने एक बहुपयोगी छाता बनाकर प्रदर्शनी में लगाया था, जिसकी चर्चा खूब हुई थी। छाते में रोशनी के लिए टॉर्च, गर्मी से बचने के लिए पंखा और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगा हुआ था। यह छाता धूप और बारिश से तो बचाता ही है साथ ही जरूरत पड़ने पर हवा भी देता है। इसे एयर कंडीशनर छाता नाम दिया। छाते में बैट्री लगी थी और उसे चार्ज करने के लिए छाते के ऊपर ही एक सोलर प्लेट भी लगी है।

खेल-खेल में तीरंदाजी से संचिता ने बनाई पहचान

बीते दिनों देश के 49 बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली रिया जैन और दिल्ली की संचिता तिवारी ने भी यह पुरस्कार हासिल किया। एक को जहां कला, तो दूसरी को तीरंदाजी के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। जानते हैं दोनों ने कैसे शुरू किया वो सफर, जो उन्हें इस पुरस्कार तक ले गया...

मेडल और ट्रॉफियों के साथ भोपाल की रिया जैन। फाइल

दिल्ली की संचिता तिवारी। सौजन्य : परिजन

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली

इरादे मजबूत और हौसले बुलंद हों तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली की रहने वाली संचिता तिवारी इसकी मिसाल हैं, जिनकी प्रतिभा का हर कोई कायल है। महज चार साल पहले स्कूल में खेल-खेल में तीरंदाजी में हाथ आजमाने वाली संचिता तिवारी को यह पता ही नहीं चला कि कब यह उनका शौक बन गया। मयूर विहार स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं कक्षा की इस छात्रा ने अपने हुनर की बदौलत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बाल शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया है। वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अभिषेक वर्मा को अपना आदर्श मानती हैं।

झांसी की रानी हैं पसंद: शुरुआती दिनों के बारे में संचिता बताती हैं वह दूसरे बच्चों को तीरंदाजी करते देखती थीं। जब उन्हें पता चला कि धनुष-बाण काफी पुराना खेल है तो वह इसकी ओर आकर्षित हुईं। इसके पीछे का राज खोलते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मी बाई बचपन से ही काफी पसंद रही हैं और उन्हीं की तरह वह बहादुर बनना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने माता-पिता से तीरंदाजी के लिए अनुमति मांगी और उन्होंने भी बेटी को फौरन अनुमति दे दी।

रियलिटी डांस शो में भी भाग ले चुकी हैं: संचिता के मुताबिक, बचपन में वह कथक करती थीं और इंडिया डांसिंग सुपरस्टार की प्रतिभागी भी रही हैं। उन्होंने अब तक डांस, एंकरिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पेंटिंग, डिबेट आदि में 250 से भी ज्यादा मेडल और सर्टिफिकेट जीते हैं। संचिता बताती हैं कि उनके कोच लोकेश चंद उन्हें रोज तीरंदाजी का प्रशिक्षण देते हैं और उनके बेहतर प्रशिक्षण की वजह से ही वह आज इस पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। इसके साथ ही वह पुरस्कार का सारा श्रेय माता-पिता और बड़े भाई आशुतोष को देती हैं।

40 मेडल कर चुकी हैं अपने नाम

संचिता ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया है और अब तक वह 40 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। इनमें 15 अंतराष्ट्रीय, तीन राष्ट्रीय और 22 राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब पहले खेलो इंडिया के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मुझे मशाल ग्रहण करने का मौका मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

मनोज तिवारी : घरेलू क्रिकेट का असली खिलाड़ी

चर्चित चेहरा

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

गत 20 जनवरी को हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के ग्रुप-बी में तिहरा शतक जमाने के बाद मनोज तिवारी ने कुछ इस अंदाज में अभिवादन स्वीकार किया था। फाइल

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भले ही वह गहरी छाप न छोड़ पाए हों, लेकिन घरेलू क्रिकेट के असली खिलाड़ी तो वही हैं। इस बात को उन्होंने पिछले दिनों हैदराबाद के खिलाफ रणजी मैच में नाबाद 303 रनों की नायाब पारी खेलकर एक बार फिर साबित किया है। ये हैं 34 साल के मनोज तिवारी। बंगाल क्रिकेट का चर्चित चेहरा। मनोज ने अपने अब तक के क्रिकेट करियर में जितने उतार-चढ़ाव देखे हैं उतने शायद ही किसी और ने देखे हों, लेकिन मजबूत हौसले के साथ आगे बढ़ते रहने का जज्बा ही उनकी 'यूएसपी' है। एक क्रिकेटर के लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण वाले दिन ही उसे चोट लग जाए और वह सीधे मैच से बाहर हो जाए। मनोज ने वह दिन भी देखा, उसकी तकलीफ भी सही, लेकिन वह रुके नहीं क्योंकि उन्हें मालूम था कि किस्मत दूसरा मौका सबको देती है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें मौका मिल ही गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सफर लंबा नहीं हो पाया।

इसे चोट का नतीजा कहें या फिर चयनकर्ताओं की उपेक्षा, मनोज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया, जिसका उनकी प्रतिभा दावा करती है। प्रथम श्रेणी के 119 मैचों में 8752 रन यह बताने के लिए काफी हैं, जो उन्होंने 51.78 की औसत से बनाए हैं। इनमें 27 शतक शामिल हैं, जिनमें छह दोहरे शतक और एक तिहरा शतक भी है। ऐसा भी नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी झोली खाली रही है। मनोज ने 12 अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय मैचों में एक शतक व एक अर्धशतक लगाया है। इसके साथ ही पांच विकेट भी चटकाए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि शतकीय पारी के बावजूद अगले 14 मैचों में उन्हें मौका नहीं मिला।

दिल में बसता है एक शायर: बंगाल के हावड़ा के फारशोर रोड इलाके के रहने वाले मनोज का पहला प्यार भले ही क्रिकेट हो, लेकिन उनके दिल में एक शायर भी बसता है। दोस्तों के साथ शेर-ओ-शायरी करना उन्हें काफी पसंद है। वह बड़े चाव से शायरी सुनते हैं। उन्होंने कई शायरियां भी लिखी हैं, जिसे वह सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। मनोज को क्रिकेट के अलावा फुटबॉल और बास्केटबॉल काफी पसंद है। घूमने-फिरने के भी शौकीन हैं।

बल्ले पर लिख डाला बेटे का नाम: मनोज अच्छे क्रिकेटर होने के साथ एक जिम्मेदार पिता भी हैं। वह अपने नन्हे बेटे 'युवान' से इतना प्यार करते हैं कि अपने बल्ले पर उसका नाम ही लिख डाला है। मनोज उसे अपने लिए भाग्यशाली मानते हैं। परिवार में मां बीना तिवारी, पत्नी सुष्मिता तिवारी और एक साल आठ महीने का बेटा युवान है। पिता श्याम सुंदर तिवारी रेलकर्मी थे।

यूं पड़ गए थे विवाद में: यूं तो मनोज का विवादों से नाता न के बराबर रहा है, लेकिन पिछले दिनों वह भारतीय चयनकर्ता देवांग गांधी को लेकर एक विवाद में घिर गए थे। दरअसल, ईडन गार्डेंस स्टेडियम में रणजी मैच चलने के दौरान देवांग गांधी के ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करने पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए आइसीसी के उपस्थित अधिकारी से इसकी शिकायत कर दी थी। इसे लेकर काफी शोर मचा था। मनोज ने कहा था कि उन्होंने आइसीसी के नियमों का पालन करते हुए यह किया। संयोग की बात यह है कि इसके कुछ दिन बाद ही मनोज देवांग के बाद बंगाल से रणजी मैच में तिहरा शतक लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए।

क्रिकेट के 'कम बैक' मैन: मनोज वाकई में क्रिकेट के 'कम बैक' मैन हैं। चोट के बावजूद उन्होंने कई बार टीम इंडिया में वापसी की। हालांकि, उन्हें अंतिम एकादश में जगह नहीं मिल पाई। कुछ समय पहले बंगाल रणजी टीम की कप्तानी से खुद ही हटने वाले मनोज पर फिर से भरोसा जताते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें नए कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन की गैरमौजूदगी में फिर से कप्तानी सौंप दी है। मनोज दिल्ली के खिलाफ अगले रणजी मैच में एक बार फिर कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे। मनोज कहते हैं कि विफलता पर हताश होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अलग नजरिए से देखना जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भले ही वह ऊंचा मुकाम हासिल न कर पाए हों, लेकिन घरेलू क्रिकेट तो मानों उनके लिए ही हो। बात हो रही है मनोज तिवारी की, जिन्होंने हाल ही में हैदराबाद के खिलाफ रणजी मैच में तिहरा शतक लगाया है...

वकालत छोड़ थामी पिस्टल, सीधे पदक पर निशाना

उभरता सितारा

विजय गाहल्याण, पानीपत

दादी चंद्रो और प्रकाशी तोमर तो आपको याद ही होंगी। उम्र की जिस दहलीज पर अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी हौसला छोड़ने लगता है, उस उम्र में दोनों ने निशानेबाजी में ऐसे जौहर दिखाए कि दुनिया कायल हो गई। इसी दादी चंद्रो की कहानी अखबार में पढ़कर हरियाणा के पानीपत जिले की बेटी अनु वत्स ने वकालत को बीच में छोड़ हाथ में पिस्टल उठा ली और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दिग्गजों के बीच पदक जीत धमक कायम की।

वकालत कर जुटाए पैसे पिस्टल पर खर्च : पानीपत के सेक्टर-24 की रहने वाली 26 वर्षीय अनु वत्स के लिए निशानेबाजी की राह आसान नहीं रही। छह साल वकालत कर जोड़े गए पैसे अनु ने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिस्टल और प्रशिक्षण पर खर्च कर दिए। डेढ़ लाख रुपये की पिस्टल खरीदी। द्रोणाचार्य अकादमी में निशानेबाजी कोच जसबीर सिंह की शरण में पहुंच गईं। प्रतिदिन 10 से 12 घंटे तक अभ्यास किया। शुरू में अनु के इस फैसले से पिता रामेशवर और मां कमलेश खुश नहीं थे। उनकी चाह तो बस यही थी कि बेटी वकालत में बड़ा नाम कमाए, लेकिन जब बेटी ने पहले नार्थ जोन प्रतियोगिता में रजत और बाद में गत 21 से 24 दिसंबर तक भोपाल में हुई 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दिग्गज निशानेबाजों के बीच कांस्य पदक जीता, तो उनकी भी राय बदल गई।

अब वर्ल्ड कप शूटिंग में पदक का लक्ष्य : अनु के अनुसार, अब उनका लक्ष्य फरवरी 2020 में भारत में होने वाले शूटिंग वर्ल्ड कप में पदक जीतना है। इसके लिए 25 जनवरी से आठ फरवरी तक केरल के त्रिवेंद्रम में ट्रायल है। इसके लिए उन्होंने त्रिवेंद्रम में अभ्यास भी शुरू कर दिया है। छह से आठ फरवरी को वहीं प्रतियोगिता भी होनी है।

दो बहन और भाई भी करने लगे शूटिंग : अनु वत्स के कोच व द्रोणाचार्य अकादमी के संचालक जसबीर सिंह ने बताया कि अनु ने उनसे आठ महीने पहले कहा था कि नेशनल में पदक जीतना है। अच्छी तैयारी करा दें। पहले यकीन नहीं था कि अनु ऐसा कर दिखाएगी, लेकिन उसने कड़ा अभ्यास किया और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता जीती तो नेशनल में पदक की उम्मीद जगी। इसके बाद अभ्यास और भी कड़ा किया। अब अनु ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। अनु से प्रेरित होकर उनकी छोटी बहन रजनी, प्रियंका व भाई कार्तिक भी शूटिंग का रुख कर चुके हैं।

हरियाणा की अनु वत्स ने आठ माह पहले शूटर चंद्रो की खबर पढ़ी और वह इतना प्रभावित हुईं कि वकालत छोड़ शूटिंग के अभ्यास में जुट गईं, शुरुआत में माता-पिता का साथ नहीं मिला, लेकिन गत दिनों नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने के बाद सबने उनके फैसले को न केवल स्वीकार किया, बल्कि सलाम भी किया...

पानीपत की अनु वत्स। जागरण

रोज 500 गोली निशाने पर

अनु वत्स ने बताया कि हर रोज 500 गोलियां टारगेट पर दागती हैं। आठ माह में करीब पांच लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। एक निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी कर रही बड़ी बहन रजनी भी उनकी मदद कर रही हैं। वह पहली बार नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में शामिल हुई। इसमें ओलंपिक का कोटा प्राप्त कर चुकीं मनु भाकर, यशस्वी देशवाल सहित 30 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय शूटर सामने थीं। उसने हौसला रखा और 600 में से 568 का स्कोर कर कांस्य पदक जीत लिया। अब माता-पिता खुश हैं।

'होप' की दौड़ में सूफिया का रिकॉर्ड

इनसे मिलिए

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन ऐसे कम ही होते हैं जो खुद से बढ़कर देश और देश की एकता के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही एक नाम है राजस्थान के अजमेर की रहनी वाली 33 वर्षीय धावक सूफिया खान, जो बीते वर्ष 'मिशन होप' की वजह से सुर्खियों में थीं। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी 87 दिन, 2 घंटे और 17 मिनट में दौड़कर पूरी की थी। हाल ही में वह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जब उन्हें उनके इस मिशन की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से नवाजा गया है।

कुछ समय तक एक एयरलाइन कंपनी में नौकरी करने वाली सूफिया ने अपने दौड़ने के जज्बे को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ दी। मकसद था देश के लोगों से मिलकर एकता, भाईचारे, शांति और समानता का संदेश देना। इसी उद्देश्य से गत वर्ष 25 अप्रैल को उन्होंने मिशन होप की शुरुआत की। उनका लक्ष्य 100 दिनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के 22 शहरों से गुजरना और इस दौरान लोगों से मिलना था। होप यानी कि मानवता (ह्यूमेनिटी), एकता (वननेस), शांति (पीस) और समानता (इक्वेलिटी)। लक्ष्य 100 दिन का था, लेकिन 87 दिन में ही वह इसे पूरा करने में सफल हुईं। इस दौरान वह जिस भी शहर से गुजरीं वहां के लोगों ने उनका और उनकी इस पहल का स्वागत किया। बकौल सूफिया, उनके लिए इस दौड़ से ज्यादा लोगों से मिलना और उनसे बात करना ज्यादा अहम रहा।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट के साथ अजमेर की सूफिया खान। फाइल

वह कहती हैं कि वह जिस भी शहर में गईं वहां के लोग भी उनके साथ दौड़े। लोगों के इस साथ ने उनके हौसले को बढ़ाया, जिसकी बदौलत ही वह अपने लक्ष्य को जल्द हासिल कर पाईं।

सिर्फ मेरी जीत नहीं: हाल ही में सूफिया को जब उनके इस अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से नवाजा गया तो उनका कहना था कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो उनके इस अभियान में उनके साथ दौड़ा। हर वह व्यक्ति जिसने उनके इस अभियान की सराहना की। अपनी यात्रा के अनुभव के बारे में सूफिया का कहना था कि वह 22 शहरों से गुजरीं, जहां हर धर्म के लोग उनसे मिले। बकौल सूफिया, यात्रा के दौरान जिस तरह से वह हर धर्म के लोगों से मिलीं, वह सब उन्हें मानवता का संदेश दे रहा था। भारत अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों का देश है। आज, एक इंसान भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों, भाईचारे और संस्कृति से दूर जा रहा है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

राजस्थान के अजमेर की रहने वाली सूफिया खान को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से नवाजा गया है। उन्हें यह खिताब उनकी बीते वर्ष पूरी की गई उस दौड़ के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा को 87 दिनों में पूरा किया था...

पहले भी बना चुकी हैं रिकॉर्ड

वर्ष 2018 में भी सूफिया एक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। तब उन्होंने 16 दिनों में 720 किमी की दूरी को दौड़कर पूरा किया था। ऐसा करने वाली वह पहली महिला धावक बनी थीं। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया।

रोबोटिक हृदय के बाद नहीं होगी अंग प्रत्यारोपण की जरूरत

विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसा है कि जो इस सदी को मानव कल्याण की सदी में परिवर्तित कर रहा है। वैज्ञानिक नित नई तकनीकों को सामने ला रहे हैं, जिनके जरिये चिकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आने वाला है। माना जा रहा है कि रोबोटिक हृदय के बाद अंग प्रत्यारोपण से निजात मिल सकेगी।

8 वर्षों में अंग प्रत्यारोपण से निजात

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रोबोटिक हृदय के सामने आने के बाद आठ सालों में अंग प्रत्यारोपण की समस्या से निजात मिल जाएगी। नीदरलैंड, कैंब्रिज और लंदन के विशेषज्ञ मिलकर एक 'सॉफ्ट रोबोट' हृदय विकसित कर रहे हैं, जो कि शरीर के नजदीक खून के दौरे को नियमित रखेगा। उनका लक्ष्य तीन सालों में इसके कार्यशील नमूने को जानवरों में और उसके बाद 2028 तक मानवों में प्रत्यारोपित करना है।

ऐसे काम कर रही है टीम

ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की अगुआई वाली टीम आनुवंशिक हृदय दोषों को ठीक करने का तरीका विकसित करने पर काम कर रही है। कैम्ब्रिज और वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट की कोशिकाओं का मानचित्र बनाने में जुटी है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण का पता लगाया जा सके। बेल्जियम में कैथोलिक विश्वविद्यालय और शेफील्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में नई 'पहनने योग्य' तकनीक का निर्माण किया जा रहा है।

आमूलचूल बदलाव के दिख रहे संकेत

रोबोटिक दिल के साथ ही चुने गए प्रोजेक्ट्स में हृदय रोग के लिए टीका, हृदय के दोषों के लिए आनुवंशिक इलाज और इनमें सबसे बेहतरीन अगली पीढ़ी के लिए 'पहनने योग्य' तकनीक शामिल है, जो कि दिल का दौरा पड़ने और स्ट्रोक होने से पहले हो पता कर सकता है। यह तकनीक कई मायनों में आमूलचूल बदलाव लाने वाली होगी।

हाइब्रिड हार्ट प्रोजेक्ट

एम्सटर्डम विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 'हाइब्रिड हार्ट' प्रोजेक्ट सिंथेटिक रोबोटिक सामग्री का उपयोग करता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा स्वीकृत डिवाइस को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला में निर्मित मानव कोशिकाओं की परतों के साथ मिलकर हृदय के संकुचन को दोहराता है। यह एक वायरलेस बैट्री द्वारा संचालित होता है। यह सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह हृदय प्रत्यारोपण की जगह लेगा।

अरबों का है प्रोजेक्ट

यह उपकरण हृदय रोग के उपचार को बदलने के लिए तीन करोड़ पौंड (करीब दो अरब 79 करोड़ रुपये) की राशि के पुरस्कार के लिए चयनित चार परियोजनाओं में से एक है। हृदयवाहिनी से जुड़े बेहतरीन शोधकर्ताओं की टीम में ऑक्सफोर्ड, इंपीरियल कॉलेज लंदन, हार्वर्ड और शेफील्ड के विशेषज्ञों सहित दुनिया के कई अन्य बड़े शोधकर्ता शामिल हैं।

बीएचएफ का सबसे बड़ा निवेश

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन (बीएचएफ) तीन करोड़ पौंड के 'बिग बीट चैलेंज' का वित्त पोषण कर रहा है। उसे 40 देशों की टीमों से 75 आवेदन प्राप्त हुए थे। चार फाइनलिस्टों को आगामी छह माह में अपने विचारों को मूर्तरूप देने के लिए शुरुआती राशि के तौर पर 50 हजार पौंड दिए गए हैं। इनमें से एक को गर्मियों में मुख्य पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। यह बीएचएफ के 60 साल के इतिहास में विज्ञान को आगे बढ़ाने में अकेला सबसे बड़ा निवेश है।

वायरलेस चार्जिंग शरीर में मौजूद बैट्री बनियान या जैकेट में लगी डिवाइस से वायरलेस चार्ज की जा सकती है। जैकेट या बनियान उतारने पर यह एक घंटे तक काम कर सकती है।

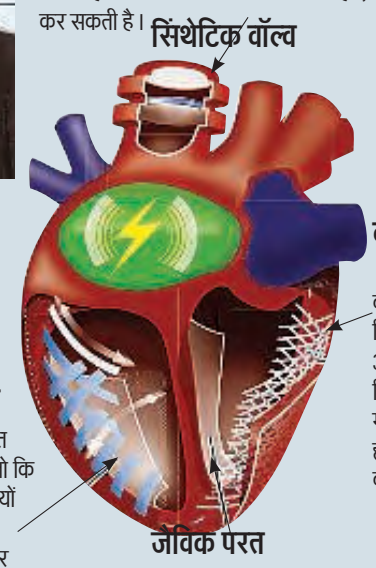

बाहरी परत यह मरीज की कोशिकाओं से निर्मित होती है और आश्वस्त करती है कि प्रतिरक्षा प्रणाली मरीज के रोबोटिक हृदय को स्वीकार करेगा।

कृत्रिम ऊतक नर्म, लेकिन मजबूत सिंथेटिक लेयर, जो कि हृदय की मांसपेशियों की नकल करता है। यह सिकुड़ और छोड़कर के रक्त को पंप करता है।

जैविक परत यह विशिष्ट रक्त कोशिकाओं को प्राप्त करती है, जो कि धीरे-धीरे नए ऊतकों का आकार देगी।

पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ी कटौती

नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम में लगातार गिरावट का फायदा घरेलू बाजार को मिल रहा है। शनिवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 27 पैसे और डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बड़ी कटौती की। इसके बाद नई दिल्ली में पेट्रोल 74.16 रुपये, मुंबई में 79.76 रुपये और कोलकाता में 76.77 रुपये प्रति लीटर का बिका। नई दिल्ली में डीजल का दाम 67.31 रुपये, मुंबई में 70.56 रुपये और कोलकाता में 69.67 रुपये प्रति लीटर रहा। (आइएएनएस)

देश का मोबिलिटी सॉल्यूशन अब पूरी तरह एक्सपीरिएंस आधारित होता जा रहा है। हमारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मुहिम भी उसी के इर्द-गिर्द है।

— वेणु श्रीनिवासन, चेयरमैन टीवीएस मोटर कंपनी

भारत के खिलाफ मामला वापस लेगा ब्राजील

फैसला ▶ ब्राजील के राष्ट्रपति व भारत के प्रधानमंत्री ने रखी मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों की नींव, 15 समझौते हुए

गन्ना किसानों के मुद्दे पर भारत के खिलाफ ब्राजील ने लगाई थी डब्ल्यूटीओ में गुहार

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

भारत और ब्राजील के बीच कूटनीति, रणनीति और कारोबारी सहयोग के मुद्दे पर दूरियां निश्चित तौर पर अब कम होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो के बीच शनिवार को हुई बातचीत के बाद दोनो देशों के बीच 15 क्षेत्रों में समझौते हुए और कुछ पुराने मुद्दों को सुलझाने पर भी सहमति बनी। मोदी के आग्रह पर ब्राजील गन्ना उत्पादकों के मुद्दे पर भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में दर्ज कराया मामला भी वापस लेने को तैयार हो गया है। साथ ही भविष्य में रणनीतिक क्षेत्र में किस तरह से सहयोग किया जाए, इसका साफ खाका भी तैयार किया गया है।

नई दिल्ली में शनिवार को ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोलसोनारो से गर्मजोशी से मिलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एएनआइ

गणतंत्र दिवस में होंगे मुख्य अतिथि

बोलसोनारो शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे और रविवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वह भारत के राजकीय मेहमान होंगे। यह तीसरा मौका है जब ब्राजील के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनाया गया है। इस बार की खास बात यह है कि भारत सरकार ने दो ब्राजीली महिलाओं लिया दिस्किन और ग्लोरिया अरेरिया को पद्मश्री देने का एलान किया है। बोलसोनारो के साथ उनकी पुत्री लॉरा बोलसोनारो, पुत्रवधू लेटिसिया फर्मो, उनकी सरकार के कई सैन्य अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों व उद्योगपतियों का एक समूह भी आया है।

शनिवार को बोलसोनारो की पहले मोदी के साथ और फिर दोनो नेताओं के नेतृत्व में अधिकारी स्तर की बातचीत हुई। बातचीत के बाद मोदी ने बताया कि दोनो देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की सहमति जताई है। उनकी घोषणा के कुछ ही देर बाद आधिकारिक स्तर पर इस साझेदारी का प्रारूप जारी किया गया। इसमें राजनीतिक व रणनीतिक समन्वय को प्रगाढ़ करने, कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण के अलावा विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दोनो देशों ने कारोबार व उद्योग को ऐसा क्षेत्र माना है जिसमें रिश्तों को गहराई देने की काफी संभावनाएं है। भारत की तरह ब्राजील भी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। ऐसे में दोनो देशों ने वर्ष 2022 तक 15 अरब डॉलर (करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये) के द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी ब्राजील की कंपनियों का सिर्फ एक अरब डॉलर का निवेश भारत में हुआ है जबकि भारतीय कंपनियों ने ब्राजील में सात अरब डॉलर की राशि निवेश की है। बहरहाल, अब दोनो देशों के बीच विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालयों के बीच लगातार संपर्क स्थापित करने की सहमति बनी है जिससे कारोबार की अड़चनों को दूर करने में मदद मिलेगी।

ब्राजील में तेजी से तेल उत्पादन बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि अगले एक दशक में वह दुनिया का एक प्रमुख तेल उत्पादक देश बनेगा। भारत ने ब्राजील से तेल खरीदने की रुचि भी दिखाई है। ब्राजील भी इसके लिए ज्यादा ही इच्छुक है, लेकिन समस्या दूरी है। तेल की ट्रांसपोर्ट लागत को कम करने के लिए दोनो देश काम करेंगे। वैसे शनिवार को दोनो देशों के बीच बायोफ्यूल क्षेत्र में भी एक समझौता हुआ है। ब्राजील इस सेक्टर में एक बड़ी शक्ति है। ब्राजील की कंपनियां अब भारत में भी बायोफ्यूल से जुड़े शोध व अनुसंधान का काम कर सकेंगी। खासतौर पर भारत में एथनॉल के उपयोग को बढ़ाने पर दोनो देश काम शुरू करेंगे। भारतीय कंपनियां तेल व बायोफ्यूल में ब्राजील में ज्यादा निवेश करने को इच्छुक हैं। एक अहम सहमति रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर बनी है। रक्षा उत्पादन में संभावनाओं को तलाशने के लिए सोमवार को भारत व ब्राजील की रक्षा कंपनियों की एक विशेष बैठक भी है। संयुक्त घोषणापत्र के मुताबिक रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए जल्द ही संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी।

कमजोर नीतियों के कारण घुट रहा लोहा इंडस्ट्री का दम

कारोबारी जगत ने विशेष पैकेज की मांग की है। प्रतीकात्मक

धरमिंदर सिंह, फतेहगढ़ साहिब

▶ देशभर में एक जैसी नीति लागू होने और सटोरियों पर शिकंजा कसने की उम्मीद कर रहा उद्योग

एक दशक पहले आर्थिक मंदी के कारण एशिया की जानी-मानी लोहा नगरी मंडी गोबिंदगढ़ की औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया था। ताले लटक गए थे। धीरे-धीरे सरकारों ने आर्थिक मंदी तो दूर कर दी, लेकिन कमजोर नीतियों के कारण आज भी लोहा इंडस्ट्री का दम घुट रहा है। इन हालातों में इंडस्ट्री को मजबूती देने के लिए कारोबारियों की आम बजट से ढेर सारी उम्मीदें रहती हैं। कुछ वर्षों से आम बजट में इन उद्योगों की अनदेखी की गई है।

सात वर्ष पहले मंडी गोबिंदगढ़ में करीब 375 रोलिंग मिलें थीं। उनकी संख्या अब 225 रह गई है। यहां 100 के करीब फर्नेस इकाइयां हैं, जो किसी समय मात्र चालीस रह गई थीं। अब इस नगरी को आर्थिक मंदी की नहीं, बल्कि गलत नीतियों के कारण उजड़ रही इंडस्ट्री की चिंता है।

टैक्स व विभिन्न राज्यों में मिलती अलग-अलग छूट से यहां के उद्योगपति परेशान हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इंडस्ट्री लगाने के लिए इतनी ज्यादा छूट है कि उद्योगपति पंजाब से पलायन करना ही उचित समझते हैं। महंगी बिजली भी इंडस्ट्री के विकास में रुकावट बनी हुई है। यही नहीं, लोहा नगरी में उद्योगपतियों से ज्यादा सटोरियों और सट्टेबाजों ने अपनी धाक जमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संचालित इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ट्रेडिंग (आइसीएक्स) से तय होते दामों से मंडी गोबिंदगढ़ ही नहीं, पूरे पंजाब के मिल मालिक परेशान हैं। आइसीएक्स पर कोई नियंत्रण नहीं होने कारण वहां मनमर्जी के दाम तय होते हैं। ऐसे तौर-तरीकों पर पाबंदी की मांग की गई है।

ऑल इंडिया स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनोद वशिष्ठ कहते हैं कि आर्थिक मंदी नहीं है। नई तकनीकों के साथ इकाइयां अपग्रेड हो गई हैं। प्रोडक्शन बढ़ी है जबकि डिमांड कम है। अपग्रेड न होने वाली छोटी इकाइयां बंद हो रही हैं। लोहा करोबारी राकेश गोयल का मानना है कि गाजियाबाद से तय होने वाले दामों से करोड़ों रुपये का माल चंद मिनटों में लाखों का रह जाता है। इस पर पहल के आधार पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। वहीं, मिल मालिक अशोक जैन मानते हैं कि सरकार नई इकाइयां लगाने पर जोर दे रही है लेकिन बंद इकाइयों चालू करने पर ध्यान नहीं दे रही। जैसे किसानों को कर्ज माफी की छूट है, वैसी रियायत घाटा पड़ने पर उद्योगपतियों को भी मिलनी चाहिए। लोहा कारोबारी दिनेश गोयल कहते हैं कि यदि सही मायने में मंडी गोबिंदगढ़ की लोहा नगरी को पुनर्जीवित करना है तो इसे विशेष पैकेज देना होगा। इस पैकेज से उद्योग का कद बढ़ेगा।

जानकारों के मुताबिक सभी प्रदेशों में एक जैसी योजना व रियायत ही होनी चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में बैंक लोन नहीं चुका पाने पर कोई रियायत नहीं मिलती। इसी वजह से घाटे का शिकार हुई मिलों पर बैंकों ने ताले लगा रखे हैं और अंदर पड़ी मशीनरी कबाड़ बन चुकी है। ऐसे उद्योगपतियों को लोन भरने के लिए रियायत होनी चाहिए और बैंकों को मिलें बंद करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

न्यूज गैलरी

टेलीकॉम कंपनियों से वसूली के लिए जनहित याचिका दायर

नई दिल्ली : टेलीकॉम कंपनियों से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) की वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सेव कंज्यूमर राइट्स फाउंडेशन ने गुहार लगाई है कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) को टेलीकॉम कंपनियों से वसूली के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 23 जनवरी तक एजीआर बकाया भुगतान कर देना था। कुछ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर कर दी थी, जिसके बाद डीओटी ने अधिकारियों को कंपनियों पर कार्रवाई से रोक दिया था। (एएनआइ)

देबाशीष पांडा एसबीआइ बोर्ड में किए गए नामित

नई दिल्ली : सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (एसबीआइ) के निदेशक बोर्ड में देबाशीष पांडा को अपना नामित प्रतिनिधि नियुक्त किया है। वे वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर हैं। एसबीआइ ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया कि पांडा को तत्काल प्रभाव से बैंक के बोर्ड में निदेशक के तौर पर शामिल कर लिया गया है। पांडा की नियुक्ति रवि मित्तल के स्थान पर हुई है। मित्तल को सूचना व प्रसारण मंत्रालय में सचिव के तौर पर पदोन्नत किया गया है। (प्रेट्र)

गैर-जीवन बीमा कंपनी बेच सकेंगी स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी

चेन्नई : बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने गैर-जीवन बीमा कंपनियों स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी बेचने की अनुमति दे दी है। इरडा ने एक अधिसूचना में कहा कि गैर-जीवन बीमा कंपनियां एक अप्रैल से पहले आरोग्य संजीवनी पॉलिसी की बिक्री कर सकती हैं। इस पॉलिसी को स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी माना गया है। इससे पहले इरडा ने गैर-जीवन बीमा कंपनियों से कहा था कि वे इस वर्ष पहली अप्रैल से पहले स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी की बिक्री नहीं कर सकती हैं। (आइएएनएस)

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेग्मेंट में उतरी टीवीएस मोटर

बेंगलुरु : टीवीएस मोटस कंपनी ने शनिवार को ई-स्कूटर लांच कर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेग्मेंट में कदम रखा है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कंपनी का यह स्कूटर लांच किया। फुल चार्ज में 75 किमी तक चलने वाले इस स्कूटर की बेंगलुरु में ऑन-रोड कीमत 1.15 लाख रुपये है। (प्रेट्र)

आइसीआइसीआइ बैंक का लाभ बढ़ा

▶ एस्सार स्टील से हुई वसूली का दिखा फायदा, ग्रॉस एनपीए में भी तीसरी तिमाही के दौरान दर्ज की गई गिरावट

मुंबई, प्रेट्र : निजी क्षेत्र दूसरे सबसे बड़े कर्जदाता आइसीआइसीआइ बैंक के शुद्ध लाभ में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान करीब डेढ़ गुना बढ़ोतरी हुई है। बैंक ने शनिवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 4,670 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। उससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक को 1,874.33 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बैंक का कहना है कि एस्सार स्टील से हुई वसूली और कुछ कोर इनकम में बढ़ोतरी का फायदा शुद्ध लाभ में झलका है। हालांकि बैंक ने यह नहीं बताया कि एस्सार स्टील से उसने कितने रकम की वसूली की है।

स्टैंडअलोन आधार पर भी आइसीआइसीआइ बैंक का लाभ तीसरी तिमाही में बढ़कर 4,146 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 1,605 करोड़ रुपये रहा था। बैंक की शुद्ध ब्याज आय समीक्षाधीन तिमाही में 24 प्रतिशत बढ़कर 8,545 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान 3.77 प्रतिशत और घरेलू एडवांस में 16 प्रतिशत का उछाल देखा गया। बैंक ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसकी अन्य स्रोत से आय 18.77 प्रतिशत बढ़कर 4,043 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जबकि कोर फ्री इनकम में 17 प्रतिशत का उछाल देखा गया।

आइसीआइसीआइ बैंक के प्रेसिडेंट संदीप बत्रा ने कहा कि एक संकटग्रस्त ब्रोकिंग कंपनी और एक दक्षिण भारतीय औद्योगिक ग्रुप को दिए कर्ज के चलते समीक्षाधीन तिमाही में उसके स्लिपेज में बढ़ोतरी हुई है। समीक्षाधीन अवधि में बैंक की स्टैंडअलोन प्रोविजनिंग 51 प्रतिशत घटकर 2,083 करोड़ रुपये रह गई। वहीं, सकल फंसा कर्ज (एनपीए) घटकर 5.95 प्रतिशत पर आ गया, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 7.75 प्रतिशत पर था। हालांकि समीक्षाधीन अवधि में बैंक के रिटेल कारोबार का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 2.14 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में दो प्रतिशत रहा था।

बैंक के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में कई क्षेत्रों से कॉरपोरेट लोन की मांग आई। इनमें टर्म लोन भी शामिल हैं। बत्रा ने कहा कि बैंक अच्छी रेटिंग वाले ग्राहकों को कर्ज मुहैया कराने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

आंकड़ों के आईने में

4,670 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा बैंक का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ

4,146 करोड़ रुपये पर पहुंच गया स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ समीक्षाधीन अवधि में

8,545 करोड़ रुपये रही बैंक की शुद्ध ब्याज आय 24 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ

3.77 प्रतिशत रही नेट इंटरेस्ट मार्जिन, घरेलू एडवांस में 16 प्रतिशत का उछाल

4,043 करोड़ रुपये रही अन्य स्रोत से आय, 18.77 प्रतिशत का हुआ इजाफा

2,083 करोड़ रुपये रह गई 51 प्रतिशत घटकर स्टैंडअलोन प्रोविजनिंग

5.95 प्रतिशत रह गया ग्रॉस एनपीए, जो 7.75 प्रतिशत पर था

स्टील का भाव 15 हजार रुपये टन तक बढ़ने का खतरा

भिलाई, नईदुनिया : स्टील का भाव अब हर इंसान को रुलाने जा रहा है। स्टील निर्मित हर उत्पाद का भाव बढ़ने के आसार हैं। सरिया, चैनल, मोटर पार्ट्स, पाइप, कील समेत सैकड़ों उत्पाद महंगे हो जाएंगे। इन उत्पादों की लागत दो माह में छह हजार रुपये प्रति टन बढ़ गई है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अधीन आने वाली कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएमडीसी) ने लौह अयस्क का भाव 16 दिनों में 875 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया गया है। इसकी मार छोटे इस्पात कारखानों पर दिखने वाली है। आम जनता को भी ज्यादा कीमत पर लोहा खरीदना पड़ेगा। निर्माण कार्यों पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा।

उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार की नीतियों से दोहरी मार पड़ रही है। तीन माह पूर्व स्टील का भाव 24 हजार रुपये प्रति टन था। कच्चे माल का भाव बढ़ते ही 31 हजार रपये प्रति टन तक रेट पहुंचना तय है। फिनिश्ड प्रोडक्ट का भाव प्रति टन 10-15 हजार रुपये प्रति टन तक बढ़ सकता है। इनमें 20 प्रतिशत टैक्स भी शामिल है। लोहा महंगा होने से निर्माण कार्यों की लागत भी बढ़ जाएगी।

शहरी लक्जरी बसों को परमिट से छूट का प्रस्ताव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ नौकरीपेशा वर्ग को ऑफिस आने-जाने में होगी सुविधा

▶ जाम की समस्या से भी निजात मिलने की उम्मीद

शहरों में सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था को सुगम, सुविधाजनक और किफायती बनाने के लिए सरकार एयरकंडीशंड लक्जरी बसों को परमिट से छूट देने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में सड़क मंत्रालय ने सभी साझीदारों से एक माह के भीतर सुझाव मांगे हैं।

इस संबंध में निकाली गई मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय शहरों में सुरक्षित, विश्वसनीय, गरिमामय, आरामदेह तथा किफायती सार्वजनिक बस परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए लक्जरी सेग्मेंट की बसों को परमिट की जरूरत से मुक्त करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बस बॉडी कोड रूल्स-052 के दायरे में आने वाली बसों पर लागू होगा।

अभी मोटर वाहन एक्ट-1988 की धारा-66 की उपधारा-3 के अनुच्छेद एन के तहत 22 या अधिक सीटों वाली लक्जरी बसों के लिए परमिट लेना जरूरी है। यदि प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो गजट अधिसूचना के जरिये 22 से अधिक सीटों वाली एयरकंडीशंड लक्जरी बसों को इन प्रावधानों से छूट दे दी जाएगी।

इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग (आइएफटीआरटी) के संयोजक एसपी सिंह ने कहा कि यह सड़क परिवहन क्षेत्र को गैरजरूरी नियम-कायदों की जकड़न से मुक्त करने वाला एक बड़ा उदारवादी कदम है। इसके लागू होने से बस ट्रांसपोर्ट उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा। परमिट की बाध्यता के कारण अभी इस उद्योग में गिने-चुने बस ऑपरेटरों का वर्चस्व है। शहरी सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में देश-विदेश की अनुभवी तथा नई स्टार्ट-अप कंपनियों के प्रवेश से नौकरीपेशा वर्ग को उम्दा किस्म की प्राइवेट बसों में सफर करने मौका मिलेगा। इससे जाम तथा प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी।

उप्र, पंजाब व छत्तीसगढ़ सहित 16 राज्यों ने आरबीआइ से मांगा लोन

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 16 राज्य सरकारें फिर कर्ज लेने की कतार में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक हजार करोड़ और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक 2500 करोड़ रुपये के लोन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) में आवेदन किया है। सरकारें यह राशि 10 वर्ष के लिए लेना चाह रही हैं।

राज्यों ने अपनी प्रतिभूति (बांड) के एवज कुल 18,170 करोड़ के लिए आवेदन किया है। राज्यों को कितने ब्याज दर पर लोन मिलेगा, इसका फैसला 28 जनवरी को होगा। आरबीआइ ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

किस राज्य को कितना लोन चाहिए : लोन का आवेदन लेकर रिर्जव बैंक पहुंचे राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी राज्य हैं। बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु ने दो-दो हजार करोड़, गुजरात 1500 करोड़, आंध्रप्रदेश, बिहार, हरियाणा और तेलंगाना ने एक-एक हजार करोड़ के लिए आवेदन दिया है। इनके अलावा राजस्थान 750, पंजाब छह सौ, असम, ओडिशा पांच-पांच सौ, केरल 420 और त्रिपुरा चार सौ करोड़ का लोन लेने की कतार में हैं।

स्लैब घटाने के अलावा अन्य विकल्पों से भी टैक्स में राहत पर हो रहा विचार

बजट से उम्मीदें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ बीमा क्षेत्र में निवेश पर मिलने वाली आयकर छूट इसका एक बड़ा विकल्प हो सकती है

पिछले वर्ष मिली कॉरपोरेट टैक्स में छूट के बाद अब सबकी निगाहें आगामी आम बजट में व्यक्तिगत आयकर में मिलने वाली संभावित छूट पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण खजाने की हालत को देखते हुए इस दिशा में कितना कदम बढ़ा पाती हैं, यह तो बजट आने पर ही स्पष्ट होगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में सरकार अन्य उपलब्ध विकल्पों के जरिये व्यक्तिगत आयकर में राहत दे सकती है।

माना जा रहा है कि बीमा क्षेत्र में निवेश पर मिलने वाली आयकर छूट एक बड़ा विकल्प हो सकती है। खासतौर पर चुनिंदा बीमा प्लान पर इस आशय का कदम उठाया जा सकता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार व्यक्तिगत आयकर की छूट में वृद्धि कर सकती है।

प्रतीकात्मक

एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ विनीत अरोड़ा मानते हैं कि ये प्लान न केवल सस्ते, बल्कि ग्राहकों के लिए बेहद उपयोगी भी हैं। सरकार को ऐसे प्लान में निवेश करने पर 25,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का प्रावधान करना चाहिए। लोगों में बीमा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) भी लगातार टर्म बीमा प्लान को प्रोत्साहित कर रहा है। अभी बीमा में डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत व्यक्तिगत आयकर पर छूट का प्रावधान है। सरकार के पास एक विकल्प सभी तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट को भी टैक्स फ्री बनाने का है।

इसी तरह कॉरपोरेट टैक्स में हुई कटौती के दायरे से बाहर रह गए सभी छोटे उद्यमियों को सरकार व्यक्तिगत आयकर में कुछ राहत दे सकती है। यह राहत उनकी तरफ से किए गए निवेश पर भी आधारित हो सकती है। ब्रिकवर्क रेटिंग के मुताबिक सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था में मांग सृजित करने की है। लेकिन ऐसा करने में उसके सामने राजकोषीय संतुलन की चुनौती भी है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि फिलहाल मांग सृजित करने का फोकस केवल उन्हीं क्षेत्रों पर हो जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। एजेंसी के मुताबिक इनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, पावर, टेलीकॉम, स्टील और रियल एस्टेट प्रमुख हैं। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने और रोजगार सृजन में इन सभी क्षेत्रों की अहम भूमिका रहती है।

टैक्स सेविंग के नए तरीकों को मौजूदा कानूनों से नहीं मिल रही कोई मदद

भारतीय बचतकर्ता और निवेशक टैक्स बचाने के नए तौर-तरीके अपना रहे हैं। मैं पहले भी लिख चुका हूं कि अब व्यक्तिगत निवेशक हर माह 8,000 करोड़ रुपये से अधिक रकम एसआइपी में निवेश कर रहे हैं। ताजा निवेश का यह प्रवाह काफी स्थिर है और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की रकम को भी जोड़ लें तो यह भारतीय इक्विटी मार्केट का मजबूत आधार बन गया है।

निवेशक जहां महंगाई दर से अधिक रिटर्न देने वाले और लंबी अवधि के निवेश की नई दुनिया की ओर जा रहे हैं, वहीं कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर हमारा कानून अब भी पुरानी सोच में उलझा हुआ है। भारत में इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स का स्ट्रक्चर बढ़ती अर्थव्यवस्था के बजाए काफी हद करीब पांच दशक पहले के अमीर विरोधी विचार पर खड़ा है। इसके अलावा यह ऐसे निवेशकों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है जो अपने रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं और बड़ी रकम जुटाना चाहते हैं।

इस समस्या की मूल वजह यह है कि टैक्स कानून कैपिटल गेन्स यानी पूंजीगत लाभ होने को ट्रांजैक्शन मानता है। म्यूचुअल फंड निवेश में जब भी निवेशक फंड की यूनिट बेचता है तो उसको होने वाला मुनाफा या गेन्स को टैक्स कानून के तहत कैपिटल गेन्स माना जाता है। अगर फंड में निवेश बनाए रखने की अवधि एक साल से कम है तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है और निवेश बनाए रखने की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो यह लांग टर्म कैपिटल गेन्स है। इक्विटी फंड में लांग टर्म कैपिटल गेन्स 2005 में खत्म कर दिया गया था और 2018 तक यह शून्य था।

वर्तमान टैक्स कानून कुछ इस तरह का है कि वह लंबी अवधि के निवेशकों को दंडित करता है जबकि यह लंबी अवधि के निवेशकों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। लंबी अवधि में एक ऐसा समय आता है जब निवेशक को लगता है कि उसने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, उससे बेहतर विकल्प बाजार में आ गया है। ऐसे में अगर निवेशक उस फंड में निवेश बेचकर रकम दूसरे फंड में लगाता है तो उसे पहले फंड से मिलने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। तो इससे या तो उसका रिटर्न कम होता है या निवेशक टैक्स देने से बचने के लिए कम रिटर्न के साथ ही समझौता करे। निवेशक अपने निवेश का पूरा फायदा उठा सके इसके लिए जरूरी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का निवेश बेचकर दूसरे इक्विटी फंड में निवेश करने को ट्रांजैक्शन नहीं माना जाए। यह मांग लंबे समय से की जा रही है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (एम्फी) ने भी वित्त मंत्री के सामने यह मांग रखी थी। वर्ष 2018 के पहले लोग इस मांग को लेकर ज्यादा मुखर नहीं थे क्योंकि लांग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स शून्य था। हालांकि मैं यहां शून्य टैक्स से अलग बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अपना निवेश रकम खर्च करने के लिए भुनाता है तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगना चाहिए। लेकिन लंबी अवधि के निवेश को भुनाकर दूसरे फंड में निवेश करने पर टैक्स नहीं लगना चाहिए।

दिलचस्प बात यह है कि कुछ इसी तरह का प्रावधान टैक्स कानून में पहले से है। सेक्शन 54 में प्रावधान है कि लांग टर्म कैपिटल गेन्स को अगर कम अवधि में आवासीय प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया जाए तो टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि अजीब बात यह है कि टैक्स कानून में आवासीय प्रॉपर्टी को ऐसा असेट टाइप माना गया है जिसमें रकम को लगाया जाना चाहिए। सेक्शन 54 के तहत आप लंबी अवधि के निवेश को बेचकर मिलने वाली रकम से एक घर खरीद सकते हैं और अगर आप इस घर को तीन साल से अधिक समय तक रखते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। यह विशेष सुविधा किसी और तरह के निवेश पर उपलबध नहीं है।

यह नियम पुराने जमाने में ठीक था। उस समय घर ही लंबी अवधि का निवेश माना जाता था। बड़ी रकम वाले वित्तीय निवेश बहुत कम होते थे। लेकिन अब कोई बचतकर्ता अपने पर्सनल फाइनेंस को इस तरह से नहीं देखता है। चाहे इस बजट में किया जाए या बाद में, सेक्शन 54 का फायदा दूसरी तरह की बचत और असेट्स को भी मिलना चाहिए जिनमें लोग पैसा लगा रहे हैं।

धीरेंद्र कुमार, सीईओ वैल्यू रिसर्च

बोनस

वर्तमान टैक्स कानून लंबी अवधि के निवेशकों को दंडित करता है, जबकि उसे लंबी अवधि के निवेशकों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। इसकी मूल वजह यह है कि टैक्स कानून कैपिटल गेन्स को ट्रांजैक्शन मानता है। लंबी अवधि के निवेश में एक ऐसा समय आता है जब निवेशक को लगता है कि उसने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है उसका बेहतर विकल्प आ गया है। दिक्कत यह है कि अगर निवेशक उस फंड से निवेश बेचकर रकम दूसरे फंड में लगाता है तो उसे पहले फंड से मिलने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। ऐसी टैक्स व्यवस्था में निवेशकों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।

500 साल पुरानी प्रति बरामद हुई है क्रिस्टोफर कोलबंस की। इसे संघीय एजेंटों ने डेलावेयर में बरामद कर लिया है। यह पत्र एक दशक पहले इटली के एक पुस्तकालय से चोरी हो गया था। इसे अप्रैल, 1493 में स्पेनिश भाषा में हाथ से लिखा गया था।

नेपाल पर ग्लोबल वार्मिंग का अधिक असर

▸ विदेश मंत्री ग्यावली ने कहा, सागरमाथा संवाद में जलवायु परिवर्तन पर होगी प्रमुखता से बात

काठमांडू, प्रेट्र: हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में बर्फ पिघलने और सिकुड़ते ग्लेशियर के चलते ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ रहा है। विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा कि यह वह क्षेत्र है, जो 24 करोड़ लोगों की पानी की जरूरतें पूरी करने के साथ ही उन्हें रहने लायक मौसम प्रदान करता है।

भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बात करते हुए नेपाली विदेश मंत्री का कहना था कि अप्रैल में नेपाल सरकार द्वारा आयोजित 'सागरमाथा संवाद' के पहले संस्करण में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी प्रमुखता से बात होगी। उन्होंने बताया कि नेपाल में ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ीं प्राकृतिक आपदा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। पिछले साल मार्च में आया तूफान इसकी पुष्टि करता है, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई थी। ग्यावली के अनुसार, नेपाल के जल विज्ञान विभाग द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि तूफान की घटना ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि मौसम में इस तरह का परिवर्तन ऐसे लोगों और समाज को

नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली की फाइल फोटो। ट्विटर से

नुकसान पहुंचाता है, जिनका इसे खराब करने में कतई कोई योगदान नहीं होता है। नेपाल भी इनसे से एक है। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में नेपाल का हिस्सा मात्र 0.027 फीसद है, लेकिन इसके बावजूद वह जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों से बुरी तरह प्रभावित है। यह हाल तब है, जब उसका 45 फीसद भूभाग वनों से आच्छादित है।

0.056 फीसद की दर से बढ़ रहा तापमान

पिछले 45 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपाल का औसत अधिकतम तापमान 0.056 फीसद सालाना की दर से बढ़ रहा था। यह बढ़ोतरी औसत वैश्विक अधिकतम तापमान की वृद्धि से अधिक है। ग्यावली ने यह भी कहा कि अगर इसी तरह तापमान में वृद्धि जारी रही तो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के दो-तिहाई ग्लेशियर सदी के अंत तक पिघल जाएंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों में जलस्तर गिरा

एक तस्वीर दिखाते हुए नेपाली विदेश मंत्री ग्यावली ने कहा कि नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए अब और अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। इसकी वजह यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के चलते कुंए और झरने सूख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत से लगते नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र में भी भूजल खतरनाक स्तर तक गिर गया है।

गोलीबारी में दो रोहिंग्या महिलाओं की मौत

यंगून, एएफपी: म्यांमार की सेना और विद्रोहियों के बीच हुई गोलीबारी में दो रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं की मौत हो गई। सात अन्य घायल हो गए। यह घटना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उस आदेश के बाद घटी है, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार रोकने के लिए म्यांमार को सभी उपाय करने को कहा गया था।

सैन्य प्रवक्ता जॉ मिन तुन ने बताया कि एक महिला की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी ने उत्तरी रखाइन प्रांत के अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ा। सेना ने इन मौतों के लिए अराकान आर्मी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अराकान आर्मी ने सेना पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस इलाके में यह घटना हुई है, वहां पर सेना के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं चल रही है। बता दें कि अगस्त, 2017 में अराकान रोहिंग्या सैलवेशन आर्मी ने रखाइन में पुलिस और सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए थे। इसके बाद म्यांमार की सेना ने बड़ी कार्रवाई की थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कार्रवाई में दस हजार लोग मारे गए और सात लाख से ज्यादा को पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ी।

अमेरिका में गर्भपात के विरोध में रैली

दुनिया भर में गर्भपात कानूनों को लेकर चल रही बहस के बीच शुक्रवार को अमेरिका के वॉशिंगटन में हजारों लोगों ने 'मार्च फॉर लाइफ' रैली की। कैपिटल हिल के करीब आयोजित रैली को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संबोधित किया। राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि वे मेरे पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं अपके लिए लड़ रहा हूं। यह 1973 में गर्भपात को वैध घोषित किए जाने के बाद पहली बार था जब अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने मार्च फॉर लाइफ रैली को संबोधित किया। एपी

कई देशों में कोरोना वायरस ने दी दस्तक, बढ़ी दहशत

महामारी ▸ वैश्विक स्तर पर 1300 से लोग ज्यादा हुए संक्रमित, सबसे अधिक चीन में

चीन में नए साल का उल्लास फीका पड़ा, हांगकांग में इमरजेंसी

बीजिंग, एजेंसियां : चीन से फैल रहे जानलेवा कोरोना वायरस से लगभग पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। चीन की यात्रा से अपने देशों को लौट रहे कई लोग इससे संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस वायरस से वैश्विक स्तर पर अब तक 1300 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें से सर्वाधिक 1287 मामले अकेले चीन में सामने आए हैं, जिसमें 237 की हालत गंभीर बताई जा रही है। करीब दो हजार संदिग्ध मामले भी बताए जा रहे हैं। चीन में इस रहस्यमय वायरस से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी के केंद्र वुहान समेत छह करोड़ की आबादी वाले हुबेई प्रांत में आवाजाही बंद कर दी गई है।

वायरस के प्रकोप के चलते चीन में शनिवार से प्रारंभ हुए नए साल (लूनर ईयर) का उल्लास भी फीका पड़ गया है। सान्या शहर समेत कई लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है। चीन की दीवार के कुछ हिस्से और शंघाई डिजनीलैंड समेत प्रमुख मंदिरों को भी बंद कर दिया गया है। नए साल पर मंदिरों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। अमेरिकी कॉफी चेन स्टारबक्स ने हुबेई प्रांत में एक हफ्ते के लिए अपने सभी आउटलेट बंद कर दिए हैं। मैकडोनाल्ड ने भी प्रांत के पांच शहरों में इस तरह का कदम उठाया है। जबकि चीन के नियंत्रण वाले हांगकांग में इमरजेंसी घोषित की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) चीन के लिए हेल्थ इमरजेंसी पहले ही घोषित कर चुका है। पिछले माह मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से वायरस का संक्रमण शुरू हुआ था। यहीं से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को भीड़ से दूर रहने के साथ ही मास्क और सुरक्षात्मक सूट पहनने को कहा जा रहा है।

इलाज में जुटे डॉक्टर की गई जान : सरकारी चाइना ग्लोबल टेलीविजन के अनुसार, वुहान में रोगियों के उपचार के दौरान वायरस की चपेट में आए 62 वर्षीय लियांग वुडांग नामक डॉक्टर भी मौत हो गई।

फ्लाइट, ट्रेन और बसों में निगरानी बढ़ी : वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए फ्लाइट, ट्रेन और बसों में निगरानी बढ़ा दी गई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने सभी परिवहन विभागों को रोकथाम के उपाय कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है।

450 सैन्य डॉक्टर भी उतारे : चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि वुहान में 1230 मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया है। जबकि स्थानीय मीडिया के अनुसार, मदद के लिए शहर में 450 सैन्य डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं।

ये हैं वायरस के लक्षण : कोरोना वायरस का अभी कोई ज्ञात उपचार नहीं है। सांस संबंधी दूसरी बीमारियों की तरह ही बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत इस संक्रमण के लक्षण हैं। यह न्यूमोनिया का कारण भी बन सकता है।

चीन के हुबेई प्रांत के सर्वाधिक प्रभावित वुहान शहर के अस्पताल में पीड़ितों के इलाज में जुटी चिकित्सकों की टीम। रायटर

खतरनाक कोरोना वायरस से पीड़ित भारतीय मूल की शिक्षिका प्रीति माहेश्वरी (फाइल फोटो)। साथ में अस्पताल में उपचाराधीन प्रीति। ट्विटर से

इन देशों में पहुंचा वायरस

कोरोना वायरस अब तक हांगकांग, मकाउ, ताइवान, नेपाल, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड, वियतनाम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दस्तक दे चुका है। अमेरिका में दो और ऑस्ट्रेलिया में चार मामलों की पुष्टि हुई है। ये सभी चीन से लौटे बताए गए हैं। पाकिस्तान में भी एक चीनी नागरिक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ब्रिटेन और फ्रांस में भी मामले आने की खबर है।

700 भारतीय छात्र भी फंसे

भारत के लिए चिंता की बात यह है कि आवाजाही बंद होने के चलते वुहान समेत हुबेई के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 700 भारतीय छात्र भी फंस गए हैं। भारतीय दूतावास इनके संपर्क में है।

वुहान में 15 दिन में बनेगा दूसरा अस्पताल

वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वुहान में 15 दिनों में 1300 बिस्तर की क्षमता वाला एक और अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा। अभी शहर के बाहरी इलाके में 25 हजार वर्ग मीटर के प्लाट पर एक हजार बेड वाला एक अस्पताल बनाया जा रहा है। यह अस्पताल महज दस दिनों में बनकर तीन फरवरी तक तैयार हो जाएगा। इसके लिए युद्धस्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। श्रमिकों को तीन गुना ज्यादा यानी रोजाना 1200 युआन (करीब 12 हजार रुपये) मेहनताना दिया जा रहा है।

गुरुग्राम पर मंडराया कोरोना का खतरा बिहार में अलर्ट

जेएनएन, नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में चीनी नागरिकों आवाजाही अधिक होने के कारण कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। दूसरे राज्य भी विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। पंजाब के बाद बिहार ने भी शनिवार को इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया।

आइटी और दूसरे क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियों का आफिस और उद्योग होने के कारण गुरुग्राम में चीनी नागरिकों का आना-जाना ज्यादा होता है। लिहाजा यहां कोरोना वायरस फैलने का खतरा अधिक है। सिविल सर्जन डॉ. जसवंत सिंह पूनिया ने कहा कि हम पूरी तरह सतर्क हैं। सभी प्राइवेट अस्पतालों को बोला गया है कि मरीज की तुरंत सूचना दी जाए। बिहार में भी एहतियात बरतने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने निर्देश में कोरोना वायरस से संबंधित समीक्षा, निगरानी, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में अमृतसर व मोहाली एयरपोर्ट पर विशेष सावधानी बरती जा रही है। यहां चीन से आने वाले यात्रियों की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चार क्षेत्र चीन सीमा से सटे होने के कारण राज्य में विशेष सावधानी बरती जा रही है।

तुर्की में भूकंप का कहर, 22 की मौत

▸ 1000 से अधिक लोग घायल, इमारतों के मलबे में अभी भी कई लोग फंसे

▸ पूर्वी हिस्से में शुक्रवार रात दर्ज किया गया 6.8 तीव्रता का भूकंप

इस्तांबुल, एजेंसियां : तुर्की के पूर्वी हिस्से में शुक्रवार रात को 6.8 तीव्रता वाले भूकंप ने जबरदस्त कहर ढाया। इसकी चपेट में आकर जहां 22 लोगों की मौत हो गई वहीं 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एक इमारत के मलबे के नीचे कई लोग अभी भी फंसे हैं। यह जबरदस्त भूकंप राजधानी अंकारा से 750 किमी पूर्व में स्थित एलाजिग प्रांत में आया। सीरिया, ईरान सहित लेबनान के बेरूत और त्रिपोली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एएफएडी) के मुताबिक, भूकंप स्थानीय समयानुसार शुक्रवार रात 8:55 बजे आया और इसका केंद्र सिवरिस कस्बे में था। 390 बार और धरती हिलने की बात कही जा रही है, जिसमें से 14 की तीव्रता चार से ज्यादा थी। एलाजिग प्रांत में जहां 18 लोगों की मौत हुई है वहीं चार लोग पड़ोसी मालट्या प्रांत के निवासी बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि एलाजिग प्रांत में भूकंप से गिरी इमारतों के मलबे में दबे 39 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसमें एक गर्भवती महिला भी है। मलबे में अभी भी 22 लोग फंसे हैं। जिस इलाके में भूकंप आया है वहां का तापमान माइनस पांच डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हैं, जिसके चलते राहत कार्यों में परेशानी आ रही है। आम लोगों को गर्म रखने के लिए लकड़ी और प्लास्टिक जलाई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने एनटीवी ब्राडकास्टर को बताया कि भूकंप के तेज झटके 10 से 12 सेकेंड तक महसूस किए गए। हालांकि कुछ इसे 30 से 35 सेकेंड तक भी बता रहे हैं। इसके बाद कम तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र धरती से पांच किमी नीचे था, लेकिन इसके झटके आसपास के चार प्रांतों में भी महसूस किए गए। बता दें कि चार हजार की आबादी वाला सिवरिस कस्बा एलाजिग शहर के दक्षिण में हजारा झील के किनारे स्थित है। यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के साथ ही टिगरिस नदी का स्रोत भी है।

1999 में आया था 7.4 तीव्रता का भूकंप : इससे पहले 1999 में पश्चिमी तुर्की में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में एक हजार लोगों सहित 17 हजार लोग मारे गए थे। पिछले साल सितंबर में भी 5.7 तीव्रता का भूकंप इस्तांबुल में आया था।

तुर्की के पूर्वी हिस्से में आए भीषण भूकंप से एलाजिग क्षेत्र में जमींदोज हुआ भवन। रायटर

ईरान किसी भी हद तक यूरेनियम शोधन में सक्षम

दुबई, रायटर : ईरान किसी भी सीमा तक यूरेनियम का शोधन करने में सक्षम है। यह देश के नेतृत्व को तय करना है कि उसे किस स्तर का यूरेनियम चाहिए। यह बात ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के उप प्रमुख ने संस्था की वेबसाइट के माध्यम से कही है। उल्लेखनीय है कि परमाणु हथियार बनाने में उच्च सीमा तक शोधित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। उस स्तर का यूरेनियम तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिक दक्षता की जरूरत होती है।

उप प्रमुख अली असगर जरीन ने कहा, इस समय ईरान के नेतृत्व को निर्णय लेना है। परमाणु ऊर्जा संगठन उस निर्णय के अनुसार यूरेनियम को किसी भी सीमा तक शोधित कर देगा। ईरान ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि 2015 में अमेरिका समेत छह शक्तिशाली देशों के साथ हुए समझौते से पीछे हटकर वह यूरेनियम शोधन की सीमा में लगी रोक को खत्म कर सकता है। फिलहाल वह संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों के साथ सहयोग कर रहा है और समझौते का पालन करते हुए उन्हें परमाणु संयंत्र का निरीक्षण करने दे रहा है। ईरान फिलहाल समझौते में उल्लेखित सीमा तक ही यूरेनियम का शोधन कर रहा है। यह शोधन परमाणु बिजली पैदा करने और यूरेनियम के शांतिपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है।

कोरोना वायरस के लिए हेल्पलाइन नंबर, सात नए लोग निगरानी में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली।

▸ हर्षवर्धन की तैयारियों की समीक्षा, चीन यात्रा पर एक नई एडवाइजरी

कोरोना वायरस से फिलहाल भारत महफूज जरूर है, लेकिन सात लोग निगरानी में हैं। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले निगरानी में रखे गए चार लोगों में यह वायरस नहीं मिला। वायरस के खतरे से निपटने और इसके संदिग्ध की तत्काल पहचान कर इलाज सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर और चीन यात्रा के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले यात्रियों की जांच की तैयारियों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की टीमों का गठन भी किया गया है। कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि चीन से आए सात लोगों को निगरानी में रखा गया है और उनके सैंपल को पुणे स्थित आइसीएमआर-एनआइवी लैब भेजा गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने 24 घंटे काम करने वाला कॉल सेंटर (011-23978046) चालू किया है। कॉल सेंटर से केंद्रीय टीम जिला व राज्य स्तर पर निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से चीन या अन्य कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटे यात्रियों पर नजर रखेगी। विदेश मंत्रालय ऐसे यात्रियों की सूची उपलब्ध करा रहा है।

हवाई अड्डों पर निगरानी के लिए टीमें

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए विशेषज्ञों की टीम का गठन किया है। यह टीम नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि हवाई अड्डे पर रविवार को पहुंच जाएगी। इसके साथ ही हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से भी बात की। राज्य को हर संभव केंद्रीय मदद का भरोसा दिया है। उत्तराखंड की सीमा नेपाल से मिलती है, जहां कोरोना वायरस के केस मिले हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के खिलाफ तैयारियों पर व्यक्तिगत निगरानी रखने को कहेंगे।

हर्षवर्धन ने कहा कि जो भी लोग इस महीने एक तारीख के बाद चीन से वापस आए हैं, यदि उनको बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ होती है तो उन्हें तत्काल डाक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपने चीन यात्रा के बारे में बताना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से एडवाइजरी जारी की है जिसमें चीन की यात्रा करने वाले यात्रियों को हिदायत दी गई है। इसके अनुसार, यदि चीन में रहते हुए सर्दी-खांसी की शिकायत हो तो वे तत्काल मुंह को कपड़े से ढंक लें।

पीएमओ ने तैयारियों की समीक्षा की

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की शनिवार को समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने चीन में कोरोना वायरस के फैलने के आलोक में उठाए गए कदमों के बारे में बताया। अधिकारियों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों और प्रयोगशालाओं की तैयारी के बारे में भी जानकारी दी।

चेतावनी

हाल ही में इस्लामाबाद से लौटीं अमेरिका की वरिष्ठ राजनयिक एलिस वेल्स ने दी चेतावनी

एफएटीएफ की शर्तें न मानना पाक के लिए होगा विनाशकारी

वाशिंगटन, प्रेट्र : पाकिस्तान अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित होगा।

अमेरिका में दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि देश को एफएटीएफ की 'ग्रे सूची' से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उसने आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रगति की है।

वेल्स ने यहां मीडिया से कहा, 'जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान एफएटीएफ के दायित्वों को पूरा नहीं करता है और काली सूची में आता है तो यह पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम तथा निवेशकों को आकर्षित करने की उसकी क्षमता के लिए विनाशकारी होगा।'

इस्लामाबाद समेत दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा करके हाल ही में लौटीं वेल्स ने कहा, 'हम एफएटीएफ के दायित्वों को पूरा करने की ओर पाकिस्तान की प्रगति को देखकर खुश हैं।' वह उस सवाल का जवाब दे रही थीं कि अगर पाकिस्तान एफएटीएफ के नियमनों या नियमों को पूरा नहीं करता है तो क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उसको मिलने वाली वित्तीय मदद पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के प्रभाग के मंत्री हम्माद अजहर के नेतृत्व वाला पाक प्रतिनिधिमंडल एफएटीएफ की सिफारिशों को लागू करने के लिए इस्लामाबाद द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एफएटीएफ को जानकारी देने के लिए बीजिंग में है। एफएटीएफ ने गत अक्टूबर में पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद तथा अन्य आतंकवादी समूहों के वित्त पोषण पर लगाम लगाने में नाकामी के लिए 'ग्रे' सूची में डालने का फैसला किया था।

अगर वह अप्रैल तक इस सूची से नहीं हटता है तो पाकिस्तान को काली सूची में डाला जा सकता है, जिसके बाद उसे गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिकी राजनयिक ने कश्मीर में इंटरनेट बहाली पर खुशी जताई

▸ घाटी में विदेशी राजनयिकों की यात्रा को उपयोगी कदम करार दिया

वाशिंगटन, एएनआइ: वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक एलिस वेल्स ने कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा की आंशिक बहाली जैसे प्रगतिशील कदमों पर खुशी जताई है।

दक्षिण व मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री वेल्स ने कहा कि उनकी और अन्य विदेशी राजनयिकों की घाटी यात्रा को भारतीय मीडिया ने भी प्रमुखता से स्थान दिया है। बता दें कि अमेरिका, वियतनाम, बांग्लादेश, मालदीव, मोरक्को, फिजी, नार्वे, फिलीपींस, अर्जेंटीना सहित 15 देशों के राजदूतों और राजनयिकों ने इस महीने की शुरुआत में घाटी की यात्रा की थी।

हाल ही संपन्न अपनी तीन देशों की यात्रा के बाद वेल्स ने कश्मीर में विदेशी राजनयिकों की यात्रा को उपयोगी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बिना किसी बाधा के विदेशी राजनयिकों को घाटी यात्रा की अनुमति देने का आग्रह करते हैं। ऐसे सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की अपील करते हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं है। उन्होंने बताया, 'भारत यात्रा के दौरान मुझे सीएए को लेकर काफी बातें सुनने को मिलीं।

मुझे लगता है कि वहां जो कुछ भी चल रहा है, वह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। वहां लोग सड़कों पर हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों, मीडिया और अदालतों में बहस चल रही है। मैं कानून के तहत समान सुरक्षा के सिद्धांत की वकालत करती हूं।' वेल्स ने कहा कि निष्क्रिय विदेश नीति से आगे निकलकर भारत अब अपने हितों को तरजीह दे रहा है।

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के आरोपों पर विपक्ष की चर्चा पूरी

▸ अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया में आज दिया जाएगा जवाब

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की पैरोकार डेमोक्रेट सांसदों की टीम ने शुक्रवार को सीनेट में आरोपों के समर्थन में अपना वक्तव्य पूरा कर लिया। वरिष्ठ सांसद एडम स्किफ के नेतृत्व वाली प्रतिनिधि सभा की टीम ने कहा, ट्रंप ने अपने पद का दुरुपयोग किया और संसद की जांच में बाधा डाली। इस टीम ने तीन दिन में 24 घंटे तक अपनी बात रखी। शनिवार (भारतीय समयानुसार मध्य रात्रि के बाद) ट्रंप के पैरोकार आरोपों का जवाब देंगे।

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली सीनेट में प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने आरोप लगाया है कि रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में अपने बहुमत का गलत फायदा उठा रही है और वह ट्रंप पर आरोपों को लेकर भेदभाव कर रही हैं।

एडम स्किफ ने सीनेट को संबोधित करते हुए कहा, उम्मीद करते हैं कि अमेरिका को स्वच्छ न्याय मिलेगा, जो उसका अधिकार भी है। कहा, संविधान के अनुच्छेद-दो का उदाहरण देकर बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि वह किन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं। उसका उद्देश्य क्या होगा। अब ट्रंप के पैरोकारों को आरोपों का जवाब देने के लिए तीन घंटे मिलेंगे। इस दौरान ट्रंप के वकीलों की टीम और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसद अपनी बात रख सकते हैं।

अमेरिका के इतिहास में ट्रंप तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। ट्रंप कुछ भी गलत न करने के अपने बयान पर अडिग हैं। महाभियोग की प्रक्रिया को उन्होंने पूरी तरह से झूठी और राजनीतिक फायदा उठाने की नीयत वाली बताया है।

ये भी जानिए

ऑकलैंड के ईडन पार्क में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल (538) ने बनाए हैं। वह इस मैदान पर शतक लगाने वाले भी एकमात्र बल्लेबाज हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और जीत हासिल करने उतरेगी टीम इंडिया

न्यूजीलैंड के साथ दूसरा टी-20 मुकाबला आज गेंदबाजी में हो सकता है बदलाव

ऑकलैंड, प्रेट्र: भारतीय टीम के यहां ईडन पार्क में रविवार को होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले में विजेता संयोजन में बदलाव करने की संभावना नहीं है, लेकिन गेंदबाजी विभाग में कुछ बदलाव हो सकते हैं।

जसप्रीत बुमराह शुक्रवार को सीरीज के शुरुआती मुकाबले में दोनों टीमों में एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे, जिन्होंने आठ रन प्रति ओवर से कम रन खर्च किए थे। मुहम्मद शमी (चार ओवर में 53 रन देकर कोई विकेट नहीं) और शार्दुल ठाकुर (तीन ओवर में 44 रन देकर एक विकेट) पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इच्छानुसार बाउंड्री लगाईं। शमी के अंतिम एकादश में अपना स्थान बरकरार रखने की उम्मीद है, इसलिए ठाकुर की जगह नवदीप सैनी को शामिल किया जा सकता है। हालांकि, सैनी अपनी अतिरिक्त तेजी के कारण इस छोटे मैदान पर ज्यादा रन लुटा सकते हैं। यह देखना होगा कि भारत तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों और दो स्पिनरों के संयोजन पर बना रहता है या फिर कुलदीप यादव को टीम में युजवेंद्रा सिंह चहल और रवींद्र जडेजा के साथ शामिल कर सकता है। भारत के पास वाशिंगटन सुंदर दूसरा स्पिन विकल्प है। अगर भारत अतिरिक्त स्पिनर उतारता है तो ऑलराउंडर शिवम दुबे तीसरे तेज गेंदबाजी का विकल्प होंगे। परिस्थितियों को देखते हुए जडेजा और चहल ने शुक्रवार को अच्छा प्रदर्शन किया था, इन दोनों ने एक-एक विकेट लिया था। इसके अलावा चहल और कुलदीप वनडे विश्व कप समाप्त होने के बाद से एक साथ नहीं खेले हैं। बल्लेबाजी में विराट कोहली कप्तान के रूप में संतुष्ट थे, क्योंकि मध्यक्रम ने दबाव के समय में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। श्रेयस अय्यर ने 29 गेंद में नाबाद 58 रन की पारी खेलकर अपना चौथा स्थान मजबूत कर लिया है। यह दौरे की अच्छी शुरुआत थी, जिसमें टीम ने 204 रन के लक्ष्य को हासिल कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। भारतीय टीम के लिए रवानगी से पहले लगातार फेरबदल करने को लेकर चिंता बनी हुई थी जैसा कि 2019 विश्व कप से पहले वनडे टीम में हुआ था। अय्यर की फॉर्म ने उन सभी चिंताओं को समाप्त कर दिया है। इस बल्लेबाज ने पिछले साल सितंबर से भारत के सभी 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 11 पारियों में 34.14 के औसत से दो अर्धशतक जमाए और इनमें उनका स्ट्राइक रेट 154.19 रहा। लोकेश राहुल के विकेटकीपिंग कौशल के साथ मनीष पांडे और दुबे के बारी-बारी से मैच फिनिश करने की जिम्मेदारियां निभाने से भारत का टी-20 बल्लेबाजी लाइन-अप संतुलित लगता है। न्यूजीलैंड की टीम महसूस कर रही होगी कि उसका कुल स्कोर 10-15 रन कम रह गया और साथ ही मैदान में गंवाए मौकों से मेहमान बल्लेबाजों ने फायदा उठाया। न्यूजीलैंड को अगर तीन दिन के अंदर भारत की 2-0 की बढ़त को रोकना है तो उन्हें संभलना होगा। भारत ने फरवरी 2019 में भी यहां जीत हासिल की थी। हालांकि, तब तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड के वही अंतिम एकादश उतारने की उम्मीद है।

नवदीप सैनी • फाइल फोटो, एपी

अब हमें और भी ज्यादा आक्रामक गेंदबाजी करनी होगी : सोढ़ी

ऑकलैंड, प्रेट्र: न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी का मानना है कि पांच मैचों की सीरीज में वापसी के लिए दूसरे टी-20 मैच में भारत की विश्व स्तरीय बल्लेबाजी के खिलाफ उन्हें गेंद से और भी ज्यादा आक्रामक होना होगा। सोढ़ी ने शनिवार को कहा कि हमने (पहले टी-20 मैच में) 200 रन का स्कोर बनाया। अगर हम गेंद से ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं तो पहले मैच से हमारे लिए यही सीख होगी। अगर हम ज्यादा रन लुटाते हैं या फिर विकेट लेने के कुछ मौके गंवाते हैं तो आप कोशिश करने के बाद ही यह सब सीख सकते हो। आपको देखना होगा कि मैच कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन, यह हर बल्लेबाज के लिए अलग होता है और गेंदबाज के लिए भी। आपको कप्तान से चर्चा करनी होती है और गेंदबाजी इकाई से भी। मिशेल सेंटनर और मैं ऐसा काफी करते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली रात हम आउटफील्ड पर थे, हमने केन विलियमसन से इस बारे में काफी बातें कीं। मैंने दो-तीन ओवर स्पैल गेंदबाजी की और इसमें से एक रक्षात्मक स्पैल था, दूसरा आक्रामक स्पैल था। इसलिए हमें पूरे मैच में उसी आक्रामकता से गेंदबाजी करनी होगी।' इस स्पिनर ने कहा कि भारत पर दबाव बनाना मुश्किल है जिसमें कुछ विश्व स्तरीय बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को दूसरे टी-20 मैच में वापसी के लिए तरीका ढूंढना होगा। सोढ़ी ने शुक्रवार को 36 रन देकर दो विकेट झटके थे। उन्होंने कहा, 'उनकी टीम में पांच या छह विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं और जब वे फॉर्म में हों तो उन्हें रोकना हमेशा ही मुश्किल होगा। ईडन पार्क के आकार को देखते हुए भी यह चुनौती ही होगा।'

ईश बोले, न्यूजीलैंड को दूसरे मैच में वापसी के लिए कुछ और तरीका तलाश करना होगा

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित, केएल राहुल (विकेटकीपर), मनीष पांडे, रिषभ पंत, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, जडेजा, कुलदीप यादव, चहल, मुहम्मद शमी, बुमराह, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी और वाशिंगटन सुंदर।

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), मार्टिन गुप्टिल, रॉस टेलर, स्कॉट कुग्गेलिन, कोलिन मुनरो, कोलिन डि ग्रैंडहोम, टॉम ब्रूस, डेरेल मिशेल, मिशेल सेंटनर, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), हैमिश बेनेट, ईश सोढ़ी, टिम साउथी, ब्लेयर टिकनर।

केएल के विकेटकीपिंग करने से टीम इंडिया को मिल गया सही संयोजन

राहुल के 'दस्ताने' में कैद पंत का करियर

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

कर्नाटक के लिए विकेटकीपिंग करने वाले केएल राहुल भारत के लिए 36 टेस्ट, 29 वनडे और 37 टी-20 खेलने के बाद टीम इंडिया के मुख्य विकेटकीपर बन गए हैं। रिषभ पंत के चोटिल होने के कारण राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के दो वनडे में विकेटकीपिंग की थी लेकिन तब वह इसकी पहली पसंद नहीं थे लेकिन उन दो मैचों में उनकी कीपिंग और बल्लेबाजी ने विराट को असफल पंत से दूर होने का मौका दे दिया। यही कारण है कि विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 में पंत के उपलब्ध होने के बावजूद राहुल को विकेटकीपर के तौर पर उतारा और कर्नाटक के इस विकेटकीपर ने अपने ही प्रदेश के पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ की याद दिलाते हुए अर्धशतक ठोका।

द्रविड़ की याद दिलाते राहुल: राहुल द्रविड़ और केएल राहुल...दोनों ही कर्नाटक से आते हैं। एक भारत के सर्वकालिक दिग्गजों में शामिल है तो दूसरा उसका अनुसरण कर रहा है। विराट कोहली के केएल को विकेटकीपिंग देने के फैसले ने द्रविड़ की याद दिला दी। द्रविड़ मूलतः विकेटकीपर नहीं थे लेकिन इंग्लैंड में हुए 1999 विश्व कप में केन्या के खिलाफ मुकाबले में नयन मोंगिया के चोटिल होने के कारण कप्तान मुहम्मद अजहरुद्दीन ने उन्हें दस्ताने थमाए। द्रविड़ ने इससे पहले प्रथमश्रेणी मैच में सिर्फ एक स्टंपिंग की थी। वह श्रीलंका के खिलाफ टांटन में अगले मैच में भी विकेटकीपर के तौर पर उतरे और पूरे 50 ओवर दस्ताने थामे रहे। खास बात यह रही कि इन दोनों मैचों में द्रविड़ ने शतक ठोंका। सौरव गांगुली की कप्तानी में पहली बार द्रविड़ ने जून 2000 में ढाका में श्रीलंका के खिलाफ विकेटकीपिंग की। दक्षिण अफ्रीका में हुए 2003 विश्व कप में सात बल्लेबाज खिलाने के लिए गांगुली ने वर्ष 2002 से ही द्रविड़ को वनडे में स्थायी विकेटकीपर बना दिया। वह विश्व कप में भी विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर खेले। वर्ष 2004 तक विकेटकीपिंग का सिलसिला लगातार जारी रहा।

टी-20 विश्व कप की तैयारी: खास बात यह है कि कभी बल्लेबाज की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज की तरह अंतिम-11 में फिट करने वाले कप्तान सौरव गांगुली अब बीसीसीआइ अध्यक्ष हैं और वह रिषभ पंत के खेल को पसंद भी करते हैं। रिषभ आइपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य बल्लेबाज हैं और पिछले साल गांगुली उसी टीम के सलाहकार थे। अब विराट ने गांगुली के पुराने दांव को ही चलकर पंत को अंतिम-11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अपने दोस्त राहुल की गोटी फिट कर दी है। अगर ओपनर शिखर धवन फिट भी हो जाते हैं तो विराट राहुल को विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप में खिला सकते हैं क्योंकि राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में पांचवें नंबर पर भी अच्छी बल्लेबाजी की थी।

पंत को नुकसान: दिल्ली के युवा विकेटकीपर पंत पर टीम प्रबंधन ने पूरा विश्वास जताते हुए लगातार मौके दिए, लेकिन उन्होंने हर मोर्चे पर निराश किया। 11 टेस्ट, 16 वनडे और 27 टी-20 खेलने वाले पंत की विकेटकीपिंग कुछ खास नहीं है लेकिन बल्लेबाजी में एक्स फैक्टर के कारण उन पर ऐतबार जताया जा रहा था। टीम को लगता था कि वह महेंद्र सिंह धौनी की जगह ले लेंगे लेकिन वह अपनी भूमिका समझने में नाकाम रहे। राहुल जिस फॉर्म में हैं उसे देखते हुए पंत को फिलहाल तो मौका मिलते नजर नहीं आ रहा है। इस बारे में विराट ने भी कहा था कि केएल, राहुल द्रविड़ की तरह विकेटकीपिंग करके टीम का संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें अंतिम एकादश में एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाने का मौका मिल रहा है।

केएल राहुल • फाइल फोटो, एएफपी

राहुल पर फैसला टीम प्रबंधन का : गांगुली

नई दिल्ली : बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने लोकेश राहुल के प्रदर्शन की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि वह टेस्ट में भी अपनी इस फॉर्म को जारी रखेंगे। पंत की जगह राहुल को अंतिम एकादश में खिलाने पर गांगुली ने कहा कि विराट कोहली यह फैसला लेते हैं। टीम प्रबंधन और कप्तान राहुल की भूमिका पर फैसला लेते हैं। उन्होंने (राहुल) वनडे और टी-20 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा किया था लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन नीचे गिरता गया। सीमित ओवरों के प्रारूप में वह काफी अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद है वह अपने इस अच्छे खेल को आगे भी जारी रखेंगे। टी-20 विश्व कप में विकेटकीपरों के बीच रेस के सवाल पर बीसीसीआइ अध्यक्ष ने कहा कि चयनकर्ता, विराट और रवि (शास्त्री) इस पर निर्णय लेंगे। वे जो भी सोचेंगे, वैसा ही होगा।

12 टी-20 मैच खेले गए हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक। इनमें से भारत ने चार और न्यूजीलैंड ने आठ मैच जीते हैं

06 टी-20 मैच हुए हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक न्यूजीलैंड में। इनमें से दो भारत और चार न्यूजीलैंड जीता है

02 टी-20 मैच हुए हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में अब तक। इन दोनों में ही भारत ने जीत दर्ज की। भारत को इनमें से एक जीत मौजूदा सीरीज के पहले मैच में मिली

02 टी-20 मैच भारत ने जो ऑकलैंड में जीते हैं उन दोनों में ही उसने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है। यहां भारत के पास अब अपनी जीत की हैट्रिक पूरा करने का मौका है

एक नजर में

भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराया

ऑकलैंड: कप्तान रानी रामपाल के दो गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को न्यूजीलैंड डेवलपमेंट टीम पर 4-0 की जीत के साथ ओलंपिक वर्ष का पहला दौरा शुरू किया। रानी के दो गोल के अलावा शर्मिला और नमिता टोप्पो ने गोल किए। भारतीय टीम गुरुवार को यहां पहुंची और वह मेजबानों से चार मुकाबलों में आमने सामने होगी। इसके अलावा भारतीय टीम एक मैच में ब्रिटेन से भिड़ेगी। भारतीय टीम ने 1-0 की बढ़त बनाने के बाद लगातार पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए लेकिन इन्हें गोल में नहीं बदल सकी। युवा शर्मिला ने फिर तीसरे क्वार्टर में बढ़त दोगुनी कर दी और फिर रानी ने चौथे क्वार्टर में अपना दूसरा गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया। नमिता टोप्पो ने भारतीय टीम के लिए चौथा गोल दागा। (प्रेट्र)

पुरुष हॉकी टीम के कैंप के लिए 32 खिलाड़ी चयनित

नई दिल्ली: हॉकी इंडिया ने चोट से वापसी करने वाले ड्रैगफ्लिकर वरुण कुमार को शनिवार को पुरुष राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए चुने 32 खिलाड़ियों में शामिल किया। विश्व चैंपियन बेल्जियम के खिलाफ अगले महीने होने वाले एफआइएच प्रो लीग मुकाबले के लिए यह शिविर लगाया जाएगा। नीदरलैंड पर एफआइएच हॉकी प्रो लीग में शानदार जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम अब भुवनेश्वर में शिविर में हिस्सा लेगी। बेल्जियम के खिलाफ यह मैच आठ और नौ फरवरी को खेला जाएगा। कोर ग्रुप में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है जिसमें पीआर श्रीजेश, कृष्ण बहादुर पाठक, सूरज कार्केरा, हरमनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार, बीरेंद्र लाकड़ा, रूपिंदर पाल सिंह, गुरिंदर सिंह, अमित रोहिदास, कोथाजीत सिंह खडांगबम, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, नीलकांत शर्मा और विवेक सागर प्रसाद शामिल हैं। चिंगलेनसाना सिंह का भी नाम युवा स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह, राजकुमार पाल, नीलम संदीप जेस, दिप्सन टिर्की, एसवी सुनील, आकाशदीप सिंह, रमनदीप सिंह, सिमरनजीत सिंह, मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, गुरसाहिबजीत सिंह, शमशेर सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, जसकरण सिंह, गुरजंट सिंह और सुमित भी शामिल हैं। (प्रेट्र)

एसीसी अनुमति दे तो तटस्थ स्थल पर एशिया कप खेल सकता है भारत : वसीम

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) वसीम खान ने शनिवार को संकेत दिए कि यदि खेल की महाद्वीपीय संस्था अनुमति दे तो एशिया कप में भारत के लीग मैच तटस्थ स्थल पर हो सकते हैं। हालांकि, पहले खबरें आ रही थीं कि वसीम खान ने धमकी दी है कि अगर भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तानी टीम भी 2021 में भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप में भाग लेने से इन्कार कर देगी।

पाकिस्तान को इस साल सितंबर में एशिया कप टी-20 टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है, लेकिन मौजूदा राजनैतिक माहौल को देखते हुए भारत की भागीदारी पर संदेह बना हुआ है। यह कहते हुए कि इसका फैसला एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) करेगी, पीसीबी के सीईओ ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि यदि भारत एशिया कप में नहीं खेलेगा तो वह 2021 में होने वाले टी-20 विश्व कप में नहीं खेलेंगे, जिसकी मेजबानी भारत करेगा, क्योंकि यह एक आइसीसी का टूर्नामेंट है। खान ने कहा, 'सवाल यह है कि यदि भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करता है तो क्या होगा? मेरी प्रतिक्रिया पर एसीसी को फैसला लेने की जरूरत है, लेकिन जब से हमें मेजबानी के अधिकार दिए गए हैं, हम पूरी तरह से एशिया कप को पाकिस्तान में आयोजित करने की उम्मीद कर रहे हैं। एसीसी को तब यह फैसला करने की जरूरत होगी कि भारत के मैच कहां खेले जाएंगे।'

जब यह पूछा गया कि भारत अपने मैच तटस्थ स्थल पर खेल सकता है तो खान ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'शायद। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल होता है तो यह एसीसी पर निर्भर करता है कि वह फैसला करे कि फाइनल कहां खेला जाएगा। अभी तक प्रारूप और कार्यक्रम को लेकर अभी तक कोई अंतिम चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यह आइसीसी का फैसला होगा।' खान ने पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का जोरदार खंडन किया जिनमें कहा गया कि पीसीबी 2021 में भारत में टी-20 विश्व के लिए अपनी टीम नहीं भेजेगा। पीसीबी के सीईओ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कभी भी नहीं कहा कि पाकिस्तान भारत का दौरा नहीं करेगा।

पीसीबी सीईओ ने टी-20 विश्व कप से पाकिस्तान के हटने की धमकी का किया खंडन

खलील भारत-ए के न्यूजीलैंड दौरे से बाहर

क्राइस्टचर्च, प्रेट्र: बायें हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद कलाई की चोट के कारण शनिवार को भारत-ए के न्यूजीलैंड के मौजूदा दौरे से बाहर हो गए।

बीसीसीआइ के बयान के मुताबिक, 'खलील अहमद 22 जनवरी को लिंकन में न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ भारत-ए के वनडे मैच के दौरान अपनी कलाई में फ्रेक्चर करा बैठे। उनके हाथ में प्लास्टर बंधा है जिससे बायें हाथ का यह तेज गेंदबाज भारत-ए के बचे हुए दौरे पर नहीं खेल पाएगा। एनसीए उसका रिहैबिलिटेशन देखेगा।' बीसीसीआइ ने हालांकि इस तेज गेंदबाज की जगह किसी अन्य के नाम की घोषणा नहीं की है। भारत के लिए 11 वनडे और 14 टी-20 मैच खेल चुके खलील ने न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ दूसरे वनडे में आठ ओवर में 46 रन देकर दो विकेट लिए थे, जबकि पहले वनडे में 9.1 ओवर में 43 रन देकर चार विकेट झटके थे।

बुंडिशलीगा में हालैंड का जलवा बरकरार

डोर्टमंड, रायटर: अपने पदार्पण मुकाबले में हैट्रिक लगाने वाले बोरुसिया डोर्टमंड के युवा स्टार इर्लिंग हालैंड (77वें व 87वें मिनट) का जलवा लगातार दूसरे मुकाबले में भी जारी रहा, जिन्होंने दो और गोल करते हुए जर्मन फुटबॉल लीग बुंडिशलीगा में अपनी टीम को कोलोग्ने पर 5-1 से जीत दिलाई। हालैंड बुंडिशलीगा के शुरुआती दो मैचों में पांच गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने।

वहीं, हालैंड के साथी खिलाड़ी 19 वर्षीय जॉर्डन सांचो ने लीग में अपना 11वां गोल दागा। खेल के पहले ही मिनट में राफेल ग्यूरेरो ने गोल करके डोर्टमंड को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि मार्को रीउस (29वें मिनट) ने टीम को पहले हाफ में दोहरी बढ़त दिलाई। जॉर्डन (48वें मिनट) ने दूसरे हाफ के शुरुआती मिनटों में गोल दागकर अपनी टीम को एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर कर दिया। इसके बाद 65वें मिनट में स्थानापन्न के तौर पर उतरे हालैंड ने दो गोल दागे। जर्मन लीग के दोनों मुकाबलों में हालैंड ने पिच पर कुल 59 मिनट बिताए हैं और इस दौरान पांच गोल दागे हैं। नॉर्वे का यह स्टार ऑस्ट्रिया के क्लब सल्जबर्ग को छोड़कर डोर्टमंड जुड़ा था।

हैरी पोटर के स्टार भरेंगे एफए कप में जोश

लंदन, एएफपी: इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब बॉर्नेमाउथ के मैनेजर इडी होव को उम्मीद है कि हैरी पोटर फिल्म के स्टार उनकी एफए कप में सोमवार को आर्सेनल के खिलाफ होने वाली भिड़ंत में जादुई असर दिखा सकती है। हैरी पोटर फिल्म सीरीज में फ्रेड विस्ले की भूमिका निभाने वाले जेम्स फेल्प्स बॉर्नेमाउथ के अभ्यास सत्र में दिखाई दिए। होव ने कहा कि सच बताऊं तो मुकाबले के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी जादू की उम्मीद कर रहे हैं। अगर कोई जादू होता है तो हम इसे स्वीकार करेंगे।

फुटबॉल डायरी

- जर्मन लीग के पहले दो मैचों में पांच गोल करने वाले पहले खिलाड़ी
- डोर्टमंड ने कोलोग्ने को 5-1 से पराजित किया

रेबिक ने मिलान को दिलाई जीत: इटालियन फुटबॉल लीग सीरी-ए में एसी मिलान ने ब्रेसिया को 1-0 से हरा दिया, जहां एंटी रेबिक ने मुकाबले का इकलौता गोल दागा। वहीं, इस मुकाबले के दौरान 38 वर्षीय ज्लाटन इब्राहिमोविच गोल करने का एक आसान मौका चूक गए। खेल के 40वें मिनट में इब्राहिमोविच को थियो हर्नांडेज से मिले क्रॉस को केवल छह मीटर की दूरी से गेंद को गोल पोस्ट में डालना था, लेकिन वह गेंद को बाहर मार बैठे।

राफा ने बुस्टा को हराया, फेडरर का मैच देखने के बाद बिना सोए कोर्ट पर उतरे थे स्पेनिश स्टार

राफेल नडाल ने बनाई चौथे दौर में जगह

मेलबर्न, एएफपी: दुनिया के नंबर एक पुरुष खिलाड़ी राफेल नडाल ने आसान जीत के साथ साल के पहले ग्रैंडस्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली।

स्पेन के स्टार नडाल शुक्रवार को देर रात रोजर फेडरर के जॉन मिलमैन के खिलाफ रोमांचक मुकाबले को देखने के बाद हमवतन पाब्लो कारेनो बुस्टा के खिलाफ रॉड लेवर एरीना पर उतरे। फेडरर और मिलमैन के मैच को लेकर 33 वर्षीय नडाल ने कहा, 'मैंने यह मैच रात एक बजे तक देखा। इस मैच को देखे बिना नींद आना असंभव था।' उन पर थकान का कोई असर नहीं दिख रहा था और उन्होंने एक घंटे 38 मिनट तक चले पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर के मुकाबले में 6-1, 6-2, 6-4 से जीत हासिल की। नडाल मेलबर्न में जीत के साथ फेडरर के रिकॉर्ड 20 ग्रैंडस्लैम खिताब की बराबरी कर सकते हैं।

अन्य नतीजों में ऑस्ट्रिया के पांचवीं वरीय डोमिनिक थिएम ने टेलर फ्रिट्ज को 6-2, 6-4, 6-7, 6-4 से पस्त किया। वहीं, रूस के आंद्रे रूबलेव ने डेविड गोफिन पर 2-6, 7-6, 6-4, 7-6 से जीत हासिल की। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फर्नांडो वर्डास्को को 6-2, 6-2, 6-4 से हराकर अंतिम-16 में प्रवेश किया। 2014 के चैंपियन स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका भी चौथे दौर में पहुंच गए हैं। तीसरे दौर में वावरिंका जब जॉन इस्नर के खिलाफ 6-4, 4-1 से आगे चल रहे थे तब उनके विरोधी ने चोट की वजह से हटने का फैसला किया।

मोंफिल्स की सफाई: वहीं, गाएल मोंफिल्स ने ईर्नेस्ट गुल्बिस को 7-6, 6-4, 6-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। मालूम हो कि मोंफिल्स के टूर्नामेंट से पहले कंप्यूटर वीडियो गेम खेलते हुए चोटिल होने की खबर आई थी जिस पर उन्होंने सफाई दी। मोंफिल्स ने कहा मैंने चोट की खबर को मजाकिया लहजे में कहा था, लेकिन चूंकि मैं बिलकुल ठीक हूं इसलिए आपका अपमान हो गया। मैं अच्छी टेनिस खेल रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे चोट लग गई थी। प्ले स्टेशन में खेलते हुए कैसे चोट लग सकती है।

मैच के दौरान राफेल नडाल • एएफपी

विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप आगे बढ़ीं, प्लिस्कोवा बाहर

मेलबर्न: विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप ने शनिवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ अंतिम-16 में जगह बनाई। वहीं, अमेरिका की दिग्गज सेरेना विलियम्स और गत चैंपियन नाओमी ओसाका के बाहर होने के एक दिन बाद दूसरी वरीय कैरोलिना प्लिस्कोवा का सफर भी महिलाओं के ड्रॉ से खत्म हो गया। इस तरह शीर्ष तीन वरीय महिला खिलाड़ियों में से प्लिस्कोवा और ओसाका के हारने से हालेप और 2016 की विजेता एंजिलिक कर्बर के लिए बड़ी बाधा हट गई। हालेप ने कजाखिस्तान की यूलिया पुतिंतसेवा को 6-1, 6-4 से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई, जिसमें उनका सामना बेल्जियम की एलिस मर्टन्स से होगा, जिन्होंने सिसी बेलिस के खिलाफ 6-1, 6-7, 6-0 से जीत हासिल की। वहीं, कर्बर ने कैमिला जॉर्जी को 6-2, 6-7, 6-3 से शिकस्त दी और अब उनकी भिड़ंत रूस की 30वीं वरीय अनास्तासिया पावलीयुचेंकोवा से होगी, जिन्होंने प्लिस्कोवा को 7-6, 7-6 से पराजित किया। स्विट्जरलैंड की छठी वरीय बेलिंडा बेनसिक ने इस्टोनिया की एनेट कोंटावेट के खिलाफ केवल एक ही गेम जीता और वह 0-6, 1-6 से हारकर बाहर हो गईं। क्रोएशिया की 19वीं वरीय डोना वेकिच भी अपने से निचली रैंकिंग की पोलैंड की इगा स्वियाटेक से 5-7, 3-6 से हार हो गईं। वहीं, दो बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन गर्बाइने मुगुरुजा ने पांचवीं वरीय एलीना स्वितोलीना को आसानी से सीधे सैटों में 6-1, 6-2 से पराजित किया।

> यह इस टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बेहतरीन मैच था। मैं दिन ब दिन सुधार कर रहा हूं इसलिए मैं बेहद खुश हूं। मैंने अच्छी सर्विस की और अच्छे फोरहैंड लगाए, जो मेरी जीत के अहम कारण रहे।
>
> **राफेल नडाल**, स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी

शॉट लगाती सिमोना हालेप • एपी

पाकिस्तान ने बांग्लादेश से जीती टी-20 सीरीज

लाहौर, प्रेट्र: कप्तान बाबर आजम और सीनियर बल्लेबाज मुहम्मद हफीज के अर्धशतकों की मदद से पाकिस्तान ने यहां शनिवार को बांग्लादेश को दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में नौ विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने 2-0 की अजेय बढ़त बनाते हुए सीरीज पर कब्जा जमाया।

पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज अहसान अली (00) का विकेट दूसरे ओवर में ही गंवा दिया। तेज गेंदबाज सैफुल इस्लाम की गेंद पर महमूदुल्लाह ने उनका कैच लपका। इसके बाद दुनिया के नंबर एक टी-20 बल्लेबाज बाबर ने अपना 13वां अर्धशतक जड़ते हुए 44 गेंदों पर नाबाद 66 रन बनाए, जबकि हफीज 49 गेंदों पर नाबाद 67 रन की पारी खेली। आजम ने सात चौके व एक छक्का जड़ा, जबकि हफीज ने अपनी 11वीं अर्धशतकीय पारी में नौ चौके व एक छक्का लगाया। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 131 रन की अटूट साझेदारी निभाई, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 137 रन का लक्ष्य 16.4 ओवर में हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने लगातार दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज तमीम इकवाल के 53 गेंदों पर 65 रनों के बावजूद बांग्लादेश की टीम एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में असफल रही और 20 ओवर में सिर्फ छह विकेट पर 136 रन ही बना सकी।

तंत्र के गण

उत्सव गणतंत्र का...

यह प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के छोटे से गांव सराही के लोगों की है, जिन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण-संवर्द्धन को लेकर जो जज्बा दिखाया, उसकी कीर्ति प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची और सरकार उस झील को पक्षी विहार बनाने के लिए प्रेरित हुई, जो सूख चुकी थी और ग्रामीणों ने श्रमदान कर जिसे नया जीवन दिया। अब यह झील सैकड़ों पक्षियों का बसेरा है (दाएं)।

जीवन का अधिकार

जीवन के मूल अधिकार में जल और पर्यावरण संरक्षण का ध्येय भी समाहित है।

18 को जागरण ने प्रकाशित की थी कहानी, 23 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया निर्देश

सराही के नायकों की हर ओर सराहना

जज्बे को सलाम, सूखाग्रस्त गांव में बना दी सात किमी नहर

राधाकिशन शर्मा • बिलासपुर।

शासन के भरोसे विकास की आस लगाए बैठे ग्रामीणों के लिए युवाओं की एक टीम ने नई उम्मीद जगा दी है। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का गांव फूलवारी समस्या ग्रस्त है। यहां पथरीली व असमतल जमीन बड़ी समस्या थी। यहां शासन की ओर से नहर निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। इस बीच युवा नितेश साहू व उनकी टीम ने पहल की। ग्रामीण भी उनके सहयोग में आगे आए। अब करीब सात किलोमीटर की कच्ची नहर तैयार हो गई है।

फूलवारी के ग्रामीणों को पिछले तीन वर्षों से गर्मी के दिनों में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तीन से चार किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। फूलवारी से लगा हुआ ग्राम फूलझर है। नितेश साहू को स्वच्छता व जल संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। नितेश ने युवाओं की टीम तैयार की और करीब 2500 की आबादी वाले फूलवारी गांव पहुंचे। ग्रामीणों को इकठ्ठा किया। पीएम मोदी की योजना के बारे में विस्तार से बताया। जल संकट को दूर करने के लिए पहले जल संरक्षण की आवश्यकता बताई और अपना काम शुरू कर दिया। पहले दिन नितेश के साथ 20 युवाओं की टीम ने काम संभाला। बस्ती से लगी हुई जमीन जहां बारिश का पानी आसानी के साथ एकत्रित हो सकता है उसका चयन किया। इसके बाद नहर की खोदाई में जुट गए। 20 दिन बाद ग्रामीणों की भीड़ वहां इकठ्ठी हो गई। युवाओं ने ग्रामीणों की मदद से पथरीली जमीन पर नहर बनाना शुरू किया। चार महीने की कड़ी मेहनत रंग लाई। अब सात किलोमीटर लंबी नहर लाइन बिछा दी गई है। वर्षों से बंजर जमीन पर पानी की धारा बहने लगी है। नितेश कहते हैं, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में कई नाले रखरखाव के अभाव में मृत हो गए हैं, अब इनकी बारी है।

सूखी झील को ग्रामीणों ने दिया नवजीवन, पीएमओ ने कहा बनाएंगे पक्षी विहार

25 जनवरी को जब दैनिक जागरण की टीम सराही गांव पहुंची तो मानो उत्सव का माहौल था। गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर यह उत्सव दोगुने उत्साह से भरा प्रतीत हो रहा था। गांव का हर व्यक्ति दैनिक जागरण में प्रकाशित उस खबर की चर्चा में रत था, जिसमें यह लिखा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार को निर्देश देकर सराही की झील को पक्षी विहार के रूप में विकसित करने को कहा है...।

जगदीप शुक्ल की रिपोर्ट।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित गांव सराही में दैनिक जागरण में अपने गांव की गौरवगाथा पढ़ते ग्रामीण। दूरदर्शन ने बनाई फिल्म। • जागरण

सराही गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य मो. शुएब इंटरवल में सभी बच्चों से रूबरू हैं। उनके हाथों में दैनिक जागरण है। वह इसमें छपी सराही की खबर पढ़कर विद्यार्थियों को सुना रहे हैं। इसके साथ ही वह गांव के लोगों के जज्बे को सराहते हुए उनसे सीख लेने की बात कह रहे हैं। इसी तरह चौपाल में भी एक बुजुर्ग खबर पढ़कर सुना रहे हैं...।

दैनिक जागरण की टीम अभी-अभी यहां पहुंची है। मो. शुएब इससे बेखबर बच्चों को बताने में जुटे हैं कि ग्रामीणों ने श्रमदान से झील को जीवनदान देकर कितना महान काम किया है। यह भी समझाते हैं कि सराही झील आसपास के गांवों के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी। तभी वहां दूरदर्शन की टीम पहुंचती है। इसे देख मो. शुएब बच्चों से झील को नवजीवन देने वाले नायकों का अनुसरण करने की अपील करके बात खत्म कर देते हैं। यह सिर्फ एक तस्वीर है। चौपाल से लेकर खेत-खलिहान तक गांव के इन नायकों की सराहना के स्वर गूंज रहे हैं। दैनिक जागरण ने इनके जजबे और हौसले से पूरे देश को परिचित कराया तो दूरदर्शन अब सबको इसका दीदार कराने के लिए यहां आया है।

रूठे मेहमान को मनाने को श्रमदान : दशक भर के भीतर गांव के लोगों ने सराही झील को सूखने की कगार पर पहुंचते देखा। कई हैंडपंप भी सूख गए। झील में पानी बेहद कम होने के चलते कई वर्षों से प्रवासी परिंदे यहां आना छोड़ चुके थे। गांव के हर शख्स को यह अखरता था। यह कलरव फिर कैसे गूंजे, इसकी युक्ति सुशील सिंह ने निकाली। सबने श्रमदान से झील को जिंदा करने की युक्ति को सराहा और साथ चल पड़े। इस तरह सराही, मीरनगर और बनगांवा के लोगों ने काम शुरू किया। 20 जून 2019 से 10 जुलाई 2019 तक श्रमदान करके ग्रामीणों ने असंभव लगते काम को संभव कर डाला। बारिश से पहले काम पूरा करने के लिए तीन-चार दिन जेसीबी भी चलवाई। इसका भुगतान भी ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से किया। झील के निचले किनारों पर बांध बनाने के बाद अभी पूरब दिशा में झील की मेड़बंदी बाकी है। इसके लिए ग्रामीणों में जोश नजर आता है। गांव के लोग श्रमदान करके इसे निपटाने के लिए तैयार हैं। सराही झील के नायक सुशील सिंह, अजीत प्रताप सिंह, दिलीप सिंह, रंगीलाल, रामलखन, रामनरेश, सचिन, नौमीलाल, परौती, रामसिंह आदि का कहना है कि उन्हें दोबारा मौका मिला तो बढ़ चढ़कर श्रमदान करेंगे। झील के कायाकल्प में सहयोग देने वाले सराही की ग्राम प्रधान सरपता और मीरनगर के ग्राम प्रधान ज्ञान मिश्र आगे भी इसके लिए तैयार हैं। ये सभी अब झील के पक्षी विहार बनाए जाने की खबर से उत्साहित है।

छिछले भाग में पसाढ़ी चावल भी होता है

सराही झील बहुत पुरानी बताई जाती है। यह दरियाबाद-टिकैतनगर मार्ग के किनारे स्थित है। राजस्व अभिलेखों में यह नहर और झील के रूप में दर्ज है। इसका हिस्सा मुख्य रूप से सराही और बनगांवा ग्राम पंचायत में आता है। 43 हेक्टेयर की इस झील का हिस्सा सराही ग्राम पंचायत में 27.5 और बनगांवा में 15.5 हेक्टेयर आता है। छिछले भाग में पसाढ़ी चावल भी होता है। इन दिनों झील कपासी हंस, भूरे रंग की टिटहरी, घोंघिल, जघिल, सारस, सैंडपाइपर, सेल्ही, लाल एनजन, कपासी चील, मुस्लिहिया आदि पक्षियों से गुलजार है।

झील की उपयोगिता

- झील भूजल स्तर को बढ़ाती है और आसपास के वातावरण को सुहावना बनाती हैं।
- इसके अंदर गाद जमा होती है, जिससे जलीय पारिस्थितिक तंत्र को ताजे पोषक तत्व मिलते रहते हैं।
- कार्बन को पृथक करने का भी कार्य करती हैं जिससे जलवायु शुद्ध होती ही रहती है, जो कि मानव के हितकारी है।
- झील अपने अंदर बड़ी मात्रा मे जल समाहित कर लेती हैं, जिससे बाढ़ की संभावना कम होती है।
- झील आमोद-प्रमोद और मनोरंजन का वातावरण भी बनाती हैं, इससे मछली सहित कई खाद्य पदार्थ मिलते हैं।

इनके प्रयासों से गूंजा कलरव

करीब एक दशक से जलस्तर में गिरावट के चलते पीने के पानी और सिंचाई को लेकर आनी वाली दिक्कतों में अब राहत मिली है। एक साल पहले तक 45 फीट पर भी पानी नहीं मिलता था। गांव में कई हैंडपंप सूख गए थे। अब फिर पाने देने लगे हैं। इससे गांव की प्रगति के द्वार खुलेंगे।

ज्ञान मिश्रा, प्रधान मीननगर।

यह बहुत पुरानी झील है। झील के सूख जाने के कगार पर पहुंच जाने के चलते प्रवासी पड़्क्षरदे रूठ गए थे। सुशील सिंह ने बांध के जरिये इसमें पानी का ठहराव रोकने की बात कही। इस पर मुझसे जो बन पड़ा सहयोग किया। आज पक्षियों का दोबारा आना अच्छा लग रहा है।

अजीत सिंह, सराही।

झील सूखी तो नगर पंचायत टिकैतनगर के चेयरमैन और विधायक दरियाबाद से गुहार लगाई गई लेकिन, फिर भी झील के अस्तित्व को बचाने को लेकर कोई पहल नहीं की गई। ग्रामीणों के सहयोग से बांध बनवाकर पानी का ठहराव किया गया, जिससे फिर से प्रवासी पक्षियों का कलरव गूंज रहा है।

-दिलीप सिंह, पर्यावरण प्रेमी

वर्ष 1980 के दशक में नाले के जरिए सरयू से मगरमच्छ सराही झील में आ जाते थे। तब झील में पानी खूब रहता था। धीरे-धीरे झील का पानी सूखने लगा। बारिश का जो पानी झील में आता था वह नाले के जरिए सरयू में बह जाता था। अब दोबारा पानी और पड़्क्षरदों से झील आबाद है।

-राम नरेश, कंचनपुर।

शिखर पर निस्वार्थ सेवा कर रही हैं परीकुल

रीतिका मिश्रा • नई दिल्ली

केदारनाथ के ऊंचे हिमाल शिखरों पर निस्वार्थ सेवा कर रही 13 वर्षीय परीकुल भारद्वाज की उड़ान हौसलों से भी ऊपर है। इतनी कम उम्र में परीकुल ने उच्च शिखरों पर जोखिम उठाकर नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा की मिसाल पेश की है। बेहद कठिन इलाके में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सहायता प्रदान करती है परीकुल।

ये परीकुल के बुलंद हौसलें ही है जो उन्हे उनके द्वारा किए गए काम के लिए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। राजधानी दिल्ली की रहने वाली परीकुल अभी दिल्ली कैंट स्थित माउंट सेंट मैरी स्कूल में कक्षा नौंवी की छात्रा है। परीकुल बताती है उनके लिए तीर्थयात्रियों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है।

45 तीर्थयात्रियों को बचाई जान : परीकुल ने 2 जून 2019 को 14 हजार फीट की ऊचाई पर अचानक बर्फीली हवाओं के चलते हताहत और बीमार पड़े 45 तीर्थयात्रियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परीकुल ने ऊचाई वाले इलाको में बचाव कार्य के लिए संयुक्त अभ्यास के तहत सिक्स सिग्मा के साथ आइटीबीपी, एनडीआरएफ, बीएसएफ और वायु सेना से भी प्रशिक्षण लिया है। वो अपने प्रशिक्षण के कठोर दिनों को याद करते हुए बताती है कि एक बार उनको रस्सी पकड़ कर पहाड़ से नीचे उतरना था। उनको इसमें बहुत डर लग रहा था फिर उनकी मां ने उनसे कहा कि अगर रस्सी पकड़ कर वो नीचे नहीं उतरी तो वो उन्हें पहाड़ से सीधा धक्का दे देंगी फिर ऊचाई से सारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। उनकी मां के इतने कहने पर ही उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरना शुरु कर दिया। और धीरे- धीरे उनका पहाड़ों से डर कब प्रेम में बदल गया पता हीं नही चला। ऊंचे पर्वतों पर किसी की जान बचाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हैं। वे इतनी ऊंचाइयों पर अपनी समाज सेवी गतिविधियों द्वारा समाज हित योगदान देने वाली, लोगों की जान बचाने के लिए कार्य करने वाली सबसे कम आयु की पहली युवती हैं। उन्होंने समाज के प्रति असाधारण, साहस, बहादुरी, जुनून, समर्पित सेवा भाव और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। वे किसी भी वर्ग, पंथ,धर्म या जाति इत्यादि की परवाह किए बिना उच्च शिखरों पर जोखिमों से भरी होने पर भी अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। अपने 2017, 2018 और 2019 में लगातार तीन वर्षों से वे अपने ग्रीष्मावकाश के दौरान, हिमालय की ऊंची चोटियों पर निस्वार्थ रूप से प्रतिवर्ष अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 45 दिनों तक केदारनाथ के दर्शनों के लिए आए तीर्थ यात्रियों की 14000 फीट पर सात डिग्री तापमान में अथक सेवा प्रदान करती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 में केदारनाथ यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने परीकुल को लोगो की सेवा करते देखा और वो परीकुल के इस जुनून से इस कदर प्रभावित हुए की न सिर्फ परीकुल से आकर मिले बल्कि उसके बुलंद हौसलों से प्रभावित होकर परीकुल के बारे में सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया।

माता और पिता ने किया प्रेरित : परिकुल बताती है कि पहले उनके माता-पिता साल 2009 से लगातार केदारनाथ यात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सेवाएं देकर मदद करते आए है। लेकिन, साल 2013 में जब परिकुल की गर्मी की छुट्टियां पड़ी तो उनके माता- पिता परीकुल को भी केदारनाथ साथ ले गए। जिसके बाद परिकुल ने खुद आगे बढ़कर श्रद्धालुओं की मदद की। श्रद्धालुओं के प्रति इस कदर सेवा का भाव देखकर परीकुल के माता-पिता ने उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया ताकि वो पहाड़ों के मौसम और रास्तों के प्रति खुद को बेहतर तैयार कर पाए। परीकुल के पिता डॉ. प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि वो बेटी को मिले सम्मान से बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार एक अच्छे विचार व संस्कार का नतीजा है। बेटी ने पूरे परिवार व देश का मान बढ़ाया है। वे इस कम आयु में ही राष्ट्र के लिए गौरव सिद्ध हुई हैं।

केदारनाथ में मौजूद एक चिकित्सा केंद्र में सेवाएं देने के दौरान परीकुल। जागरण

- राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया।
- कहती हैं, मेरे लिए तीर्थयात्रियों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है।

भीख नहीं, सीख से बदल रहीं गरीब बच्चों की जिंदगी

संजय वर्मा • पटियाला

गरीबी उन्मूलन

जरूरतमंदों को भीख नहीं, सीख देने के संकल्प पर चलते हुए पटियाला की मुखविंदर ने भीख मांगने वाले एक दर्जन से अधिक बच्चों की जिंदगी बदल दी है। मुखविंदर के समर्पण और मेहनत का ही सुखद परिणाम है कि ये बच्चे भीख मांगने के बजाय अब अपना काम कर कर रहे हैं। मुखविंदर की आर्थिक मदद से ये बच्चे अब गुब्बारे, भेलपूरी और खाने-पीने की अन्य चीजें बेच रहे हैं। यह छोटा सा प्रयास धीरे-धीरे ही सही समाज की तस्वीर बदल रहा है। मुखविंदर कहती हैं कि छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदली जा सकती है।

हर किसी की मदद का ऐसे लिया संकल्प : निजी स्कूल में अध्यापिका मुखविंदर आज से पांच साल पहले एक आम एक नागरिक की तरह जिंदगी जी रही थी। उस दौरान उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा था। उनको अस्पताल ले जाने में किसी ने भी मदद नहीं की। किसी तरह उनको अस्पताल पहुंचाया गया। पिता की जान बच तो गई, लेकिन इस घटना ने मुखविंदर की जिंदगी बदल दी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करेंगी। उनके मन में सवाल उठा कि लोगों की किस तरह मदद करें। इस दौरान उन्होंने देखा कि ट्रैफिक लाइटों और धार्मिक स्थल के पास छोटे-छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। मुखविंदर ने उन बच्चों से बात की तो पता लगा कि उनके माता-पिता इतने समर्थ नहीं हैं कि वे उन्हें पढ़ा सकें। घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। उसी दिन मुखविंदर ने फैसला लिया कि वे ऐसे बच्चों की छोटा-मोटा काम शुरू करवाने में मदद करेंगी। इसके लिए उन्होंने मुख टीम फॉर नीडी का गठन किया। इसके जरिये मुखविंदर ने गरीब बच्चों को आर्थिक मदद शुरू कर दी, ताकि वे गुब्बारे और खाद्य पदार्थ बेचने का काम शुरू कर सकें। वह उन बच्चों से समय-समय पर मिलती भी रहती हैं, ताकि उनका मार्गदर्शन होता रहे। वह स्कूल से मिलने वाला वेतन इन बच्चों की सहायता पर खर्च कर देती हैं।

नमकीन बेच रहे राहुल और रणजीत के साथ मुखविंदर और उनकी टीम। जागरण

झारखंड में बिरहोरों को बचाने की जंग लड़ रहा यह बुजुर्ग डॉक्टर

युवतियों व महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन देकर इनका प्रयोग करने का संकल्प कराते डॉ. अशोक। जागरण

मोहन गोप • धनबाद

स्वस्थ समाज

धनबाद का तोपचांची प्रखंड माओवाद प्रभावित है। यहां के चलकरी गांव में विलुप्त हो रही बिरहोर आदिम जनजाति के 50 परिवार रहते हैं। इन परिवारों में कुल सदस्यों के संख्या लगभग 300 है। बिरहोर समुदाय विलुप्तप्राय जानजातियों की सूची में शामिल है और अभी भी इस समुदाय के लोग विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके हैं। अपने खास जिद्दी मिजाज के कारण जंगलों में आदिम जीवनशैली का दामन थामे ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक की सुविधाओं से भी दूर हैं। बीमार होने पर अस्पताल नहीं जाते। स्वच्छता और वैज्ञानिकता के मायने भी कम ही समझते हैं। यही कारण है कि जनजातीय समाज में मृत्युदर भी ज्यादा है। ऐसे में इनका संरक्षण करना और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने इनके लिए कुछ विशेष योजनाओं और सुविधाओं के प्रावधान बनाए हैं, लेकिन इसका लाभ ये लोग कम ही उठा पाते हैं।

इस ओर जब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआइएमएफआर) से सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए वैज्ञानिक डॉ. अशोक शर्मा का ध्यान गया तो उन्होंने बिरहोरों के लिए कुछ करने की ठानी। धनबाद के डिगवाडीह में रहने वाले अशोक अब इस जनजाति को कुपोषण के खतरे बता सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हर मंगलवार व शुक्रवार को वे घर से करीब 50 किमी दूर जाते हैं और वहां बिरहोर परिवार के सदस्यों को शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। समुदाय के लोगों में मधुमेह, रक्तचाप व अन्य बीमारियों की जांच करते हैं और इस आधार पर उन्हें परामर्श देते हैं। जरूरत पर अपने परिचित चिकित्सक डॉ. एसके भगानिया से भी परामर्श दिलाते हैं। डॉ. अशोक शर्मा पिछले दो वर्षों से इस मुहिम में शिद्दत से लगे हैं। बिरहोरों की सेवा में उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया है। पेंशन से मिलने वाली राशि का 30 फीसद से अधिक हिस्सा वे बिरहोरों पर हर माह खर्च कर देते हैं। न कोई संगठन, न कोई संस्था। अशोक बस एक झोला लेकर निकल पड़ते हैं, अपने अभियान में। वह कहते हैं कि उन्हें इससे संतुष्टि मिलती है। अभियान रंग भी लाने लगा है। भरोसा है कि बिरहोर समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के प्रति नई चेतना जागेगी और उनकी मुश्किलें दूर होंगी।

चलकरी गांव में रह रहे बिरहोरों का मुख्य पेशा रस्सी और पत्तल बनाना है। डॉ. अशोक शर्मा ने 150 बिरहोरों का एक रजिस्टर तैयार किया है।

करमी बिरहोरिन के रक्तचाप की जांच करते सिंफर से सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त डॉ. अशोक शर्मा। जागरण

पौष्टिक अनाज व फल कराते हैं उपलब्ध

डॉ. अशोक ने बताया कि सफाई के प्रति लापरवाही से बीमारियां आती हैं। पौष्टिक भोजन न मिला तो कुपोषण का खतरा बढ़ता है। हम विटामिन व प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए बिरहोर समुदाय के लोगों को अंकुरित सोयाबीन, चना, राजमा, मूंग, उड़द, मूंगफली खाने की सलाह देते हैं। प्रोटीन व विटामिन युक्त अनाज, संतरा, नींबू समेत मौसमी फल का महत्व बताकर यह सामग्री उनके बीच वितरित भी करते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत रक्तचाप, मधुमेह की जांच करते हैं। उन्हें धूप के भी फायदे बताते हैं। डॉ. अशोक के परिवार में पत्नी सुधा, इंजीनियर बेटा विवेक शर्मा व बेटी प्रतिभा शर्मा है। बेटी शादी के बाद दुबई में रहती है। सेवा के इस काम में परिवार का भी सहयोग मिलता है।

रंग ला रही मुहिम, शिक्षा व स्वास्थ्य का मोल समझने लगे लोग

एक समय था जब माहवारी जैसे विषय पर बिरहोर महिलाएं किसी से बात तक नहीं करती थीं। डॉ. शर्मा ने उन्हें पीरियड के दौरान गंदे कपड़े की जगह सेनेटरी नेपकिन का प्रयोग करने की सलाह दी। इन्हें वे हर सप्ताह गांव में जाकर बांटते भी हैं। अब यहां की महिलाएं व युवतियां नैपकिन का प्रयोग करने लगी हैं। बिरहोर भोजन से पहले व बाद में अब हाथ जरूर धोते हैं। शिक्षा का महत्व भी अब उन्हें समझ में आने लगा है, बच्चों को ये स्कूल भेजने लगे हैं। गांव की करमी व चांदनी बिरहोरिन ने बताया कि दादा हमारी मदद को मसीहा बनकर आए हैं। हमारी स्वास्थ्य जांच करते हैं। स्वस्थ रहने के उपाय बताते हैं। ऐसे जरूरत के सामान लाते हैं जो हमने प्रयोग नहीं किए थे।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 26 जनवरी 2020
आजकल
16
www.jagran.com

मोर राष्ट्रीय पक्षी घोषित, अमर जवान ज्योति की स्थापना

आज ही के दिन 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया। आज ही के दिन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। वहीं सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता मिली। इसी दिन 1965 में हिंदी राजभाषा बनी।

पहली बार टेलीविजन का सार्वजनिक प्रदर्शन

आज ही के दिन 1926 में स्कॉटलैंड के आविष्कारक जॉन लॉजी बेयर्ड ने पहली बार टेलीविजन का प्रदर्शन किया था। लंदन में आयोजित प्रदर्शन के दौरान उन्होंने इसे टेलीविजर नाम दिया। उस वक्त एक सेकेंड में 12 .5 तस्वीरों को गुजारा गया। हालांकि तस्वीरें ज्यादा स्पष्ट नहीं थीं।

जेल में 14 वर्ष रहीं स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू

आज ही 1915 में स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म मणिपुर के छोटे से गांव में हुआ था। 13 साल की उम्र में ही वह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ीं। 17 अक्टूबर 1932 को समर्थकों के साथ उन्हें उम्रकैद की सजा हुई। रानी गाइदिन्ल्यू 1933 से 1947 तक जेल में रहीं। रानी का खिताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। 1960-66 तक एजे फिजो के नागा नेशनल काउंसिल से लड़ने के लिए वह भूमिगत रहीं। बाद में उनके समर्थकों को नगालैंड आर्म्ड पुलिस की बटालियन के रूप में शामिल कर लिया गया। 17 फरवरी 1993 को उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

हाथियों ने लिया बर्फ का मजा

मॉस्को, एजेंसी : आपने बर्फ में खेलने का मजा तो जरूर लिया होगा लेकिन किसी हाथी को ऐसा करते हुए शायद ही देखा हो। रूस में एक सर्कस के दो हाथी सारी बंदिशों को पार कर बर्फ में खेलने के लिए निकल पड़े। येकेतेरिनबर्ग सर्कस के मुताबिक, 45 साल की हथिनी कार्ला और 50 साल का हाथी रोनी सेंट पीट्सबर्ग जाते वक्त अपने संचालकों से बंधन छुड़ाकर कर बर्फ में घूमने लगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इनमें से एक हाथी बर्फ में लेट रहा है और संचालक उसे नियंत्रित करने की कोशिशों में जुटे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद बहुत से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक शख्स ने कहा कि हाथी बहुत ही समझदार होते हैं तो दूसरे ने कहा कि आजादी हर किसी को प्यारी होती है। यहां की एक सड़क को हाथियों के कारण बंद करना पड़ा।

लैब में बनी विष ग्रंथि से निकलेगा जहर

उपलब्धि ▶ सांप के जहर से बनने वाली दवाओं और एंटी वेनम के निर्माण में आएगी तेजी

दुनियाभर में करीब एक लाख लोगों की सांप काटने से हर साल होती है मौत

लंदन, प्रेट्र : भविष्य में सांपों के जहर से बनने वाली दवाएं और एंटीवेनम के निर्माण में बड़ी सफलता मिलने वाली है। दरअसल, वैज्ञानिकों ने लैब में सांपों की विष ग्रंथि को विकसित किया है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक सांप का जहर तैयार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के इस कदम से कई तरह की दवाइयों को बनाने में भी मदद मिल सकती है।

यह अध्ययन 'सेल' जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने केप कोरल सांप के ऑर्गन लैब में बनाए। यह सांप दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस विधि से विष के उत्पादन में अभूतपूर्व तेजी लाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात कि यह विधि अपेक्षाकृत सस्ती भी है। गौरतलब है कि पहले की विधि के अनुसार, सांपों को पालना पड़ता है और फिर उनकी विष ग्रंथियों से जहर निकालना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खर्चीला और अधिक समय लेने वाला काम है। शोधकर्ताओं ने बताया कि अभी तक विभिन्न प्रयोगशालाओं में मनुष्य और चूहों की कोशिकाओं से बने ऑर्गन ही बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अब पहली बार किसी सरीसृप के ऑर्गन को विकसित किया गया है।

इस तरह बनाई विष ग्रंथि : शोधकर्ताओं ने विष ग्रंथि बनाने के लिए केप कोरल सांप का चयन किया। इन सांपों के अंडों को उनके सेने से पहले ही हटा दिया गया।

इसके बाद उससे प्राप्त किए गए ऊतकों को एक विशेष जेल में रखकर विकसित किया गया। विष ग्रंथियों का विकास इतनी तेजी से हुआ कि एक हफ्ते में ही वे पूर्ण विकसित हो गईं। शोधकर्ताओं ने इस दौरान सांप की ग्रंथि बनाने के साथ ही उसके लिवर, पैंक्रियाज और आंत भी बनाए।

वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले केप कोरल सांप की विष ग्रंथियां बनाईं। प्रतीकात्मक

जहर में होते हैं बेहद शक्तिशाली घटक

हर सांप के जहर में दर्जनों अलग-अलग प्रकार के घटक होते हैं। ये बेहद शक्तिशाली मॉलीक्यूल हैं जो उनके शिकार को भागने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। ये घटक शिकार के मस्तिष्क, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, रक्त में जमावट आदि विभिन्न प्रणालियों को प्रभावित करते हैं।

एक लाख लोग गंवा देते हैं जान : नीदरलैंड की उट्रेच यूनिवर्सिटी के हैंस क्लेवर्स ने बताया कि एक साल में लगभग एक लाख लोग सांप के काटने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। उन्होंने बताया कि विकाससील देशों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। फिर भी 19वीं सदी से एंटी वेनम बनाने के तरीकों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। नई विधि एक नई उम्मीद लेकर आई है। इससे उनके इलाज या बचाव में काफी मदद मिलने की उम्मीद है।

वैज्ञानिकों ने पहली बार खोजा 'वैम्पायर' स्टार

केप्लर स्पेस टेलीस्कोप से एकत्रित आंकड़ों की मदद से लगाया पता। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन डीसी, एएनआइ : खगोलविदों ने केप्लर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक 'वैम्पायर' स्टार (तारा) खोजने का दावा किया है। यह तारा ब्रह्मांड में रहस्यमयी तरीके से विस्फोट के जरिये काफी तेजी से फैलता है। उनका कहना है कि इसका पता केप्लर स्पेस टेलीस्कोप से एकत्रित आंकड़ों की मदद से लगाया गया है। प्रमुख शोधकर्ता रेयान रिडन-हार्पर का कहना है कि हमें अध्ययन के दौरान एक ड्वार्फ नोवा मिला। यह अचानक विस्फोट करने वाले तारों का समूह है, जिसके घटकों में व्हाइट ड्वार्फ भी होते हैं। यह एक ऐसा तारा है कि हमारा सूरज भी अरबों वर्षों के अंतराल के बाद इस तरह का बन जाएगा और इसके घटकों में ब्राउन ड्वार्फ दिखेंगे। यह ड्वार्फ 10 गुना कम घना और ग्रह की तरह दिखने वाला एक असफल तारा है।

द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में अपने पीएच.डी के तौर पर इसका अध्ययन करने वाले हार्पर ने बताया, 'यह दुर्लभ घटना हमें ड्वार्फ नोवा से विशाल विस्फोट की वजह से मिलती है। यह बिलकुल वैम्पयार स्टार सिस्टम की तरह हो सकता है।' उन्होंने आगे बताया, 'केप्लर से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि 30 दिनों की अवधि के दौरान ड्वार्फ नोवा तेजी से मद्धम होने और धीरे-धीरे अपनी सामान्य चमक में आने से पहले 1600 गुना अधिक चमकीला हो जाता है।' यह चमक ड्वार्फ के इर्द-गिर्द के पदार्थों को हटाने की वजह पैदा होती है, जो एक डिस्क में व्हाइट ड्वार्फ के चारों ओर रहता है। इस डिस्क का तापमान 11,7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे विशाल विस्फोट

▶ **ड्वार्फ नोवा नामक यह तारा बहुत ही जल्द सामान्य से 1600 गुना अधिक चमकीला हो जाता है**

होता है। यह अध्ययन दुर्लभ रूप से होने वाली खगोलीय परिघटना का पता लगाने के लिए किया गया है, जो बड़ी तेजी से होती हैं। जैसे- सुपरनोवा के तीव्र विघटन से गामा किरणों का विस्फोट, न्यूट्रोन तारों की टक्कर या वैसी घटनाएं जिन्हें पहले कभी टेलीस्कोप की मदद से नहीं देखा गया।

रिडन हार्पर ने यह खोज एएनयू केसहयोगियों, स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नोत्रे डेम की मदद से की है। उन्होंने बताया, 'इस ड्वार्फ नोवा की खोज चौंकाने वाली थी, क्योंकि हम इसकी खोज नहीं कर रहे थे। लेकिन इससे हमें गजब के आंकड़े और इन वैम्पायर तारों को समझने की नई दिशा मिली।' उन्होंने बताया कि हमारा अगला कदम केप्लर आंकड़ों का बारीकी से अध्ययन करना और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनट सर्वे सैटेलाइट के आंकड़ों को विस्तार देना होगा। हार्पर ने कहा, 'इन आंकड़ों के संयुक्त अध्ययन से ब्रह्मांड में सबसे तेजी से होने वाली विस्फोट की घटना को समझने में मदद मिलेगी। यह भी संभव है कि हम उन दुर्लभ घटना का भी पता लगा सकें, जिसे अभी तक कोई भी टेलीस्कोप नहीं लगा पाया है।'

हार्पर के अध्ययन की समीक्षा करने वाले डॉ. ब्रैड टकर का कहना है, 'हमने इसका उपयोग तारों के विस्फोट को, ब्लैकहोल के गुप्त रहस्यों और अब हाल में वैम्पायर तारों को देखने में किया है। यह पहली बार हुआ है।'

तकनीकी कारणों से टला इस साल रूस का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण

मॉस्को, आइएएनएस : रूस के इस साल का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीकी कारणों के चलते 24 घंटे के लिए टाल दिया गया है। रूस के सोयुज 2.1ए रॉकेट द्वारा एक सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाना था। पहले यह प्रक्षेपण शुक्रवार को किया जाना था। अंतरिक्ष उद्योग से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, प्लेसेत्स्क प्रक्षेपण केंद्र से मेरिडियन उपग्रह के साथ सोयुज 2.1ए रॉकेट के प्रक्षेपण को तीन तकनीकी कारणों से टाला गया है। सूत्रों के अनुसार, इसे अनिश्चितकाल के लिए भी स्थगित किया जा सकता है। प्रक्षेपण को टालने का आदेश ईंधन भरने से पहले ही दे दिया गया था।

रूस में अंतरिक्ष बलों के कमांडर कर्नल-जनरल अलेक्जेंडर गोलोवको ने बताया था कि रक्षा मंत्रालय साल 2020 के जनवरी माह में एक और मेरिडियन-एम उपग्रह को लांच करेगा। पहला प्रक्षेपण इसी लांच पैड से 11 दिसंबर, 2019 को किया गया। मेरिडियन दूसरी पीढ़ी का संचार उपग्रह है, जिसने मोलनिया और रादुगा अंतरिक्ष वाहनों को प्रतिस्थापित किया। सक्रिय उपग्रहों का जीवनकाल सात साल का है।

हाई स्कूल के बाद हर दिन सात मिनट कम हो जाती है शारीरिक गतिविधि

वाशिंगटन डीसी, एएनआइ : बढ़ती उम्र, हमारी शारीरिक गतिविधियों और जीवनशैली में विशेष संबंध होता है। हालिया अध्ययन में यही समझने की कोशिश की गई है कि हाई स्कूल पूरा करने के बाद पेशेवर दुनिया में कदम रखने के साथ ही हमारी शारीरिक गतिविधियां कम होती जाती हैं और मां बनने के बाद वजन में वृद्धि में होती है। यह अध्ययन ओबेसिटी रिव्यू में प्रकाशित हुआ है, जिसे कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर डाइट एंड एक्टिविटी रिसर्च (सीईडीएआर) के शोधकर्ताओं ने किया है। शोधकर्ताओं की टीम ने दो अध्ययन किए, जिसमें हाई स्कूल के बाद रोजगार में प्रवेश करने और फिर मां बनने के बाद के बदलावों का विश्लेषण किया गया है।

पहले अध्ययन में पाया गया कि हाई स्कूल छोड़ने के बाद हमारी शारीरिक गतिविधि प्रतिदिन लगभग सात मिनट कम हो जाती है। विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे अधिक बदलाव तब होता है, जब व्यक्ति यूनिवर्सिटी जाता है। तब व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि (सामान्य से कठिन)

▶ **पढ़ाई, रोजगार और बच्चों की देखभाल जैसे दबावों से आता है व्यवहार में बदलाव**

▶ **दूरगामी स्वास्थ्य के लिहाज से साबित हो सकते हैं खतरनाक**

प्रतीकात्मक।

11.4 मिनट प्रतिदिन कम हो जाती है। यह भी पाया गया कि हाई स्कूल छोड़ने के बाद व्यक्ति के खानपान की गुणवत्ता में गिरावट आती है। सीईडीएआर और कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में एमआरसी एपिडेमिलॉजी यूनिट के डॉ. एलेनॉर विनपेनी का कहना है, 'स्कूलों में स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की वजह बच्चे अपेक्षाकृत बेहतर माहौल रहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का दबाव, रोजगार और बच्चों की देखभाल जैसी चीजों से व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आता है, जो दूरगामी स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है।' उन्होंने आगे बताया, 'जब व्यक्ति में स्वस्थ या अस्वस्थ आदतें बनने लगती हैं, तो वाकई में यह महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि वही आदतें पूरे वयस्क जीवन तक चलती रहती हैं। अगर हम अपने वयस्क जीवन में अस्वस्थ आदतों को पहचानना शुरू कर दें, तो हम उसमें बदलाव लाने की दिशा में काम कर सकते हैं।'

दूसरे अध्ययन में शोधकर्ताओं की टीम ने मां बनने पर वजन, खानपान और शारीरिक गतिविधियों का विश्लेषण किया। अध्ययन करने वाली टीम ने पाया कि बिना बच्चों वाली और औसतन 164 सेंटीमीटर की लंबाई वाली महिला का वजन पांच से छह वर्षों में 7.5 किलोग्राम तक बढ़ा, जबकि इसी लंबाई की महिला जब मां बनती है, तो उसका वजन 1.3 किलोग्राम और अधिक बढ़ जाता है।

अब धोखाधड़ी रोकने के लिए टिंडर पर होगा फोटो सत्यापन

टोक्यो, प्रेट्र : मशहूर डेटिंग एप टिंडर अब सदस्यों के फोटो सत्यापन का काम शुरु करने जा रहा है। फोटो सत्यापन का मकसद यह है कि इस एप में धोखाधड़ी को कम किया जा सके। इससे इस एप में आने वाले लोग दूसरों के वास्तविक चेहरे देख उनका चयन कर पाएंगे।

मशहूर डेटिंग एप टिंडर के सीईओ एली सीडमैन ने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा, 'हर दिन हमारे लाखों सदस्य हम पर भरोसा करके साइट पर आते हैं कि हम उन्हें नए लोगों से मिलवाएंगे। हम नई तकनीकों के माध्यम से एप को और अधिक पारदर्शी बनाने पर काम कर रहे हैं।' नई तकनीक के माध्यम से टिंडर के सदस्य को इस एप पर अपनी रियल टाइम फोटो डालनी होंगी। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उन फोटो की मैचिंग प्रोफाइल फोटो से की जाती है। इस तरह फोटो का सत्यापन होता है। फोटो सत्यापित होने के बाद उस पर एक नीला चेकमार्क लग जएगा। यह चेकमार्क इसलिए होगा, ताकि दूसरे उनकी प्रमाणिकता पर भरोसा कर सकें।

फोटो न्यूज

बांध हादसों के मृतकों को अनोखी श्रद्धांजलि

ब्राजील के प्रसिद्ध आर्टिस्ट मुंडानो ने बांध के धराशायी होने से मारे गए लोगों को अनोखे ढंग से श्रद्धांजलि दी। साओ पाउलो में मुंडानो ने बांध स्थल की मिट्टी में रंग मिलाकर मृत लोगों के भित्ती चित्र बनाए। पिछले साल 25 जनवरी को साओ पाउलो में बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी का बांध टूटने से 166 लोगों की मौत हो गई थी और कई सौ लोग लापता हो गए थे। रायटर

उच्च प्रोटीन के आहार से हार्ट अटैक का खतरा

शोध अनुसंधान

उच्च प्रोटीन वाला आहार वजन कम करने और मांसपेशियों के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन इसका हृदय की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक नए अध्ययन का दावा है कि इस तरह के आहार से दिल के दौरे (हार्ट अटैक) का खतरा बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, चूहों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि उच्च प्रोटीन वाले आहार से धमनियों में प्लैक जमा होने लगता है। इसके चलते धमनियां अवरुद्ध होने लगती हैं। ज्यादा प्लैक जमा होने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर बाबक रजानी ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि उच्च प्रोटीन वाला आहार वजन घटाने में मददगार होता है, लेकिन पशुओं पर किए गए अध्ययनों में इस तरह के आहार और हृदय संबंधी समस्याओं क बीच गहरा संबंध पाया गया है।' -आइएएनएस

लिथियम की मामूली खुराक अल्जाइमर में कारगर

भूलने की बीमारी अल्जाइमर के उपचार में लिथियम की अहम भूमिका पाई गई है। इस रासायनिक पदार्थ की मामूली खुराक से इस बीमारी को रोका जा सकता है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि मूड डिसआर्डर में जितनी मात्रा में लिथियम की सलाह दी जाती है, उससे 400 गुना कम खुराक देने से अल्जाइमर की रोकथाम हो सकती है। इससे स्मृति भी दुरुस्त हो सकती है। अल्जाइमर डिजीज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, यह निष्कर्ष चूहों पर किए गए एक शोध के आधार पर निकाला गया है। परीक्षण के दौरान चूहे पर पहले पारंपरिक लिथियम फार्मूले को आजमाया गया। चूहे को उसी मात्रा में खुराक दी गई, जितनी मात्रा मूड डिसआर्डर में देने की सलाह दी जाती है। इसका चूहे में प्रतिकूल असर देखने को मिला। इसके बाद नए फार्मूले के आधार पर खुराक दी गई। इसका सकारात्मक प्रभाव पाया गया। -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

महिलाओं को वर्दी में देखकर गर्व होता है : अंगद बेदी

गणतंत्र दिवस से जुड़ी सबसे खास याद साझा करते हुए अंगद बेदी कहते हैं कि एक बार वह 26 जनवरी के दिन परेड देखने गए थे। वहां फाइटर प्लेन का शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा था। उसे देखकर वह हैरत में पड़ गए थे। अंगद के मुताबिक, 'फाइटर प्लेन को इतने करीब से देखने के बाद पांच-छह साल की उम्र में मेरे मन में भारतीय एयरफोर्स पायलट बनने की ख्वाहिश जाग गई थी। मेरे चचरे भाई ने कहा कि तुम्हें टॉम क्रूज की 'टॉप गन' फिल्म देखनी चाहिए, जिसमें वह यूनिफॉर्म में प्लेन उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। उस फिल्म में टॉम क्रूज ने एविएटर चश्मा और पायलट वाला सूट पहना था। मेरी भी ख्वाहिश थी कि कभी मैं वह यूनिफॉर्म पहनूं।' अंगद बेदी बताते हैं, 'मैं 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' फिल्म की शूटिंग कर रहा था। फिल्म में मैं आर्मी ऑफिसर बना हूं। फिल्म में बहन बनी जाह्नवी कपूर एयरफोर्स पायलट का किरदार निभा रही हैं। जब मैंने उन्हें फाइटर प्लेन के पायलट वाली यूनिफॉर्म में देखा तो बचपन की सारी यादें फिर ताजा हो गईं। मैं हमेशा से खुद को यूनिफॉर्म में देखना चाहता था। जाह्नवी को देखकर लगा कि महिलाएं यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगती हैं। पुरुष भी यूनिफॉर्म में उतने ही जांबांज लगते हैं, लेकिन जब महिलाएं वर्दी पहनती हैं, तो देश के लिए गर्व की बात होती है। इससे दूसरे देश हमारे देश को एक अलग नजर से देखते हैं। वह देश की ताकत का अंदाज लगा सकते हैं, जहां महिलाएं इतने उच्च स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह सम्मान की बात है।'

इमानदारी और सच्चे मन से दूसरों की मदद करना ही है असल देशभक्ति : काजल अग्रवाल

'सिंघम', 'स्पेशल 26' जैसी फिल्मों में नजर आईं काजल अग्रवाल का कहना है, '26 जनवरी के दिन अगर शूटिंग होती हैं, तो हम सेट पर भी ध्वजारोहण करते हैं। पूरा माहौल देशभक्तिमय होता है, लेकिन केवल देशभक्ति का ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता है। मूल्य और नैतिकता सीखना भी जरूरी है। ईमानदारी और सच्चे मन से किसी की मदद करना हमारे हिंदुस्तानी मूल्यों में शामिल है। असल देशभक्ति यही है। हमारी अतिथि देवोभवः की संस्कृति है। इन बातों को सामान्य जीवन में शामिल करना चाहिए। कुछ समय पहले मुझे मिलिट्री फोर्सेस के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था। उनके जीवन को करीब से जाना। उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातें बताईं। युद्ध के मैदान पर जब होते हैं, तो क्या महसूस करते है, मुश्किलें क्या होती हैं, परिवार से दूर रहने का दर्द क्या होता है। सैनिकों की ये कहानियां दिल को छू लेती हैं। हम उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं।'

अपने वक्त से पहले की फिल्म थी 'रंग दे बसंती' : अतुल कुलकर्णी

गणतंत्र दिवस के आसपास देशभक्ति से जुड़ी फिल्में रिलीज होती आई हैं। 14 साल पहले 2006 में इसी दिन रिलीज हुई फिल्म 'रंग दे बसंती' ने देशभक्ति का एक नया चेहरा दिखाया था। इस फिल्म में रामप्रसाद बिस्मिल का किरदार निभाने वाले अभिनेता अतुल कुलकर्णी का कहना है कि 'रंग दे बसंती' ने पिछले 14 साल में उन्हें हर वक्त कुछ न कुछ दिया है। अतुल कहते हैं कि यह फिल्म मॉडर्न क्लासिक फिल्म रही है। 'रंग दे बसंती' की सोच अपने वक्त से बहुत आगे की थी। निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा के लिए उस वक्त इस फिल्म को बनाना आसान नहीं था।' अतुल बताते हैं कि फिल्म की रिलीज के बाद

मेहरा ने कहा था कि अच्छी फिल्म की पहचान यह होती है कि वह बनने के बाद फिल्ममेकर के बजाय दर्शकों की बन जाती है। अतुल कहते हैं, 'फिल्म में कैंडल मार्च से विरोध-प्रदर्शन करने का सीन था। उसके बाद इंडिया गेट पर विरोध में कैंडल मार्च हुआ था। कहीं न कहीं वह प्रेरणा 'रंग दे बसंती' से ली गई थी।'

सोनू नई पीढ़ी को समझाते हैं इस दिन का महत्व

हर किसी की तरह सोनू सूद के लिए भी गणतंत्र दिवस खास रहा है। वह कहते हैं कि इस दिन का जिक्र होते ही दूरदर्शन पर सुबह का वह वक्त याद आ जाता है, जब घर पर टेलीविजन लगा दिया जाता था और इस पर इंडिया गेट पर चल रही परेड दिखाई जाती थी। अब तो हर चैनल पर परेड देखने को मिल जाती है। सोनू कहते हैं कि भारतीय होने पर गर्व तो हमेशा ही रहता है, लेकिन इस दिन यह भावना और बढ़ जाती है। जब छोटा था, तब स्कूल में ध्वज फहराने जाते थे। बिल्डिंग की सोसाइटी में भी खास समारोह किया जाता था, उसमें भी हिस्सा लेते थे।

श्वेता त्रिपाठी घर की छत से देखती थीं उड़ते हुए लड़ाकू विमान

'मसान', 'हरामखोर' और 'गॉन केश' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का शानदार प्रदर्शन कर चुकी अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी दिल्ली से ताल्लुक रखती हैं। वह दिल्ली में बिताए गणतंत्र दिवस को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव मानती हैं। दिल्ली की यादें ताजा कर वह बताती हैं, 'मेरे पिता दिल्ली में एक आइएएस अधिकारी थे। अब वह रिटायर हो चुके हैं। तब हमारा घर दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास था। गणतंत्र दिवस के दिन सुबह-सुबह दूरदर्शन पर इंडिया गेट पर हो रहे परेड को देखना हमारे लिए एक रिवाज जैसा था। इससे हमें पढ़ाई न करने का बहाना भी मिल जाता था। कार्यक्रम के अंत में लड़ाकू विमान और गुब्बारे उड़ाए जाते थे। इसे देखने के लिए हम भागकर छत पर जाते थे। हमारी छत से पूरा कार्यक्रम दिखता था। उस समय आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर सीना गर्व से तन जाता था। दिल में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती थी। मेरे लिए यह बचपन की सबसे बेहतरीन यादें हैं। दूरदर्शन पर यह परेड इतनी खूबसूरती से दिखाई जाती थी कि हमने कभी इंडिया गेट जाकर परेड देखने के बारे में नहीं सोचा। कुछ दिनों बाद पापा का तबादला अंडमान-निकोबार हो गया। वहां पर स्कूल में होने वाले मार्ट पास्ट में मैं सबका नेतृत्व करती थी। आगे से पीछे की सभी लड़कियों को विभिन्न मुद्राओं में खड़े होने का निर्देश देना भी मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है।' इस साल श्वेता 'मिर्जापुर 2' में काफी अहम किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा वह कुछ फिल्में भी कर रही हैं।

26 जनवरी को मार्च पास्ट करने का जोश दोगुना होता था : श्रद्धा कपूर

राष्ट्रगान जब भी बजता है, तब हर भारतीय के चेहरे पर गर्व की भावना साफ नजर आती है। श्रद्धा कपूर का कहना है कि राष्ट्रगान और भारतीय ध्वज को लेकर यह एहसास तब से ही रहा है, जब चीजों को समझने लायक हुईं। वह कहती हैं, 'स्कूल में 26 जनवरी को उपस्थिति जरूरी होती थी। रोज के मुकाबले उस दिन स्कूल का टाइम अलग होता था। जल्दी उठना पड़ता था, फिर भी ऊर्जा होती थी। टीचर्स और स्कूल के दोस्तों के बाच झंडा फहराने के बाद जब राष्ट्रगान बजता था, तो वह पल ही अलग होता था। मैंने मार्च पास्ट में भी भाग लिया है। मार्च पास्ट में अनुशासन की जरूरत पड़ती है। उस दिन मार्च पास्ट करने का जोश दोगुना होता था। आज भले ही मैं स्कूल में नहीं हूं, लेकिन इस दिन को लेकर भावनाएं बिल्कुल नहीं बदली हैं।'